



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 23, 2015/चैत्र 2, 1937

No. 168]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 23, 2015 /CHAITRA 2, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

[रक्षोपाय महानिदेशालय (सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद कर)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2015

**विषय : 400 श्रृंखला के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयात से संबंधित रक्षोपाय जांच—अंतिम जांच परिणाम**

**सा.का.नि. 219 (अ).**—सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और उसके अंतर्गत बने (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 को ध्यान में रखते हुए।

**1. प्रक्रिया**

1. मेरे समक्ष मैसर्स जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, जिंदल सेंटर, 12 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 द्वारा सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 5 के अंतर्गत एक आवेदनपत्र एएसटीएम ए240/ए240एम के अनुरूप सभी मार्टेन्सिटिक एवं फेरिटिक ग्रेडों और अन्य स्टैंडर्ड्स में जैसे यूएनएस, आईएस, चाइनीज डीआईएन, जेआईएस, बीआईएस, ईएन आदि समनुरूप। तुलनीय विनिदेशनों को शामिल करते हुए 400 सीरीज के क्रोमियम टाइप के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों, जिनमें (i) 1700 एमएम और उससे ऊपर की चौड़ाई के और (ii) जेबीएस (जिंदल ब्लेड स्टील) ग्रेड और उसके समकक्ष के शामिल नहीं हैं," (जिन्हें एतद्पश्चात् विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) कहा गया है) के भारत में आयातों पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए दायर किया गया है जिससे 400 सीरीज के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के घरेलू उत्पादों की भारत में 400 सीरीज के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के बढ़ते आयातों द्वारा कारित गंभीर क्षति/गंभीर क्षति की चुनौती से रक्षा की जा सके।

2. रक्षोपाय नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का घरेलू उत्पादकों के संयंत्रों का स्थल दौरा करके आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया। इस बात से संतुष्ट होने पर कि नियम 5 के अंतर्गत सभी अपेक्षाएं पूरी होती हैं, सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6 के अंतर्गत भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच शुरू करने का नोटिस दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को जारी किया गया और उसे उसी दिन भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित कराया गया।

3. घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदनपत्र के अगोपनीय पाठ की एक प्रति के साथ दिनांक 19 सितम्बर, 2014 के जांच शुरुआत नोटिस की एक प्रति केंद्रीय सरकार वाणिज्य मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों को प्रमुख निर्यातक देशों की सरकारों को भारत स्थित उनके राजदूतावासों के जरिए और घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदनपत्र के अनुबंध 6 से 9 के अंतर्गत उल्लिखित हितवद्ध पक्षकारों को, जिनमें घरेलू उद्योग भी शामिल है, सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6(2) और 6(3) के अनुसार प्रेषित की गई।

4. उपलब्ध सूचना के अनुसार ज्ञात निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रश्नावलियां इस अनुरोध के साथ भेजी गई कि वे इस जांच शुरूआत नोटिस की तारीख से 30 दिनों के अंदर अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत कराएं।

5. निम्नलिखित पक्षकारों से यह अनुरोध प्राप्त हुआ कि उन्हें हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना जाए और उनके इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया :

- (क) वियतनाम कम्पटीशन अथॉरिटी (वीसीए), उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय (वियतनाम समाजवादी गणराज्य की ओर से) 25 न्यू क्वीन सेंट, होआन कीम, हनोई सिटी वियतनाम
- (ख) जापान चैम्बर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया (जेसीसीआईआई) फ्लैट नं. 106, नीलगिरि अपार्टमेंट्स, 9, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
- (ग) जापान सरकार, जापान का राजदूतावास, 50जी, शांति पथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
- (घ) भारत गणराज्य में रूसी परिसंघ का व्यापार प्रतिनिधिमंडल, ब्लॉक 50 ई, न्याय मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
- (ङ) अर्थव्यवस्था मंत्रालय, औद्योगिक कार्य विभाग – पाटनरोधी निदेशालय, पीओ बॉक्स-3625, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
- (च) गोशी इंडिया आटो पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, 363, 364, सेक्टर 3, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, बावल, फेज-II, जिला रेवाड़ी, हरियाणा-123501, भारत
- (छ) ईएलपी एडवोकेट्स एंड सालिसिटर्स, 1502, डालामल टावर्स, नरीमन प्वाइंट मुंबई-400021, मैसर्स आउटोकुम्पू ओयज की ओर से
- (ज) मेटल वन कारपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सूद टावर, प्रथम तल, 25, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
- (झ) मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (एमएसएसएमए), 63, जमनादास भवन, भूतल, 10वीं खेतवाड़ी लेन, मुंबई-400004, लक्ष्मीकुमारन एंड श्रीधरन एडवोकेट्स, 5 लिंक रोड, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110014 की ओर से
- (ञ) स्पेशल स्टील एसोसिएशन आफ जापान (जेएसएसए), 3.2.10, निहोनबासी – कायाबाचो, चोउ-कू, टोकियो, 103-0025
- (ट) स्पेशल स्टील एसोसिएशन आफ जापान (एसएसएजे), टेक्को, काइकान बिल्डिंग 3.2.10, निहोनबासी – कायाबाचो, चोउ-कू, टोकियो, 103-0025
- (ठ) जेएफई स्टील कारपोरेशन, हिविया कोकुसाई बिल्डिंग, 2-3, उचिसाइवाई – जे 2 कोम, टियोडा-कू, टोक्यो-100-0011, जापान
- (ड) निशिन स्टील कंपनी लिमिटेड, शिन कोकुसाई बिल्डिंग, 4-1, मरुनोउची 3 कोमे, टियोडा-कू, टोक्यो 100-8366 जापान
- (ढ) निपन स्टील एंड सुमिकिन स्टेनलेस स्टील कारपोरेशन, 2-6-1, ओटेमाची, चियोडा-कू, टोकियो 100-0004, जापान
- (ण) मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, पालम गुडगांव रोड, गुडगांव-122015, हरियाणा
- (त) मरूइजी कुमा स्टील ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 27, सेक्टर-2ए, आईएमटी मानेसर, गुडगांव-122050 (हरियाणा)
- (थ) हीरो मोटो कार्प लिमिटेड, 37 केएम स्टोन, दिल्ली-जयपुर राजमार्ग, सेक्टर 33, गुडगांव-122001 (हरियाणा)
- (द) मैसर्स पोस्को वीएसटी, 319, न्हान ट्रेक 1, इंडस्ट्रियल जोन, डांग नाइ प्राविन्स वियतनाम
- (ध) मैसर्स पोस्को, 1 क्योडांग-डांग, नाम-गु, पोहांग-सि, क्योंगसांगबुक डू, 790-785, कोरिया गणराज्य, (उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए पोस्को साउथ एशिया सं. 105, प्रथम तल, पार्क सेंटरा भवन, सेक्टर 30, गुडगांव-122001 को प्राधिकृत किया)
- (न) जापान आयरन एंड स्टील फेडरेशन, 3.2.10, निहोनबासी कायाबाचो चोउ-कू, टोक्यो, 103, 0025 जापान
- (त) पीटी जिंदल स्टेनलेस इंडोनेशिया, कावासैन इंडस्ट्री मैस्पिआन वी, देसा, सुकोमुल्यो, मान्यर ग्रेसिक 61151, जावा तिमूर, इंडोनेशिया
- (प) पोस्को थिनाक्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड, 31/एफ यूनिट 3101-3 सीआरसी टावर, आल सीजन्स प्लेस, 87/2 बायरलेस रोड लुम्पिनी, पारहुम्बन बैंकाक 10330, थाईलैंड
- (फ) मिनिस्ट्री आफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री मलेशिया (एमआईटीआई) लेवल 14, ब्लाक 8, सरकारी कार्यालय परिसर, जालान डुटा, 50622 कुआलालाम्पुर, मलेशिया
- (ब) वीराना पीटीई लिमिटेड, 20 कोलयेर कुआय, # 09-02, सिंगापुर 049319

- (भ) पीटी जिंदल स्टेनलेस इंडोनेशिया, क्वानसान इंडस्ट्री, मैस्पियान वी, देसा सुकोमुल्यो, मान्यर ग्रेसिक 61151, जावा तिमूर, इंडोनेशिया।

6. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिव्यक्त विचारों पर समुचित निर्धारण करने के लिए विचार किया गया। अवाप्त अथवा प्राप्त अगोपनीय सूचना को सार्वजनिक फाइल में रखा गया।

## II. हितबद्ध पक्षकारों को विचार (जांच शुरूआत नोटिस के पश्चात)

### क. रूसी परिसंघ का उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय

जांच की अवधि वर्ष 2011 से 2014 तक सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के उपशीर्षक संख्या 72193112, 72193111, 72193210, 72193310, 72193410, 72193510, 72202021, 72209021 के अंतर्गत आने वाली वस्तु के रूसी परिसंघ से भारत को आयात वर्ष 2011 में 5.05 टन, वर्ष 2012 में 3.17 टन, वर्ष 2013 में 5.16 टन और वर्ष 2014 में 5.98 टन हुए थे। तदनुसार, रूसी परिसंघ से भारत को इन उत्पादों का हिस्सा बहुत कम है और यह इन वस्तुओं के भारत को होने वाले कुल आयात का 0.01 प्रतिशत से अधिक नहीं है और इससे भारतीय उद्योग को गंभीर क्षति कारित नहीं हो सकती।

### ख. वियतनाम कम्पटीशन अथॉरिटी ("वीसीए"), वियतनाम सरकार

- (क) उत्पादन, घरेलू उद्योग की बिक्री, अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री, उत्पादकता, रोजगार और संस्थापित क्षमता में वृद्धि हुई है और विकास की प्रवृत्ति है। इसलिए, यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग को न तो क्षति हुई और न ही गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हुई।
- (ख) जांच शुरूआत सूचना में बढ़ते आयातों और गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंधों में कोई स्पष्टीकरण नहीं है।
- (ग) आयातित विचाराधीन उत्पाद में वृद्धि बढ़ती मांग के कारण हुई है। विशेष रूप से इस तथ्य के कारण कि घरेलू उद्योग घरेलू मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है।
- (घ) वियतनाम ने वियतनाम के सीमा शुल्क प्राधिकारियों से इस विचाराधीन उत्पाद की निर्यात सांख्यिकी के अनुसार भारत को इस विचाराधीन उत्पाद की अल्प मात्रा का निर्यात किया है।

### ग. इंडोनेशिया सरकार

इंडोनेशिया से आयात में वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में 0.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अतः, इंडोनेशिया से आयात 3 प्रतिशत से कम हैं और वे विश्व व्यापार संगठन, पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.1 के अंतर्गत भारतीय घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर सकते हैं।

### घ. तुर्की सरकार

इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर (ट्रेड मैप) सांख्यिकी के अनुसार, भारत को स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयात में तुर्की का अपना हिस्सा, मात्रा के रूप में और 6 अंकीय एचएस कोड में भी, 3 प्रतिशत से कम अनुपात में है, जिसका स्पष्टीकरण रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 9.1 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाना चाहिए।

### ड. मैसर्स वीराना पीटीई लिमिटेड (निर्यातक, सिंगापुर)

- (क) इस विचाराधीन उत्पाद की श्रृंखला बहुत व्यापक (विभिन्न ग्रेडों और आकारों सहित) है और उपयुक्त एवं समुचित क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ इसमें विशिष्ट ग्रेड तक कम करने/संशोधन करने की जरूरत है। इस विचाराधीन उत्पाद में ऐसे आकार के उत्पाद भी शामिल हैं जिनका भारत में न तो याचिकाकर्ता द्वारा और न ही किसी अन्य विनिर्माता द्वारा उत्पादन किया जाता है। 400 सीरीज ग्रेडों के कुल आयात में 80-90 प्रतिशत आयात 409 ग्रेड का होता है।
- (ख) इस जांच का दायरा विशिष्ट ग्रेडों तक (उदाहरणार्थ 409, 410 एस आदि) प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए जिनका उत्पादन और बिक्री याचिकाकर्ता द्वारा की जा रही है।
- (ग) कोल्ड रोल्ड 400 सीरीज ग्रेडों में, किसी सामग्री का न केवल रासायनिक संघटन या उसका आकार बल्कि उस सामग्री का फिनिश या मोटाई सहिष्णुता महत्वपूर्ण होती है। यदि बिना विस्तृत जांच के ही रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण कर दिया जाता है तो इससे विशेष रूप से ऑटोमोबाइल सेक्टर को भारी नुकसान होगा।
- (घ) इस उत्पाद की कीमत पर विचार करते हुए, भौगोलिक स्थिति के कारण इसके भाड़े का प्रभाव बहुत अधिक है। याचिकाकर्ता के उत्तर भारत और पूर्वी भारत के संयंत्र हैं। अधिकांश विनिर्माता पुणे, महाराष्ट्र आधारित हैं। याचिकाकर्ता निम्नवत प्रभार प्रभारित कर रहा है :

हिसार संयंत्र से पुणे : आईएनआर 2808/एमटी यूएसडी 46.80/एमटी\*

ओडिशा संयंत्र से पुणे : आईएनआर 4206/एमटी आईयूएसओ 70.10/एमटी\*

इसलिए, याचिकाकर्ता को वर्ष 2014-15 (की पहली तिमाही) में आईएनआर-957/एमटी का वित्तीय घाटा हो रहा था, यह वित्तीय घाटा अधिक आयातों के कारण न होकर परिवहन लागत के कारण हो रहा था।

- (ड) उत्पादक की बिक्री में निरंतर और वर्ष 2011-12 से वृद्धि हो रही है। वर्ष 2013-14 में उसकी बिक्री 81344 थी और यह बढ़कर वर्ष 2014-15 में 89672 हो गई। इसकी बिक्री में +10.23 प्रतिशत की निवल वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, उत्पादन के संबंध में आयात 90 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013-14 में 81 हो गए।
- (च) आयातों में यह वृद्धि इसलिए हुई कि घरेलू बरतन विनिर्माता अपने बरतनों का विनिर्माण करने में 430वीए/28 ग्रेड का प्रयोग करने लगे, इससे पहले उनके लिए 200/201 आदि ग्रेड ही उपयोगी थे, जिनका उत्पादन याचिकाकर्ता द्वारा किया जाता था।

- (छ) याचिकाकर्ता पहले ही भारी सस्मिडी का लाभ उठा रहा है जैसे स्टेनलेस स्टील स्क्रेप पर आयात शुल्क शून्य है, जिससे उत्पादन लागत के लगभग 70 प्रतिशत का कामप्रोमाइज हो जाता है। व्यापारीगण परिष्कृत उत्पाद के आयातों पर 7.50 प्रतिशत के आयात शुल्क का भुगतान करते हैं।
- (ज) घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए 400 सीरीज ग्रेड कोल्ड रोल्ड पर पाटनरोधी शुल्क पहले से ही अधिरोपित है।
- (झ) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता को आबंटित कोल ब्लॉक पहले ही रद्द कर दिया है। इसलिए, यद्यपि याचिकाकर्ता की संस्थापित उत्पादन क्षमता है, फिर भी उन्हें निकट भविष्य में इस सामग्री का वास्तविक रूप से उत्पादन करने में संसाधनों के अभाव के कारण अपनी संस्थापित उत्पादन क्षमता का उपयोग करने में दिक्कत महसूस हो रही होगी।
- (ञ) कई ऐसे व्यापारी/आयातक हैं जो अपनी आजीविका का अर्जन करने के लिए पूरी तरह से इस ट्रेड पर निर्भर हैं। भारत में कई लघु व्यापारी/आयातक/विनिर्माता ऐसे हैं, जिन पर इस रक्षोपाय शुल्क का प्रभाव पड़ेगा, परंतु, उनके पास आंकड़े एकत्र करने और इस अधिसूचना का उत्तर देने के संसाधन नहीं हैं।
- (ट) 400 सीरीज में सभी ग्रेडों का भारी मात्रा में आयात नहीं किया जाता है। इसलिए याचिकाकर्ता को उसके व्यापार को प्रभावित करने वाले ग्रेडों का विवरण स्पष्ट रूप से और विशिष्ट रूप से देना चाहिए।

#### च. विवेक मेटल्स

विवेक मेटल्स 400 सीरीज की स्टेनलेस स्टील का आयातक और ऑटोमोबाइल्स, सालर पैनल्स, किचन उपकरणों और अलंकरण उद्योगों के विनिर्माताओं को आपूर्तिकर्ता है जो केवल ब्राइट फिनिश (दर्पण फिनिश) का प्रयोग करते हैं जिनका जिंदल, सेल आदि सहित भारत में कोई भी विनिर्माण नहीं करता है।

#### छ. डीजीएस एसोसिएट्स – पोस्को वियतनाम

वियतनाम का अपना आयात 1 प्रतिशत से कम है इसलिए नगण्य है। ऐसे विकासशील देशों से इस संबद्ध में उत्पाद के आयात प्रतिशत का जोड़, जिनका आयात हिस्सा 3 प्रतिशत से कम है, भी 9 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

#### ज. डीजीएस एसोसिएट्स – पोस्को थाईनाक्स

थाईलैंड से आयातों का व्यक्ति औसत प्रतिशत लगभग 1 प्रतिशत है और इसलिए यह नगण्य है।

#### झ. मैसर्स पीटी जिंदल स्टेनलेस इंडोनेशिया

इंडोनेशिया से 400 सीरीज के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों का आयात लगभग "शून्य" है और वर्ष 2013-14 में भी इंडोनेशिया से आयात में 77 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। वर्ष 2013-14 में भारत द्वारा प्राप्त 400 सीरीज के कुल आयातों का केवल 0.13 प्रतिशत है जबकि किसी देश पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए उसका निर्यात न्यूनतम 3 प्रतिशत होना चाहिए और इसलिए इंडोनेशिया, उपर्युक्त आंकड़ों के अनुसार, इस श्रेणी में कमी नहीं आई।

#### ञ. पोस्को-कोरिया

1. भारत को निर्यातित विचाराधीन उत्पाद का 99 प्रतिशत से अधिक उत्पाद की अंतिम रूप से खपत ऑटोमोबाइल या ऑटोमोटिव संघटक उत्पादनकर्ताओं द्वारा की जाती है। चूंकि 400 सीरीज की स्टेनलेस स्टील के उत्पादों का व्यापक तौर पर प्रयोग ऑटोमोबाइल एक्झास्ट सिस्टम के कोल्ड और हाट दोनों तरह के संघटकों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, इसलिए उन्हें अधिक व्यापक और उत्तरदायी प्रविधियों का अनुप्रयोग करना अपेक्षित होता है।

2. पास्को महानिदेशक (रक्षोपाय) से यह भी अनुरोध करता है कि वह घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित न किए जाने वाले 400 सीरीज की स्टेनलेस के कुछ ग्रेडों के कोल्ड रोल्ड का अपवर्जन कर दें।

- (क) 429ईएम : ताप प्रतिरोधक स्टेनलेस स्टील। एसआई, टीआई, एमएन ओर सीयू को जोड़ा जाता है जबकि सीएंगन अंतर्वस्तु को कम किया जाता है। इसमें अत्यधिक उच्च ताप सहन शक्ति होती है, यह आक्सीकरण प्रतिरोधक होता है, इसमें आकृतिरूपकता और बेल्डिंग क्षमता होती है। इसका प्रयोग मुख्यतः ताप प्रतिरोधक पार्ट्स जैसे एक्झास्ट मैनीफोल्ड और फ्रंट पाइप के रूप में होता है – समकक्ष ग्रेड : पीओएस429ईएम
- (ख) 430 जेआईएल : 430 स्टेनलेस स्टील में सीयू और एनबी को जोड़ा जाता है; जो संक्षारण प्रतिरोध, कर्षण क्षमता, झलाई क्षमता और उच्च ताप आक्सीकरण प्रतिरोध को बढ़ा देता है। इसका मुख्य रूप से प्रयोग ऑटोमोटिव एक्झास्ट सिस्टम्स, होम अप्लायन्सेस, और भवन की बाह्य सामग्री के रूप में किया जाता है। समकक्ष ग्रेड : एसटीएस 430 जेआईएल, एसयूएस 430 जेआईएल, ईएन 14511 और आदि है।
- (ग) 444: उच्चतर सीआर और एमओ तत्व बड़ी अंतः ग्रेन्युलर संक्षारण प्रतिरोध और एससीसी प्रतिरोध उत्पन्न करता है। इसका प्रयोग मुख्यतः हाट वाटर प्रणाली, हीट एक्चेंजर और ऑटो एक्झास्ट प्रणाली के लिए किया जाता है।  
\*समकक्ष ग्रेड : एसटीएस 444, एसयूएस 444, एएसटीएम 444, ईएन1.4521 आदि
- (घ) 445एनएफ : उच्चतर सीआर तत्व संक्षारण प्रतिरोध और वेल्ड क्षमता बढ़ा देता है। इसका प्रयोग मुख्यतः इलेवेटर, घर में प्रयोग किए जाने वाले बरतनों और इलेक्ट्रॉनिक संघटकों के लिए किया जाता है।  
\*समकक्ष ग्रेड : पीओएस 445एनएफ

- (ड) 446एम : उच्चतर सीआर तत्व होने के कारण 445 स्टेनलेस स्टील के संक्षारण तत्व से श्रेष्ठतर है। इसका प्रयोग मुख्यतया तटवर्ती और औद्योगिक क्षेत्रों में छतों और बाह्य भवन सामग्री के लिए किया जाता है।

\*समकक्ष ग्रेड : पीओएस 446एम

3. पोस्को द्वारा क्षमता संवर्धन का कार्य पूरा कर लिए जाने के बावजूद पोस्को की बेशी क्षमता नहीं है।
4. पोस्को स्टेनलेस विभाग ने संपूर्ण विश्व भर में फैली दीर्घकालिक वैश्विक उपभोक्ता आपूर्ति श्रृंखला के समर्थन में, अपने गुणवत्ता प्रबंधन में सुधार करने और उत्पादकता को इष्टतम बनाने के लिए वर्ष 2008 से 2011 तक कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम तथा अन्य देशों में वैश्विक विस्तार करना प्रारंभ किया। पोस्को और इसकी वैश्विक अनुपंगियों के लिए भारत मुख्य बाजार नहीं है।
5. याचिकाकर्ता ने क्षमता उपयोग का परिकलन करते समय अविश्वसनीय आंकड़ों को उद्धृत किया है और याचिकाकर्ताओं के आंकड़े जेएसएल की वार्षिक रिपोर्ट में प्रदान कराए गए आंकड़ों से बिल्कुल भिन्न हैं। इसलिए, पोस्को ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों को एक साथ रखकर याचिकाकर्ता की क्षमता उपयोग का पुनः परिकलन किया। अत्यधिक क्षमता वृद्धि के मद्देनजर वर्ष 2011-12 में उनके क्षमता उपयोग में 51.95 प्रतिशत की कमी आई है। उत्पादन प्रक्रिया का सामान्यीकरण होने से, इनके क्षमता उपयोग में एक बार पुनः सुधार हुआ और वर्ष 2013-14 के दौरान बढ़कर यह 85.33 प्रतिशत हो गया।
6. यह क्षति भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण नहीं हुई, बल्कि याचिकाकर्ता के अपने आंतरिक कारणों से हुई है। इन कारणों से संक्षेप में निम्नलिखित उल्लेख किया जा सकता है :

- (i) ओडिशा में नए संयंत्र की स्थापना – जिससे उच्च स्टार्ट-अप लागत हुई।
- (ii) बेशी क्षमता से अतिरिक्त मालसूची संग्रह हुआ और न्यूनतम कीमतों पर बिक्री की गई।

7. यह याचिकाकर्ता पाटनरोधी शुल्क के अलावा प्रशुल्क अवरोधों का भी लाभ उठा रहा है।

#### ट. यूरोपियन कमीशन

1. वर्ष 2011-12 और 2012-13 के बीच आयातों में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उसके पश्चात वह स्थिर हो गए। वर्ष 2014-15 की अत्यधिक अभिनव अवधि में आंकड़ों को पहली तिमाही के आंकड़ों के आधार पर वार्षिकीकृत किया गया है और इसलिए यह निश्चित नहीं है कि संपूर्ण वर्ष के आंकड़े प्राप्त हो जाने के पश्चात यही प्रवृत्ति वास्तव में जारी रहेगी।
2. इस अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मांग में 49 प्रतिशत तक वृद्धि के मद्देनजर इस उद्योग के बाजार हिस्से में 2 प्रतिशत से कम की मामूली सी गिरावट आई है।
3. जहां तक लाभ/हानि का संबंध है, यह उद्योग वर्ष 2010 से पाटनरोधी शुल्क लगे होने के बावजूद इस अवधि (2011-12) की शुरुआत से ही घाटे में चल रहा था।
4. भारी क्षमता विस्तार के मद्देनजर, क्षमता उपयोग जो पहले 60 प्रतिशत तक था, लगभग 10 प्रतिशत तक प्रतिशत बिंदु घटकर 49 प्रतिशत रह गया।
5. यह घाटा वर्ष 2012-13 में उद्योग की क्षमता निर्माण के अनुरूप इकट्ठा होना शुरू हो गए। विश्लेषण की अवधि के समय आयात कीमतें स्थिर बनी रहीं। उनमें वर्ष 2013-14 में वृद्धि हुई और इस अवधि की समाप्ति पर वे अपने शुरुआती स्तर पर हैं।
6. यह क्षति संपूर्ण विश्व में क्षमता में बढ़ोतरी होने और मांग में कमी आने के बावजूद पाटनरोधी शुल्क पहले से ही प्रभावी होते हुए घाटे की यह स्थिति बेशी क्षमता निर्माण की शुरुआत से ही हो गई है।

#### ठ. मैसर्स तीर्थकर स्टील एंड अलायाज इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड, शुभलक्ष्मी मेटल्स टयूब्स प्राइवेट लिमिटेड, पैसिफिक मेटल ट्रेडिंग कंपनी और बीवीएस ओवरसीज, आश्विन इम्पेक्स, आदि नाथ मेटल्स और रैनफ्लेक्स मेटल्स

1. मैसर्स जिंदल स्टेनलेस स्टील (जिसका बाजार हिस्सा 90 प्रतिशत है), अपनी राजनीतिक और वित्तीय शक्ति का प्रयोग करके, एकाधिकार सृजित करके भारतीय उद्योग को पगु बनाना चाहता है।
2. उक्त अवधि के दौरान अनावश्यक जांचों की शुरुआत कराके और उत्पाद के दायरे में वृद्धि करके, जिससे पहले छूट थी या जिसका पहले अपवर्जन था, स्थिति को बदतर बनाकर उद्योग को परेशानी में डालने का प्रयास कर रहे हैं।

#### ड. मैसर्स बाहूरू स्टेनलेस एसडीएन बीएचडी, मलेशिया

अभी हाल ही में अवधि में मलेशिया से संबद्ध वस्तु के आयात 3 प्रतिशत के निर्धारित न्यूनतम स्तर से कम है और इसलिए मलेशिया से संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध रक्षोपाय जांच जारी रखने का कोई विधिक आधार नहीं है।

#### ढ. आल इंडिया स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

1. घरेलू उद्योग देश में लगभग 85 प्रतिशत उत्पादन पर नियंत्रण करता है। इस माल पर जांच की अवधि के दौरान भारी पाटनरोधी शुल्क पहले से ही लगा था और उन्हें भारी संरक्षण प्राप्त है।
2. आयातों में विभिन्न कारकों से बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है, जैसे —

- (क) उद्योग की जटिल जरूरतें।
- (ख) जिंदल किचेनवेयर अनुप्रयोग के लिए वीए फिनिश 400 सीरीज स्टेनलेस स्टील का निर्माण नहीं करता है।
- (ग) कई स्टेनलेस स्टील किचेनवेयर, एसेसरीज, होटल के उपकरणों, जिन्हें केवल वीए फिनिश 400 सीरीज स्टेनलेस स्टील से ही बनाया जा सकता है, के लिए निर्यात मांग है।
- (घ) जिंदल किचेनवेयर उद्योग के लिए 430 ग्रेड की 0.3 और 0.4 एमएम की मोटाई की नियमित आपूर्ति नहीं करते हैं।
- (ड) जिंदल, किचेन में प्रयोग किए जाने वाले चाकुओं के लिए प्रयुक्त उच्च कार्बन युक्त 420 जे2 ग्रेड का उत्पादन नहीं करते हैं।

- (च) आज की तारीख तक, जिंदल 430 ग्रेड की कर्षण गुणवत्ता को बनाए रखने में असफल रहे हैं और गहन कर्षण करने पर, उनकी स्टेनलेस स्टील रोपिंग के सामान्य स्तर से अधिक होती है और उसमें अन्य कंपनियां भी होती हैं जो यूरोप, जापान तथा यूएसए में ग्राहकों अस्वीकार्य होती है।
- (छ) जिंदल चाहते हैं कि उनका एकछत्र साम्राज्य बना रहे।
- (ज) जिंदल लिखित में कोई वचनबद्धता नहीं देते हैं।
- (झ) जिंदल में रक्षोपाय और पाटनरोधी शुल्कों का अधिरोपण करने के लिए कई आवेदनपत्र देकर स्टेनलेस स्टील के लघु प्रयोगकर्ताओं को तंग करने और उनकी क्रोध शांत करने की दक्षता है।
- (ञ) जिंदल अपने दावे को सही सिद्ध करने के लिए अनंतिम आयात आंकड़ों का गलत प्रतिनिधित्व करके और उनमें फेरबदल करके गुमराह कर रहे हैं और उन्हें इस बात की अच्छी तरह से जानकारी है कि स्टेनलेस स्टील किचेनवेयर के विनिर्माताओं के पास जिंदल के विरुद्ध मुकदमा लड़ने और उनके आंकड़ों की जांच करने के लिए महंगे वकील नियुक्त करने के लिए पर्याप्त जमा पूंजी नहीं है।

#### ण. मैक्सिको का दूतावास

- (क) इस उत्पाद की सही-सही पहचान नहीं की गई है। प्राधिकारी निर्यातकों को पूर्णतया हानि में छोड़ देते हैं क्योंकि ये अपनी सुरक्षा में सभी संगत आरोपों का प्रस्तुतिकरण नहीं कर सकते हैं।
- (ख) शुरुआती निर्धारण जो इसका वर्ण करता है में तो बिल्कुल विश्लेषण किया ही नहीं गया था और जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा जिन सूचनाओं और दस्तावेजों पर विचार किया गया था उनका और यह निर्धारण करने का कोई कारण नहीं बताया गया था कि यह विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उत्पाद किस तरह समान उत्पाद हैं अथवा से प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पाद हैं, तदनुसार, समान या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पादों की पहचान किए बिना इस जांच को तो कभी शुरू ही नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि इस जांच में रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 और 4ग, का पालन नहीं किया गया है।
- (ग) शुरु निर्धारण में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए उत्पादन की मात्रा और शेष भारतीय उत्पादकों द्वारा किए गए उत्पादन का विश्लेषण ही नहीं किया गया है जिससे कि जांचकर्ता प्राधिकारी यह सत्यापित कर सकें कि याचिकाकर्ता वास्तव में घरेलू उत्पादन के एक बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करता है। शुरुआती निर्धारण में वर्णित सूचना को किसी भी रूप में पर्याप्त और भारत के ऊपर उल्लिखित दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप, अन्य पक्षकार पूरी तरह से असहाय रह गए हैं, क्योंकि लागू विधिक ढांचे का उल्लंघन किया गया है।
- (घ) चूंकि यह एक वैश्विक रक्षोपाय है इसलिए जांचकर्ता प्राधिकारी को यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य देने चाहिए थे कि भारत को यह निर्यात अनपेक्षित परिस्थितियों के कारण हो रहे थे। तथापि, शुरुआती निर्धारण में ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं थीं और न ही यह उल्लेख किया गया था यह अनपेक्षित परिस्थितियां किस तरह न्यायसंगत हैं, इस तरह गाट के अनुच्छेद -XIX के पैराग्राफ 1क, के बिल्कुल विपरीत ढंग से कार्य किया था।
- (ङ) शुरुआती जांच में ऐसा कोई स्पष्टीकरण या विश्लेषण नहीं था जो इस अभिवचन को न्यायसंगत ठहराता हो कि आयातों में यह वृद्धि "इतनी अधिक मात्रा" में और "ऐसे हालात" में हुई कि इस घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई। जब हम यह विचार करते हैं कि आयात जो वर्ष 2012-13 में 87051 एमटी के थे, बढ़कर वर्ष 2013-14 में 87178 एमटी के हो गए, तो यह भी महत्वपूर्ण है।
- (च) ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि अनपेक्षित परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थीं और यह कि भारत द्वारा अपने डब्ल्यूटीओ अभिगमन में अवाप्त दायित्व के कारण, कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों का आयात इतनी अधिक मात्रा में बढ़ा और उसमें यह वृद्धि ऐसी परिस्थितियों में हुई कि उससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई।
- (छ) शुरुआती निर्धारण में उन कारणों का बिल्कुल कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि आयातों की मात्रा में यह वृद्धि पर्याप्ततः अभिनव, अचानक, तीव्र और परिमाणात्मक रूप से एवं गुणात्मक रूप से बहुत अधिक मात्रा में हुई जिससे भारतीय उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई। शुरुआती निर्धारण में यह कमी हितबद्ध पक्षकारों को एक बार पुनः पूर्णतः असहाय स्थिति में छोड़ देता है, जो हमारे विचार से, भारत द्वारा की गई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के पूर्णतया विपरीत है।
- (ज) यह स्पष्ट नहीं है कि कतिपय उत्पादों को किस तरह अपवर्जित कर दिया गया, इस बात का संयोग हो सकता है कि मैक्सिको के कुछ उत्पादों का अपवर्जन कर दिया गया हो और हो सकता है कि उन पर कभी विचार ही न किया गया हो। उस मामले में उदाहरणार्थ, उस उपशीर्षक में शामिल उत्पादों का अपवर्जन कर दिया गया हो तो मैक्सिको के आयात तो निश्चय रूप से ही कुल आयातों के 3 प्रतिशत से कम होंगे, ऐसी स्थिति में रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 9 के अनुसार मैक्सिको के विरुद्ध कोई प्रासंगिक साधन अपनाने से अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए।
- (झ) शुरुआत निर्धारण में विचाराधीन उत्पाद की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है और न ही आयातित एवं घरेलू उत्पादों के बीच समानता अथवा उनके बीच प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा के बारे में कोई विश्लेषण किया गया है और इस कारण से, यह निर्धारण नहीं हो सका घरेलू उत्पादक कौन है और घरेलू उद्योग क्या है। स्पष्टतः, इन कमियों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कोई तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक आधार पर नहीं है और इसके परिणामस्वरूप, शुरुआती निर्धारण एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों में परिभाषित मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

- (ज) वह तथ्य जिसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए था, यह है कि यदि उत्पादन, बिक्री, उत्पादकता और रोजगार के संबंध में कोई क्षति नहीं हुई तो अन्य कारकों का व्यवहार गंभीर क्षति की मौजूदगी पर विचार करने के लिए क्यों और कैसे पर्याप्त है।
- (ट) शुरुआती निर्धारण में संबद्ध आयातों में कथित वृद्धि तथा गंभीर क्षति की मौजूदगी के बीच कारणात्मक संबंधों के बारे में कोई विश्लेषण नहीं दिया गया है।

#### त. ताईपेई इकनामिक एंड कल्चरल सेंटर इन इंडिया

महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा प्रदान कराई गई सूचना और ताईवान की सीमाशुल्क सांख्यिकी यह दर्शाती है कि उपर्युक्त उत्पाद के ताईवान से भारत को निर्यात वर्ष 2011-15 की अवधि के दौरान भारत को हुए कुल निर्यातों का औसतन 1.2 प्रतिशत ही है। ताईवान की सांख्यिकी भारत को इन उत्पादों के निर्यात में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है और वर्ष 2011 से भारत में संबद्ध उत्पादों के आयात में ताईवान का हिस्सा 3 प्रतिशत से अधिक नहीं है। इसलिए इस मामले में रक्षोपाय करार का अनुच्छेद 9.1 प्रभावी होगा।

#### थ. आउटोकम्पु स्टेनलेस ओयाज, फिनलैंड

- (क) भारत में स्टेनलेस स्टील पर व्यापार उपचारी साधनों का एक लंबा इतिहास है। इस उत्पाद पर सबसे बड़े स्रोत से शुल्क पहले से ही प्रभावी है।
- (ख) याचिकाकर्ता ने पाटनरोधी जांच में साइबेक्स आंकड़े दिए। इन आयात आंकड़ों की विश्वसनीयता पर संदेह किया गया और जापान से आयात की मात्रा न्यूनतम होने के कारण उसका प्रासंगिक रूप से अपवर्जन कर दिया गया।
- (ग) अत्यधिक अभिनव समय (वर्ष 2014-15 की) की जांच (वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही) केवल 3 माह के ही वास्तविक आयात आंकड़ों पर आधारित हैं, न कि संपूर्ण वित्तीय वर्ष के आंकड़ों पर। वर्ष 2014-15 के आयात आंकड़े प्रत्याशित अवधि के हैं और अभिनव विगत की अवधि की संपुष्टि नहीं करते हैं। अतः, संबंधित आयातों का विश्लेषण असत्य एवं त्रुटिपूर्ण है।
- (घ) यदि आयात आंकड़ों का वार्षिकीकरण करके भी उनका विश्लेषण किया जाता है तो भी आयातों में लगभग कोई वृद्धि प्रदर्शित नहीं होती है और वर्ष 2013-14 से भारत को आयातों की कुल मात्रा का स्तर स्थिर बना हुआ है और वह कोई अचानक, तीव्र, बहुत अधिक वृद्धि प्रतिबिम्बित नहीं करता है।
- (ङ) महानिदेशक (रक्षोपाय) ने विशिष्ट रूप से तथाकथित सर्वधित आयातों की पक्षपात रहित जांच प्राप्त करने के लिए 6 माह या उससे अधिक की अवधि पर विचार किया है।
- (च) महानिदेशक रक्षोपाय का यह निर्णय कि संबंधित आयातों पर पहुंचाने के प्रयोजनार्थ केवल 3 माह के आयात आंकड़ों अर्थात् अप्रैल, 2014 से जून, 2014 तक के आंकड़ों पर ही विचार करना त्रुटिपूर्ण है और यह अपने विगत के उदाहरणों एवं प्रक्रिया से अलग है तथा यह निर्णय मनमाना, अनुचित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
- (छ) जांच शुरुआत अधिसूचना में प्रदान कराई गई मांग घरेलू मांग का परिकलन करने के लिए सभी तत्वों के योग से मेल नहीं खाती है।
- (ज) याचिकाकर्ता ने अन्य उत्पादकों के उत्पादन के लिए बाजार आसूचना को, उसे साक्ष्यांकित करने के लिए अल्पतम साक्ष्य दिए बिना भी, सूचना का स्रोत माना है और महानिदेशक (रक्षोपाय) ने उसे बिना कोई साक्ष्य मांग ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया।
- (झ) याचिकाकर्ता ने प्रत्येक घरेलू उत्पादक के और स्वयं अपने उत्पादन की विस्तृत सूची प्रदान किए बिना, अपने को छोड़कर, अन्य सभी भारतीय उत्पादकों के लिए सार सूचना प्रदान कराई है।
- (ञ) याचिकाकर्ता द्वारा याचिका के अनुबंध 16 में यथा उल्लिखित सौदावार आयात आंकड़े अपूर्ण हैं और वे केवल जनवरी, 2014 से जून, 2014 की अवधि के आंकड़ों को ही कवर करते हैं।
- (ट) यह स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि वैश्विक माल आपूर्ति अंतर एक अनपेक्षित घटना है और यह कि इस कारण उनसे भारत में आयातों में वृद्धि नहीं हुई।
- (ठ) संपूर्ण विश्व में मांग एवं आपूर्ति के बीच भारी अंतराल होने के कारणों में से एक कारण याचिकाकर्ता द्वारा अपने उत्पादन में विस्तार करना था जिसका आशय यह है कि संपूर्ण विश्व में मांग और आपूर्ति में अंतराल से याचिकाकर्ता एवं निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा के माहौल में कोई परिवर्तन नहीं आया।
- (ड) याचिकाकर्ता ने चीन के विभिन्न कोल्ड रोलड स्टेनलेस स्टील उत्पादों के आयात आंकड़ों का सार प्रस्तुत किया है। याचिकाकर्ता को चाहिए कि वह उपर्युक्त आयात आंकड़ों के सारांश का स्रोत बताए बल्कि वह स्रोत किए गए अनन्तिम आंकड़ों सहित उनके आधार एवं तरीके को भी बताए जहां से यह सारांश तैयार किया गया।
- (ढ) अनपेक्षित परिस्थितियों की अपेक्षा विगत में आए परिवर्तनों से संबंधित होती है न कि भावी परिवर्तनों से संबंधित। याचिकाकर्ता ने यह दावा करते समय कि चीन के उत्पादकों की क्षमताओं में वृद्धि हुई है निर्यातों में कथित वृद्धि पर ही भरोसा किया है जिसमें उन्होंने चीन के घरेलू उत्पादन और चीन में स्पष्ट के बीच अंतर और प्रक्षेपित वृद्धि को शामिल किया है।
- (ण) किसी भी अवसर पर चीन में मांग और आपूर्ति के अंतराल तथा द्वारा आयात/ निर्यात की निबल स्थिति नहीं बताई गई हैं।

- (त) याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़े का अध्ययन करने से यह परिलक्षित होता है कि ईयू और कोरिया से आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई। वर्ष 2014-15 के आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं।
- (थ) याचिकाकर्ता ने यह साक्ष्यांकित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि यह तथाकथित बेसी क्षमता को जांच की अवधि में चीन या किसी अन्य बाजार के बजाय भारत को विपथित हुई है और इस संबंध में केवल अभिकथन और विवरण ही दिया गया है।
- (द) न तो जांच शुरूआत अधिसूचना में और न ही घरेलू उद्योग की याचिका में अनपेक्षित परिस्थितियों या घटनाओं के बारे में कोई ऐसी सूचना दी गई है जिससे आयातों में इतनी अधिक मात्रा में आयात में वृद्धि हुई हो जिससे घरेलू उद्योग को क्षति कारित हुई हो या क्षति कारित होने की चुनौती उत्पन्न हो गई हो।
- (ध) निम्नलिखित के संबंध में भारी गोपनीयता का दावा किया गया है :
- वर्ष 2011-12 से 2014-15 (अप्रैल से जून, 2014) के सौदावार आयात आंकड़े।
  - लागत निर्धारण सूचना कम से कम अनुक्रमणिका तो दी जानी चाहिए थी।
  - याचिकाकर्ताओं तथा अन्य घरेलू उत्पादकों की अलग-अलग उत्पादन मात्रा।
  - चीन के सीमा शुल्क से आयात आंकड़ों का विवरण नहीं दिया गया है और न ही उसका कोई औचित्य बताया गया है।
  - हीन्ज एच. परिसर साप्ताहिक फैक्स सेवा से रिपोर्ट तथा चाइना मेटल इन्फार्मेशन नेटवर्क अंतर्दृष्टि से सूचना।
  - चीन, जापान, कोरिया और ईयू को सीआरयू आंकड़े।
  - संपूर्ण समायोजन योजना।
- (न) महानिदेशक रक्षोपाय ने वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए वार्षिकीकृत आंकड़ों का निर्धारण करने हेतु अप्रैल, 2014 से जून, 2014 तक की अवधि के लिए आंकड़ों पर विचार करके गलती की है। इसके बावजूद आयात वर्ष 2012-13 और 2013-14 में समान स्तर पर बने रहे और वर्ष 2014-15 में स्पष्ट वृद्धि अस्थायी, अनुमानित आंकड़ों पर आधारित है।
- (प) भारत में उत्पादन की तुलना में आयातों में संगत वृद्धि नहीं हुई।
- (फ) उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हो गई।
- (ब) बाजार हिस्सा स्थिर बना रहा।
- (भ) वह आधार जिस पर क्षमता का पृथक्करण किया गया है और केवल विचाराधीन उत्पाद के लिए विचार किया गया है, स्पष्ट नहीं किया गया।
- (म) वर्ष 2012-13 में याचिकाकर्ता द्वारा भारी क्षमता संवर्धन किया गया, इसके बावजूद उत्पादन और क्षमता उपयोग का पर्याप्त रूप से उपयोग किया गया।
- (य) याचिकाकर्ता घरेलू स्रोतों से लागत प्रभावी कीमतों पर क्रोमाइट अयस्क के प्रापण में चुनौतियों के कारण उच्चतर क्षमता उपयोग प्राप्त करने में सक्षम रहा।
- (कक) जांच शुरूआत अधिसूचना की शुरूआत के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता की मालसूची की अनदेखी की गई है।
- (खख) याचिकाकर्ता का इति स्टाक विचाराधीन उत्पाद के लिए कुल क्षमता का लगभग 2 प्रतिशत अनुरक्षित रखा गया है।
- (गग) न कीमत अधोरोदन, न कीमत निग्रहण।
- (घघ) इस अवधि के दौरान फेरोक्रोम, जो कुल उत्पादन लागत का लगभग 35 प्रतिशत होता है, के लिए वास्तविक लागत कम हो गई है।
- (ङ.ङ.) याचिकाकर्ता, संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घाटे की स्थिति में रहा और इसलिए, याचिकाकर्ता की लाभप्रदता में प्रेक्षित गिरावट के लिए संवर्धित आयातों के उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
- (चच) याचिकाकर्ता के संवर्धित घाटों को आयातों में तथाकथित वृद्धि पर उपरोपित नहीं किया जा सकता है और वह घाटा ब्याज लागत और आपवादिक घाटों के कारण हुआ है।
- (छछ) यह सिद्ध करने के लिए कि आयातों में वृद्धि की कोई चुनौती आसन्न है जिससे क्षति और अधिक तीव्र होने की संभावना है, का कोई अल्प साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- (जज) केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता की लाभप्रदता स्वतः नहीं क्षति के तब भी प्रतिबिम्बित करती थी जब आयातों में तथाकथित वृद्धि नहीं हुई थी, इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि याचिका द्वारा सामना की गई गंभीर क्षति के लिए संवर्धित आयात उत्तरदायी है।
- (झझ) याचिकाकर्ता पर कई कारकों का काफी विपरीत प्रभाव पड़ा जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ विपरीत शुल्क संरचना, स्टील स्क्रेप के आयातों के लिए आधारभूत सीमाशुल्क में वृद्धि, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि और मुद्रा की स्थिरता शामिल है।
- (ञञ) यद्यपि घरेलू उद्योग के क्षति हो रही थी फिर भी क्षमताओं में वृद्धि करने से क्षति हुई जो स्व-प्रोद्भूत है। यह अस्थिरता गंभीर बनी रही और उससे कारणात्मक संबंध भंग हुए।
- (टट) ऑटो पार्ट्स के आपूर्तिकर्ता एक्झास्ट सिस्टम का विनिर्माण करने के लिए स्टेनलेस स्टील का आयात कर रहे हैं जिससे कि उत्सर्जन के मानदंड पूरे हो सके। ऑटो उद्योग को उद्बुद्धित शुल्क की उच्च लागत वहन करनी पड़ती है या वैकल्पिक रूप से उन्हें निर्वातक प्रणाली का फिर से आयात करना पड़ेगा।



**द. मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मर्चेन्ट्स एसोसिएशन और मेटल वन कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड**

1. भारत और जापान के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी करार, भारत और कोरिया के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी करार और भारत आशियन एफटीए में उन मामलों में, जिनमें इस करार के अंतर्गत रक्षोपाय जांच शुरू की जाती है को अपनाए जाने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देशों का प्रावधान है। इसलिए इस जांच को समाप्त कर दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि सही मंच रक्षोपाय महानिदेशालय न होकर संबंधित एफटीए के अंतर्गत गठित तंत्र है।
2. आयात आंकड़ों की छंटाई करने के लिए प्रयोग की गई क्रियापद्धति का याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। याचिका में किए गए सभी दावों के समुचित विश्लेषण के लिए, यह अनुरोध किया जाता है कि डीजीएस सौदावार अनंतिम आयात आंकड़े प्रदान करेंगे और उनकी छंटाई करके एमएस एक्सेल फॉर्मेट में सभी हितवद्ध पक्षकारों को प्रदान कराएंगे।
3. केवल 3 माह की आयात सांख्यिकी का वार्षिकीकरण करना वर्ष 2014-15 के लिए वास्तविक आयात आंकड़ों का निर्धारण करने का गलत तरीका है।
4. रक्षोपाय विधि के अंतर्गत क्षति मार्जिन की कोई संकल्पना नहीं है। अतः, रक्षोपाय शुल्क के सही-सही स्तर जिसके लिए आवेदक ने अनुरोध किया है, अज्ञात है। इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय विधि के अंतर्गत ऐसी कोई क्रियापद्धति निर्धारित नहीं है जो डीजीएस को रक्षोपाय शुल्क के स्तर पर पहुंचने के लिए मार्गदर्शित कर सके। अतः पारदर्शिता के उद्देश्य से, डीजीएस को वह क्रियापद्धति का प्रकटन करना अपेक्षित है, जो रक्षोपाय शुल्क का स्तर निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया गया है।
5. आवेदक ने, यह स्थापित करने के लिए कि वर्तमान मामले में अनपेक्षित विकास मौजूद है, कोई तथ्यात्मक या विधिक आधार प्रस्तुत नहीं किया है।
6. गाट 1994 के अनुच्छेद XIX में प्राधिकारी पर दोहरा दायित्व डाला गया है। प्रथमतः इसमें प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे गाट के अंतर्गत संबद्ध उत्पाद से संबंधित सदस्य देश द्वारा किए गए प्रशुल्क रियायत सहित विशिष्ट प्रतिबद्धताओं की पहचान करें। द्वितीयतः, उन्हें उपर्युक्त विशिष्ट प्रतिबद्धताओं और भारत में संबद्ध वस्तु के संबंधित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करना होता है।
7. यदि आवेदक असफल भी रहता है तो प्राधिकारी पर यह दायित्व रहता है कि वह इस मुद्दे का विश्लेषण करे और इस संबंध में जांच परिणाम दें। ऐसा न करने से प्राधिकारी द्वारा किसी भी जांच परिणाम के अपर्याप्त, अतर्कित और गाट के अनुच्छेद XIX के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं के अनुकूल नहीं माना जाएगा।
8. चूंकि सीईपीए के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं के अनुसरण में सीमा शुल्क कम हो जाता है, जापान से आयातों में भी समान वृद्धि प्रदर्शित हुई है। इससे यह स्पष्टतः प्रदर्शित होता है कि आयातों में यह वृद्धि भारत द्वारा किए गए एफटीए के कारण हुई है और अनपेक्षित नहीं माना जा सकता है।
9. वर्ष 2012-13 और 2013-14 के बीच आयातों मामूली सी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014-15 के आंकड़े, जो तीन माह के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित हैं, उनके लिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उनसे पूरे वर्ष की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। आयातों में इस वृद्धि को आयातों में "अचानक" या "तीव्र" वृद्धि के रूप में नहीं कहा जा सकता है और इसे "क्रमिक" विकास कहा जा सकता है। अतः, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि आयातों में अचानक, अभिनव तीव्र या महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं कहा जा सकता है और आवेदक द्वारा इस तर्क को नामंजूर किया जा सकता है।
10. उत्पादन, बिक्री और क्षमता जैसे सभी पैरामीटर से कोई क्षति प्रदर्शित नहीं होती है, परंतु कुल क्षमता से 400 सीरीज के लिए पृथक्कारी क्षमता के लिए निर्धारित क्रियाविधि अभी भी स्पष्ट नहीं है।
11. उतराई मूल्य का परिकलन आकलनीय मूल्य में सीमाशुल्क और शिक्षा उपकर जोड़ा जाता है न कि आयातों के सीआईएफ मूल्य को। तथापि, वर्तमान मामले में, आवेदक ने उतराई मूल्य का निर्धारण आयातों के सीआईएफ मूल्य के साथ-साथ सीमाशुल्क और शिक्षा उपकर को जोड़कर किया है। इसने उतराई मूल्य के परिकलन को बहुत अधिक कम कर दिया और कीमत अधोरदन भी प्रवर्धित कीमत अधोरदन रेंज को प्रदर्शित कर रहा है।
12. डीजीएस को भारत में आयातित स्लिट फार्म की तुलना (चौड़े क्वाइल फार्म में उचित समायोजन जोड़ने के पश्चात) आवेदक द्वारा बेची गई संबद्ध वस्तु की स्लिट फार्म से की गई।
13. कीमत अधोरदन, अवमंदन और निग्रहण आंकड़े आवेदक द्वारा दायर एनसीवी याचिका में अनुक्रमित फार्म में भी नहीं दी गई है।
14. आवेदक को विद्युत और ईंधन व्यय पर भारी धनराशि लगानी पड़ी जो आवेदक को होने वाले घाटे के लिए बड़े कारणों में से एक है।
15. वर्ष 2011-12 की शुरुआत में भी, जब आयात बहुत कम थे, आवेदक को घाटा हो रहा था।
16. आवेदक को अपनी क्षमता दोहरी करने के लिए हुए संबंधित नियत व्यय के कारण भी भारी घाटा हुआ।
17. संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण से संबद्ध वस्तु के आयातों के क्षतिकारी प्रभाव पहले ही दूर हो गया है। यदि आवेदक पहले से ही अधिरोपित संरक्षण के स्तर से संतुष्ट नहीं है तो वह पाटनरोधी शुल्क के लिए एमटीआर का अनुरोध कर सकता है।
18. जिन कारकों का समाधान करने की मांग समायोजन योजना में की गई है वे पहले ही मौजूद थे और वे आयातों की मौजूदगी से स्वतंत्र रूप से मौजूद हैं और उनकी पहचान आवेदक द्वारा पहले ही कर ली जानी चाहिए।

19. समायोजन योजना के संबंधित उत्पाद विशिष्ट होनी चाहिए और उसका प्रयोग, प्रश्नावली उत्पाद पर ध्यान दिए बिना, संपूर्ण कंपनी की समस्या का समाधान करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
20. आवेदक ने यह उल्लेख किया है कि उसके कंसल्टेंट ने लागत को कम करने के लिए पांच स्तरीय कार्यनीति का सुझाव दिया था परंतु उसका प्रकटन अगोपनीय रूप से भी नहीं किया गया है कि वह कार्यनीति है क्या।

#### घ. मैसर्स मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड

1. जांच की अवधि के दौरान अर्थात् वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारंभ होकर वर्ष 2014-15 तक की अवधि (जांच की अवधि), उन्होंने विचाराधीन उत्पाद का जापान से आयात किया था।
2. चूंकि इस एफटीए के अंतर्गत द्विपक्षीय रक्षोपाय की एक सुरक्षित विशिष्ट प्रणाली और तंत्र का प्रावधान किया गया। परंतु प्राधिकारी ने द्विपक्षीय रक्षोपायों और विशेष शर्तों तथा उसमें निर्धारित प्रक्रिया को संबंध में इस एफटीए के प्रावधानों की पूर्णतया अनदेखी की है।
3. घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद की गुणवत्ता और जापान सहित अन्य देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की गुणवत्ता के बीच भारी अंतर है। जापान से आयातित वस्तुओं का विनिर्माण एक अत्याधुनिक पेटेंटेड प्रविधि द्वारा किया जाता है और वह उत्पाद विशिष्ट डिजाइन, विनिर्देशनों और श्रेष्ठतर गुणवत्ता का होता है।
4. याचिकाकर्ता ने महत्वपूर्ण आर्थिक पैरामीटरों जैसे कीमत अधोविक्रयण रेंज, प्रमुख कच्चे माल की सूची, किए गए निवेश, निवल मान, अवक्षयण व्यय, ब्याज व्यय आदि के संबंध में कुछ भी जानकारी प्रदान नहीं की है।
5. प्रदान कराई गई समायोजन योजना अधूरी है और अधिकांश सूचना को याचिकाकर्ता द्वारा गोपनीय माना गया है।
6. प्राधिकारी को रक्षोपाय शुल्क के स्तर का निर्धारण करने के लिए अपनाई जाने वाली क्रियापद्धति का प्रकटन करना अपेक्षित है।
7. आयातक की एक सुस्थापित सशक्त परीक्षण एवं जांच प्रक्रिया है, जिसमें केवल कच्चे माल/उत्पाद के परीक्षण में 2-3 वर्षों का समय लग जाता है। आयातक के लिए यह अव्यवहार्य होगा कि वह संबद्ध उत्पाद का आयात करना बंद कर दे या आयात का अनुपूरण घरेलू उद्योग के उत्पादनों से करने लगे।
8. यह नोट करना प्रासंगिक है कि इस तथ्य के प्रति जागरूक होने के बावजूद भी कि प्रतिवादी उन पक्षकारों में से एक हो सकता है जो इस रक्षोपाय की कार्यवाही से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, याचिकाकर्ता, एक नोटिस प्राप्तकर्ता के रूप में, ने हमें जानबूझकर आवेदनपत्र में यह विशेषीकृत नहीं किया है और प्राधिकारी भी प्रतिवादी को नोटिस के रूप में सूचीबद्ध करने में असफल रहे हैं।

#### द. कोरिया का दूतावास

- (क) इस रक्षोपाय जांच का उत्पाद अत्यधिक सजातीय होना चाहिए जिससे उसे भौतिक अभिलक्षणों और अंतिम प्रयोगों के अनुरूप समान या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पाद के माना जा सके।
- (ख) भारत के घरेलू स्टील उत्पादक आटोमोटिव इक्विपमेंट सिस्टम का उत्पादन करने में अंतर्ग्रस्त प्रविधि की कमी के कारण अंतिम प्रयोक्ताओं द्वारा अपेक्षित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं जबकि भारत को निर्यातित 99 प्रतिशत से अधिक कोरियाई उत्पाद का आटोमोबाइल या आटो पार्ट्स के उत्पादकों द्वारा अंततः खपत की जाती है।
- (ग) इस जांच के उत्पाद जैसे 429ईएम, 430जेआईएल, 444, 445 एनएफ और 446 एम का भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन नहीं किया जाता है। इस संबंध में कई भारतीय आटोमोबाइल या आटो पार्ट्स कंपनियां अभी आयातित स्टील उत्पादों पर निर्भर हैं।
- (घ) यदि घरेलू उद्योग की असफलता की स्थिति को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं तो उनका मूल्यांकन अलग से एवं स्वतंत्र रूप से किया जाना चाहिए।
- (ङ) सीआरयू स्टेनलेस स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स आउटलुक के अनुसार याचिकाकर्ता ने वर्ष 2012-2013 में एक नए संयंत्र की स्थापना की जिससे इसकी क्षमता बढ़ाकर मौजूदा क्षमता से दोगुनी हो गई। इसका आशय यह है कि याचिकाकर्ता का বেশी निवेश तथा उच्च स्टार्ट अप लागत एवं उच्च मालसूची लागत एवं उत्पादन के शुरूआती स्तर पर बिक्री की न्यूनतर कीमत के कारण उसका वित्तीय निष्पादन कम हुआ।
- (च) विशेष रूप से यह नोट किया जाना चाहिए कि यद्यपि घरेलू उद्योग तथाकथित वित्तीय घाटे का सामना कर रहा था, फिर भी आयातों में कोई भारी वृद्धि नहीं हुई। घरेलू उद्योग के निष्पादन के संकेतकों में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण संकेतक उसको हुआ लाभ और हानि होती है। घरेलू उद्योग को वर्ष 2012-13 में 315/-रुपए/प्रति एमटी का और वर्ष 2013-14 में 953/-रुपए/प्रति एमटी का तथाकथित वित्तीय घाटा हुआ। तथापि, आयात जो वर्ष 2012-13 में 87051 एमटी थे बढ़कर वर्ष 2013-14 में 87178 एमटी हो गए।
- (छ) यद्यपि याचिकाकर्ता ने यह दावा कि है कि उसे गंभीर क्षति सहन करनी पड़ी है, तथापि, उसको हुए वित्तीय घाटे इस संबद्ध वस्तु के आयात के कारण न होकर याचिकाकर्ता के अपने ऊपर उल्लिखित आंतरिक कारणों से हुआ था। इसका आशय यह है कि याचिकाकर्ता संबंधित आयातों तथा गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करने में असफल रहा।

- (ज) रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से भारत में अनुप्रवाही उद्योग तथा उपभोक्ताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- (झ) घरेलू उत्पाद स्टेनलेस स्टील के सीमित दायरे के उत्पादों का ही उत्पादन कर सकते हैं जिसका प्रयोग आटोमोबाइल जैसे अन्य उत्पादों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। विविध विदेशी सामग्री का आयात किए बिना अंतिम उत्पादों का दायरा भी सीमित हो जाएगा और उसका भारत के जनहित पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

#### घ. मैसर्स पाक्सल कारपोरेशन

- (क) आयातों में होने वाले इस उद्रेक के प्रमुख कारणों से एक कारण चीन में पिछले 5-7 वर्षों से तीव्र बिल्ड-अप क्षमता को ऐसे स्तर पर बनने के लिए उपरोपित किया जा सकता है, जो उसकी घरेलू मांग में हुई वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक है।
- (ख) चीन में स्टेनलेस स्टील के भारी मात्रा में हो रहे बेशी उत्पादन को भारत जैसे बढ़ती बाजारों में विपथित किया जा रहा है।
- (ग) अन्य देशों द्वारा भी इस स्टेनलेस स्टील का निरंतर पाटन किया जाता रहा है जैसा कि स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं से स्पष्ट है।
- (घ) घरेलू उद्योग द्वारा अपना क्षमता विस्तार करने और आधुनिकीकरण करने के लिए किया गया भी निवेश इस समय उहापोह की स्थिति में है और यह उद्योग निरंतर अपी उत्तरजीविता के लिए संघर्ष कर रहा है क्योंकि चीन, कोरिया और जापान जैसे देशों से स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों के आयात से उसे सामना करना पड़ रहा है।

#### III. सार्वजनिक सुनवाई

(1) दिनांक 14 जनवरी, 2015 को एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया गया। इस सार्वजनिक सुनवाई के लिए नोटिस सभी हितबद्ध पक्षकारों को 15 दिसम्बर, 2014 को प्रेषित किया गया था। इस सार्वजनिक सुनवाई के दौरान निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने अपने विचार व्यक्त किए थे।

मैसर्स जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड (घरेलू उद्योग)
जापान का राजदूतावास
इंडोनेशिया का राजदूतावास
कोरिया का राजदूतावास
मैक्सिको का राजदूतावास
तुर्की का राजदूतावास
मैसर्स निप्पन स्टील एंड सुमकिन स्टेनलेस स्टील कारपोरेशन
मैसर्स निशिन स्टील कंपनी लिमिटेड; और
मैसर्स जेएफई स्टील कारपोरेशन
मैसर्स आउटोकम्पु स्टेनलेस ओथ्रय फिनलैंड
मैसर्स आउटोकम्पु निरोस्टा जीएमबीएच, जर्मनी
मैसर्स शंघाई क्रूप स्टेनलेस कंपनी लिमिटेड
मैसर्स पास्को कोरिया
मैसर्स वीराना पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर
मैसर्स बाहूरू स्टेनलेस, मलेशिया
मैसर्स मेटल वन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड स्टेनलेस स्टील मर्चेन्ट्स एसोसिएशन
मैसर्स मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड
मैसर्स हिन्दुस्तान सिरिंजेज एंड मेडिकल डिवाइसेस लिमिटेड
मैसर्स गोशी इंडिया आटो पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
मैसर्स पोस्को वियतनाम/पोस्को थाइनाक्स

(2) सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6 के उपनियम (6) के अनुरूप मौखिक रूप से अभिव्यक्त अपने विचारों का लिखित प्रस्तुतिकरण भी करें। तत्पश्चात, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए लिखित प्रस्तुतिकरणों की प्रतियां सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाती हैं। हितबद्ध पक्षकारों को इन अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए लिखित प्रस्तुतिकरणों की प्रतियुक्तियां, यदि कोई हो, दायर करने का भी अवसर प्रदान किया गया। उपर्युक्त नियमावली के अनुरूप निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने अपने लिखित प्रस्तुतिकरण किए।

(3) सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर किए गए लिखित प्रस्तुतिकरणों का संक्षिप्त सारांश निम्नलिखित है:

**क. मैसर्स टीपीएम कंसल्टेन्ट्स ने मैसर्स जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (घरेलू उद्योग) की ओर से लिखित प्रस्तुतिकरण दायर किया। टी/टी आंकड़े प्रदान नहीं कराए गए**

- (क) हितवद्ध पक्षकारों द्वारा व्यापक रूप से यह तर्क दिया गया कि महानिदेशक रक्षोपाय ने आयातों की यथार्थता और पर्याप्तता की जांच नहीं की है क्योंकि टी/टी आंकड़े प्रदान नहीं कराए गए और यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि टी/टी आंकड़े तो महानिदेशालय को भी नहीं दिए गए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि निदेशालय को टी/टी डाटा प्रदान कराए गए थे। एक ऐसी स्थिति में जहां निदेशालय रक्षोपाय जांच की शुरुआत करने से पहले ही विस्तृत सत्यापन कार्य का आयोजन करता है वहां यह बड़ा आश्चर्यजनक प्रतीत होता है कि हितवद्ध पक्षकारों ने यह भरोसा कर लिया कि निदेशालय ने इन आंकड़ों की जांच किए बिना ही याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई समाप्त सूचना को इस अंकित मूल्य पर ही स्वीकार कर लिया।
- (ख) इसके अतिरिक्त, यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता का विधि के अंतर्गत यह दायित्व नहीं है कि वह सौदावार आयात लिस्टिंग अन्य हितवद्ध पक्षकारों को प्रदान कराए।
- (ग) यह टी/टी आंकड़े महानिदेशक (रक्षोपाय) को स्वयं को इस सूचना की यथार्थता के संबंध में संतुष्ट करने के प्रयोजनार्थ संगत हैं और यह आंकड़े महानिदेशक (रक्षोपाय) को प्रदान कराए गए थे।
- (घ) याचिकाकर्ता ने समस्त टी/टी आंकड़े महानिदेशक (रक्षोपाय) को प्रदान करा दिए थे और वह सभी विरोधकर्ता हितवद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध करा दिए गए थे। इसलिए इस संबंध में हितवद्ध पक्षकारों द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है।
- (ङ) अपनाई गई क्रियापद्धति और दिसम्बर, 2014 तक की अवधि के लिए आयात सूचना भी प्रदान करा दी गई है।

**एक तिमाही के आंकड़े आयातों में वृद्धि का निर्धारण नहीं कर सकते हैं**

- (च) विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आयातों में वृद्धि का निर्धारण करने के लिए एक तिमाही के आयात आंकड़े अपर्याप्त हैं और यह कि, इस निदेशालय ने विगत में कमी भी आयातों में वृद्धि का निर्धारण करने के लिए इतने अल्प समय के आंकड़ों पर विचार नहीं किया है। तथापि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि निदेशालय ने भारत में सोडा ऐश और कास्टिक सोडा के आयातों से संबंधित मामले में दो/तीन माह को आयात सांख्यिकी के आधार पर जांच प्रारंभ कर दी है।
- (छ) याचिकाकर्ता ने कभी भी यह प्रस्तुत नहीं किया कि महानिदेशक (रक्षोपाय) को तीन माह की अवधि के आंकड़ों के आधार पर आयातों में उद्रेक की मौजूदगी का निष्कर्ष निकालना चाहिए। याचिकाकर्ता ने पहले ही दिसम्बर, 2014 तक की अवधि के लिए सूचना प्रदान करा दी है और महानिदेशक (रक्षोपाय) अप्रैल से दिसम्बर, 2014 तक की अवधि के दौरान आयातों के आधार पर आयातों में उद्रेक का निर्धारण कर सकते हैं।
- (ज) कुछ हितवद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क भी दिया गया कि यदि मौजूदा अवधि के लिए एक तिमाही के आंकड़ों को अपनाया जाता है तो महानिदेशक रक्षोपाय से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विगत वर्ष के आंकड़ों पर भी तिमाही आधार पर ही विचार करें। इस संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी जांच शुरुआत अधिसूचना या याचिका में जब कोई सूचना वार्षिक आधार पर प्रस्तुत की जाती है, तब भी महानिदेशक (रक्षोपाय) ने आयातों, क्षमता, उत्पादन क्षमता उपयोग, बिक्री, स्टॉक, रोजगार के संबंध में माह-प्रतिमाह सूचना पर भी विचार किया है। केवल समेकित वार्षिक आंकड़े जांच शुरुआत के नोटिस में दिए गए हैं। अतः, महानिदेशक (रक्षोपाय) का निर्णय वार्षिक आंकड़ों के साथ-साथ माह-दर-माह आधार पर भी दिया गया है।

**पाटनरोधी शुल्क पहले से ही अधिरोपित है**

- (झ) हितवद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग की रक्षा करने के लिए 400 सीरीज ग्रेड के कोल्ड रोल्ड उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क पहले से ही अधिरोपित है। तथापि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की रक्षा करने में सक्षम नहीं रहा। जबकि आयातकों ने स्वयं ही यह तर्क दिया है कि अधिकांश आयात व्यापक उत्पादों का है, जो पाटनरोधी जांच में विचारे गए विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है। इसके अतिरिक्त, जापान से होने वाले आयातों पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगा है और संकीर्ण चौड़ाई वाले उत्पादों (सीआर <400 एमएम) पर पाटनरोधी शुल्क बेंचमार्क फार्म के आधार पर लगा हुआ है जहां आयात बेंचमार्क कीमतों से अधिक पर हो रहे हैं।
- (ञ) याचिकाकर्ता महानिदेशक (रक्षोपाय) से यह अनुरोध करता है कि वह डीजी सिस्टम्स से आंकड़े मंगा लें और आयात की उस मात्रा का सुनिश्चयन कर लें जो पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किए बिना किया गया। यह सूचना तत्काल तथ्यात्मक स्थिति को स्पष्ट कर देगी और यह दर्शाएगी कि कई देशों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किए जाने के बावजूद भी पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करने के पश्चात शायद ही कोई आयात किया गया है।

**कंपनी का गैर-विलयन**

- (ट) हितवद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया कि इस कंपनी का गैर-विलयन किया जा रहा है। हम इसके साथ इस स्कीम के संबंध में सेवी के पास प्रस्तुत दस्तावेजों का सार (अगोपनीय आधार पर) प्रस्तुत कर रहे हैं। यह देखा जा सकता है कि इस स्कीम के पीछे का औचित्य शेयर होल्डर मूल्य का प्रकटन करना है जिससे कि इसकी लाभप्रदता में वृद्धि हो सके और कंपनी द्वारा ऋण की कारामदता में सुधार हो सके।
- (ठ) दस्तावेज में विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है कि अंतरणकर्ता कंपनी आयातों के अंतर्प्रवाह के कारण, खासकर चीन से, आंशिक रूप से ऋण निस्तारणता की भारी समस्या का सामना कर रही है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि सभी

सीरीज के लिए आयातों में भारी अंतर्प्रवाह नहीं हुआ होता तो ओडिशा संयंत्र बेहतर क्षमता उपयोग के साथ कार्य कर रहा होता और ऋण की कारामदता का कोई ही नहीं उठा होता। इसके अतिरिक्त, आयातों के अंतर्प्रवाह से कीमत निग्रहण हुआ, जिसने घरेलू उद्योग को इनपुट लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतों में वृद्धि करने से वंचित कर दिया।

- (ड) अब जेएसएल की कुल देयता को जेएसएल (हिसार लिमिटेड) जेयूएसएल और जिंदल कोक लिमिटेड के बीच विभाजित किया जाएगा। इस समय जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत आंकड़े ओडिशा फेज-2 और हिसार के हैं। इसलिए, गैर-विलयित निकायों का उपयोग व्यावहारिक रूप से इस याचिका में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुरूप ही होगा।

#### विचाराधीन उत्पाद

- (ढ) इस विचाराधीन उत्पाद का आयात कई सीमा शुल्क एचएस कोडों के अंतर्गत रिपोर्ट किया गया है और इसलिए यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतक है और यह किसी भी रूप में वर्तमान याचिका और प्रस्तावित जांच पर बाध्यकारी नहीं है। इस संबद्ध वस्तु का प्रयोग हवाई गुड्स, प्रसंस्कृत उपकरणों अब दुग्धशाला उपकरणों, आटोमोटिव संघटकों, रेल कार्टस, मेट्रो के कोच, आर्किटेक्चर, भवन और निर्माण आदि के लिए किया जाता है।
- (ण) कई हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि इस विचाराधीन उत्पाद का दायरा उपयुक्त नहीं है। तथापि, किसी भी पक्षकार ने यह सिद्ध नहीं किया है कि यह दायरा किस तरह उपयुक्त नहीं है और इस विचाराधीन उत्पाद के दायरे में और कौन से उत्पाद प्रकारों को शामिल किया जाए जिन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। अतः, इस संबंध में किए गए सभी तर्क निराधार हैं, काल्पनिक हैं और असाध्यांकित हैं।
- (त) विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और आयातित उत्पाद टाटा मोटर्स, जनरल मोटर्स, ह्यून्डई बजाज आदि जैसे आटो उद्योग के लिए प्रतिस्थापनीय नहीं हैं।
- (थ) कुछ उपभोक्ताओं और विदेशी उत्पादकों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आयात आवश्यक है क्योंकि कुछ उपभोक्ताओं ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित उत्पाद का अनुमोदन नहीं किया है। इस संबंध में याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करता है कि यह कोई प्रश्न नहीं है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद को उपभोक्ताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। संगत प्रश्न यह है कि क्या उपभोक्ताओं ने अपनी जरूरतों के लिए याचिकाकर्ता से इस उत्पाद की मांग की है और घरेलू उद्योग ने तकनीकी अक्षमताओं के आधार पर उसकी आपूर्ति करने से खेद व्यक्त किया हो। याचिकाकर्ता किसी उत्पाद की आपूर्ति केवल तभी कर सकता है जब उपभोक्ता उसे उस वस्तु की आपूर्ति करने का आदेश दे। केवल वे ग्रेड जिनकी याचिकाकर्ता ने आपूर्ति नहीं की है 429, 432, 444 और 1.4521 है और उसकी आपूर्ति न करने का कारण यह है कि याचिकाकर्ता को इन ग्रेडों की आपूर्ति करने का कभी कोई आर्डर ही नहीं मिला है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह दावा भी नहीं किया है कि याचिकाकर्ता से किसी विशिष्ट उत्पाद का आयात करने के लिए कहा गया और याचिकाकर्ता ने तकनीकी अक्षमताओं के कारण उसकी आपूर्ति करने से मना कर दिया हो।
- (द) कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया कि आयात की गई कुछ वस्तुएं विशेष प्रयोजन के लिए होती हैं जैसे सर्जिकल ब्लेड्स। तथापि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस उत्पाद की आपूर्ति करने के लिए याचिकाकर्ता को कोई आर्डर नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता ऐसी किसी वस्तु की आपूर्ति नहीं कर सकता है जिसका उसे आर्डर ही नहीं मिला है। यदि याचिकाकर्ता को आर्डर मिला होता तो याचिकाकर्ता उस माल की आपूर्ति कर सकता है।

#### घरेलू उद्योग

- (ध) याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग है। घरेलू उद्योग को सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 (धारा 8ख) के 6(ख) में निम्नवत परिभाषित किया गया है, "घरेलू उद्योग" का आशय समान वस्तु या भारत में प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी वस्तु के समग्र रूप से ऐसे उत्पादकों से है जिनका उस वस्तु या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी वस्तु का भारत में सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु का भारत में कुल उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता हो।
- (न) यह आवेदनपत्र मैसर्स जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड द्वारा दायर किया है। इस संबंधित उत्पाद के भारत में चार अन्य उत्पादक भी हैं। इन ज्ञात उत्पादकों का उत्पादन और उसकी बिक्री का आकलन बाजार आसूचना के अनुसार किया गया है।
- (त) यह तर्क दिया गया कि अपनी क्षमताओं में वृद्धि के बावजूद आधार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आवेदक का आधार उसके उत्पादन पर आधारित है, न कि उसकी उत्पादन क्षमता पर। इसे अतिरिक्त, यह देखा जा सकता है कि कुल भारतीय उत्पादन में याचिकाकर्ता के हिस्से में वृद्धि हुई है।

#### संबंधित आयात

- (प) याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि विधि के अंतर्गत यह अपेक्षा है कि आयातों में अचानक, भारी उद्रेक प्रदर्शित होना चाहिए।
- (फ) याचिकाकर्ता पुनः यह प्रस्तुत करते हैं कि आयातों में अचानक अत्यधिक अभिनव और तीव्र वृद्धि का आशय यह नहीं है कि यह वृद्धि अनिवार्यतः जांच की अवधि की समाप्ति पर या निर्धारण के समय पर होनी चाहिए। अंतिम समय से अंतिम समय की तुलना में और हस्तक्षेपकारी प्रवृत्ति का निर्धारण आयातों में वृद्धि का निर्धारण करने के लिए किया जाना चाहिए।
- (ब) याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि संबंधित उत्पाद के आयातों में भारी वृद्धि संगत रूप से और समग्र रूप से दोनों तरह से व्यक्त हुई है। आयातों में यह वृद्धि अचानक और बहुत अधिक हुई है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई या गंभीर

क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई। इस प्रकार, इस विचाराधीन उत्पाद के आयात "नियमावली के आशय से अंतर्गत" निम्नलिखित क्षति कारित करते हुए पाए गए हैं।

#### समग्र रूप में आयातों में वृद्धि

- (भ) यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा विचारे गए आयात सांख्यिकी सही नहीं है। अतः यह अनुरोध किया जाता है कि महानिदेशक कृपया डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त सौदेवार आयात आंकड़ों का विश्लेषण करे। इसके लिए विस्तृत क्रियाविधि पहले ही प्रदान कराई जा चुकी है।
- (म) यह देखा जा सकता है कि आयातों में समग्र रूप में भारी वृद्धि दर्ज की है। इस आयात में अक्टूबर-दिसम्बर, 2014 की अवधि में भारी वृद्धि हुई है। आयातों में यह वृद्धि तिमाही-वार भी हुई। अतः यह देखा जा सकता है कि आयातों में यह वृद्धि अचानक तीव्र एवं अत्यधिक, अभिनव अवधि में हुई है।

#### घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में आयातों में वृद्धि

- (कक) भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि अत्यधिक अभिनव अवधि में अधिकतम वृद्धि हुई है।

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 पहली तिमाही	2014-15 दूसरी तिमाही	2014-15 तीसरी तिमाही
उत्पादन के संबंध में आयात (%)	81.26	89.61	80.11	94.19	81.79	96.01

#### घरेलू खपत/मांग के संबंध में संवर्धित आयात

- (खख) इस विचाराधीन उत्पाद के लिए खपत और मांग का याचिकाकर्ता ने निर्धारण भारत में इस उत्पाद के निर्यातों, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और अन्य घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों के रूप में किया है। इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में भारत में इस विचाराधीन उत्पाद की खपत के संबंध में तीव्रता से वृद्धि हुई है। आयातों में यह वृद्धि इतनी अधिक हुई कि खपत के संबंध में आयात भारतीय खपत का केवल 50 प्रतिशत ही बनते हैं। यह वह स्थिति है जब याचिकाकर्ता ने स्वयं ही अपनी क्षमताओं में विस्तार किया और उसके पास देश में इस उत्पाद की वर्तमान एवं संभावित मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है।

#### आयातों में वृद्धि के कारण

- (गग) यह प्रस्तुत किया जाता है कि गाट 1994 के अंतर्गत भारत द्वारा उपगत प्रतिबंधता यथामूल्य 40 प्रतिशत प्रशुल्क रियायत को मंजूरी दी थी। अतः, भारत सरकार ने गाट 1994 के अंतर्गत सरकार द्वारा उपगत प्रतिबंधता के अंतर्गत घरेलू उद्योग प्रशुल्क कम कर दिया है। किए गए एफटीए से प्रशुल्क रियायतों में और अधिक कमी हुई है। अधिकांश आयात जापान, कोरिया, चीन, ईयू, मैक्सिको और यूएसए से हुआ है। सबसे बड़ा उद्रेक चीन से हुआ है। आयातों में यह वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हुई है :

#### क. वर्ष 2010 से संपूर्ण विश्व में मांग आपूर्ति में भारी अंतर

- चीन, जो कभी निवल आयातक था, अब आत्मनिर्भर हो गया है और उसने बेशी क्षमता अर्जित कर ली है।
- चीन के उत्पादकों की तेजी से बढ़ी क्षमताओं के कारण चीन से निर्यातों में वृद्धि हुई है जिसके कारण उन्हें विभिन्न लाभ हुए हैं जो निम्नलिखित हैं :
- चीन की फेरोक्रोम क्षमता में अचानक वृद्धि और उसकी कम कीमत रिडकटेंट (कोक), करेंसी, सस्ती बिजली, कम ब्याज दर की भारी मात्रा में उपलब्धि के कारण हुई है।

- पश्चिमी यूरोप में मांग एवं आपूर्ति में भारी अंतर
- जापान में मांग एवं आपूर्ति में भारी अंतर
- कोरिया में घरेलू मांग अधिक न होने के बावजूद अपनी क्षमताओं में आक्रामक रूप से वृद्धि होना
- भारत की सरकार द्वारा कोरिया और जापान जैसे देशों के साथ किए गए एफटीए/पीटीए
- भारत में पाटनरोधी शुल्क लगे होने के बावजूद सतत आयात
- विभिन्न बड़े निर्यातकों के विरुद्ध व्यापार उपचारी उपायों का अधिरोपण।

#### घरेलू उद्योग को क्षति :

- याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि विधि के अंतर्गत निदर्शित सभी पैरामीटर यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, जो निम्नलिखित हैं :
- आयातों में भारी वृद्धि हुई है।
- बाजार के भारी हिस्से पर आयातों द्वारा कब्जा कर लिया गया है।

- ग. विक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग, उत्पादकता, लाभ में गिरावट आई है।
- (ङङ) इस विचाराधीन उत्पाद की मांग का निर्धारण भारत में इस उत्पाद के आयातों, घरेलू उद्योग की घरेलू विक्री और अन्य घरेलू उत्पादकों की घरेलू विक्रियों के रूप में की गई है। क्षति अवधि के दौरान इस विचाराधीन उत्पाद की समग्र मांग में वृद्धि हुई है।
- (चच) आयातों में यह वृद्धि समग्र रूप में और उत्पादन एवं खपत के संगत रूप में भी वृद्धि हुई है।
- (छछ) स्टील संयंत्र की विलक्षणताएं : स्टेनलेस स्टील संयंत्र इलेक्ट्रिक आर्क फरनेस (क्योंकि इसका मुख्य कच्चा माल स्कैप है) पर चलता है। इस फरनेस को चौबीसों घंटे चलाना पड़ता है क्योंकि किसी विशिष्ट बैच के पूरा होने के पश्चात् यदि कोई रूकावट आती है तो जब तक अगला बैच प्रसंस्करण के लिए तैयार होगा तब तक फरनेस ठंडी पड़ जाएगी और फरनेस चैम्बर को पुनः गरम करने के लिए विद्युत की भारी खपत अपेक्षित होती है। इसलिए इस संयंत्र की उपगत तकनीकी प्रकृति के कारण फरनेस को निरंतर आधार पर गरम रखना होता है अथवा दूसरे शब्दों में इसे क्षमता उपयोग के इष्टतम स्तर पर बनाए रखना होता है। इसके क्षमता उपयोग को कम करने से न केवल इसकी उत्पादन की प्रतियुक्ति निर्धारित उपरिशीर्ष लागत बढ़ जाएगी बल्कि अधिक बिजली की खपत होने के कारण उच्चतर वैरिएबल लागत भी बढ़ जाएगी। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए एक अभिलक्षक स्टील उत्पादक अपने संयंत्र को इसे बंद किए बिना सतत आधार पर चलाते हैं।
- (जज) इस अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है परंतु इसमें अक्तूबर-दिसम्बर, 2014 की अत्यधिक अभिनव अवधि में गिरावट हुई है।
- (झझ) यह प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने एक नए स्थान पर एक नवीन ग्रीनफील्ड संयंत्र से नवीन उत्पादन सुविधाओं की शुरुआत की है। याचिकाकर्ता ने विभिन्न प्रकार के हाट एंड कोल्ड स्टील उत्पादों का उत्पादन करने के लिए उड़ीसा में एक नए संयंत्र, जिसकी मेल्टिंग क्षमता 1 मिलियन एमटी ग्रीन फील्ड है, की स्थापना की है। यह सुविधा घरेलू और निर्यात बाजार दोनों के लिए है।
- (ञञ) याचिकाकर्ता के पास इस विचाराधीन उत्पाद के लिए समर्पित क्षमता नहीं है इसलिए (क) याचिकाकर्ता ने इस विचाराधीन उत्पाद को वर्ष 2011-12 (ओडिशा में वाणिज्यिक उत्पादन का पहला साथ) में उपलब्ध क्षमता और इस अवधि में क्षमता उपयोग पर विचार किया है। इस अवधि में क्षमता उपयोग के स्तर पर विचार उत्तरवर्ती वर्षों के दौरान क्षमता का परिकलन करने के लिए विचार किया है; और (ख) इस विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षमता उपयोग के अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने सभी प्रकार के कोल्ड रोलड उत्पादों के लिए क्षमता उपयोग की जानकारी प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, इस कंपनी ने विभिन्न कोल्ड रोलड उत्पादों के लिए अपनी क्षमता में संवृद्धि की है, जिसमें विचाराधीन उत्पाद, जिसकी क्षमता 427500 एमटी थी, बढ़कर इस समय 765,000 एमटी हो गई है। इस प्रकार की क्षमताएं, क्षमताओं का वाणिज्यीकरण होने के साथ ही पूर्णतया प्रचालनात्मक नहीं हो जाती है। इसलिए इस विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षमता पर वर्ष 2011-12 में प्राप्त उत्पादन के आधार पर विचार किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि एक बार जब यह कंपनी उत्पादन के इस स्तर को प्राप्त कर लेगी तो इस उत्पाद की इस क्षमता के संबंध में कोई विवाद नहीं रहेगा।
- (टट) यह देखा जा सकता है कि मांग में वृद्धि होने के बावजूद इस अवधि में क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने पूर्ण क्षमता पर विचार करते हुए भी क्षमता उपयोग का निर्धारण किया है। यह देखा जा सकता है कि घरेलू बाजार में स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोलड फ्लैट उत्पादों का उत्पादन करने के लिए क्षमता पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने और पर्याप्त मांग होने के बावजूद अनुप्रयुक्त बनी रही।

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 पहली तिमाही	2014-15 दूसरी तिमाही	2014-15 तीसरी तिमाही
क्षमता	एमटी	427,500	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000
उत्पादन	एमटी	262,275	364,855	447,833	509,616	532,246	464,188
क्षमता उपयोग	%	61.35	47.69	58.54	66.62	69.57	60.68

(ठठ) बाजार हिस्सा : बाजार हिस्से का उतार-चढ़ाव अधोलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

बाजार हिस्सा (%)	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 पहली तिमाही	2014-15 दूसरी तिमाही	2014-15 तीसरी तिमाही
घरेलू उद्योग	45.33	42.75	44.59	43.50	46.13	43.57
आयात	46.15	49.36	47.79	50.31	47.59	50.39
सभी प्रकार के उत्पादों की कुल क्षमता	4,27,500	7,65,000	7,65,000	7,65,000	7,65,000	7,65,000
भारत में मांग	1,40,600	1,76,342	1,82,423	2,06,121	2,02,835	2,11,098

\*पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही के आंकड़े वार्षिकीकृत आधार पर हैं।

- (डड) यह देखा जा सकता है कि आयातों ने लगभग आधी बाजार पर एक ऐसी स्थिति में अधिपत्य कर लिया है जहां घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त क्षमता है और घरेलू बाजार में आयातों की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।
- (ढढ) इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह गिरावट घरेलू उद्योग द्वारा आयातों के उद्रेक का मुकाबला करने के लिए किए गए प्रयासों, अपने उत्पाद की बिक्री अपनी कीमत की लागत पर और घाटे पर करके, आक्रामक रूप से किया है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा, विगत में न्यूनतर क्षमताओं के साथ प्राप्त बाजार हिस्से की तुलना में बहुत कम है। अतः, न्यूनतर क्षमता पर उच्चतर बाजार हिस्सा और उच्चतर क्षमता से न्यूनतर बाजार हिस्से की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि घरेलू उद्योग पर संवर्धित आयातों का विपरीत प्रभाव पड़ा है।
- (णण) घरेलू बिक्री : अधोलिखित दी गई जानकारी से यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की बिक्रियों में वृद्धि हुई है :

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 पहली तिमाही	2014-15 दूसरी तिमाही	2014-15 तीसरी तिमाही	
घरेलू बिक्रियां (एमटी)	63,729	75,391	81,344	89,673	93,566	91,966	

\*पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही के आंकड़े वार्षिकीकृत आधार पर हैं।

- (तत) यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग बिक्री में वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री का यह स्तर अत्यधिक वित्तीय घाटे की भारी कीमत पर प्राप्त किया जा सका है।
- (थथ) यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में यह वृद्धि भारी क्षमताओं के संस्थापन के बावजूद, मांग में हुई वृद्धि की तुलना में कम है। आयातों में वृद्धि प्रदर्शित हुई है। इस विचाराधीन उत्पाद के कतिपय देशों से पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने के बावजूद आयातों की मात्रा में गिरावट नहीं आई है। बल्कि उसमें वास्तव में वृद्धि हुई है।

#### कीमत प्रभाव

- (दद) कीमत निग्रहण/अवमंदन : आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत के स्तर से कम रही है। यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत तथा बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई है। तथापि, बिक्री कीमत में यह वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि की तुलना में कम है। जबकि, क्षति अवधि के दौरान उत्पादन लागत में 24 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, वहीं बिक्री कीमत में लगभग 5 प्रतिशत तक ही वृद्धि हुई है। यह आयात उत्पादन लागत के स्तर से कम है और इस प्रकार बाजार में घरेलू कीमतों का भारी निग्रहण कर रहे हैं।



	2011-12	2012-13	2013-14 पहली तिमाही	2014-15 दूसरी तिमाही	2014-15
उत्पादन लागत (रुपए/एमटी)	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100	106	119	122	125
बिक्री कीमत (रुपए/एमटी)	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100	102	103	106	105

(धध) लाभप्रदता : घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटा सहन करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग द्वारा सहन किया गया यह घाटा क्षति अवधि के दौरान निरंतर बढ़ता रहा है जैसाकि अधोलिखित तालिका से देखा जा सकता है :

	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	पहली तिमाही 2014-15	दूसरी तिमाही 2014-15
लाभ	रुपए/एमटी	-100	-315	-953	-957	-1,148
नकद लाभ	लाख रुपए	100	-212	-1,258	-1,501	-1,803

(नन) निवेश पर प्रतिलाभ : क्षति अवधि के दौरान निवेश पर प्रतिलाभ भी ऋणात्मक रहा और इसमें गिरावट आई है।

	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	पहली तिमाही 2014-15	दूसरी तिमाही 2014-15
आरओसीई- एनएफए	%	4.07%	-0.73%	-10.88%	-12.59	-15.67

(नत) यह प्रस्तुत किया जाता है कि वित्तीय घाटे से घरेलू उद्योग अक्षम हो रहा है। लगाई गई पूंजी पर प्रतिलाभ संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान ऋणात्मक बना रहा। पुनः यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारी वित्तीय घाटे के कारण घरेलू उद्योग की समग्र वृद्धि ऋणात्मक रही है।

#### घरेलू उद्योग की क्षति – यदि केवल हिसार संयंत्र पर विचार किया जाता है

(पप) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को यह कीमत क्षति अपनी क्षमताओं में विस्तार करने के कारण हुई है। तथापि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता के इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए दो संयंत्र हैं – एक हिसार में और दूसरा ओडिशा में। याचिकाकर्ता ने इन दोनों संयंत्रों के लिए अलग-अलग क्षति सूचना प्रदान की है। यह देखा जा सकता है कि हिसार संयंत्र का स्टैंड अलोन आधार पर निष्पादन दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है। इससे स्पष्टतः यह सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में दावाकृत गिरावट ओडिशा संयंत्र का वाणिज्यीकरण किए जाने के कारण नहीं आई है।

#### गंभीर क्षति संबंधी निष्कर्ष

(फफ) पूर्वोक्त से घरेलू उद्योग यह प्रस्तुतिकरण करता है कि यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि :

- क. इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में समग्र रूप से और भारत में उत्पादन एवं खपत के संगत रूप से वृद्धि हुई है;
- ख. (i) मांग में वृद्धि, (ii) भारी क्षमता संवर्धन, (iii) पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने के बावजूद घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है;

- ग. एक ओर तो आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, न ही घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन करने तथा अपनी कीमतों की लागत पर बिक्री करने के प्रयासों के बावजूद, घरेलू उद्योग अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने में सक्षम नहीं हो सका, बाजार हिस्सा बढ़ाने के प्रश्न का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
- घ. क्षमता में वृद्धि और संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने के बावजूद घरेलू उद्योग की विधिसम्मत बाजार को भी छीन लिया गया है।
- ङ. घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में वृद्धि उस अनुपात में करने में सक्षम नहीं हुआ जिस अनुपात में उसकी लागत में वृद्धि हुई थी। इसके परिणामस्वरूप, आयात, घरेलू उद्योग की कीमतों का निग्रहण कर रहे थे।
- च. घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभ (भारी घाटा) और निवेश पर प्रतिलाभ में गिरावट आई है।
- (बब) अतः यह देखा जा सकता है कि अभिनव अवधि में भारत में उत्पादों के आयात में समग्र रूप से और भारत में उत्पादन तथा खपत के संगत रूप से वृद्धि हुई है। आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में, मांग में वृद्धि होने और घरेलू उद्योग द्वारा पर्याप्त क्षमता विस्तार के बावजूद गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हो रहा है क्योंकि वह कम कीमत के आयातों के कारण उत्पादन लागत के अनुपात में बिक्री कीमत में वृद्धि करने में अक्षम रहा है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संवर्धित आयातों से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित हुई है।

### गंभीर क्षति की चुनौती

- (भभ) घरेलू उद्योग को पहले से ही हुई गंभीर क्षति के अलावा, विचाराधीन उत्पाद के संवर्धित आयात घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित कर रहे हैं। याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि जबकि इस विचाराधीन उत्पाद के आयात घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित कर रहे हैं, वहीं यदि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण तत्काल नहीं किया जाता है तो उस क्षति के और अधिक बढ़ने की संभावना है।

### क्षति के अन्य कारक

- (मम) यद्यपि कोई अन्य ऐसे ज्ञात सूचीबद्ध कारक नहीं हैं जिनकी महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा जांच किया जाना अपेक्षित हों जिन अन्य ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को संभावित क्षति कारित कर रहे हों। संवर्धित आयातों के अलावा कोई अन्य ऐसे कारक नहीं हैं जो घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित कर रहे हों।
- क. उत्पाद की मांग : इस विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। अतः, घरेलू उद्योग को क्षति मांग में गिरावट के कारण नहीं आई है।
- ख. खपत के प्रतिमान में परिवर्तन : इस विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के प्रतिमान में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अतः, खपत के प्रतिमान में परिवर्तन ने घरेलू उद्योग को क्षति में अपना योगदान नहीं दिया है।
- ग. विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं : ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया नहीं है जिससे घरेलू उद्योग क्षति में योगदान मिला हो।
- घ. प्रविधि में विकास : इस उत्पाद का उत्पादन करने की प्रविधि में कोई अंतर नहीं आया है। इसलिए, प्रविधि में विकास क्षति का एक कारक नहीं हो सकता है।
- ङ. निर्यात निष्पादन : घरेलू उद्योग ने केवल अपने घरेलू प्रचालनों के लिए ही सूचना प्रदान कराई है और इसलिए निर्यात निष्पादन क्षति का एक कारण नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त, इस उत्पाद के संवर्धित आयात घरेलू उद्योग को निर्यात की शरण लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अतः, घरेलू उद्योग को निर्यातों में क्षति भी बढ़ते आयातों के कारण हुई है। क्षति का यह विश्लेषण केवल घरेलू प्रचालनों के संबंध में है। इसलिए घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में संभावित गिरावट घरेलू उद्योग को दावाकृत क्षति का एक संभावित कारण नहीं है।
- च. घरेलू उद्योग उत्पादित और बिक्रीकृत अन्य उत्पादों का निष्पादन : घरेलू उद्योग को दावाकृत क्षति इस विचाराधीन उत्पाद के कारण ही आई है। याचिकाकर्ता ने आंकड़ों का पृथक्करण किया है और आंकड़े केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में ही उपलब्ध कराए हैं।

### कारणात्मक संबंध

- ककक. पिछले पैराग्राफों में की गई अभिव्यक्तियों के अनुसार कुछ संभावित ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को दावाकृत क्षति कारित नहीं की है। इस उत्पाद के संवर्धित आयातों ने घरेलू उद्योग को क्षति कारित की है। इस संबंध में निम्नलिखित संगत है :
- क. अभिनव अवधि में घरेलू उद्योग में आयातों की मात्रा में अचानक, तीव्र एवं भारी वृद्धि हुई है।
- ख. आयातों की मात्रा बहुत अधिक है और वह बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है।
- ग. भारत के उत्पादन और मांग के संबंध में आयातों में भारी वृद्धि हुई है।
- घ. घरेलू उद्योग भारत में संवर्धित आयातों को देखते हुए भारी अनुपयुक्त क्षमताओं का उपयोग कर रहा है।
- ङ. यह आयात (i) कीमत निग्रहण, (ii) वित्तीय घाटा, (iii) नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक प्रतिलाभ, (iv) घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमताओं का कम उपयोग।
- च. आयातों में वृद्धि हुई है और उसके प्रत्यक्ष परिणामों के रूप में जहां आयातों के बाजार हिस्से में भारी वृद्धि हुई है वहीं भारतीय उद्योग का हिस्सा कम बना रहा या उसमें गिरावट आई है।

**जनहित**

खखख. याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण जनहित में होगा। जनहित पर रक्षोपाय साधनों के प्रभाव का सामान्यतः अध्ययन तीन भिन्न पक्षकारों के परिदृश्य के मद्देनजर किया जाता है – उत्पादक, उपभोक्ता और सामान्य जनता। जब इस संदर्भ में विचार किया गया तो, वर्तमान मामले में रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण को जनहित में माना गया है, जैसा कि निम्नलिखित से देखा जा सकता है :

- क. उत्पादकों का हित : इस विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण घरेलू विनिर्माताओं के हित में होगा। यह साधन घरेलू उद्योग को संवर्धित आयातों से होने वाली अन्य क्षति बचाएगा।
- ख. उपभोक्ताओं का हित : रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना उपभोक्ताओं के लिए हितकर होगा क्योंकि भारतीय घरेलू उद्योग को, इस विचाराधीन उत्पाद का उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने में सक्षम एवं प्रतिस्पर्धी बनाएगा जो उपभोक्ताओं के हित में होगा। यदि वर्तमान स्थिति को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो घरेलू उद्योग पुनः क्षति का सामना करेगा, और वह विदेशी उत्पाद को अधिक सुविधा प्रदान करेगा।
- ग. अंततः जनहित : एक सुदृढ़, प्रतिस्पर्धी, भारतीय उद्योग होना अंततः जनहित में होगा। यह उस स्थिति में संभव नहीं होगा जब संवर्धित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति जारी रखने की अनुमति दी जाती है। विभिन्न अन्य ऐसे सेगमेंट हैं जो घरेलू उद्योग पर आधारित हैं : जैसे पैकिंग बैग्स, पैकिंग ड्रम्स, पैलेट्स, श्रम एवं श्रम ठेकेदार, सेवा, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता, उपभोज्य वस्तुएं, ईंधन आदि, ट्रांसपोर्टर्स एवं संभारतंत्र प्रदायक, बैंक एवं वित्तीय संस्थान।
- घ. देश में घरेलू उद्योग के लिए जरूरत : यदि संवर्धित आयातों को रोका नहीं जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी और उसकी स्थिति बदतर हो जाएगी। यदि, घरेलू उद्योग का पतन एक ऐसी स्थिति तक होने की अनुमति दी जाती है जिसमें यह प्रचालन नहीं कर सकती है, तो भारतीय उपभोक्ता लगभग पूरी तरह से विदेशी उत्पादकों पर निर्भर से जाएंगे।
- ङ. देश में मौजूदा एवं प्रसंभावित मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता : भारतीय घरेलू उत्पादकों की देश में संभावित/भावी मांग और मौजूदा मांग को पूरा करने की अपेक्षित क्षमता एवं सक्षमता है। इस कारण, उन पर इस विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने का भरोसा किया जा सकता है।
- च. श्रम गहन उद्योग – संबद्ध वस्तु का विनिर्माता उद्योग एक श्रम गहन उद्योग है और यह भारत में श्रमिकों को भारी पैमाने पर रोजगार दिलाता है। इसको संवर्धित आयातों के कारण क्षति सहन करने दिए जाने से देश में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
- छ. सतत उत्पादन प्रक्रिया : संबद्ध वस्तु का विनिर्माण करना एक सतत उत्पादन प्रक्रिया है; यदि घरेलू उद्योग को एक ऐसे बिंदु पर पहुंचाने की अनुमति दे दी जाती है जहां से उसे अपना उत्पादन करना असंभव हो जाए तो जरूरत पड़ने पर उत्पाद को दुबारा शुरू नहीं किया जा सकता है।
- ज. अंतिम उपभोक्ता पर कोई भारी वित्तीय प्रभाव नहीं : अंतिम उत्पादों की लागत पर इसका प्रासंगिक प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है। याचिकाकर्ता ने उपभोक्ताओं के पार्श्वचित्र की जांच की और पाया कि इस विचाराधीन उत्पाद की खपत बिल्कुल ही महत्वहीन है जैसाकि अधोलिखित तालिका से देखा जा सकता है :

क्र.सं.	सेक्टर	अंतिम अनुप्रयोग की लागत के प्रतिशत के रूप में घरेलू उद्योग की 400 सीरीज की कोल्ड रोल्ल स्टेनलेस स्टील की लागत	400 सीरीज की बिक्री का प्रतिशत
1	ऑटोमोटिव	0.12% से 0.43%	57%
2	रेलवे वाहन से रेलवे कोच	1% से 7%	3%
3	बरतन एवं रसोई का सामान	0.10%	23%
4	आर्किटेक्चर भवन एवं विनिर्माण	0.25%	
5	उपभोक्ता उपकरण (सफेद वस्तुएं एवं ब्राउन वस्तुएं)	0.1% से 5.46%	
6.	औद्योगिक अनुप्रयोग	0.11% से 0.16%	17%
क	प्रासेस उद्योग अनुप्रयोग	0.15% से 1.65%	
ख	चिकित्सा उपकरण सेक्टर	4%	
ग	विविध इंजीनियरिंग वस्तुएं	लगभग 0.2%	

गगग. उपर्युक्त मद्देनजर यह प्रस्तुत किया जाता है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण जनहित में होगा और अंतिम प्रयोक्ताओं के हित संरक्षित होंगे।

#### समायोजन योजना

घघघ. याचिकाकर्ता रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण चार वर्ष तक करने के लिए अनुरोध करता है। घरेलू उद्योग की समायोजन योजना इस प्रस्तुतिकरण के साथ संलग्न है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने समायोजन योजना का विस्तृत विवरण प्रदान कराया है। महानिदेशक (रक्षोपाय) ने इस समायोजन योजना के संबंध में कोई पड़ताल नहीं की है। न ही महानिदेशक (रक्षोपाय) ने यह पाया है कि इस संबंध में प्रदान कराई गई सूचना अपर्याप्त है। यदि महानिदेशक (रक्षोपाय) यह मानते हैं कि समायोजन योजना से संबंधित कोई सूचना अपर्याप्त है तो घरेलू उद्योग को समुचित रूप से निदेश दिए जाने की जरूरत है।

#### निष्कर्ष

ङङङ. इस जांच से यह स्पष्टतया सिद्ध हो गया है कि इस विचाराधीन उत्पाद के आयात नियमावली के आशय के अंतर्गत संबंधित आयात हैं। घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है। घरेलू उद्योग को यह गंभीर क्षति संबंधित आयातों के कारण हुई है। रक्षोपाय शुल्क से संबंधित सभी पैरामीटर पूर्णतया पूरे होते हैं।

#### प्रार्थना

चचच. इसलिए, उठाए गए तर्कों से प्रदान कराई गई सूचना और किए गए प्रस्तुतिकरणों के आलोक में प्राधिकारी कृपया (क) यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 400 सीरीज के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोलड फ्लैट उत्पादों के भारत में संबंधित आयात ने घरेलू उत्पादों को गंभीर क्षति कारित की है और गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न कर दी है और इसलिए 400 सीरीज के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोलड फ्लैट उत्पादों के भारत में होने वाले आयातों पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में होगा। (ख) घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई गंभीर क्षति के ध्यान में रखते हुए रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश कर सकते हैं।

#### ख. मैक्सिको के दूतावास, नई दिल्ली द्वारा दायर किया गया लिखित प्रस्तुतिकरण

- (क) याचिका या शुरुआत निर्धारण में इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया था कि क्या भारी मात्रा में आयात किया गया है अथवा, किसी भी अवस्था में वह क्रियाविधि जो यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग की गई थी कि क्या अनुमानित आयात मात्रा की विकृति नहीं हुई है।
- (ख) कोई भी जांच शुरुआत करने के लिए आयातों की मात्रा का विशुद्ध एवं परिशुद्ध अभिज्ञान करना एक अपेक्षा होती है क्योंकि इस पहलू का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में और इन आयातों के घरेलू उद्योग पर प्रभाव में वृद्धि हुई है और इन पहलुओं को जांच उत्तरवर्ती अवस्था में सुधार नहीं किया जा सकता है।
- (ग) जांच के इस स्तर पर याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण नामंजूर कर दिया जाना चाहिए और उस प्रक्रिया को रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण किए बिना तत्काल खारिज कर दी जानी चाहिए।
- (घ) मैक्सिको का आयात निश्चित रूप से कुल आयातों के 3 प्रतिशत से कम होगा, यह वह मामला है कि जिसमें मैक्सिको को रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 9 के अनुसार किसी प्रासंगिक साधन को अपनाने से अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए।

#### ग. मैसर्स हिन्दुस्तान सिरिंजेज और मेडिकल डिवाइसेस लिमिटेड द्वारा दायर किया गया लिखित प्रस्तुतिकरण

- (क) वे सर्जिकल ब्लेड्स (एचएस कोड 90189022) का विनिर्माण करने के लिए स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप (एचएस कोड 72209090) का स्विटजरलैंड से आयात कर रहे हैं जो मुख्यतः यूएसए और यूरोप से निर्यात करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
- (ख) स्टेनलेस स्टील ग्रेड/रसायन संघटन, जिसका वे सर्जिकल ब्लेडों का विनिर्माण करने के लिए आयात कर रहे हैं, वे तीव्र एवं स्थाई कटिंग एज और दुर्घटनात्मक टूटफूट से बचने के लिए ब्लेड की दृढ़ीकर्ता सुनिश्चित करने के लिए भारत में उपलब्ध नहीं हैं।
- (ग) उनकी स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप की औसत आयात कीमत 300/- प्रति किलोग्राम से अधिक है। जबकि याचिकाकर्ता की विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) की औसत कीमत रेंज 82/- रुपए से 90/- रुपए प्रति किलोग्राम है। उनकी आयात कीमत याचिकाकर्ता की औसत कीमत से इसे 4 गुना अधिक होती है।
- (घ) उनकी आयातित स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप्स की याचिकाकर्ता के विचाराधीन उत्पाद के साथ प्रत्यक्षतः/अप्रत्यक्षतः कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और यह मुख्यतः निर्यात बाजार में खपत के लिए होता है। स्टेनलेस स्टील ब्लेडों का लगभग 95 प्रतिशत निर्यात किया जाता है।
- (ङ) स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से चिकित्सा/स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों की लागत बढ़ जाएगी और वे निर्यात बाजार में अप्रतिस्पर्धी बन जाएंगे।

#### घ. मैसर्स पास्को कोरिया द्वारा दायर किया गया लिखित प्रस्तुतिकरण

- (क) कई आटोमोबाइल उत्पादक अभी भी आयातित स्टील उत्पादों पर निर्भर हैं क्योंकि भारत के घरेलू आपूर्तिकर्ता अंतिम प्रयोक्ताओं के अपेक्षित मानदंडों को पूरा नहीं कर पाते हैं।
- (ख) आकस्मिक रक्षोपाय शुल्क लगाने से भारत की घरेलू बाजार में एकाधिकारवाद को प्रोत्साहन मिलेगा और उसके परिणामस्वरूप, स्थानीय आटोमोबाइल के विनिर्माताओं के लिए आपूर्ति की कमी हो सकती है जब तक कि वे अपने गुणवत्ता मानदंडों को कम नहीं कर देते हैं।

- (ग) 400 सीरीज के कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस के निम्नलिखित ग्रेडों का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है और उन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जित किया जा सकता है।
- 429ईएम, पीओएस 429ईएम – ताप प्रतिरोधक पार्टस जैसे एक्झास्ट मैनीफोल्ड और फ्रंट पाइप के लिए प्रयोग किया जाता है।
  - 430 जेआईएल, एसटीएस 430 जेआईएल, एसयूएस 430 जेआईएल, ईएन 1.4511 और आदि : इसका प्रयोग प्रमुखतः आटोमोटिव निष्कासन प्रणाली, घरेलू उपकरणों और भवनों को एक्स्टीरियर सामग्री के लिए किया जाता है।
  - 444, एसटीएस 444, एसयूएस 444, एसटीएम 444, ईएन 1.4521 और आदि : इसका प्रयोग मुख्यतः गरम जल प्रणाली, ताप एक्सचेंजर और आटो एक्झास्ट सिस्टम के लिए किया जाता है।
  - 445एनएफ, पीओएस 445एनएफ : इसका मुख्यतः प्रयोग एलिवेटर, घरों में प्रयोग किए गए बरतनों और इलेक्ट्रॉनिक संघटनों के लिए किया जाता है।
  - 446एम, पीओएस 446 एम : इसका प्रयोग मुख्यतः तटवर्ती एवं औद्योगिक क्षेत्रों में छत एवं बाह्य भवन सामग्री के लिए किया जाता है।
- (घ) पास्को माननीय महानिदेशक (रक्षोपाय) से विनम्रतापूर्वक यह अनुरोध करता है कि वह अपने अंतिम निर्धारण से पूर्व यह सत्यापित करें कि अप्रैल, 2014 और मार्च, 2015 के बीच आयात की गई वास्तविक मात्रा कितनी है।
- (ङ) यद्यपि, याचिका के अनुसार वर्ष 2011-12 और 2012-13 के बीच कुल आयातों में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यह मुख्यतः भारतीय घरेलू मांग में वृद्धि होने के कारण हुई है। इतनी अधिक वृद्धि होने के बावजूद, भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा हमेशा लगभग 50 प्रतिशत के आसपास रहा है। इसे कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं माना जा सकता है।
- (च) याचिकाकर्ता की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, अत्यधिक क्षमता वृद्धि के मद्देनजर उनके क्षमता उपयोग में वर्ष 2011-12 में 51.95 प्रतिशत तक कमी आई है। उत्पादन प्रक्रिया में सामान्यीकरण होने से क्षमता उपयोग में एक बार पुनः सुधार हुआ और वर्ष 2013-14 के दौरान बढ़कर 85.33 प्रतिशत हो गया। तथापि, याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को छुपा लिया और यह गलत सूचना दी कि उनका क्षमता उपयोग वर्ष 2013-14 के दौरान केवल 58.54 प्रतिशत था।
- (छ) यह क्षति भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण नहीं हुई परंतु यह क्षति याचिकाकर्ता के आंतरिक कारणों से हुई। इन कारणों का संक्षेप में उल्लेख निम्नवत किया जा सकता है :
- ओडिशा में स्थापित नया संयंत्र – जिसमें स्टार्ट अप लागत में वृद्धि हुई।
  - बेशी क्षमता, जिसके कारण अतिरिक्त मालसूची हुई और बिक्री कम कीमत पर हुई।

**ड. मैसर्स लक्ष्मी कुमार एंड श्रीधर एडवोकेट्स ने मैसर्स मेटल वन कारपोरेशन इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड, मैसर्स बाहुरु स्टेनलेस एसडीएन, मलेशिया और मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मर्चेन्ट्स एसोसिएशन की ओर से लिखित प्रस्तुतिकरण दायर किया।**

- (क) वर्तमान जांच को खारिज कर दिया जाना अपेक्षित है क्योंकि आवेदक द्वारा चुनी गई अवधि और डीजीएस द्वारा विचार की गई अवधि अनुचित एवं अयथार्थ है। आवेदक यह प्रकटन करने में असफल रहा कि जनवरी, 2014 के पश्चात् से, संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले इसके ओडिशा संयंत्र के समक्ष प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने की समस्या उत्पन्न हो गई और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उसको बंद किए जाने की समस्या सदैव बनी रही।
- (ख) आवेदक ने अपनी याचिका में केवल 3 माह (अप्रैल, 2014 से जून, 2014 तक) की अवधि की आयात सांख्यिकी प्रस्तुत की है और वह भी प्रत्येक माह के लिए नमूना आधार पर।
- (ग) प्राधिकारी को आयात सांख्यिकी पीडीएफ प्ररूप में प्रदान कराई गई और उसमें भी यह क्रियापद्धति प्रदान नहीं कराई गई कि अनंतिम आयात आंकड़ों की छंटाई करके इस विचाराधीन उत्पाद के अंतिम आंकड़ों पर कैसे पहुंचा जा सकता है और वही आंकड़े हितवद्ध पक्षकारों को प्रदान कराए गए और वह भी दिनांक 15.01.2015 को मौखिक सुनवाई के पश्चात्, डीजीएस के समक्ष तर्क वितर्क करके।
- (घ) चूंकि आवेदक ने आयात सांख्यिकी न तो एक्सेल फॉर्मेट में उपलब्ध कराई और न ही उसके लिए कोई क्रियापद्धति प्रदान कराई, प्राधिकारी को पीडीएफ आयात आंकड़े प्रदान कराए गए और वह भी बिना किसी क्रियापद्धति के, इसलिए उन्हें नामंजूर कर दिए जाने की जरूरत है और उसके परिणामस्वरूप केवल इस आधार पर इस जांच को भी खारिज किया जा सकता है।
- (ङ) आवेदक द्वारा उत्तरवर्ती रूप से दिनांक 15 जनवरी, 2015 को प्रदान कराई गई आयात आंकड़ों का परिशोधन करने की क्रियाविधि त्रुटिपूर्ण है और उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। आवेदक ने आयात आंकड़ों की छंटाई एक ऐसे ढंग से की है जिसके परिणामस्वरूप आयात आंकड़े बढ़-चढ़कर प्रस्तुत किए गए हैं।
- (च) क्रियापद्धति के स्टेप 1 और स्टेप 3 में, यदि आवेदक ने आयात आंकड़ों का पृथक्करण सौदों के विवरण के आधार पर किया है तो वह अध्याय शीर्ष संख्या 7219 तथा 7220 के मामले में समान कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध था। परंतु आवेदक द्वारा वह कार्य नहीं किया गया है। इससे आवेदक द्वारा आयात आंकड़ों के पृथक्करण पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है।
- (छ) क्रियापद्धति के स्टेप 5 में, यह कहना गलत है कि आटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए केवल 400 सीरीज के कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील का ही प्रयोग किया जाता है। अन्य ग्रेड्स भी हैं जैसे 300 सीरीज (304एल) जिनका प्रयोग भी आटोमोटिव सेक्टर द्वारा किया जाता है। आवेदक ने "आटोमोटिव प्रयोजन के लिए" उल्लेख करते हुए उत्पादों का विवरण देकर, अन्य

सीरीज को भी जैसे 300 सीरीज को भी इसमें शामिल किया है, तद्वारा आयात की मात्रा का स्फीतन किया है। इसके मद्देनजर आवेदक द्वारा प्रदान कराए गए आयाता आंकड़ों को नामंजूर कर दिया जाना चाहिए।

- (ज) अध्याय शीर्ष 72193210, 72193310, 72193410, 72193510, 72202021, 72209021 के के अंतर्गत आने वाले संव्यवहारों पर विचार करके आवेदक द्वारा अपनाई गई क्रियापद्धति पूरी तरह से गलत है और उसे अस्वीकार कर दिया जाना अपेक्षित है। यह नहीं माना जा सकता है कि ऊपर उल्लिखित अध्याय शीर्षों में केवल 400 सीरीज के कोल्ड रोल्ड उत्पादों का उल्लेख है क्योंकि उनमें 300 सीरीज के कई संव्यवहारों का उल्लेख भी है, जो उपर्युक्त अध्याय शीर्षों के अंतर्गत ही आते हैं। उपर्युक्त अध्याय शीर्षों के लिए वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए आयात सांख्यिकी का सौदा-दर-सौदावार विवरण, जिसमें 300 सीरीज का विवरण भी है, प्रस्तुतिकरणों के प्रदर्श 3 के रूप में प्रदान कराया गया है।
- (झ) मैसर्स मेटल बन कारपोरेशन इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा अपनाई गई क्रियापद्धति निम्नलिखित है :
1. प्रथमतः, अनन्तिम आयात आंकड़ों का परिशोधन किया गया और आवेदक घरेलू उत्पादक द्वारा भरोसा किए गए अध्याय शीर्षों के लिए आयात सांख्यिकी का अभिज्ञान किया गया।
  2. द्वितीयतः, इस तरह परिशोधित आयात सांख्यिकी से उन संव्यवहारों को अलग किया गया जो 400 सीरीज के अलावा थे (321, 301, 303, 316, 304, 201, 310, 200, 305, 202, 309, 347 और 240 सीरीज) उनका वर्गीकरण "एनपीयूसी" के रूप में किया गया।
  3. तृतीयतः, इस पृथक्कृत आयात सांख्यिकी से विवरण में उन सौदों को अलग किया गया जिनमें "एचआर" अथवा "एचआरएसएस" अथवा "एचआर" या "एचआरएसएस" अथवा "हाट रोल्ड" का उल्लेख था और फिर उन्हें "एनपीयूसी" के रूप में वर्गीकृत किया गया।
  4. चतुर्थतः, उन संव्यवहारों को जिनका उल्लेख किसी भी रूप में नहीं किया गया कि क्या वह जांच शुरूआत नोटिस में यथापरिभाषित संबद्ध उत्पाद है या नहीं, का पृथक्करण करके, उसे "अज्ञात" के रूप में वर्गीकृत किया गया।
  5. उपर्युक्त की तरह संशोधित किए गए आयात आंकड़ों पर "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में विचार किया गया।
- (ञ) उपर्युक्त विश्लेषण करने पर अप्रैल-जून, 2014 की अवधि की संपूर्ण मात्रा 22655 एमटी बनती है। इसके विपरीत, आवेदक घरेलू उत्पादक द्वारा इसी अवधि के लिए प्रदान कराई गई आयात मात्रा 25925 एमटी है।
- (ट) जहां केवल 3 माह की अवधि के आंकड़ों में इतना अधिक अंतर मौजूद हो वहां पूर्ववर्ती अवधि के लिए भी आंकड़ों में भारी अंतर हो सकता है, इससे आवेदक घरेलू उत्पादक द्वारा प्रदान कराई गई आयात सांख्यिकी भरोसेमंद तो बिल्कुल ही प्रतीत नहीं होती है।
- (ठ) 3 महीनों की आयात सांख्यिकी का वार्षिकीकरण करना वर्ष 2014-15 के लिए वास्तविक आयात आंकड़ों का निर्धारण करने का एक उपयुक्त तरीका नहीं है।
- (ड) आवेदक द्वारा उत्तरवर्ती अवधि जुलाई, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक की अवधि के लिए प्रदान कराई गई आयात सूचना भी असफल सिद्ध होगी जब तक कि आवेदक मांग और क्षति पैरामीटरों जैसे उत्पादन, बिक्री मालसूची, लाभप्रदता आदि से संबंधित समनुरूपी सूचना प्रदान नहीं कराता है।
- (ढ) आवेदक द्वारा प्रदान कराई गई आयात सांख्यिकी को नामंजूर कर दिए जाने की जरूरत है और आयातों में वृद्धि से संबंधित साक्ष्य उपयुक्त फॉर्मेट में प्रदान न कराए जाने के कारण इस जांच को खारिज कर दिया जाना चाहिए।
- (ण) आवेदक घरेलू उत्पादक को चाहिए कि वह आयात सांख्यिकी का वर्णन एक्सेल वर्जन में उपलब्ध कराए और अनन्तिम आयात आंकड़ों से इस विचाराधीन उत्पाद को अभिज्ञात करने का ढंग भी बताए।
- (त) नवम्बर, 2014 के पश्चात् से आवेदक का संयंत्र कमोवेश रूप से बंद ही कर दिया गया था और उसके पुनः प्रचालनरत होने की अभी तक कोई खबर नहीं है। अतः, क्षति पैरामीटर निश्चय ही ऋणात्मक परिणाम प्रदर्शित करेंगे।

#### अनपेक्षित विकास

- (थ) गाट के अनुच्छेद XIX में 2 अनिवार्य शर्तों को पूरा करना अपेक्षित है : (i) अनपेक्षित विकास और (ii) इस करार के अंतर्गत प्रशुल्क रियायतों सहित उपगत दायित्व का प्रभाव; जिसके कारण ऐसे आयातों में वृद्धि होती है जो घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति कारित करते हैं या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न कर देते हैं। जब तक यह शर्त पूरी नहीं होती है तब तक रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण नहीं किया जा सकता है।
- (द) आवेदक को यह दर्शाना होता है कि कतिपय विकास किस तरह से अनपेक्षित विकास थे, जब भारत ने गाट 1994 के अंतर्गत दायित्वों को उपगत किया तो भी उनसे जांच की अवधि में आयातों में वृद्धि हुई। यदि आवेदक उपर्युक्त का स्पष्टीकरण देने से असफल रहता है तो भी प्राधिकारी पर यह दायित्व रहता है कि वह उपर्युक्त विश्लेषण करे।
- (ध) न तो याचिका में और न ही संबद्ध जांच के लिए जारी जांच शुरूआत अधिसूचना में ऐसे किसी अनपेक्षित विकास का अभिज्ञान किया गया है जिससे संबद्ध उत्पाद के आयात में वृद्धि हुई हो।
- (न) परस्पर एफटीए की मौजूदगी का मतलब "अनपेक्षित विकास" नहीं है और यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध एक सामान्य ज्ञान है।
- (त) भारत में स्टील उत्पादों के लिए डब्ल्यूटीओ के समक्ष 40 प्रतिशत के रूप में एक बाध्यता दर वचनबद्धता की है। भारत ने सीमा शुल्क को एकपक्षीय रूप से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया। भारत द्वारा कुछ देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार

- करार में उल्लिखित निबंधनों के अनुरूप इस शुल्क में और भी कमी करने का प्रावधान है। अतः, शुल्क में यह कमी करना, सरकार का अपना नीतिगत निर्णय था, जिसका उल्लेख गाट के अंतर्गत उपगत दायित्व के रूप में नहीं किया जा सकता है।
- (प) याचिका में यथा उल्लिखित, आयातों में यह वृद्धि आशियान और जापान एवं कोरिया सहित सीईपीए के साथ किए गए एफटीए की मौजूदगी के कारण हो सकती है।
- (फ) चूंकि सीईपीए के अंतर्गत प्रतिबद्धता के अनुसरण में सीमाशुल्क कम हो गया, इसलिए जापान से होने वाले आयातों में भी समनुरूपी वृद्धि प्रदर्शित हुई है। इससे स्पष्टतः यह प्रदर्शित होता है कि आयातों में यह वृद्धि भारत द्वारा किए गए एफटीए के कारण हुई है।

### वैकल्पिक उपचार की मौजूदगी

- (ब) भारत ने कोरिया आरपी, थाईलैंड, चीन जनगण, ईयू, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका और ताईवान से 400 सीरीज स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयातों पर दिनांक 20 फरवरी, 2010 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 14/2010-सीमाशुल्क (जिसे एक समीक्षा के अनुसरण में दिनांक 6 सितम्बर, 2011 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 86/2011 सीमाशुल्क के तहत संशोधित किया गया) के तहत और दिनांक 04 अक्टूबर, 2012 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 46/2012-सीमाशुल्क के तहत पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण पहले ही कर दिया गया है।
- (भ) वर्तमान मामले में संबद्ध वस्तु के आयातों द्वारा कारित क्षतिकारी प्रभावों को तो संबद्ध उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करके पहले ही समाप्त कर दिया गया है।
- (म) यदि आवेदक यह महसूस करता है कि पाटनरोधी शुल्क द्वारा प्रदान कराया गया संरक्षण पर्याप्त नहीं है तो वह एक अंतरिम समीक्षा करने के लिए आवेदन कर सकता है जिसमें आवेदक द्वारा सहन की गई क्षति के स्तर के आधार पर पाटनरोधी शुल्क में वृद्धि की जा सकती है।

### आयातों में कोई तीव्र उद्रेक नहीं

- (कक) आयात अभिनव, अचानक, तीव्र या बहुत अधिक नहीं हुए जिनके कारण श्रेसहोल्ड के मापदंड भी पूरे नहीं हो रहे हैं।

### किसी गंभीर क्षति या कारणात्मक संबंध का कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं

- (खख) आवेदक उद्योग ने गंभीर क्षति का मामला बनने के लिए कोई भरोसेमंद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उसने कई इस तथ्य के बावजूद कि आवेदन में दिए गए साक्ष्यों के आधार पर इस मामले से गंभीर क्षति का कोई मामला नहीं बनता है, आवेदक ने कई संवेदनशील तथ्यों को क्षति सूचना से रोक दिया है।
- (गग) कुल क्षमता से 400 सीरीज के लिए क्षमता का पृथक्करण करने के लिए विहित क्रियापद्धति अभी भी स्पष्ट नहीं है।
- (घघ) आवेदक द्वारा किए गए उल्लेख के अनुसार, आधार वर्ष से क्षमता उपयोग की तुलना वर्ष 2014-15 से करने मात्र से ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि क्षति हुई है और यह एक गलत अधिगम है तथा इसमें सुधार करने के साथ-साथ आवेदक द्वारा क्षमता संवर्धन करने की आवश्यकता भी है।
- (ङङ) वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान आवेदक को विद्युत और ईंधन व्यय पर भारी राशि उपगत करनी पड़ी, जो आवेदक को हुई क्षति के कारणों में से एक कारण है।
- (चच) विद्युत व्यय में हुई असाधारण वृद्धि से आवेदक को होने वाले क्षति के लिए आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
- (छछ) आवेदक को भारी घाटा अपनी क्षमता को दोगुना करने के लिए उपगत संवर्धित नियत व्यय के कारण भी हो सकता है।
- (जज) आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि आवेदक की नियत लागत में वर्ष 2010-11 से निरंतर वृद्धि हो रही है। नियत लागत में यह वृद्धि लाभप्रदता में जिसे आवेदक द्वारा दायर याचिका में प्रक्षेपित किया गया है प्रपाती गिरावट के कारण आई है। यह भी देखा जा सकता है कि अवक्षयण प्रभारों एवं वित्त प्रभारों में वृद्धि के साथ-साथ भी आवेदक को भारी घाटा हुआ है, एतद्वारा इन दोनों के बीच सकारात्मक सह-संबंध प्रदर्शित होता है। अतः, लाभप्रदता में भारी गिरावट के लिए आयातों को दोषी ठहराया अतर्किक है, और वह भी ऐसी स्थिति में जब आयाता मात्रा संवर्धित उतराई मूल्य के स्तर के समान ही बनी रही। इससे यह प्रदर्शित होता है कि कुछ अन्य कारक भी हैं, जैसे असामान्य रूप से उच्च मूल्यहास और वित्तीय प्रभार, जो आवेदक को क्षति कारित कर रहे हैं। निष्कर्षात्मक रूप से इससे यह प्रदर्शित होता है कि आवेदक को हुई क्षति के लिए कुछ अन्य कारक उत्तरदायी हैं न कि आयात। इसलिए, वर्तमान जांच में कारणात्मक का विश्लेषण असफल रहता है और इस कारण इस जांच को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

- (झझ) विद्युत एवं ईंधन लागत, अवक्षयण और वित्त प्रभारों के संबंध में प्रति यूनिट उत्पादन लागत में वर्ष 2011-12 की तुलना में वृद्धि हुई है। इससे यह सिद्ध होता है कि आवेदक को हुआ घाटा वास्तव में अन्य कारकों के कारण हुआ है, न कि आयातों के कारण।

(लाख रुपए में)	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
सीआरएसएस 400 सीरीज का उत्पादन (याचिका के अनुसार)		67,876	83,240	94,929
विद्युत एवं ईंधन (करोड़ रुपए में)		815.5	1,235.18	1272.08
प्रति यूनिट (रुपए/एमटी)		<b>0.012</b>	<b>0.015</b>	<b>0.013</b>
अवक्षयण	35,614	40,861	70,130	68,766
प्रति यूनिट (रुपए/एमटी)		<b>0.60</b>	<b>0.84</b>	<b>0.72</b>
वित्तीय प्रभार	38,874	51,680	99,029	123,470
प्रति यूनिट (रुपए/एमटी)		<b>0.76</b>	<b>1.19</b>	<b>1.30</b>

- (जज) उतराई मूल्य का परिकलन आकलनीय मूल्य में सीमाशुल्क और शिक्षा उपकर जोड़कर किया जाता है, न कि आयातों के सीआईएफ मूल्य से।
- (टट) आवेदक संबद्ध वस्तु की बिक्री स्लिट रूप में करता है न कि वाइड कॉइल फार्म में। इसी तरह, भारत में संबद्ध वस्तु का आयात वाइड कॉइल फार्म में किया जाता है जिसे पहले स्लिट फार्म में काटा जाता है और फिर भारत में उनकी बिक्री की जाती है। आयातित वस्तुओं और घरेलू समान वस्तुओं के बीच वस्तु वार तुलना करने की सही विधि संबद्ध वस्तु के केवल स्लिट फार्म से तुलना करना हो सकती है, न कि भारत में आयातित वाइड कॉइल्स की आयात कीमतों से तुलना करके।
- (ठठ) आवेदक ने यह उल्लेख नहीं किया है कि क्या कोई कीमत अधोविक्रयण, कीमत निग्रहण या कीमत अवमंदन हुआ है और इनसे संबंधित आंकड़ों को प्रदान कराए बिना ही क्षति का दावा कर दिया है। चूंकि यह सूचना याचिका को अगोपनीय पाठ में प्रदान नहीं कराई गई है, इसलिए, बिना कहे ही यह कहा जा सकता है कि उक्त सूचना महानिदेशक रक्षोपाय को भी गोपनीय रूप में प्रदान नहीं कराई गई है।

#### संवर्धित आयातों और गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करने की जरूरत

- (डड) भारतीय रक्षोपाय नियमावली के नियम 5 और 11 के साथ पठित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख के अनुसार प्राधिकारी को इन "संवर्धित आयातों" और आवेदक को हुई "गंभीर क्षति" के बीच कारणात्मक संबंध के बिना वर्तमान जांच में रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण नहीं किया जा सकता है।
- (ढढ) आवेदक द्वारा दायर की गई याचिका स्पष्टतः यह दर्शाती है कि :
- क. वर्ष 2011-12 के प्रारंभ में भी, जब आयात बहुत कम थे, आवेदक को घाटा हो रहा था।
- ख. आवेदक के निष्पादन पर इन आयातों का कीमत प्रभाव कहीं भी मौजूद नहीं है क्योंकि आयातों में थोड़ी सी भी वृद्धि (मात्रा और कीमत दोनों रूपों में) आवेदक की लाभप्रदता में भारी अननुपातिक गिरावट ला सकती थी। यह प्रवृत्ति वर्ष 2011-12 और 2012-13 के बीच दृष्टिगोचर है।
- ग. वर्ष 2012-13 और 2013-14 के बीच आवेदक के निष्पादन और आयातों के बीच सह संबंध का अभाव है अथवा समग्र ऋणात्मक सह संबंध है, जिससे यह सिद्ध होता है कि उनके बीच कारणात्मक संबंध का अभाव है। हालांकि आयात मात्र स्थिर बनी रही और वर्ष 2012-13 तथा वर्ष 2013-14 के बीच आयात कीमतों में वास्तव में वृद्धि हुई, फिर भी, प्रति यूनिट घाटा तीन गुना हो गया, नकद घाटे में लगभग 6 गुना वृद्धि हो गई और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ में 15 गुना से अधिक गिरावट आई।

#### असाध्य समायोजन योजना

- (णण) समायोजन योजना संबंधित उत्पाद विशिष्ट होनी चाहिए और उसका प्रयोग प्रश्नाधीन उत्पाद पर ध्यान दिए बिना, कंपनी की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
- (तत) चूंकि कुछ भी उल्लेख रिकार्ड में नहीं किया गया है, इसलिए आवेदक की कोई ठोस समायोजन योजना नहीं है और वह रक्षोपाय शुल्क का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है।



- (थथ) समस्त विवरण गोपनीय रखकर आवेदक ने यह सुझाव दिया है कि इस पुनर्समायोजन के परिणामस्वरूप विद्युत लागत में कमी की जा सकती है। तथापि, उसने इसके समर्थन में, अपने दावे को साक्ष्यांकित करने के लिए कोई समर्थनकारी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।
- (दद) आवेदक ने अनन्तिम साधन की जरूरत के लिए भी कोई साक्ष्य नहीं दिया है।
- (धध) महानिदेशक रक्षोपाय ने आवेदक की गोपनीयता के दावे को स्वीकार कर लिया और इस तथ्य के बावजूद भी कि याचिका की एनबीसी में इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है कि इस सूचना का गोपनीय के रूप में क्यों माना जाए और इस सूचना को सार्वजनिक तौर पर संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत क्यों नहीं किया जा सकता है, अपना निष्कर्ष निकाल लिया।
- (नन) पारदर्शिता के उद्देश्य से महानिदेशक रक्षोपाय को उस क्रियाविधि का प्रकटन करना अपेक्षित है जिसका प्रयोग वह रक्षोपाय शुल्क के स्तर का निर्धारण करने के लिए कर सकते हैं।

**च. मैसर्स ईएलपी एडवोकेट्स एंड सालिसिटर्स ने मैसर्स निप्पन स्टील एंड सुमिकिन स्टेनलेस स्टील कारपोरेशन, मैसर्स निशिन स्टील कंपनी लिमिटेड, मैसर्स जेएफई स्टील कारपोरेशन, मैसर्स आउटोकुम्पु स्टेनलेस स्टील ओयज, फिनलैंड, आउटोकुम्पु निरोस्टा जीएमबीएच, जर्मनी और शंघाई क्रुप स्टेनलेस कंपनी की ओर से लिखित प्रस्तुतिकरण किया।**

#### **सूचना की पर्याप्तता एवं यथार्थता**

- (क) याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान कराए गए लेनदेनवार आंकड़े अधूरे हैं और वह जनवरी, 2014 से जून, 2014 तक की अवधि को ही कवर करते हैं।
- (ख) इस जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ भरोसा किए गए अंतिम आयात आंकड़ों पर पहुंचने के लिए वह आधार और ढंग जिनपर उक्त आयात आंकड़ों का पृथक्करण एवं परिष्करण किया गया है, इस याचिका में वर्णित नहीं किया गया है।
- (ग) वह आयात आंकड़े जिनके आधार पर वर्तमान जांच शुरू की गई है, उनमें स्वयं यह प्रविष्टि है कि वे प्रथमतः इस विचाराधीन उत्पाद के संबंधित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान कराए गए आयात आंकड़ों में विभिन्न प्रविष्टियां हैं जहां ग्रेड को अभिज्ञात नहीं किया गया है।
- (घ) आयात आंकड़ों का निर्धारण नए सिरे से किया जाना चाहिए और गैर-विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किए गए सभी संव्यवहारों को आयात आंकड़ों से कड़ाई से हटा दिया जाना चाहिए। आयात आंकड़ों को अंतिम रूप देते वक्त, उसे हितवद्ध पक्षकारों के बीच परिचालित किया जाना चाहिए और सभी हितवद्ध पक्षकारों को उनका सत्यापन करने और सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए नया अवसर दिया जाना चाहिए।
- (ङ) कई उत्पादों का विनिर्माण तो याचिकाकर्ता द्वारा अब भी नहीं किया जा रहा है और इसलिए उनका अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए।

#### **अनपेक्षित परिस्थितियों का अभाव**

- (च) गाट के अनुच्छेद-XIX के अंतर्गत यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि उसमें यह प्रदर्शित होना चाहिए कि आयातों में वृद्धि अनपेक्षित विकास के परिणामस्वरूप कारित हुई है।
- (छ) न तो घरेलू उद्योग की याचिका में और न ही जांच शुरुआत नोटिस में अनपेक्षित परिस्थितियों या उन घटनाओं का कोई उल्लेख किया गया है जिनके कारण आयातों में इतनी अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है।
- (ज) याचिकाकर्ता को अभी भी यह सिद्ध करना है कि वैश्विक मांग एवं आपूर्ति का अंतर अनपेक्षित विकास था।
- (झ) याचिकाकर्ता का दावा परस्पर विरोधाभासी है और यह उसके द्वारा चीन द्वारा आयातों/निर्यातों की प्रवृत्ति और याचिका के क्रमशः पृष्ठ 16 एवं 17 पर दर्शाए गए चीन में मांग आपूर्ति अंतर से संबंधित प्रदान कराई गई सूचना से असंगत है।
- (ञ) वह लागत लाभ जो उत्पादकों को अन्य देशों में होना चाहिए, वह आयातों में अचानक वृद्धि का आधार नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त, यह लागत लाभ न तो अनपेक्षित है और न ही वे गाट के अंतर्गत भारत की रियायतों या दायित्वों से उत्पन्न हुए हैं।
- (ट) याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान कराए गए आयात आंकड़ों का एक अध्ययन मात्र यह प्रदर्शित करता है कि ईयू से आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है और वास्तव में वर्ष 2014-15 (वार्षिकीकृत) में ईयू से होने वाले आयातों में मामूली सी वृद्धि हुई है परंतु उन्होंने वर्ष 2012-13 की तुलना में सतत गिरावट प्रदर्शित की है।
- (ठ) जापान में मांग आपूर्ति अंतर अर्थात् स्पष्ट मांग की तुलना में कम उत्पादन, स्थिर बना हुआ है जो यह दर्शाता है कि प्रश्नाधीन अवधि किसी तरह का अनपेक्षित विकास नहीं देखा गया।
- (ड) एक एफटीए/पीटीए के अनुसरण में शुल्क की दरों में घटौती न तो अनपेक्षित विकास है और न ही अप्रत्याशित विकास, बल्कि यह एक सामान्य रूप से ज्ञात तथ्य है।
- (ढ) याचिकाकर्ता का यह प्रस्तुतिकरण कि पाटनरोधी शुल्क लगे होने के बावजूद आयात लगातार हो रहे हैं एक अनपेक्षित विकास है, पूर्णतया निराधार एवं अतर्किक है।
- (ण) केवल उन तीन देशों अर्थात् वियतनाम, ताईवान और ब्राजील के कारण, जिन्होंने भारत में आयातों में वृद्धि कारित की है, मलेशिया, चीन, इंडोनेशिया, कोरिया, जर्मनी, फिनलैंड, वियतनाम और ताईवान में आधारित उत्पादकों पर व्यापार उपचारी उपाय अधिरोपित करना केवल काल्पनिक है और यह सही नहीं है।

**याचिकाकर्ता द्वारा गोपनीयता का दुरुपयोग**

- (त) याचिकाकर्ता माननीय महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा 6 सितम्बर 1997 को जारी व्यापार नोटिस संख्या एसजी/टीएन/1/97-के अनुबंध के रूप में प्रश्नावली में यथापेक्षित आंकड़ों का पर्याप्त प्रकटन प्रदान करने में असफल रहा।
- (थ) याचिकाकर्ता की लागत निर्धारण सूचना को गोपनीय के रूप में चिन्हित किया गया है और उसकों तो कम से कम अनुक्रमित कर दिया जाना चाहिए।
- (द) याचिकाकर्ताओं तथा अन्य घरेलू उत्पादकों की अलग-अलग वास्तविक उत्पादन मात्रा प्रदान नहीं की गई है।
- (ध) चीन के सीमाशुल्क से आयात आंकड़े का विवरण प्रदान नहीं कराया गया है।
- (न) हीन्ज एच. पारिसेर वीक्ली फैक्स सर्विस से प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों की सूचना चीन की मांग, आपूर्ति, निर्यात और आयात के संबंध में प्रदान नहीं कराई गई है।
- (त) चीन, जापान, कोरिया और ईयू के सीआरयू आंकड़े प्रदान नहीं कराए गए हैं।
- (प) याचिकाकर्ता के लिए संपूर्ण समायोजन योजना प्रदान नहीं कराई गई है और उसने बिना किसी कारण के इस सूचना को गोपनीय रखने की मांग की है।

**संवर्धित आयात**

- (फ) 12 माह की वास्तविक अवधि के बजाय केवल 3 माह (अप्रैल 14 से जून 14) के आंकड़ों के आधार पर संपूर्ण वर्ष (2014-15) के लिए विश्लेषण किया गया जिससे ऐसा लगता है कि "संवर्धित आयातों" की जांच प्रत्याशित अवधि के आधार पर की गई है, न कि अभिनव विगत की अवधि के आधार पर।

**क्षति का अभाव**

- (ब) याचिकाकर्ता अपनी क्षति के दावे के संबंध में आवश्यक पैरामीटरों अर्थात् उत्पादन, बाजार हिस्सा और मांग, याचिकाकर्ता की बिक्री, उत्पादकता, क्षमता एवं क्षमता उपयोग, मालसूची, कीमत प्रभाव, लाभप्रदता और गंभीर क्षति की चुनौती के आधार पर पर्याप्त साक्ष्य प्रदान कराने में असफल रहा है।

**क्षति कारित करने वाले अन्य कारकों तथा कारणात्मक संबंधों का भंग होना**

- (भ) रक्षोपाय नियमावली के नियम 11(1)(ख) में प्रावधान है कि संवर्धित आयातों और गंभीर क्षति या गंभीर क्षति चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद हो।
- (म) आयातों में कथित वृद्धि ने याचिकाकर्ता के प्रचालनों पर विपरीत प्रभाव नहीं डाला है, वास्तव में याचिकाकर्ता के उत्पादन, घरेलू बिक्रियों और बाजार हिस्से में भारत में मांग की अनुरूपता में वृद्धि हुई है।
- (कक) याचिकाकर्ता पर कई अन्य कारकों का विपरीत प्रभाव पड़ा है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, परिवर्तनशील मुद्रा, क्षमता उपयोग को प्रभावित करने वाले प्रचालनात्मक मुद्दे शामिल हैं और कथित गंभीर क्षति के लिए केवल संबद्ध वस्तु के आयातों को ही उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता है।

**जनहित**

- (खख) इस विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जनहित के विपरीत होगा क्योंकि विभिन्न अनुप्रवाही उद्योग जैसे आटोमेटिव उद्योगों पर निम्नलिखित विपरीत प्रभाव पड़ेगे।
- (क) केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अंतर्गत मोटर वाहन के लिए निर्धारित सांविधिक उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के उद्देश्य से आटो उद्योग को उच्च गुणवत्ता वाली, फटींग अवरोधक स्टेनलेस स्टील उत्पादों का आयात करना होता है।
- (ख) यदि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण कर दिया जाता है तो आटो उद्योग को या तो उच्चतर कीमतों का भुगतान करना होगा या पुनः एक्स्त्रास्ट प्रणाली का आयात करना होगा जिससे भारत में बेरोजगारी बढ़ेगी।

**छ. मैसर्स मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतिकरण :  
प्रकार्यात्मक मुद्दे**

- (क) प्राधिकारी ने द्विपक्षीय रक्षोपाय के संबंध में जापान गणराज्य और भारत सरकार के बीच हुए एफटीए के प्रावधानों और उसमें उल्लिखित विशेष शर्तों एवं प्रक्रियाओं की पूरी तरह से अनदेखी की है। इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना दोनों राष्ट्रों के संबंधों के लिए भी घातक होगा।
- (ख) गाट 1994 के अनुच्छेद XIX का अनुपालन नहीं किया गया है।

**याचिका की उपयुक्तता एवं यथार्थता**

- (ग) आवेदक द्वारा प्रदान कराए गए आयात आंकड़ों की यथार्थता पर संदेह है। आवेदक ने इस विचाराधीन उत्पाद का निर्धारण करने के लिए कोई क्रियापद्धति नहीं बताई है जिससे आंकड़ों की प्रामाणिकता पर गंभीर शंका उत्पन्न हो रही है।
- (घ) इस विचाराधीन उत्पाद के आयात आंकड़े प्राप्त करने और प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुतिकरण करने की समय-सीमा के बीच समयान्तराल कम होने के कारण प्रतिवादी को तथाकथित आयात आंकड़ों का विश्लेषण करने और उन्हें स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने में दिक्कत हुई।

**विचाराधीन उत्पाद और उसका दायरा**

- (ङ) आवेदक द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद और आयातित उत्पाद के बीच मौलिक और पर्याप्त अंतर है। प्रतिवादी द्वारा निर्मित पीयूसी आवेदक द्वारा निर्मित विचाराधीन उत्पाद से बेहतर गुणवत्ता का है। प्रतिवादी इस उत्पाद का उत्पादन अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके और उपभोक्ताओं की अनूठी विशिष्टताओं के अनुसार करता है जिसका घरेलू उद्योग विनिर्माण करने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा प्रतिवादी की आयातित पीयूसी ज्यादातर मोटर वाहन निकास प्रणाली में प्रयोग की जाती है। इस क्षेत्र की आवश्यकताओं और विनिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाता है। इस कारण आवेदक और प्रतिवादी के पीयूसी के विशिष्ट गुणवत्ता में इस अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

**आधार**

- (च) आवेदक भारतमें पीयूसी का प्रमुख निर्माता होने का दावा करता है और यह कि कुल भारतीय उत्पादन में उसका हिस्सा 85 प्रतिशत से बढ़कर 88 प्रतिशत हो गया है। इस कारण इस तरह के उच्च बाजार हिस्सेदारी के साथ बाजार एक अग्रणी कंपनी आयात से प्रभावित होने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।

**संवर्धित आयात**

- (छ) आयात में वृद्धि मामूली है। वर्ष 2014-15 के लिए विचारित आयात आंकड़े केवल तीन महीने के हैं। इन आंकड़ों का वार्षिकीकरण करने के लिए आवेदक द्वारा कारण नहीं प्रदान कराया गया है। इसका अलावा, आयात के संबंध में आवेदक द्वारा बाद में की गई प्रस्तुतियां इस जांच शुरुआत के औचित्य को न्यायोचित नहीं ठहराती है।
- (ज) आयातों के यह वृद्धि इतनी अधिक या अचानक नहीं हुई है कि उससे घरेलू उद्योग को अचानक विकृति हो जाए। यह वृद्धि क्रमिक है और इसलिए घरेलू उद्योग को क्षति और संवर्धित आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

**गंभीर क्षति**

- (झ) गंभीर क्षति का कोई साक्ष्य नहीं है। कतिपय सूचना पर भरोसा करना और उसका प्रकटन करना तथा अन्य चुनिंदा सूचना का छिपाना यह जांच शुरू कराने के लिए आवेदक द्वारा जानबूझकर किया गया प्रयास है।

**क्षति के अन्य कारण**

- (ञ) यह महत्वपूर्ण है कि क्षति के अन्य कारक आयातों से संबंधित नहीं होने चाहिए। इस कारण उपलब्ध सूचना मात्रा प्रभाव, क्षमता, विक्री आदि में कोई क्षति प्रदर्शित नहीं करती है।
- (ट) अभी हाल ही में, आवेदक ने संवर्धित विद्युत व्यय के कारण अधिक अनपेक्षित व्यय देखा है। यह घरेलू उद्योग को क्षति का एक कारण हो सकता है।
- (ठ) याचिका में दुर्भावनावाश इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि आवेदक का ओडिशा संयंत्र पर्यावरण संबंधी मानकों का पालन न करने के कारण बंद कर दिया गया था।

**कारणात्मक संबंध**

- (ड) आवेदक ने यह याचिका बिना किसी वास्तविक सबूत के दायर की है और इस याचिका में प्रथमदृष्ट्या कोई साक्ष्य नहीं है।
- (ढ) कीमत अधोरदन का निर्धारण करने के लिए आवेदक ने आयातों के उतराई मूल्य को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया है। इसके संबंध में यह भी उल्लेख किया जाता है कि केवल तीन माह के आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
- (ण) कीमत अधोविक्रयण, अवमंदन और निग्रहण का उल्लेख अगोपनीय रूपांतर में अनुक्रमित फार्म में नहीं किया गया है।

**अनपेक्षित विकास**

- (त) याचिका में उस अनपेक्षित विकास का उल्लेख नहीं किया गया है जिनसे संवर्धित आयातों को योगदान मिला। इसके अतिरिक्त, जापान से आयातों के लिए आयात शुल्क विगत कुछ वर्षों में कम हो जाना चाहिए जैसा कि आवेदक द्वारा अपनी याचिका में माना गया है।
- (थ) घरेलू उद्योग ने अपने प्रस्तुतिकरणों में भारतीय संदर्भ में "अनपेक्षित विकास" की संकल्पना की मौजूदगी की मनाही की है। तथापि, भारत रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार और गाट का हस्ताक्षरकर्ता देश है, इसलिए इस पैरामीटर की मौजूदगी को सीधे-सीधे नकारा नहीं जा सकता है।

**समायोजन योजना**

- (द) प्रदान की गई समायोजन योजना अधूरी है और आवेदक ने अधिकांश सूचना को गोपनीय रखने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने आवेदन प्रपत्र में कई महत्वपूर्ण गोपनीय प्रश्नों का उत्तर देना मना कर दिया जैसे संवेदनशील परिस्थितियों की मौजूदगी के बारे में विस्तृत सूचना और यह कि इस विलंब से इतनी क्षति कैसे हुई जिसकी भरपाई करना असंभव हो गया।

**विविध मुद्दे**

- (ध) आवेदक ने भारी गोपनीय का आश्रय लिया है। आवेदक ने महत्वपूर्ण पैरामीटरों जैसे कीमत अधोविक्रयण रेंज, प्रमुख कच्चे माल की सूची, किया गया निवेश, निवल मूल्य, अवक्षयण, व्यय, व्याज व्यय आदि के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है। घरेलू उत्पादकों के लिए विनिर्धारित प्रश्नावली थी, जिसमें विस्तृत समायोजन योजना का उल्लेख किया गया हो उपलब्ध नहीं कराई गई है। याचिका में भी, आवेदक को अनुचित आधार पर गोपनीयता प्रदान की गई है। आवेदक द्वारा इस आशय का कोई कारण नहीं बताया गया है कि इस सूचना को गोपनीय के रूप में क्यों माना जाना चाहिए।

- (न) आवेदक ने क्षति मार्जिन के अनुरूप रक्षोपाय शुल्क का अनुरोध किया है। तथापि, रक्षोपाय जांच में कोई क्षति मार्जिन नहीं है। अतः, रक्षोपाय शुल्क का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई क्रियापद्धति का प्राधिकारी द्वारा स्पष्टता के लिए प्रकटन किया जाना चाहिए।
- (त) इस विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के लिए पहले को ही विचार चल रहा है। रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना भारत में उपभोक्ताओं पर बोझ डालने जैसा होगा। आटोमोबाइल उद्योग को भी नुकसान होगा क्योंकि आयातों और स्कैपिंग पर केंद्रीय सरकार द्वारा उद्योग के हित में पाटनरोधी शुल्क का उदग्रहण किया जा रहा है।
- (प) भारत को डब्ल्यूटी करारों और उनके प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए।
- (फ) घरेलू उद्योग "विधिक प्रत्याशा" के सिद्धांत का आश्रय ले रहा है। तथापि, यह घरेलू उद्योग को अकेले-अकेले ही संभव नहीं है। सरकार ने घरेलू उद्योग से कोई बाधा नहीं किया है और अनुच्छेद 14 एवं 21 के अंतर्गत अधिकार आवेदक पर लागू ही नहीं होते हैं।
- (ब) आवेदक ने प्रतिवादी पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए थाईलैंड जैसे अन्य देशों पर भरोसा किया है। तथापि, इन नामित कंपनियों ने इतनी अधिक वास्तविक से काम नहीं किया है।

4. निम्नलिखित हितवद्ध पक्षकारों ने अन्य हितवद्ध पक्षकारों के लिखित प्रस्तुतिकरणों पर अपनी प्रत्युक्तियां प्रस्तुत की है।

मैसर्स जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (घरेलू उद्योग)
मैसर्स निप्पन स्टील और सुमिकिन स्टेनलेस स्टील कारपोरेशन
मैसर्स निशिन स्टील कंपनी लिमिटेड
मैसर्स जेएफई स्टील कारपोरेशन
मैसर्स आटोकम्पु स्टेनलेस ओयज, फिनलैंड
मैसर्स पोस्को कोरिया
मैसर्स बाहूरू स्टेनलेस स्टील, मलेशिया
मैसर्स मेटल न इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और स्टेनलेस स्टील मर्चेन्ट्स एसोसिएशन
मैसर्स मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड

5. अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए लिखित प्रस्तुतिकरणों पर उपर्युक्त हितवद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित प्रत्युक्तियां की गई है :

क. **मैसर्स टीएफएम कंसल्टेंट द्वारा मैसर्स जिंदल स्टेनलेस की ओर से दायर प्रत्युत्तर संक्षेप में निम्नलिखित है :**

- (क) याचिकाकर्ता ने किसी दावे को नहीं छिपाया है। प्रश्नावली प्रत्युत्तर अक्टूबर में दायर किया गया जबकि अस्थायी बंदी नवम्बर के महीने में हुई थी। याचिकाकर्ता ओडिशा के उत्पादन को रोकने के लिए संक्षेप में बलात किया गया क्योंकि वह ओडिशा सरकार द्वारा दिए गए समय-सीमा के भीतर कतिपय प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को संस्थापित कराने में अक्षम रहे थे। इसके परिणामस्वरूप, यह याचिकाकर्ता इस उत्पाद का उत्पादन अस्थायी रूप से 16 नवम्बर, 2014 से 20 दिसम्बर, 2014 तक की अवधि के दौरान उत्पादन नहीं कर सका और तत्पश्चात इसके उत्पादन में व्यवधान हुआ।
- (ख) याचिकाकर्ता ने इसके साथ माह दिसम्बर, 2014 के लिए उत्पादन रिकार्ड (ईआर) संलग्न किया है जो स्पष्टतः यह दर्शाता है कि इस संयंत्र ने थोड़े दिन की बंदी के पश्चात पुनः उत्पादन शुरू किया।
- (ग) याचिकाकर्ता सौदावार आयात आंकड़े प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। टी/टी आंकड़े सूचना की यथार्थता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के प्रयोजनार्थ महानिदेशक (रक्षोपाय) के लिए ही संगत होते हैं और वह महानिदेशक (रक्षोपाय) को प्रदान कर दिए गए हैं। ऐसा होते हुए भी, महानिदेशक (रक्षोपाय) की मांग पर याचिकाकर्ता ने समस्त टी/टी आंकड़े महानिदेशक (रक्षोपाय) को प्रदान करा दिए हैं और वह आंकड़े विरोधकर्ता हितवद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। आयातों का विश्लेषण करने और एक तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए महानिदेशक रक्षोपाय को सभी संगत सूचना प्रदान करा दी गई है।
- (घ) याचिकाकर्ता ने इससे पहले दायर एक लिखित प्रस्तुतिकरणों में सितम्बर, 2014 तक की अवधि के लिए संपूर्ण सूचना प्रदान करा दी है। इसके अतिरिक्त, दिसम्बर, 2014 तक की अवधि के लिए आयात एवं मात्रा से संबंधित सभी पैरामीटर दे दिए गए हैं। इसके लिए सुनवाई के लिए हितवद्ध पक्षकारों ने विशेष रूप से अनुरोध किया था। इसके लिए महानिदेशक का याचिकाकर्ता को विशेष निदेश दिया गया था।
- (ङ) पाटनरोधी जांच के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद का दायर वर्तमान जांच के उत्पाद के दायरे से अलग है। अधिकांश आयात वाइड उत्पाद हैं, जो इस पाटनरोधी जांच में विचार किए गए विचाराधीन उत्पाद के दायरे से परे हैं। इसके अतिरिक्त, जापान से होने वाले आयातों पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगा है और संकरी चौड़ाई के उत्पादों (सीआर <400 एमएम) पर उस बेंचमार्क के आधार पर, जहां से यह आयात बेंचमार्क कीमतों से अधिक कीमत पर हो रहे हैं, पाटनरोधी शुल्क आकृष्ट कर रहे हैं।
- (च) याचिकाकर्ता ने कभी यह प्रस्तुतिकरण नहीं किया कि महानिदेशक (रक्षोपाय) आयातों में उद्रेक की मौजूदगी के संबंध में निष्कर्ष निकालने के लिए तीन माह की अवधि पर विचार करें। याचिकाकर्ता ने दिसम्बर, 2014 तक की अवधि के लिए सूचना पहले ही प्रदान कर रखी है और महानिदेशक (रक्षोपाय) कृपया आयातों में उद्रेक का निर्धारण अप्रैल-दिसम्बर, 2014 तक की अवधि में ध्यान में रखकर कर सकते हैं।

- (छ) महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, यह एक दीर्घ आह्वित प्रक्रिया अपेक्षित होती है। इस प्रकार, जांच शुरूआत के स्तर पर महानिदेशक ने रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की जरूरत के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है।
- (ज) याचिकाकर्ता ने इस विचाराधीन उत्पाद का पृथक्करण करने के लिए इसके उत्पाद विवरण पर भरोसा किया है। संक्षेप में, इस कारण की वजह से ही याचिकाकर्ता ने उन प्रविष्टियों का चयन किया जहां प्लेट/शीट/स्ट्रिप 7219 और 7220 शीर्ष के अंतर्गत आ रही थी। प्रतिवादियों ने जिस वस्तु की अनदेखी करने का चयन किया वह क्रियापद्धति का वह हिस्सा है जहां याचिकाकर्ता ने यह उल्लेख किया है कि ग्रेड अभिज्ञान भी कर दिया गया था। इसका आशय यह है कि उन मामलों में भी जहां शब्द स्टेनलेस स्टील उत्पाद के विवरण से विलग था, वहां याचिकाकर्ता ने केवल उसी प्रविष्टि को स्वीकार किया जहां 400 सीरीज स्टेनलेस स्टील ग्रेड लिखा हुआ था।
- (झ) अन्य ग्रेडों में अंतर्गस्त मात्रा, जैसे 300 सीरीज (304 एल), जिसका प्रयोग आटोमोटिव सेक्टर में नगण्य रूप से किया जाता है, और उसका विश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (ञ) ग्रेड एमएच-1 फेरिटिक ग्रेड है, जिसका सुनिश्चयन के इंटरनेट पर एक आसान सी खोज के जरिए खोजा जा सकता है। हितवद्ध पक्षकार महानिदेशक को भ्रमित करके इस जांच में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, एक हितवद्ध पक्षकार, मैसर्स मारुति ने स्वयं यह दावा किया है कि वे विचाराधीन उत्पाद का एमएच-1 का आयात जापान की कंपनियों से कर रहे हैं।
- (ट) यह वह मामला नहीं हो सकता है कि वर्ष 2013-14 तक के लिए आयातों की मात्रा पर विचार याचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरणों से किया जा रहा है और हितवद्ध पक्षकारों के निष्कर्ष को उन पर अध्यारोपित किया जा रहा है।
- (ठ) याचिकाकर्ता यह समझने में असफल रहता है कि जब इस उत्पाद का विक्रेता उपभोक्ता द्वारा अपेक्षित चौड़ाई के उत्पाद की आपूर्ति कर सकता है तो इस उत्पाद की अधिक चौड़ाई में आयात क्यों किया जाना चाहिए और फिर उस पर अतिरिक्त लागत उपगत की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित और बिक्री की जाने वाली वस्तु कुछ स्टैंड अलोन स्लिट्स द्वारा स्लिट किया जाना अपेक्षित नहीं है, और न ही वे इतनी जटिल बाजार स्थितियों में एकल पैरामीटर हो सकते हैं जिससे आयातों में वृद्धि हुई हो।
- (ड) यह सुस्थापित विधिक स्थिति है कि कई ऐसे कारक हो सकते हैं जिनके सामूहिक प्रभाव के कारण आयातों में वृद्धि हुई हो। भारत सरकार यह आवश्यक है कि एक एकल पैरामीटर, जिसके कारण आयातों में वृद्धि हुई है, को ही अभिज्ञात किया जाए न कि इस तथ्य पर इस जटिल बाजार स्थिति में किसी एक एकल पैरामीटर पर जिसके संयुक्त प्रभाव के कारण आयातों में वृद्धि हुई है।
- (ढ) भारत सरकार द्वारा डब्ल्यूटीआई के समक्ष उपगत दायित्व के परिणामस्वरूप सीमाशुल्क में प्रपाती कमी करना संबंधित आयातों के लिए शुरूआती बिंदु हो सकता है। भारत सरकार ने इस उत्पाद पर सीमाशुल्क जो लगभग दो दशक पहले 85 प्रतिशत था घटाकर चालू अवधि में 7.5 प्रतिशत कर दिया है। इन आयातों की वृद्धि का यह शुरूआती बिंदु हो सकता है।
- (ण) वैश्विक उत्पादों के साथ बेशी क्षमता अंतर्गस्त उत्पादन प्रक्रिया के मद्देनजर उत्पादन को इष्टतम बनाने के प्रयासों की वैश्विक उत्पादकों की विवश, इन विदेशी उत्पादों के लिए घरेलू और अन्य बाजारों में घटते बाजार अवसरों भारत में इस उत्पाद की बढ़ती मांग ने सामूहिक रूप से और संचयी रूप से बड़े बाजार अवसरों के रूप में भारतीय बाजार की तलाश की।
- (त) इन करारों में स्वयं यह परिकल्पना की गई है कि इन एफटीए के परिणामस्वरूप आयातों में वृद्धि हो सकती है और हालात से रक्षोपाय शुल्क लगाने की मांग भी हो सकती है। इससे स्वयं ही यह सिद्ध होता है कि इन करारों पर हस्ताक्षर करते समय इसकी पूर्वापेक्षा नहीं की गई थी कि इन करारों के परिणामस्वरूप आयातों में वृद्धि होगी और उससे घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होगी।
- (थ) यह याचिकाकर्ता का मामला है कि एफटीए एक अनपेक्षित विकास है। डब्ल्यूटीओ दायित्वों के अंतर्गत भारत द्वारा सीमाशुल्क में कमी करना तथा एफटीए के अंतर्गत दी गई रियायतें अनपेक्षित विकास है। यदि सरकार ने डब्ल्यूटीओ दायित्वों के अंतर्गत सीमाशुल्क में कमी नहीं की होती तो एफटीए के अंतर्गत दी गई प्रशुल्क रियायतों से घरेलू उद्योग को क्षति कारित नहीं हुई होती। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि यदि डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत प्रशुल्क को वार्ताओं से पहले के स्तर पर पुनर्बहाल कर दिया जाता है तो एफटीए देशों पर प्रभावी सीमाशुल्क एफटीए रियायतों क बावजूद भी घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त होता।
- (द) प्रमुख निर्यातक राष्ट्र चीन और कोरिया पर वर्ष 2013 से पाटनरोधी शुल्क लगा है। चीन जनवादी गणराज्य और ताइवान के मूल के स्टेनलेस स्टील कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के एक मामले में ईयू द्वारा दिसम्बर, 2014 में जारी एक अधिसूचना इन देशों से आयात करना पंजीकरण के अध्यधीन कर दिया गया, इसमें संबंधित उत्पादों पर शुल्क के निर्धारण के तथ्य की पहचान की गई।
- (ध) इस विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षमता का निर्धारण वर्ष 2011-12 में हुए उत्पादन के आधार पर किया है। कंपनी द्वारा उत्पादन का यह स्तर प्रदान कर लिए जाने पर इस उत्पाद के लिए क्षमता के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है, जो क्षमता उपयोग में गिरावट प्रदर्शित करता है।
- (न) जहां तक विद्युत, अवक्षयण और ब्याज लागत के प्रति यूनिट परिकलन का संबंध है, प्रतिवादी ने वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित कुल आकलनों को घरेलू उद्योग से विभाजित किया है। यह विधि उस तर्क का विरोध करती है कि प्रतिवादी ने कंपनी के लिए आंकड़ों को समग्र रूप से लिया है और इस केवल पीयूसी पर लोड किया है। इस विचाराधीन उत्पाद के लिए ओडिशा में प्रति यूनिट विद्युत और ईंधन खपत इसके प्रचालन के शुरू से कम हो गई है और फिर भी घाटा अधिक हो गया है।

- (त) सीमाशुल्क का निर्धारण करने के लिए सीआईएफ आयात कीमत में 1 प्रतिशत जोड़ा जाता है। यह 1 प्रतिशत किसी पक्षकार को देय नहीं है। ऐसा मामला होने पर इस प्रस्तुतिकरण का कोई आधार नहीं है कि आयातों के उतराई मूल्य का निर्धारण करने के लिए सीआईएफ मूल्य में 1 प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए।
- (प) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और उत्पादन लागत दोनों में वृद्धि हुई है। तथापि, बिक्री कीमत में यह वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि की तुलना में कम थी। यद्यपि इस अवधि में उत्पादन लागत में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं इसकी बिक्री कीमत में 5 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई।
- (फ) इस उद्योग को जांच अवधि की शुरुआत में भी क्षति उपगत हुई थी क्योंकि पाटित आयात क्षति कारित कर रहे थे जिसके परिणामस्वरूप पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया गया था। इसके अतिरिक्त, इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि आयात वर्ष 2011-12 में "न्यून" था।
- (ब) रुपया, जिसका स्तर वर्ष 2012-13 में 55/-रुपए था, के स्तर से घटकर वर्ष 2013-14 में 61-62/-रुपया हो गया। तथापि, भारतीय रुपए में 10 प्रतिशत से अधिक अवमूल्यन होने के बावजूद उतराई कीमत में वर्ष 2013-14 में मामूली सी ही वृद्धि हुई और तत्पश्चात उसमें वर्ष 2014-15 में वास्तव में कुछ गिरावट आई। इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता की कीमतों में भारी निग्रहण हुआ क्योंकि इस अवधि में लागत में बढ़ोतरी हुई जबकि विधिक कीमत वृद्धि नहीं हुई।
- (भ) यद्यपि यह स्वीकार किया जाता है और सराहा जाता है कि चरणबद्ध रूप से कटौती व्यापक रूप से तभी ज्ञात हुई जब एफटीए को सार्वजनिक किया गया, परंतु उस समय यह ज्ञात नहीं था कि एफटीए में की गई इन घटौतियों से घरेलू उद्योग को क्षति कारित होगी। हितबद्ध पक्षकारों को तर्क का आशय यह प्रतीत होता है कि भारत सरकार को इन मुक्त व्यापार करारों पर हस्ताक्षर करते समय इस तथ्य की पूरी जानकारी थी कि इन रियायतों से घरेलू उद्योग को सैकड़ों/हजारों उत्पादों में क्षति होगी।
- (म) याचिकाकर्ता ने हितबद्ध पक्षकारों को समायोजन योजना का अगोपनीय पाठ प्रदान किया जिसमें किए जाने के लिए प्रस्तावित पहलों की रूपरेखा बताई गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विशिष्ट विवरणों को अन्य पक्षकारों के साथ शेयर नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह याचिकाकर्ता के हित के विपरीत होगा।
- कक. नियमावली के संगत प्रावधानों से यह व्यक्त होगा कि समायोजन योजना का उल्लेख किसी साधन का अधिरोपण करने के संदर्भ में किया गया है। यह समायोजन योजना रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के प्रश्न से संबंधित नहीं है।
- खख. यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता के कीमत पैरामीटरों का प्रकटन किया जाए जबकि हितबद्ध पक्षकारों के मात्रा पैरामीटरों का भी गोपनीय के रूप में दावा किया जा रहा है।
- गग. एक ओर तो पक्षकार अधोविक्रयण की रेंज पृच्छ रहा हैं, जो रक्षोपाय नियमावली के अंतर्गत मान्य संकल्पना नहीं है, और उसी अवधि में वह क्षति मार्जिन की संकल्पना की अनदेखी कर रहा है। याचिकाकर्ता ने क्षति का दावा किया है और निदेशालय की पिछली प्रक्रियाओं पर विचार करते हुए उसे परिमणित किया है।
- घघ. सूचीबद्ध पक्षकार ही केवल वे पक्षकार नहीं हैं जिनको मेटल वन कार्प की आपूर्ति की गई। मेटल वन कार्प की आपूर्ति कई आटोमोबाइल कंपनियों को की गई है। याचिकाकर्ता ने भी इसकी बिक्री कई आटोमोबाइल कंपनियों को की है। यह एक अन्य उदाहरण है जिसमें हितबद्ध पक्षकारों ने भ्रामक और यहां तक कि झूठ अभिकथन भी किए हैं।
- ङङ. घरेलू उद्योग ने तकनीकी क्षमताओं के आधार पर माल की आपूर्ति करने से कभी खेद व्यक्त नहीं किया है। याचिकाकर्ता किसी माल की आपूर्ति तभी कर सकता है जब उपभोक्ता उस वस्तु के लिए आर्डर प्लेस करता है। तथापि, समान अनुप्रयोग के लिए ही याचिकाकर्ता ने देश में अन्य उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की आपूर्ति की है। रक्षोपाय विधि के अंतर्गत ऐसी कोई विधिक अपेक्षा नहीं है कि याचिकाकर्ता देश में इस उत्पाद के सभी उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करें।
- चच. यह याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण नहीं है कि संवर्धित आयातों के संबंध में निष्कर्ष 3 माह के आयातों के आधार पर कर लिया जाए। याचिकाकर्ता द्वारा प्रक्षेपित की गई प्रवृत्ति सही थी और वास्तव में तो आयातों में अधिक वृद्धि हुई थी।
- छछ. याचिकाकर्ता ने आयातों के मात्रा का निर्धारण इन सभी प्राविधिकताओं पर विचार करते के पश्चात ही किया है। वास्तव में, याचिकाकर्ता ने केवल उन्हीं आयात प्रविष्टियों पर विचार किया है जिनमें मापन की इकाई या तो किलोग्राम में थी या एमटी में। स्टील उद्योग में अधिकांश कारोबार भार आधार पर होता है, चाहे उपभोक्ता को उस उत्पाद की आवश्यकता भार के बजाय किसी अन्य यूनिट के आधार पर ही क्यों न हो। जहां तक इस विचाराधीन उत्पाद का भाग न बनने वाले उत्पाद का संबंध है, चूंकि याचिकाकर्ता ने उन प्रविष्टियों को किसी भी रूप में शामिल नहीं किया है, इसलिए इन प्रविष्टियों ने इस विश्लेषण को विकृत नहीं किया है।
- जज. हितबद्ध पक्षकारों ने बड़ी चालाकी से उस जांच का उल्लेख किया है जिस पर वर्ष 2009 में निष्कर्ष निकाला गया था और तत्पश्चात, यूरोपियन यूनियन, कोरिया आरपी और यूएसए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 600 एमएम से कम की चौड़ाई के 400 सीरीज के स्टेनलेस स्टील कोल्ड रोलड फ्लैट उत्पादों के आयातों से संबंधित की गई जांच की अनदेखी की है। जिसमें किसी भी प्रकार के अपवर्जन का प्रावधान नहीं किया गया था।
- झझ. अप्रतिस्थापनीयता संबंधी दावों को याचिकाकर्ता के साथ शेयर नहीं किया गया है। यह सकल रूप से अनुपयुक्त है और इससे रक्षोपाय नियमावली के नियम 7 का उल्लंघन होता है। हितबद्ध पक्षकारों को यह सिद्ध करना चाहिए कि प्रक्रिया में अंतर किस तरह आयातित उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद से भिन्न है। यह सूचना याचिकाकर्ता को विश्लेषण हेतु प्रदान कराई जानी चाहिए।

- जज. संवर्धित आयातों को किसी एक कंपनी या देश के संबंध में नहीं देखा जाना चाहिए। संवर्धित आयातों को सामूहिक रूप से सभी स्रोतों से देखना अपेक्षित है। रक्षोपाय और पाटनरोधी जांच में यह मौलिक अंतर होता है। इसके अतिरिक्त, अनपेक्षित विकास को भी अलग-अलग देशों के साथ अभिज्ञात करना अपेक्षित नहीं है।
- टट. जिन देशों के पास अतिरिक्त क्षमता है वे अपनी इन क्षमताओं का उपयोग अन्य देशों को निर्यात करके कर रहे हैं अथवा वे विगत में भारतीय बाजार में अपनी पैठ बनाने में सक्षम नहीं रहे। अब, यह कि, जब घरेलू उत्पादकों ने अपनी क्षमताओं में भारी विस्तार कर लिया है तब यह उत्पादक संवर्धित ढंग से भारतीय बाजारों की तलाश कर रहे हैं, यह तथ्य स्पष्टतः अनपेक्षित विकास है। इसके अतिरिक्त, इस अवधि में इस विचाराधीन उत्पाद की मांग में यूरोप में गिरावट आई, जो स्पष्ट रूप से एक अनपेक्षित विकास है।
- ठठ. चीन में विद्युत और कोकिंग कोल की कम लागत पर उपलब्धता चीन में काफी समय से विद्यमान थी। तथापि, चीन ने इन लागत लाभों का पूंजीकरण दक्षिण अफ्रीका में विद्युत संकट जारी हरने के कारण कर दिया जो स्पष्टतः एक अनपेक्षित विकास है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका क्रोमाइट अयस्क का सबसे बड़ा विनिर्माता है, दक्षिण अफ्रीका में विद्युत संकट है और इसलिए यह क्रोमाइट अयस्क को फेरोक्रोम, जो संबद्ध उत्पाद के सबसे महत्वपूर्ण कच्चे माल में से एक है, में संपरिवर्तित करने में सक्षम नहीं है; चीन क्रोमाइट अयस्क को दक्षिण अफ्रीका से आयात करता है; दक्षिण अफ्रीका ने कुछ बड़ी विद्युत परियोजनाओं की घोषणा की है जिनकी 2013 तक लाइन पर आने की प्रत्याशा है और उनसे विद्युत में कमी दूर होगी। तथापि, संलग्न साक्ष्य यह दर्शाएगा कि अभी कोई परियोजना शुरू भी नहीं हुई है। यह तथ्य अप्रत्याशित था जिससे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जहां चीन अपने लागत लाभ का पूंजीकरण करता रहा।
- डड. इस विचाराधीन उत्पाद की कोरिया में मांग ने भारी वृद्धि प्रदर्शित नहीं की है और यह कोरियाई उत्पादकों के पास उपलब्ध क्षमताओं का अवशोषण करने में सक्षम नहीं था। इसलिए कोरियाई उत्पादकों को अपने उत्पाद का निर्यात करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तलाश करनी पड़ी।
- ढढ. हितबद्ध पक्षकारों ने एक ओर तो यह तर्क दिया है कि एफटीए के अंतर्गत प्रशुल्क रियायतें अच्छी तरह से ज्ञात थी और इसके साथ ही, उसने यह तर्क भी दिया है कि सीमा शुल्क में कमी इतनी कम की गई कि उससे आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई। साथ ही, कई हितबद्ध पक्षकारों ने तो वास्तव में यह स्वीकार किया है कि आयातों में यह वृद्धि प्रशुल्क रियायतों के कारण आई है।
- णण. इसके अतिरिक्त, आयातों में वर्ष 2014-15 के दौरान भारी वृद्धि हुई। इसलिए वर्ष 2013-14 में शुल्कों का अधिरोपण करना एक महत्वपूर्ण विकास है जो आयातों में वृद्धि का कारण दर्शाने हेतु संगत है। शुल्क का अधिरोपण करने के पश्चात, देश की बाजार को कार्रवाई करने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह उचित ही माना जा सकता है कि अंतर्ग्रस्त संबद्ध देश द्वारा आयात इन देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जिनका अब भारत की ओर विपथन किया जा रहा है।
- तत. याचिकाकर्ता ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि चुनौतियां होने के बावजूद, उनके उत्पादन में इन चुनौतियों के कारण कमी नहीं आने दी गई। इसने कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया कि उत्पादन में कमी क्रोमाइट अयस्क प्राप्त होने में दिक्कत के कारण आई थी। इसके अतिरिक्त, यद्यपि यह संयंत्र वर्ष 2011-12 और 2012-13 में रैम्प-अप के अधीन था, तथापि यह वर्ष 2013-14 और 2014-15 में पूर्ण रूप से प्रचालनात्मक था।
- थथ. आयातों में वर्ष 2012-13 में जब लाभ में कमी आ गई तो भारी वृद्धि हुई। इसी तरह, यह आयात वर्ष 2013-14 में भी समान क्षेत्र (भारी स्तर पर) में ही बने रहे। यद्यपि, कच्चे माल की लागत में भारी वृद्धि हुई फिर भी आयात कीमतों में केवल मामूली सी वृद्धि ही हुई। इस प्रकार, लाभ में भारी गिरावट आ गई। वर्ष 2013-14 में भारी आयात जारी रहने से घरेलू उद्योग को और अधिक कीमत क्षति हुई। इसके पश्चात आयातों में चालू वर्ष के दौरान और अधिक वृद्धि हुई जिससे घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में और गिरावट आ गई। अतः, आयातों और लाभप्रदता के बीच प्रत्यक्ष कारणात्मक संबंध है।
- दद. भारत में बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए क्षमता विस्तार करने की योजना 2003-04 में बनाई गई थी। इसके पश्चात, जब पाटित आयातों में वृद्धि हुई तो याचिकाकर्ता ने यह उम्मीद की कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से पाटित आयातों के आने में कमी होगी और इससे पाटनरोधी शुल्क के अंतर्गत आने वाले सेगमेंटों में घरेलू उद्योग की बिक्री और लाभप्रदता बढ़ेगी। तथापि, पाटनरोधी शुल्क से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए और वैश्विक स्थिति में भी परिवर्तन आ गया जिसके कारण आयातों में वृद्धि हुई।
- धध. यह तर्क कि परम्परागत रूप से इस्पात के व्यवसाय में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में तब वृद्धि होती है जब आयातक अपने माल के स्टॉक की निकासी को अंतिम रूप देते हैं। यह सही नहीं है क्योंकि अप्रैल-दिसम्बर, 2014 की अवधि को आयातों का तिमाहीवार विश्लेषण इसमें बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है।
- नन. संपूर्ण विश्व यह जानता है कि चीन अपनी इस्पात क्षमताओं में वृद्धि कर रहा है। यह तथ्य कि यह अनपेक्षित, चीन में इसकी मांग की तुलना में अधिक विस्तार होगा, और यह इसका दक्षिण अफ्रीका के समक्ष उपस्थित भारी विद्युत संकट के कारण लाभ उठाने में सक्षम होगा। चीन वर्ष 2009 तक निवल आयातक बना रहा था। क्षमताओं में अचानक विस्तार करना अनपेक्षित था।
- तत. पोस्को ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है। पोस्को के पास बेशी के अभाव का दावा बिना प्रश्नावली प्रत्युत्तर के स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पूर्वाग्रह के बिना, यह एक रक्षोपाय जांच है और इसलिए किसी एक कंपनी की स्थिति/आंकड़े पूर्णतया असार हैं।
- पप. मैक्सकन आयातों का हिस्सा कुल आयातों में लगभग 12 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, मैक्सिको का राजदूतावास कुल आयातों में अधिक हिस्सा दर्शाता है।

- फफ. जब एफटीए में स्वयं ही रक्षोपाय शुल्क का प्रावधान है, तो इसका आशय यह है कि राष्ट्रों द्वारा ऐसा करार किए जाते समय ऐसी स्थिति की प्रकल्पना को ध्यान में रखा जाता है। रक्षोपाय साधन एक अस्थायी उपाय है। शुल्क राष्ट्रों के बीच आपसी संबंध बिगाड़ने के लिए नहीं होते हैं।
- बब. इस तर्क का आशय यह है कि यदि कोई कंपनी बाजार की 95-100 प्रतिशत जरूरत को पूरा करती है तो एकमात्र उत्पादक है, तो उस पर आयातों का प्रभाव पड़ने की संभावना कम होती है। विधि में अथवा परम्परा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको ऐसी स्थिति कमे आशय के लिए अपनाया जा सकता हो।
- भभ. याचिकाकर्ता पुनः यह उल्लेख करती है कि भारतीय नियमावली के अंतर्गत अनपेक्षित विकास की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। वास्तव में तो यह केवल याचिकाकर्ता का ही विचार नहीं है। महानिदेशक ने अंतिम जांच परिणामों में बार-बार यह रिकार्ड किया है कि महानिदेशक द्वारा निर्धारण किए जाने के लिए अनपेक्षित विकास एक अपेक्षा नहीं है।
- मम. आटोमोबाइल उद्योग पर पड़ा प्रभाव नगण्य है। हितबद्ध पक्षकारों ने आटोमोबाइल उद्योग के इस कथित बोझ का परिणामन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता इस उत्पाद की आपूर्ति विभिन्न कंपनियों को नियमित रूप से कर रहा है और इसलिए प्रतिवादी को भी याचिकाकर्ता से आपूर्तियां प्राप्त करने का विकल्प है।
- ककक. यदि स्टेनलेस स्टील समग्र जरूरतों का एक छोटा सा भाग है तो रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण का हिन्दुस्तान सिरिन्जेज एंड मेडिकल डिवाइसेस पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा।

**ख. मैसर्स लक्ष्मीकुमारन एंड श्रीधरन द्वारा मैसर्स मेटल वन कारपोरेशन इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड, मैसर्स बहारू स्टेनलेस एसडीएन बीएचडी और मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मर्चेंट्स एसोसिएशन की ओर से दायर पुनरुत्तर का संक्षिप्त विवरण।**

- क. वह आयात सांख्यिकी जिस पर आवेदन ने भरोसा किया है आवेदन प्रति के साथ उपलब्ध नहीं कराई गई है। आवेदन के अगोपनीय पाठ की प्रति आवेदन के अगोपनीय पाठ की प्रतिकृति होनी चाहिए। यदि आवेदन के साथ ही सौदा-दर-सौदावार आयात सांख्यिकी को वास्तव में उपलब्ध करा दिया गया है तो उसे आवेदन के अगोपनीय पाठ के साथ भी प्रदान कराया जाना चाहिए।
- ख. आयात सांख्यिकी के बारे में कुछ भी गोपनीय नहीं है (जो आवेदक के देर से किए गए प्रकटन से भी स्पष्ट है)। चूंकि वह हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसलिए इस बात की तर्कसंगत आशंका है कि आयात सांख्यिकी उपलब्ध ही नहीं कराई गई है।
- ग. केवल आवेदक ही भारत में आयातों के उद्रेक का आरोप लगा रहा है। इसलिए आवेदक पर ही यह सिद्ध करने का दायित्व भी है कि वह आयातों में भारी उद्रेक की मौजूदगी को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य उपलब्ध कराए।
- घ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण करने पर, यह पाया गया कि आवेदक ने आयात सांख्यिकी का केवल पीडीएफ पाठ की उपलब्ध कराया था।
- ङ. प्रदान कराई गई आयात सांख्यिकी की परिशुद्धता की जांच करने के लिए पीडीएफ पाठ निरर्थक होता है। उससे, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि क्या सूचीबद्ध आयातों में संबद्ध उत्पाद के ही आयात है या उसमें कुछ अन्य उत्पादों का भी उल्लेख है।
- च. आवेदक द्वारा प्रदान कराई गई क्रियापद्धति में गंभीर समस्याएं हैं और इस क्रियापद्धति के आधार पर आयात सांख्यिकी के किए गए किसी भी पृथक्करण पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
- छ. प्रतिवादी ने आयात सांख्यिकी का पृथक्करण करने के लिए अपनी स्वयं की क्रियापद्धति पहले ही प्रदान करा दी हैं और 3 माह अप्रैल 14 से जून 14 तक की आयात सांख्यिकी स्वयं ही दर्शाती है कि आवेदन के आंकड़ों से तुलना करने पर आयात की मात्रा में भारी अंतर है।
- ज. निम्नलिखित कुछ ऐसे सौदे हैं जो यह नहीं दर्शाते हैं कि क्या उन्हें विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा के अंतर्गत कवर किया गया है या नहीं, परंतु उन्हें आयात सांख्यिकी में अवश्य शामिल किया गया है :
- (i) अध्याय शीर्ष 72192299, 722191190 (हाट रोलड कॉइल से संबंधित), 72091620 (आयारन या नान अलाय स्टील के फ्लैट रोलड उत्पाद), 72189990 (इनगट्स या अन्य प्राथमिक रूप विधान में स्टेनलेस स्टील); जिनका संबद्ध उत्पाद से कोई संबंध नहीं है।
  - (ii) निम्नलिखित सौदा विवरणों के लिए, जो यह नहीं दर्शाते हैं कि क्या वे 400 सीरीज से संबद्ध हैं या नहीं :
- क. कोल्ड रोलड स्टेनलेस स्टील शीट इन कॉइल (जेएफई – एमएच-1) (साइज : 1.50 एमएम X 1028एमएम X सी) 3 कॉइल्स
- ख. कोल्ड रोलड स्टेनलेस स्टील इन कॉइल्स : एसयूएस 3402 बी: (1.00 एमएम 1260 एमएमXसी)
- ग. कोल्ड रोलड स्टेनलेस स्टील शीट – साइज : (1.2 एमएम 1260 एमएमXसी) ग्रेड : क्यूसीए 0964सी) आदि
- झ. यदि आवेदक संरक्षण के स्तर से संतुष्ट नहीं था तो उसे पाटनरोधी शुल्क के अंतर्गत अंतरिक समीक्षा (उत्पाद के दायरे का विस्तार करने के लिए उत्पाद दायरे की समीक्षा) के लिए आवेदन करना चाहिए था।
- ञ. आवेदक ने पाटनरोधी शुल्क के निवारण का भी आरोप यह कह कर लगाया है कि पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के बावजूद आयातों को पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किए बिना ही क्लीयर कर दिया जा रहा है। पाटनरोधी विधि के अंतर्गत, ऐसी स्थिति, जहां प्रवंचना की गई है, वहां उसके लिए पृथक् तंत्र की व्यवस्था है। इसका सही-सही उपचार निर्दिष्ट प्राधिकारी, डीजीएडी के पास है न कि रक्षोपाय महानिदेशक के पास।



- ट. आवेदक ने यह स्वीकार किया है कि वह कतिपय ग्रेडों जैसे 429, 432, 444 और 1.4521 की आपूर्ति नहीं करता है। चूंकि भारत में इन ग्रेडों में कोई समान प्रतिस्पर्धी वस्तु नहीं है इसलिए इन ग्रेडों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अलग कर दिया जाना चाहिए और आयातों की मात्रा का निर्धारण करते समय इन ग्रेडों के आयातों पर विचार नहीं करना चाहिए।
- ठ. आवेदक की ओडिशा स्थित कोल्ड रोलिंग मिल को नवम्बर, 2014 को प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा बंद कर दिया गया था। यह ज्ञात नहीं है कि क्या यह दुबारा खुल गया है या नहीं। आवेदक ने यह दर्शाने के लिए कि यह संयंत्र वास्तव में पुनः चालू हो गया है, अभी तक कुछ भी प्रदान नहीं कराया है।
- ड. बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाने के लिए, आवेदक ने वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 के प्रत्येक वर्ष के वार्षिकीकृत आंकड़ों की तुलना वर्ष 2014-15 की तीन तिमाहियों से की है, जबकि वह सामान्यतः अप्रैल-दिसम्बर, 2014 के वार्षिकीकृत आंकड़े दे सकता था।
- ढ. यदि अप्रैल से दिसम्बर, 2014 तक के संपूर्ण आंकड़ों को तिमाहीवार आंकड़ों के बजाय समग्र रूप में दर्शाया जाना चाहिए तो उसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित प्रवृत्ति प्रदर्शित होगी।

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आयात (एमटी)	64,889	87,051	87,178	102,200
मांग (एमटी)	140,600	176,342	182,423	206,685
मांग के संबंध में आयात (%)	46%	49%	48%	49%

- ण. आवेदक के अपने आंकड़े यह दर्शाते हैं कि आयातों में वृद्धि मांग में वृद्धि के अनुरूप ही हुई है और आयातों में कोई असाधारण या अचानक या तीव्र या भारी वृद्धि हुई है।
- त. यद्यपि वैश्विक बाजार में पिछले 5 वर्षों से भारी आपूर्ति हो रही है और इन देशों से आयात घटित हो रहे थे तो अचानक इन 3 महीनों के आयात से ही इतनी अधिक क्षति कैसे हुई कि आवेदक को प्राधिकारी के पास पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- थ. एफटीए के परिणामस्वरूप सीमाशुल्क में कमी होना एक सर्वविदित तथ्य है और भारत द्वारा उपगत इस तरह के स्वतंत्र दायित्व को अनपेक्षित विकास के रूप में नहीं देखा जा सकता है।
- द. अन्य देशों द्वारा संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध अधिरोपित व्यापार उपकारी उपायों का जिनके परिणामस्वरूप भारत को संबद्ध वस्तु का विपथन हुआ, प्रतिरोध करने के लिए भारत ने पहले से ही पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया हुआ है।
- ध. आवेदक ने यह भी आरोप लगाया गया है कि पाटनरोधी शुल्क से प्रदान कराया गया संरक्षण इस तथ्य के बावजूद भी अपर्याप्त है कि पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना भी हो रही है।
- न. जहां तक पाटनरोधी शुल्क की संभावित प्रवंचन का सवाल है, महानिदेशक डीजीएडी को यह शक्ति है कि वह पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना की जांच करे।
- त. आवेदक द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण में मुख्य त्रुटि यह है कि उसने प्रवृत्ति विश्लेषण में वार्षिक आंकड़ों की तुलना तिमाही आंकड़ों से की है। वर्ष 2014-15 को तीन तिमाहियों को क्लब करने और फिर उनका वार्षिकीकरण करने के बजाय आवेदक ने प्रत्येक तिमाही का वार्षिकीकरण कर दिया और असामान्य प्रवृत्ति दर्शाने के लिए उसने उनकी तुलना पिछले पूर्ण वर्ष के आंकड़ों से की है।
- प. कुल मांग के संबंध में आयात सदैव ही स्थिर बने रहे।
- फ. जहां तक अंतिम तिमाही के दौरान उत्पादन में गिरावट होने का संबंध है, यह गिरावट संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण नहीं बल्कि प्रदूषण मापदंडों का उल्लंघन करने पर उनके ओडिशा स्थित कोल्ड रोलड संयंत्र के बंद होने के कारण आई है।
- ब. संस्थापित क्षमता के आधार पर जांच की अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में वास्तव में सुधार हुआ है।
- भ. वर्ष 2014-15 की तीसरी तिमाही के दौरान क्षमता उपयोग में गिरावट आना अनिवार्य था क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवेदक को कोल्ड रोलड संयंत्र को बंद कर दिया था।
- म. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि आवेदक के बाजार हिस्सेवार आयातों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, वर्ष 2011-12 में आयातों का बाजार हिस्सा 47 प्रतिशत से 48 प्रतिशत था, जबकि आवेदक का बाजार हिस्सा 44 से 45 प्रतिशत था।
- कक. जहां तक घरेलू बिक्रियों के संबंध में आवेदक की स्थिति का सवाल है, यह निर्विवाद है कि उसकी घरेलू बिक्रियों में जांच की अवधि में संगत रूप से वृद्धि हुई है।
- खख. इसके अतिरिक्त, आवेदक का यह दावा अपने स्वयं के आंकड़ों के आधार पर ही निराधार है कि इसकी बिक्री में वृद्धि मांग में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं हुई।
- गग. जहां तक कीमत प्रभाव का संबंध है, आवेदक ने दावा किया है कि उसकी उत्पादन लागत में भारी वृद्धि हुई और इसके कारण वह अपनी बिक्री कीमत के उस स्तर के अनुरूप बनाने में सक्षम नहीं है। प्रथमतः, आवेदक ने पर्याप्ततः अपनी क्षमता को वर्ष 2012-13 में लगभग दो गुना कर दिया। क्षमता में इतनी अधिक वृद्धि से प्रतिष्ठापन के शुरुआती वर्षों में उत्पादन लागत में वृद्धि होना लाजमी है और जैसे-जैसे उत्पादन में सुधार होता है वैसे-वैसे इसमें कमी आती जाएगी।

घ. आवेदक की लाभप्रदता में गिरावट आयातों के कारण नहीं बल्कि आंतरिक कारणों से आई है जैसे विद्युत एवं ईंधन व्यय, उच्च मूल्यहास, वित्त प्रभार आदि।

ङ. जहां तक संबद्ध वस्तु के आयातों में वृद्धि होने और आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि होने के संबंध में आवेदक द्वारा किए गए दो अन्य प्रस्तुतिकरणों का संबंध है, यह पुनः उल्लेख किया जाता है कि आयातों में वृद्धि बहुत अधिक अथवा अचानक नहीं हुई है बल्कि यह वृद्धि बाजार मांग के प्रत्युत्तर में हुई है। यह कुल मांग में आयातों के बाजार हिस्से से स्पष्ट है, जो संपूर्ण जांच अवधि में कमोवेश रूप से स्थिर बना रहा। इस प्रकार, आवेदक के तर्क में कोई दम नहीं है और उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

च. आवेदक ने अपने लिखित प्रस्तुतिकरण के पैरा 96 में यह उल्लेख किया है कि संवर्धित आयातों के अलावा ऐसे कोई अन्य कारक नहीं हैं जिन्हें घरेलू उद्योग की क्षति के लिए उत्तरदायी माना जा सकता हो। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि कतिपय अन्य कारक भी हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है जैसे विद्युत और ईंधन लागत, अवक्षयण और वित्तीय लागत, आवेदक द्वारा स्थापित किए गए नवीन संयंत्र की स्टार्ट-अप लागत, इसके अलावा आवेदक द्वारा सहन की गई पर्यावरण समस्या जिसके कारण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उसका संयंत्र बंद भी कर दिया गया।

छ. वर्तमान मामले में आयातों में ऐसी कोई "अचानक, तीव्र, भारी और अभिनव" वृद्धि नहीं है जो "संवर्धित" आयात कहे जा सकते हों। इसके अतिरिक्त, इस तथ्य के अलावा कि आवेदक ने कोई समायोजन योजना प्रदान नहीं कराई है, जिससे वह आगे अपने वाले वर्षों में अपने पैर जमा सके। भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण कोई गंभीर क्षति नहीं हुई है।

**ग. मैसर्स ईएलपी एडवोकेट्स एंड सालिसिटर्स ने मैसर्स निप्पन स्टील एंड सुमिकिन स्टेनलेस स्टील कारपोरेशन, मैसर्स निशिन स्टील कंपनी लिमिटेड, मैसर्स जेएफई स्टील कारपोरेशन, मैसर्स आउटोकुम्पु स्टेनलेस ओयज की ओर से दायर पुनरुत्तर**

#### **खेपवार आंकड़े परिलोचित नहीं किए गए**

- क. याचिकाकर्ता ने मुद्रित आयात आंकड़ों का न्यून रिजालुशन स्कैन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया है। एतद्वारा, इन आंकड़ों का कोई भी विश्लेषण स्वतः ही दुरुह हो जाता है क्योंकि दस्तावेजों की घटिया गुणवत्ता के कारण उनकी कुछ प्रविष्टियों को तो पढ़ना भी मुश्किल था।
- ख. याचिका के अगोपनीय पाठ में तो संव्यवहार-वार आंकड़ों की केवल एक झलक ही प्रदान कराई गई थी। इस तथ्य का कोई कारण उपलब्ध नहीं कराया गया कि आयात आंकड़ों के कुछ भाग को अगोपनीय पाठ में छिपाया क्यों गया था। वास्तव में, जब उन्हीं आंकड़ों को बाद में पूर्णतया प्रकट किया गया, तो गोपनीयता के दावे का कोई औचित्य ही नहीं रहता है।
- ग. आयात आंकड़ों में कई ऐसे सौदों का उल्लेख किया गया है जो इस विचाराधीन उत्पाद के नहीं हैं, उन्हें आयातों में वृद्धि दर्शाने के लिए शामिल किया गया है।
- घ. आयात आंकड़ों को दायर तो किया गया परंतु उनके दायर करने के समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए था कि, यह आंकड़े बार-बार अनुरोध किए जाने पर देरी से और तीन माह के विलंब से प्रदान कराए गए थे।

#### **एक तिमाही के आंकड़ों से आयातों में वृद्धि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।**

- ङ. याचिकाकर्ता का यह तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है कि आयातों में कोई वृद्धि तीन माह की अवधि के वार्षिकीकरण पर आधारित नहीं है और इसलिए उसकी अनदेखी करनी चाहिए।
- च. याचिकाकर्ता ने अपने प्रस्तुतिकरणों के पैराग्राफ 8 में यह दावा किया है कि शुरूआती अधिसूचना में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका था। याचिकाकर्ता ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मानवीय महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा एक दीर्घावधि प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना अपेक्षित होता है। पैराग्राफ 10 में भी याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि जैसे-जैसे जांच में प्रगति होती है वैसे-वैसे सूचना की मात्रा एवं गुणवत्ता में सुधार होता है।
- छ. निर्यातकों ने बार-बार यह प्रकथन किया है कि संवर्धित आयातों की तुलना करने के लिए केवल एक तिमाही (वार्षिकीकृत फार्म में होते हुए भी) तुलना करने की सही क्रियापद्धति नहीं है।

#### **पाटनरोधी शुल्क पहले से ही मौजूद है**

- ज. याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की रक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पाटन के कारण घरेलू उद्योग को कारित कोई भी क्षति प्रथम दृष्टया महानिदेशक (रक्षोपाय) के अभिप्राय के अनुरूप नहीं है।
- झ. याचिकाकर्ता द्वारा अप्रैल से दिसम्बर, 2014 के लिए प्रदान कराए गए आयात आंकड़ों के सारांश के अनुरूप, उन स्रोतों से जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा हुआ था, आयात इस अवधि में हुए कुल आयातों के आधे से अधिक थे।

विवरण	2014-15 (वार्षिकीकृत)
वे देश जिन पर पाटनरोधी	38,807.00
कुल आयात	76,650.00
%	50.63

**कंपनी का गैर-विलयन**

- ज. याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता है कि कंपनी का विसम्बन्धन कई कारणों से हुआ है जिनमें से केवल एक कारण चीन जनगण से आयातों में वृद्धि होना है। इस संदर्भ में, यह नोट करना आश्चर्यजनक है कि चीन जनगण से होने वाले इन संबंध आयातों पर ही पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना चाहिए था। तथापि, इस तथ्य के प्रतिपूर्ण जागरूक होने के बावजूद कि चीन से हो रहे आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है, याचिकाकर्ता ने बड़ी चतुराई से अन्य सभी आयातों को भी अपना लक्ष्य बनाया है। इसलिए वर्तमान जांच को तत्काल डीजीएडी को भेज दिया जाना चाहिए जिससे कि वह चीन जनगण से पाटन संबंधी जांच कर सके।

**विचाराधीन उत्पाद**

- ट. निर्यातकरण विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में अपनी ओर से किए गए प्रस्तुतिकरणों पर भरोसा करते हैं।  
 ठ. उत्पाद के मौजूदा दायरे में उत्पाद की कई श्रेणियों एवं ग्रेडों को शामिल किया गया है जिन्हें पाटनरोधी जांच के उत्पाद दायरे में पहले शामिल नहीं किया है।

**समान वस्तु**

- ड. विनिर्माण का साक्ष्य प्रदान कराना और विशिष्ट कथित ग्रेडों की आपूर्ति करना एक दायित्व है। यदि वह उन विशिष्ट ग्रेडों की आपूर्ति नहीं कर सकता है तो उसकी अपनी निजी क्रियापद्धति भी होना चाहिए तो यह सिद्ध होना चाहिए कि उसके द्वारा आपूरित ग्रेड अपवर्जन के लिए कथित ग्रेडों से प्रतिस्थापनीय है।  
 ढ. घरेलू उद्योग से प्रत्येक पृथक ग्रेड के लिए बिक्री के साक्ष्य स्थापित करने वाले वाणिज्यिक बीजक प्रदान कराने के लिए कहा गया।  
 ण. प्रस्तुतिकरण के पैराग्राफ 25 में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए उस दावे के संबंध में जहां उसने यह दावा किया है कि बिना आर्डर प्राप्त किए किसी भी वस्तु की आपूर्ति नहीं की जा सकती है, यह उल्लेख किया जाता है कि उत्पाद के दायरे में कतिपय अति विशिष्ट और विशेषीकृत उत्पादों को अंतर्ग्रस्त किया जाता है जहां छोटे-छोटे अंतर भी गुणवत्ता में भारी अंतर सृजित कर सकते हैं।  
 त. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों, खासकर, निर्यातकों के अपवर्जन अनुरोध को पहले ही रिकार्ड कर लिया गया है। निर्यातकगण अपने अपवर्जन अनुरोध को पुनः दोहराते हैं और इन ग्रेडों की एक संवर्धन सूची, जिसके अपवर्जन की उन्होंने मांग की है, प्रदर्श-1 (अगोपनीय) का अद्यतन इसके साथ संलग्न कर रहे हैं।  
 थ. समान या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पादों संबंधी याचिकाकर्ता के निष्कर्ष के संबंध में यह नोट करना युक्तियुक्त है कि याचिकाकर्ता ने अपना प्रकथन अल्कोहलिक बीवरेज में कोरिया अपीलीय निकाय के जांच परिणामों, खासकर अपीलीय निकाय द्वारा "प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी या प्रतिस्थापनीय" उत्पादों के संबंध में की गई जांच पर आधारित किया है। यह नोट किया जाना चाहिए कि जिस रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है वह पाटनरोधी जांच से संबंधित है न कि रक्षोपाय जांच से संबंधित।

**घरेलू उद्योग**

- द. अन्य उत्पादकों के उत्पादन के स्रोतों का विवरण अज्ञात है। सार्वजनिक फाइल में ऐसा कोई स्रोत या ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं जिनसे यह संकेत मिलता हो कि "बाजार आसूचना" के अलावा इन आंकड़ों को अन्य किस स्रोत से एकत्र किया गया था।  
 ध. प्रक्रिया की पारदर्शिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना की आंकड़ों का स्रोत और उसकी प्रकृति। माननीय महानिदेशक (रक्षोपाय) से यह प्रमाणित करने का अनुरोध किया जाता है कि यह सूचना प्राप्त करने के लिए क्या किया गया था और इसकी सच्चाई को किस तरह प्रभावित किया गया।

**आयातों में वृद्धि**

- न. निर्यातकगण यह प्रस्तुत करते हैं कि आयातों में यह कथित वृद्धि त्रुटिपूर्ण आंकड़ों पर आधारित है जिनका निर्धारण इस उत्पाद में गैर-पीयूसी को शामिल करके किया गया है।  
 त. आयात आंकड़ों को नए ढंग से निर्धारित किया जाना चाहिए और गैर-विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सभी लेनदेनों के आयात आंकड़ों को इन आयात आंकड़ों से अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए। आयात आंकड़ों को अंतिम रूप देते समय उन्हें सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया जाना चाहिए और सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनका सत्यापन करने और सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार व्यक्त करने के लिए नवीन अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

**आयातों में वृद्धि के कारण**

- प. याचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रारंभिक प्रस्तुतिकरण और सार्वजनिक सुनवाई में उठाई गई आपत्तियों और मुद्दों का कोई समाधान नहीं किया गया है।  
 फ. जहां तक याचिकाकर्ता के इस दावे का संबंध है कि आयातों में यह वृद्धि भारत-जापान मुक्त व्यापार करार के कारण हुई है, उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी स्टॉक पालियोल (एफएसवी) के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच को 13 जनवरी, 2015 की जांच परिणाम के पैराग्राफ 39 और 40 में माननीय महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा निकाले गए निष्कर्षों पर विचार करना चाहिए।

**गंभीर क्षति**

- ब. विशिष्ट क्षति पैरामीटरों और प्रदान कराए गए आंकड़ों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने अभी भी एक बार और तीन तिमाहियों को अलग-अलग रूप से पिछले वित्तीय वर्ष की तीन तिमाहियों के साथ वार्षिकीकरण किया है।  
 भ. अंतरिम/आंशिक अवधि की तुलना करने के लिए उपलब्ध परिशुद्ध एवं व्यापक तौर पर अपनाई जाने वाली क्रियापद्धति यह है कि पिछले वर्ष की समनुरूपी अंतरिम अवधि की तुलना उससे करना चाहिए।

म. तीन तिमाहियों के लिए, याचिकाकर्ता को अप्रैल-दिसम्बर, 2014 से अप्रैल-दिसम्बर, 2013 और पिछले वर्ष की इस अवधि से तुलना करनी चाहिए।

कक. वह तीन तिमाहियों जो एक साथ वार्षिकीकृत करने के लिए पर्याप्त आंकड़े दर्शाती हैं, उनका प्रारंभिक तुलना के लिए वार्षिकीकरण और संयुक्त करना चाहिए।

#### इस्पात संयंत्र की विशिष्टताएं

खख. स्टील संयंत्र की विशिष्टताओं संबंधी याचिकाकर्ता के प्रकथन के संबंध में ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं याचिकाकर्ता में अपने प्रस्तुतिकरण के पैराग्राफ 75 में यह स्वीकार किया है कि गैर-उपरोपक कारकों के कारण कारणात्मक संबंधों का गहन भंग हुआ है। जैसाकि याचिकाकर्ता पक्षकार सदैव से ही यह दावा करते आए हैं कि याचिकाकर्ता के क्षति पैरामीटर, जयपुर संयंत्र के अच्छी तरह से निष्पादन न करने के कारण बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए हैं।

गग. जयपुर संयंत्र का न्यून उपयोग करने के कारण याचिकाकर्ता को क्षति हुई है जो अब अनुचित ढंग से संबद्ध आयातों पर उपरोपित की जा रही है।

#### क्षमता एवं क्षमता उपयोग

घघ. यह नोट करना आवश्यक है कि इस विचाराधीन उत्पाद की प्रकृति ही ऐसी है कि याचिकाकर्ता की क्षमता घटने-बढ़ने वाली क्षमता है अर्थात् याचिकाकर्ता की क्षमता का उपयोग कई प्रकार के स्टील उत्पादों का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है।

ङङ. घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता केवल इस विचाराधीन उत्पाद के लिए ही समर्पित नहीं है।

चच. याचिकाकर्ता जयपुर संयंत्र की अक्षमता, रैस्प-अप मंदी और जयपुर संयंत्र के स्थिरीकरण तथा घरेलू स्रोतों से लागत प्रभावी कीमतों पर क्रोमोइट अयस्क का प्रापण होने की समस्याओं के कारण हुई है न कि कथित संवर्धित आयातों के कारण।

#### लागत विनियोजन

छछ. याचिकाकर्ता के लिए यह संभव है कि वह अन्य उत्पादों से जुड़ी लागत और घाटों को विचाराधीन उत्पाद से जोड़ दे।

जज. इसलिए माननीय महानिदेशक (रक्षोपाय) से यह अनुरोध किया जाता है कि वह याचिकाकर्ता की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों, याचिकाकर्ता द्वारा अनुरक्षित आंतरिक रिकार्डों और प्रणालियों तथा पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय को प्रदान कराए गए लेखाकरण की जांच यह विचार करते हुए करें कि लागत निर्धारण क्रियापद्धति और आंकड़े समान ही बने रहते हैं।

झझ. इसलिए माननीय महानिदेशक (रक्षोपाय) से यह अनुरोध किया जाता है कि वह याचिकाकर्ता की लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों, याचिकाकर्ता द्वारा अनुरक्षित आंतरिक रिकार्डों और प्रणालियों तथा पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय को प्रदान कराए गए लेखाकरण की जांच यह विचार करते हुए करें कि लागत निर्धारण क्रियापद्धति और आंकड़े समान ही बने रहते हैं।

#### मांग, बाजार हिस्सा और घरेलू बिक्री

ञञ. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा अभिनव अवधि में स्थिर बना रहा है और वास्तव में, इसमें वर्ष 2012-13 में वृद्धि हुई है। अंत्य से अंत्य आधार पर यह देखा जा सकता है कि बाजार हिस्से में 1 प्रतिशत से भी कम की मामूली सी गिरावट आई है।

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (वार्षिकीकृत)
मांग	1,40,600	1,76,342	1,82,423	2,06,685
घरेलू उद्योग की बिक्री	63,734	75,386	81,342	91,735
मांग में बाजार हिस्सा	<b>45.33</b>	<b>42.75</b>	<b>44.59</b>	<b>44.4</b>

टट. विश्लेषण की अभिनव अवधि के दौरान घरेलू बिक्रियों में पर्याप्त एवं स्पष्ट वृद्धि हुई है।

#### कीमत प्रभाव

ठठ. याचिकाकर्ता ने अपने प्रस्तुतिकरण के पैराग्राफ 86 में यह दावा किया है कि उसकी बिक्री कीमत में वृद्धि उसकी उत्पादन लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं हो रही है।

डड. इस संदर्भ में, निर्यातकगण यह प्रस्तुत करते हैं कि कीमत अधोरदन अभी हाल ही की तिमाही के दौरान भी ऋणात्मक बनी रही। इसलिए याचिकाकर्ता की कीमतें, लागत की तुलना में कम, आयातों के कारण नहीं रही है। बल्कि याचिकाकर्ता ने अपनी कीमतें स्वयं कम रखी है।

ढढ. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता की उत्पादन लागत सर्वसम्मति से संयंत्र के न्यून उपयोग और कच्चे माल के अधिप्रापण में उच्च संभारतंत्र लागत रूग्ण रही हैं।

**लाभप्रदता**

ण. याचिकाकर्ता ने अद्यतन अवधि (अर्थात् अक्टूबर-दिसम्बर, 2014) के लाभप्रदता संबंधी आंकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं कराए हैं।

त. याचिकाकर्ता को ऐसे आंकड़े प्रदान करने की अनुमति नहीं देना चाहिए जो उसके दावे के लिए उपयुक्त हों और जिनमें उन आंकड़ों को छोड़कर दिया गया हो जो उसमें सुधार प्रदर्शित करते हों।

**गंभीर क्षति की चुनौती**

थ. निर्यातकों ने अपनी विस्तृत टिप्पणियां और उनके खंडन उनके प्रारंभिक प्रस्तुतिकरणों तथा सुनवाई पश्चात् किए गए लिखित प्रस्तुतिकरणों में समान हैं। निर्यातकों के पूर्व प्रस्तुतिकरणों पर भरोसा किया जाना चाहिए और यह माना जाए कि उन्हें यहां निगमित किया गया है।

**कारणात्मक संबंध तथा क्षति कारित करने वाले अन्य कारकों में संबंध भंग**

द. याचिकाकर्ता द्वारा इस संबंध में किए गए प्रस्तुतिकरण रक्षोपाय नियमावली के अनुरूप वर्णित पैरामीटरों जैसे मांग, खपत के प्रतिमान में परिवर्तन, को ही कवर करते हैं।

ध. कई अन्य ऐसे कारक हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है और उनको माननीय महानिदेशक (रक्षोपाय) के विचारार्थ रिकार्ड में प्रदान करा दिया गया है।

न. कारणात्मक संबंधों और आयातों में भारी वृद्धि तथा याचिकाकर्ता के निष्पादन में कथित गिरावट के बीच कारणात्मक संबंधों का गंभीर उल्लंघन करने के कई उदाहरण हैं। वास्तव में इस उल्लंघन को उन अन्य कारणों की मौजूदगी की वजह से और अधिक प्रमाणित किया जाता है जो याचिकाकर्ता द्वारा कथित क्षति के लिए उत्तरदायी हैं।

त. अर्जेंटीना फुटबियर ईसी3 में पैनल ने कारणात्मकता का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित अधिगम का उल्लेख किया है।

क. "क्या आयातों की उध्वगामी प्रवृत्ति क्षति कारकों की अधोगामी प्रवृत्ति से मेल खाती है, और यदि नहीं तो क्या इस बात का तर्कसंगत स्पष्टीकरण दिया गया है कि ऐसा होते हुए भी, आंकड़ों के कारणात्मकता को क्यों दर्शाया गया है।"

ख. क्या आयातित और घरेलू फुटबियर के बीच अर्जेंटीना फुटबियर बाजार में प्रतिस्पर्धा जैसा कि विश्लेषण किया गया है, की स्थिति, जैसा कि विश्लेषण किया गया है, प्रयोजनात्मक साक्ष्य के आधार पर, आयातों का क्षति के साथ कारणात्मक संबंध स्थापित करती है।

ग. क्या अन्य संगत कारकों का विश्लेषण किया गया और क्या यह सच है कि आयातों के अलावा अन्य कारकों से कारित की गई क्षति को आयातों पर उपरोपित नहीं किया गया है।

प. पैनल द्वारा ऊपर प्रतिपादित किए गए के अनुसार कारणात्मक संबंधों को सिद्ध करने के लिए किया गया यह प्रथम प्रयास है, इस तथ्य को महानिदेशक रक्षोपाय स्वीकार किया गया है।

**क्षति पैरामीटरों के साथ आयातों की विसंगतता**

फ. मात्रा पैरामीटर : आयातों में कथित वृद्धि ने याचिकाकर्ता के प्रचालनों को विपरीत ढंग से प्रभावित नहीं किया है; घरेलू बिक्रियों में वृद्धि हुई है जबकि बाजार हिस्सा स्थिर बना रहा है।

ब. आयातों और घरेलू बिक्रियों ने एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र रूप से व्यवहार किया है। वास्तव में, घरेलू बिक्री में उन वर्षों में भी अंतर आ रहा था जब आयातों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था अर्थात् वर्ष 2012-13 से 2013-14 तक।

भ. कीमत : आयातों द्वारा कीमत अधोरदन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमत बढ़ाने में सक्षम था और संबद्ध वस्तु के आयातों की उतराई कीमत में भी वृद्धि हुई है।

म. लाभप्रदता : दिलचस्प रूप से, याचिकाकर्ता द्वारा सहन की गई क्षति ऐसा प्रतीत होता है कि देश में आयातों से स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही थी।

क. याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि उसे विश्लेषण की अवधि में भारी घाटा हुआ है। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से किसी क्षति का संबंध आयातों की मात्रा या कीमत से हो।

ख. वास्तव में, उस अवधि में जब याचिकाकर्ता को अपने लाभ में सर्वाधिक क्षति हुई थी अर्थात् वर्ष 2012-13 से 2013-14 में भी आयात मात्रा और आयात कीमत में कोई अंतर नहीं आया था।

**पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव**

ग. याचिकाकर्ता ने यह स्वीकार किया है कि उसे उन पाटित आयातों के निरंतर आगमन के कारण भारी दुख होता है जिनको पाटनरोधी शुल्क द्वारा रोका नहीं जा सका। प्रासंगिक रूप से, वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में कुल आयात लगभग 57 प्रतिशत थे और वर्ष 2013-14 लगभग 61 प्रतिशत आयात वे आयात थे जिनपर पाटनरोधी शुल्क पहले से ही लगा था।

**वार्षिक रिपोर्ट से उद्घरण**

घ. याचिकाकर्ता की स्वयं अपनी आत्म स्वीकृति से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के प्रचालन कई अन्य कारकों से भी गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, विपरीत शुल्क ढांचा, स्टील स्क्रेप के आयातों पर आधारभूत सीमा शुल्क में वृद्धि, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि और मुद्रा अस्थिरता शामिल है।

डडड. याचिकाकर्ता की वित्त वर्ष 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 37 पर यह स्पष्ट रूप से रिकार्ड किया गया है कि याचिकाकर्ता की हिसार इकाई में योजित क्षमता उपयोग के 98 प्रतिशत पर काम हो रहा है जबकि जयपुर यूनिट क्षमता विस्तार के उपरांत स्थिर है और उसे कई प्रचालनात्मक मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है जिससे उसका क्षमता उपयोग प्रभावित हुआ है।

चचच. याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई क्षति आत्मकृत क्षति है जो उसने क्षति करने वाले परिदृश्य के बावजूद क्षमताओं में विस्तार करने से हुई है और उसने गंभीर स्थिरीकरण मुद्दों का सामना किया है जिससे कारणात्मक संबंध भंग होने का प्रदर्शन होता है।

### जनहित

छछछ. इस संदर्भ में अत्यधिक विनम्रतापूर्वक यह उल्लेख किया जाता है कि केवल घरेलू उत्पादकों के हितों को ही जनहित के रूप में नहीं देखा जा सकता है। माननीय महानिदेशक (रक्षोपाय) को प्रयोक्ताओं, अंतिम उपभोक्ताओं तथा बाजार पर भी समग्र रूप से विचार करना चाहिए।

जजज. यदि घरेलू उद्योग उपभोक्ताओं के एक बड़े अंश को आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है तो शुल्क अधिरोपित करना जनहित में नहीं होगा। इस संदर्भ में अत्यधिक विनम्रतापूर्वक यह कहा जाता है कि वर्तमान मामले में भी, याचिकाकर्ता उपयोक्ता उद्योग को कई तरह के माल की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है।

### समायोजन योजना

झझझ. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों से हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रारंभिक प्रस्तुतिकरणों और सार्वजनिक सुनवाई के दौरान उठाई गई आपत्तियों और मुद्दों का कोई समाधान नहीं होता है। निर्यातकों को अपनी विस्तृत टिप्पणियां और उनका खंडन प्रारंभिक प्रस्तुतिकरणों के साथ-साथ सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात किए गए लिखित प्रस्तुतिकरणों में भी किया है।

### घ. मैसर्स मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर प्रत्युत्तर का संक्षिप्त विवरण

क. प्रतिवादी इस विचाराधीन उत्पाद का निशिन स्टील जापान, निप्पन स्टील एंड सुमिकिन स्टेनलेस स्टील कारपोरेशन (एनएसएससी) – जापान, जेएफई स्टील जापान और पास्को कोरिया से आयात करता है।

### जांच की शुरुआत एवं उसकी निरंतरता

ख. याचिकाकर्ता ने अपने प्रस्तुतिकरणों में स्पष्ट रूप से इस तथ्य की अनदेखी की है कि रक्षोपाय नियमावली के अंतर्गत यह अपेक्षा है कि रक्षोपाय जांच की शुरुआत केवल तभी की जाएगी जब इस बात के "पर्याप्त साक्ष्य" हों कि उत्पाद के प्रवर्धित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति कारित हुई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आज की तारीख के अनुसार याचिकाकर्ता इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में साक्ष्यों की पर्याप्तता सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता अपनी याचिका में यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है कि क्या विचाराधीन उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध है।

ग. वित्त वर्ष 2013-14 की वार्षिक रिपोर्ट में किए गए उल्लेख के अनुसार याचिकाकर्ता के प्रचालनों पर कई अन्य कारकों का भी विपरीत प्रभाव पड़ा है, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, विपरीत शुल्क ढांचा, स्टील स्क्रेप के आयात पर आधारभूत सीमा शुल्क में वृद्धि, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि और मुद्रा की अस्थिरता शामिल है।

घ. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता की वित्त वर्ष 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 37 पर यह स्पष्ट रूप से रिकार्ड किया गया है कि याचिकाकर्ता की हिसार इकाई में योजित क्षमता उपयोग के 98 प्रतिशत पर काम हो रहा है जबकि जयपुर यूनिट क्षमता विस्तार के उपरांत स्थिर है और उसे कई प्रचालनात्मक मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है जिससे उसका क्षमता उपयोग प्रभावित हुआ है।

ड. अतः, याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई क्षति आत्मकृत क्षति है जो उसने क्षति करने वाले परिदृश्य के बावजूद क्षमताओं में विस्तार करने से हुई है और उसने गंभीर स्थिरीकरण मुद्दों का सामना किया है जिससे कारणात्मक संबंध भंग होने का प्रदर्शन होता है।

च. याचिकाकर्ता कथित प्रवर्धित आयातों और घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करने में असफल रहा है और याचिकाकर्ता पर कई अन्य कारकों का भारी विपरीत प्रभाव पड़ा है, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, मुद्रा की अस्थिरता, क्षमता उपयोग को प्रभावित करने वाले प्रचालनात्मक मुद्दे शामिल हैं तथा कथित गंभीर क्षति को संबंधित वस्तु के आयातों पर उपरोपित नहीं किया जा सकता है।

### आयात आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए अपनाई गई क्रियापद्धति और उसकी यथार्थता

छ. याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए सौदावार आयात आंकड़ों में कई विसंगतियां हैं और याचिकाकर्ता द्वारा कई स्थानों पर आयातित उत्पाद के संबंध में समुचित ग्रेडीकरण और सीरीज अभिज्ञान नहीं किया गया है। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा क्रियापद्धति संबंधी नोट में अभिज्ञात कतिपय उत्पादों तथा उसके पश्चात आयात आंकड़ों के संबंध में किए गए घरेलू उद्योग के प्रस्तुतिकरण में निर्धारित उत्पाद सही नहीं हैं और वे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर के उत्पाद हैं।

ज. याचिकाकर्ता द्वारा जिन आयात आंकड़ों पर भरोसा किया गया है उनकी यथार्थता संदेहास्पद है और उसका इस प्रतिवादी तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सशक्त यह नोट किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने केवल एक कथित तरीका प्रदान कराया है जिसमें उसने विचाराधीन उत्पाद की पहचान करने की कार्यवाई की है। तथापि, याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद का निर्धारण करने और उसका मूल्यांकन करने के लिए अपनाई गई क्रियापद्धति प्रदान नहीं की है।

- झ. आयात आंकड़ों के अंतिम रूप देने के पश्चात् उन्हें सभी हितवद्ध पक्षकारों को परिचालित किया जाना चाहिए था और सभी हितवद्ध पक्षकारों को उनकी जांच करने और सार्वजनिक सुनवाई में उन पर अपने विचार व्यक्त करने का नवीन अवसर दिया जाना चाहिए था।
- ञ. याचिकाकर्ता ने आज की तारीख तक कोई समनुरूपी सूचना प्रदान नहीं की है। मांग और क्षति संबंधी पैरामीटरों जैसे उत्पादन, बिक्री, मालसूची, लाभप्रदता आदि के संबंध में जुलाई, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक की अवधि के आयात आंकड़ों से संबंधित कोई सूचना अपने डीआई प्रस्तुतिकरणों में भी प्रदान नहीं की है।

#### समान उत्पाद – विचाराधीन उत्पाद

- ट. याचिकाकर्ता ने अपने डीआई प्रस्तुतिकरण के पैरा 23 में रक्षोपाय नियमावली में यथा-प्राविधानित समान उत्पाद की गलत परिभाषा का उल्लेख करते हुए आगे की कार्यवाई की है।
- ठ. याचिकाकर्ता अपने डीआई प्रस्तुतिकरण में अपना अभ्यावेदन गलत परिभाषा के आधार पर प्रस्तुतिकरण करने की प्रक्रिया अपनाई है और विचाराधीन उत्पाद की तुलना घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पादों से की है।

#### विचाराधीन उत्पाद की गुणवत्ता

- ड. घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद की गुणवत्ता और अन्य देशों जिसमें जापान भी शामिल है, से आयातित विचाराधीन उत्पाद की गुणवत्ता में मौलिक एवं पर्याप्त अंतर है और उस अंतर की प्राधिकारी द्वारा जांच शुरूआत अधिसूचना में अनदेखी की गई है।
- ढ. जांच की कार्यवाई के दौरान हितवद्ध पक्षकारों ने इस समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि विचाराधीन उत्पाद की गुणवत्ता घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित उत्पाद की गुणवत्ता से विशिष्ट है। प्रतिवादी द्वारा जापान गणराज्य से आयात किया जा रहा विचाराधीन उत्पाद अत्याधुनिक पेटेंटेड प्रविधि द्वारा विनिर्मित किया जाता है और वह उत्पाद विशिष्ट डिजाइन एवं विनिर्देशनों का होता है और उसकी गुणवत्ता श्रेष्ठतर क्वालिटी की होती है, जिसका घरेलू उद्योग द्वारा प्रतिवादी की जरूरत के मुताबिक विनिर्माण करने अथवा उसकी उतनी मात्रा में आपूर्ति करने की क्षमता नहीं है।

#### याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता

- ण. यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने भारी गोपनीयता का दावा किया है और याचिकाकर्ता द्वारा भारी मात्रा में सूचना प्रदान नहीं की है जिससे कि घरेलू बाजार में विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री का निर्धारण किया जा सके।
- त. याचिका के अगोपनीय पाठ में याचिकाकर्ता ने महत्वपूर्ण आर्थिक पैरामीटरों जैसे कीमत अधोविक्रयण रेंज, प्रमुख कच्चे माल की सूची किए गए निवेश, निवल माल, अवक्षयण व्यय, व्याज व्यय आदि से संबंधित जानकारी नहीं दी है।
- थ. प्रदान कराई गई समायोजन योजना अधूरी है और याचिकाकर्ता ने अधिकांश सूचना को गोपनीयता के रूप में माने जाने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता ने आवेदन प्रपत्र में कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का विस्तृत उत्तर नहीं दिया है तथा संवेदनशील परिस्थितियों की मौजूदगी और इस तथ्य की पूर्ण तथा विस्तृत जानकारी नहीं दी है कि इस विलंब इतनी अधिक क्षति कैसे हुई जिससे उसकी भरपाई होना ही संभव नहीं रहा है।
- द. याचिकाकर्ता ने प्राधिकारी को प्रदान कराई गई सूचना की गोपनीयता का दावा करने के लिए कोई कारण नहीं बताया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने उक्त सूचना को गोपनीय के रूप में माना है और उसके लिए भी कोई तर्क नहीं दिया गया है।

#### जापान से आयातित उत्पाद पर क्षति का निर्धारण

- ध. अपनी जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी ने रक्षोपाय शुल्क का निर्धारण करने के लिए किसी क्रियापद्धति का निर्धारण नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने प्राधिकारी से यथोचित क्षति मार्जिन की सीमा तक रक्षोपाय शुल्क का निर्धारण करने का अनुरोध किया है। रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से संबंधित विधि में क्षति निर्धारण की कोई संकल्पना नहीं है। अतः, स्पष्टता के उद्देश्य से प्राधिकारी से रक्षोपाय शुल्क के स्तर का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई क्रियापद्धति का खुलासा करने की अपेक्षा की जाती है।
- न. जांच शुरूआत अधिसूचना में किसी ऐसे अनपेक्षित विकास का उल्लेख नहीं है जिसके कारण इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि हुई हो।
- त. वर्तमान मामले में, याचिका और जांच शुरू अधिसूचना में किए गए उल्लेख के अनुसार वर्ष 2012-13 और वर्ष 2013-14 के बीच के आयात आंकड़ों में मामूली सी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014-15 के लिए जिन आंकड़ों पर विचार किया गया वे केवल 3 महीनों की अवधि के हैं और उनसे संपूर्ण वर्ष की प्रवृत्ति का सुझाव या प्रक्षेपण प्राप्त नहीं हो सकता है।
- प. इस विचाराधीन उत्पाद के आयात में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है और इन आयातों अचानक, तीव्र या भारी वृद्धि नहीं हुई है।
- फ. प्रवर्धित आयातों तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। इसलिए, प्राधिकारी ने यह गलत ही प्रतिपादित किया है कि वर्तमान मामले में "पर्याप्त साक्ष्य" से बहुत कम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

#### गंभीर क्षति या कारणात्मक का मामला बनाने का कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं

- ब. याचिकाकर्ता द्वारा अपनी याचिका में प्रस्तुत किए गए किसी भी पैरामीटर में क्षति, किसी गंभीर क्षति से बहुत कम, का मामला नहीं दर्शाया गया है। याचिकाकर्ता ने उत्पादन, घरेलू बिक्री और कुल बिक्री के रूप में संगत रूप से उचित साक्ष्य दिया है। इसके अतिरिक्त, इसे अपनी वर्ष 2011-12 की क्षमता को दो गुना करने में भी कोई समस्या नहीं आई।
- भ. याचिकाकर्ता ने संबद्ध उत्पादों के आयातों द्वारा सकारात्मक कीमत अधोरदन के रूप में विपरीत कीमत प्रभाव को दर्शाते हुए एक तालिका प्रदान की है। तथापि, कीमत प्रभाव का निर्धारण करने में, याचिकाकर्ता ने उच्चतर कीमत अधोरदन दर्शाने के लिए

आयातों के उतराई मूल्य की अपस्फीति की है। इस अपस्फीतिकृत उतराई मूल्य के प्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में कीमत अधोरदन भी स्फीतित रेंज में दिखाया गया है।

म. याचिकाकर्ता द्वारा याचिका के अगोपनीय पाठ में कीमत अधोविक्रयण, अवमंदन और निग्रहण आंकड़ों को अनुक्रमित रूप में भी नहीं दर्शाया गया है।

कक. याचिकाकर्ता के पिछले कुछ वर्षों, विशेषकर वर्ष 2012-13 के लाभ एवं हानि लेखों से यह प्रेक्षण किया गया है कि याचिकाकर्ता को विद्युत और ईंधन के रूप भारी व्यय करना पड़ा जो याचिकाकर्ता को हुई क्षति का एक बहुत बड़ा कारण है।

#### **घरेलू उद्योग को क्षति तथा वस्तु के आयातों के बीच कारणात्मक संबंध**

खख. प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान कराई गई किसी भी सूचना की परिपुष्टि नहीं की हैं और बिना कोई कारण बताए ही उसे प्रथम दृष्टया मामला मान लिया तथा जांच प्रक्रिया प्रारंभ कर दी।

गग. याचिकाकर्ता द्वारा जिन आंकड़ों पर भरोसा किया गया है वे प्राधिकृत आंकड़े नहीं हैं और वे मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एवं उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पूर्णतया भिन्न हैं।

घघ. विभिन्न अखबारों में अभी हाल ही में छपी रिपोर्टों के अनुसार याचिकाकर्ता का ओडिशा स्थित स्टील संयंत्र पर्यावरण मानकों का अनुपालन न करने के कारण बंद कर दिया गया था। इसलिए यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को घाटा हो रहा है और आकर्षक आयात याचिकाकर्ता को चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए, इन सबको ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह याचिका दुर्भावनापूर्ण ढंग से दायर की गई है और विचाराधीन उत्पाद के आवश्यक आयातों को कम करने का एक प्रयास है।

#### **जनहित**

डड. इस समय, आटोमोबाइल उद्योग पर भारी बोझ है और इस विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पहले से ही कई शुल्क अधिरोपित हैं तथा आटो उद्योग को उपलब्ध कराई गई उत्पाद कर छूट भी अब केंद्रीय सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई है। इस परिदृश्य के आलोक में यदि इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण किया जाता है तो घरेलू उपभोक्ताओं पर भारी बोझ पड़ेगा और आम जनता जिन वाहनों की खरीद करेगी उन आटोमोबाइलों की कीमतें पर्याप्त रूप से बढ़ जाएंगी। इसलिए रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में नहीं होगा।

#### **अनपेक्षित विकास**

चच. याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि मांग एवं आपूर्ति में संपूर्ण विश्व में भारी अंतर होने के कारण निर्यातकों ने भारत को अपना निर्यात बढ़ा दिया है। तथापि, यह सिद्ध करना आवश्यक है कि वैश्विक मांग आपूर्ति में अंतर होना एक अनपेक्षित विकास था और यह कि इस कारण उससे भारत को आयातों में वृद्धि हुई। याचिकाकर्ता को अभी भी यह सिद्ध करना है कि वैश्विक मांग एवं आपूर्ति का यह अंतर अनपेक्षित था।

छछ. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता का यह प्रस्तुतिकरण पूर्णतया निराधार एवं अतार्किक है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने के बावजूद आयातों की निरंतरता बनी रही और यह एक अनपेक्षित विकास है। इसके अतिरिक्त, यह यह दावा यह संकेत देता है कि याचिकाकर्ता जिस ढंग से व्यापार उपचारी उपयोग की मांग कर रहा है उससे आयातों पर अनुचित रूप से प्रतिबंध लगेगा। विधि में यह घिसा-पिटा उल्लेख है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण उस पाटन को दूर रखने के लिए किया जाता है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और इसका आशय आयातों को बंद करना नहीं है। अतः याचिकाकर्ता का यह प्रस्तुतिकरण अबोधगम्य एवं नाजायज है कि पाटनरोधी शुल्क के आलोक में सभी आयातों को कम कर देना एक तर्कसंगत प्रत्याशा है।

#### **अन्य मुद्दे**

जज. याचिका में प्रस्तुत की गई सूचना से यह प्रतीत नहीं होता है कि याचिकाकर्ता वर्तमान जांच में पाटित आयातों से संरक्षण प्राप्त करने की मांग कर रहा है या भारी मात्रा में हो रहे सभी आयातों से संरक्षण प्राप्त करने की मांग कर रहा है।

झझ. इसके अतिरिक्त, भारत सरकार को इन्टरनेशनल ट्रेड एंड कामर्स जैसे जापान के साथ की गई अपनी वचनबद्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। भारत सरकार तथा जापान सरकार के निवेश एवं व्यापार के विजन को भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में प्रोत्साहित किया गया है और दोनों देशों के बीच व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत में एक ऐसी प्रणाली की अनुमति देना आवश्यक है जो निर्यातकों और आयातकों पर वित्तीय दबाव न डालती हो।

ञञ. आयातों में यह वृद्धि, जैसा कि याचिका में आरोप लगाया है, आशियान के साथ मुक्त व्यापार करार और जापान तथा कोरिया के साथ सीईपीए की मौजूदगी के कारण हुई है। यहां तक कि आवेदक ने भी अपनी याचिका में यह उल्लेख किया है कि एफटीए और सीईपीए के अनुसरण में कई वर्षों से सीमा शुल्क में भारी कमी कर दी गई है।

टट. याचिकाकर्ता ने इस विचाराधीन उत्पाद के संबंध में विभिन्न देशों से आयातों के विरुद्ध थाइलैंड, ब्राजील और कई अन्य देशों में रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित होने के तथ्य पर अयथार्थ ढंग से तथा असफलतापूर्वक भरोसा किया है। यह नोट करना प्रासंगिक है कि इनमें से किसी भी देश ने जापान से होने वाले आयातों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। इससे यह सिद्ध होता है कि जापान से होने वाले आयात अत्याधुनिक एवं पेटेंटेड आयात हैं, जिनका विनिर्माण करने में घरेलू उद्योग सक्षम नहीं हैं।



**ड. मैसर्स पोस्को कोरिया द्वारा दायर प्रत्युक्ति का संक्षिप्त विवरण****आयात आंकड़ों की यथार्थता एवं यथेष्टता**

क. आयातों में उद्रेक से संबंधित यथोचित विश्लेषण के लिए सौदावार शासकीय आयात आंकड़े डीजीसीआईएंडएस से अवाप्त किए जाने चाहिए।

ख. अंतिम निर्धारण अप्रैल 2014 से मार्च 2015 के वास्तविक आयात आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए।

**समान वस्तु**

ग. 429ईएम, 430 जे1एल, 444, 445 एनएफ, 4465एम ग्रेडों को इस पीयूसी से अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता की विवरणिका से यह साक्ष्यांकित है कि यह ग्रेड ग्राहकों को आर्डर देने के लिए उपलब्ध नहीं है।

**आयातों में वृद्धि**

घ. वह मान भी लिया जाए कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान कराए गए आयात आंकड़े पूर्णतया भरोसेमंद हैं, फिर भी वर्ष 2014-15 की दूसरी तिमाही और वर्ष 2014-15 की तीसरी तिमाही के दौरान हुई वृद्धि रक्षोपाय जांच की शुरुआत के कारण हुई है। आयातकों ने, आयात अवरूद्ध होने और घरेलू कीमतों में वृद्धि होने के डर से, रक्षोपाय जांच की खबर सुनने के पश्चात अपने स्टॉक में वृद्धि करना प्रारंभ कर दी।

ड. वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही के दौरान आयातों में वृद्धि के संबंध में यह परम्परागत है कि स्टील व्यापारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान स्टील की खरीद अधिक करते हैं क्योंकि आयातकगण पिछले साल की समाप्ति पर बचे स्टॉक की क्लीयरिंग करते हैं।

च. घरेलू उत्पादन और घरेलू मांग के संबंध में आयातों में वृद्धि से संबंधित याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान कराया गया चार्ट टेढ़ा-मेढ़ा है और इसमें जांच की अवधि के दौरान पुनरावृत्ति की गई है। इसे भारी वृद्धि के रूप में नहीं माना जा सकता है।

**आयातों में वृद्धि के कारण**

छ. यद्यपि याचिकाकर्ता ने आयातों में वृद्धि के कुछ कारण सूचित किए हैं, परंतु उनमें कुछ भी अनपेक्षित नहीं है। संक्षिप्तता को ध्यान में रखते हुए पोस्को अपने उन प्रस्तुतिकरणों की पुनरावृत्ति नहीं कर रहा है और इस संबंध में दिनांक 22.01.2015 को दायर किए प्रस्तुतिकरण पर ही भरोसा किया जा सकता है।

**घरेलू उद्योग को क्षति**

ज. यद्यपि याचिकाकर्ता ने अपने लिखित प्रस्तुतिकरण के पैराग्राफ 73 में घरेलू मांग का सुझाव दिया था, तथापि ऐसा न तो कोई स्रोत है और न ही उन्होंने वह तरीका बताया जिस ढंग से उन्होंने मांग का आकलन किया। सामान्यतः, भरोसेमंद स्रोतों जैसे सीआरयू, मेटल बुलेटिन अथवा किसी स्टील एसोसिएशन द्वारा प्रदान की गई अन्य सामग्री में केवल 400 सीरीज के स्टेनलेस स्टील के लिए मांग-आपूर्ति के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए हैं।

झ. याचिकाकर्ता हाल के वर्षों में 85 प्रतिशत से अधिक क्षमता उपयोग प्रदर्शित कर रहा है और इसे "बहुत अच्छी स्थिति" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

**जनहित**

ञ. चूंकि याचिकाकर्ता ने स्वयं यह सिद्ध किया है कि वे भारत की घरेलू बाजार में प्रमुख उत्पादक हैं। आयातों को विनियमित करने का आशय है घरेलू बाजार में सीमित प्रतिस्पर्धा होना और इसके परिणामस्वरूप, उपभोक्तागण एकाधिकारिता से होने वाले दुष्परिणामों से पीड़ित होंगे जैसे अधिक मूल्य, चयन के कम अवसर, पोतलदान में विलंब, घटिया गुणवत्ता प्रबंधन आदि।

**IV. अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण**

क. मैसर्स लक्ष्मीकुमारन एंड श्रीधरन द्वारा मैसर्स मेटल वन इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड और मैसर्स बाहुरू स्टेनलेस एसडीएन, मलेशिया की ओर से दायर किया गया अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण

क. आवेदक घरेलू उत्पादक ने 19 जून, 2015 को अतिरिक्त अवधि (जुलाई 14 से दिसम्बर 14) तक के लिए आयात सांख्यिकी रिकार्ड में दर्शायी।

ख. मेटल वन ने 6 माह (जुलाई 14 – दिसम्बर 2014 तक) की अन्य अवधि के लिए आयात सांख्यिकी प्राप्त कर ली। चूंकि प्रत्युक्ति प्रस्तुतिकरण दायर करने के लिए बहुत सीमित समय दिया गया था, इसलिए मेटल वन कारपोरेशन ने प्रारंभिक प्रत्युक्ति प्रस्तुतिकरण प्राधिकारी के समक्ष इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया कि वह मेटल वन कारपोरेशन को आवेदक घरेलू उत्पादक द्वारा प्रस्तुत किए गए नए साक्ष्य को जानने के लिए अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण करने की अनुमति प्रदान करें।

ग. उपर्युक्त के अनुरूप प्राप्त आंकड़ों से उत्पाद विवरण की जांच की गई और निम्नलिखित का अपवर्जन कर दिया :

(i) 400 सीरीज से अलग ग्रेडों (321, 301, 303, 316, 304, 201, 310, 200, 305, 202, 309, 347 और 240 सीरीज) के संदर्भ में हुए लेन-देनों को पृथक कर दिया गया और उन्हें आई/आईपीयूसी के रूप में वर्गीकृत किया गया।

(ii) विवरण में जिन लेन-देनों में "एचआर" या "एचआरएसएस" या "एफआईआर" या "एचआरएसएस" या "हाट रोल्ल" शामिल थे, उनको पृथक किया गया और उन्हें "एनयूपीसी" के रूप में वर्गीकृत किया गया।

(iii) जिन लेन-देनों पर विवरण किसी भी रूप में उल्लिखित नहीं किया गया, चाहे वह जांच शुरुआत नोटिस में यथापरिभाषित संबद्ध उत्पाद ही क्यों न हो, उसे "अज्ञात" के रूप में वर्गीकृत किया गया।

- घ. उपर्युक्त विश्लेषण करने के पश्चात जुलाई 2014 से दिसम्बर, 2014 तक की कुल मात्रा 33270 एमटी पाई गई।
- ङ. इसके विपरीत, आवेदक घरेलू उत्पादक द्वारा अपने दिनांक 15 जनवरी, 2015 के पत्र के तहत इस अवधि के लिए प्रदान कराई गई आयात मात्रा 50725 एमटी है।
- च. इसके अतिरिक्त, यदि मेटल वन के अनुरूप संशोधित आयात सांख्यिकी पर विचार किया जाता है और उनकी आवेदक घरेलू उत्पादक द्वारा अपनी याचिका में प्रदान कराई गई विगत अवधि के लिए आयात सांख्यिकी से उसकी तुलना की जाती है तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी।
- छ. आवेदक घरेलू उत्पादक की आयात सांख्यिकी भी विश्वसनीय नहीं है क्योंकि इनमें कई ऐसे लेनदेन शामिल हैं जिनके लिए मापन की इकाई में नम्बर्स, पीसेस, एसक्यूएम, दर्जन, रोल, शीट, सेट और मीटर्स आदि शामिल हैं। यह ज्ञात नहीं है कि आवेदक घरेलू उत्पादक ने इस आयात लेनदेनों को एमटी में कैसे संपरिवर्तित किया।
- ज. आवेदक घरेलू उत्पादक की आयात सांख्यिकी इसलिए भरोसा करने योग्य नहीं है क्योंकि इसमें कई ऐसे लेनदेनों का विवरण शामिल है जिसमें ऐसे किसी ढंग का उल्लेख नहीं किया गया है क्या वह विचाराधीन उत्पाद है या नहीं।
- झ. अप्रैल 14 से दिसम्बर 14 की अवधि के दौरान हुए कुल 55924 एमटी आयातों में से मलेशिया से हुए आयातों की सही-सही मात्रा 1311 एनआईटी बैठती है जो कुल आयातों का केवल 2.34 प्रतिशत है। अतः, अप्रैल 14 से दिसम्बर 14 की अवधि के दौरान भी मलेशिया से भारत न्यूनतम स्तर से कम थे।

**च. मैसर्स ईएलपी एडवोकेट्स एंड सालिसिटर्स द्वारा मैसर्स निप्पन स्टील एंड सुमिकिन स्टेनलेस स्टील कारपोरेशन, मैसर्स निशिन स्टील कंपनी लिमिटेड और मैसर्स जेएफई स्टील कारपोरेशन की ओर से दायर किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण।**

- क. निर्यातकगण इस ओर से यह दोहराते हैं कि कई ऐसे ग्रेड/उत्पादन श्रेणियां हैं, जो वर्तमान जांच में उत्पाद की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं परंतु उनका उत्पादन याचिकाकर्ता द्वारा नहीं किया जाता है, इसके अतिरिक्त, कुछ ऐसी वस्तु भी हैं जो निर्यातक द्वारा विकसित पेटेंटेड उत्पाद हैं।
- ख. इसके अतिरिक्त, जिन ग्रेडों का उत्पादन याचिकाकर्ता द्वारा किया जाता है, यद्यपि वे सभी तरह से, खासकर उपभोक्ता अबोधन तथा उत्पाद के मानकों से जुड़ी तकनीकी क्षमताओं के आधार पर वे समान उत्पाद नहीं हैं जिनका कतिपय निश्चित अंतिम प्रयोगों के लिए उत्पादन किया जाता है, और जिन्हें इस समय कतिपय निर्यातकों द्वारा निर्यातित उत्पाद से प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
- ग. निर्यातकगण यह प्रस्तुत करते हैं कि इस मुद्दे की जांच करने के उद्देश्य से माननीय महानिदेशक (रक्षोपाय) को निर्यातकों के उत्पादों की तुलना याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित और विक्रीकृत आयातों से करनी चाहिए।
- घ. निर्यातकों ने कतिपय ऐसे ग्रेडों को इस विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जित करने का अनुरोध किया है, जिनका उत्पादन घरेलू उत्पादक द्वारा नहीं किया जा सकता है अथवा जहां याचिकाकर्ता के समकक्ष ग्रेड निर्यातकों के ग्रेड के विनिर्देशनों से भिन्न हैं। ऐसे ग्रेडों की सूची निम्नलिखित है :

**(i) जेएफई स्टील से उन्मोचन का अनुरोध**

स्टील ग्रेड	मुख्य प्रयोग	वह कारण जिसकी वजह जेएसएल उत्पादन नहीं कर सकता है
जेएफई 20-5 यूएसआर जेएफई 18-3 यूएसआर	कैटालिटिक कन्वर्टर (मेटल हनीकाम्ब)	<ol style="list-style-type: none"> <li>जेएफई शीघ्र ही भारत में पेटेंट अवाप्त करेगा जिसके लिए जापान में स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है।</li> <li>मेटल हनीकाम्ब की सामग्री ऑटोमोटिव या मोटर-साइकिल के विनिर्माताओं की सभी डिजायनों द्वारा विशेषीकृत है*</li> <li>प्रमाणन में लगने वाला समय अनिवार्यता तीन वर्ष के लगभग होता है*</li> <li>भविष्य में 50µएम से पतले की मांग है* परंतु जेएसएल की न्यूनतम मोटाई 50µएम है</li> <li>इन ग्रेडों में 3-5 प्रतिशत एल्युमिनियम और 18-20 प्रतिशत क्रोमियम शामिल होता है। इसलिए, सभी प्रक्रियाओं जैसे स्टील मेकिंग, कास्टिंग हाट रोलिंग, कोल्ड रोलिंग में इसका उत्पादन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसकी फ्रैक्चर टफनेस बहुत कम होती है।</li> </ol>

जेएफई 429 ईएक्स जेएफईएमएच-1 जेएफईटीएफ-1	एक्झास्ट	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. यह सभी सामग्री जेएफई के मूल ग्रेड हैं और उनका प्रयोग कार विनिर्माताओं द्वारा उनके प्रमाणन से किया जा रहा है।</li> <li>2. एक्झास्ट मेनीफोल्ड एक महत्वपूर्ण परिरक्षण पार्ट्स में से एक है।</li> <li>3. जेएसएल ने स्टैंडर्ड ग्रेड जैसे टाइप 441 के अलावा कभी भी एक्झास्ट मेनीफोल्ड के लिए विशेष सामग्री का उत्पादन नहीं किया।</li> <li>4. उच्च तापमान पर स्टैंडर्ड ग्रेड 441 की विशेषताएं जेएफई के मूल ग्रेडों की तुलना में निकृष्टतर होती हैं। इसलिए, 441 पर्यावरण के लिए इंजन में प्रयोग करने योग्य नहीं है।</li> <li>5. एक्झास्ट मेनीफोल्ड को उच्च आकृतिता की आवश्यकता होती है। जेएफई के मूल ग्रेडों को विशेष प्रक्रिया प्रविधि से बनाया जाता है। (संलग्न दस्तावेज 1)</li> <li>6. प्रमाणन के लिए लगभग तीन वर्षों का समय अवश्य है।</li> </ol>
जेएफई 443सीटी जेएफई 430 सीयूएन जेएफई 432 एलटीएम जेएफई 439एल जेएफई 409एल	एक्झास्ट सिस्टम	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. यह माल जेएफई का मूल फिनिश है, इसे केवी, केडी कहा जाता है। (फोटोग्राफ 1 और चित्र 2)</li> <li>2. केडी की सरफेस 2बी की सरफेस रफनेस से अधिक है (तालिका 1)</li> <li>3. केवी, केडी फिनिश टैंडेम – सीएएल प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है*। जेएसएल के पास टैंडेम सीएएल प्रक्रिया नहीं है।</li> </ol>

## (ii) मैसर्स निप्पन स्टील एंड सुमिकिन स्टेनलेस स्टील कारपोरेशन से प्राप्त उन्मोचन अनुरोध

स्टील ग्रेड	वह कारण जिसकी वजह से जेएसएल उत्पाद नहीं कर सकता है
<ul style="list-style-type: none"> <li>• आटोमोबाइल उद्योग की उत्कृष्ट फार्मेबिलिटी एनएसएससी 409L (एसयूएच 409एल), एनएसएससी 436एस (एसयूएस 436एल), एनएसएससी 432 (एसयूएस 436जेआईएल), एनएसएससी 439 (एसयूएस 430 एलएक्स), एनएसएससी 180 (एसयूएस 430जेआईएल), एनएसएससी एफएचजेड, एनएसएससी 190 (एसयूएस 444), एनएसएससी 190ईएम (एसयूएस 444), एनएसएससी 444एमआई (एसयूएस 444), एनएसएससी 429एनएफ (एसयूएस 429), एनएसएससी 448ईएम।</li> <li>• पेटेंट पर आधारित विश्व का केवल एक उत्पाद एनएसएससी एफडब्ल्यूआई, एनएसएससी एफडब्ल्यूआई, एनएसएससी एफडब्ल्यू2</li> </ul>	<p><b>1. एनएसएससी की उत्पादन प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी में प्रतिस्पर्धात्मक तीक्ष्णता।</b></p> <p>(याचिकाकर्ता के पास निम्नलिखित में से कोई भी सुविधा और प्रविधि नहीं है)</p> <p>1.1 मोल्टेन स्टील</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 400 सीरीज का उत्पादन करने के लिए ब्लास्ट फरनेस और कन्वर्टर प्रक्रिया के जरिए उत्कृष्ट रिफाइनिंग प्रौद्योगिकी में और उच्च शुद्धता की मोल्टेन स्टील का उत्पादन किया जाता है।</li> </ul> <p>1.2 हाट रोलिंग प्रासेस</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• सतत हाट रोलिंग मिल बेहतर लागत प्रतिस्पर्धात्मक प्रदान करता है।</li> </ul> <p>1.3 कोल्ड रोलिंग प्रासेस</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• एनएसएससी के आटोमोबाइल उद्योग के लिए 400 सीरीज के उत्पादों का उत्पादन टैंडेम कोल्ड रोलिंग मिल के जरिए किया जाता है जिनके रोलड बड़े व्यास वाले उत्कृष्ट फार्मेबिलिटी प्राप्त होती है।</li> </ul> <p><b>2. अनुप्रवाही उद्योग के रूप में इंडिया यमाहा मोटर्स ("आईवाईएम") द्वारा तुलनात्मक मूल्यांकन</b></p> <p>2.1 फार्मेबिलिटी</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• यह सुविधा न होने और उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी की उपकर्षता के कारण याचिकाकर्ता के उत्पाद आसानी से टूट जाते हैं, जिससे अनुप्रवाही उद्योग की जरूरतों को पूरा करना असंभव हो</li> </ul>

	<p>जाता है।</p> <p>2.2 संरक्षण प्रतिरोध</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• स्टील विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा निर्धारित मोल्टेन स्टील की अशुद्धता के कारण, याचिकाकर्ता के उत्पादों में आसानी से जंग लग जाती है, जिससे अनुप्रवाही उद्योग की जरूरत को पूरा करना असंभव हो जाता है।</li> </ul>	
--	--	--

### (iii) मैसर्स निशिन स्टील कंपनी लिमिटेड से प्राप्त उन्मोचन सुविधा

(क) निशिन स्टील की पेटेंटेड ओरिजिनल स्टील ग्रेड

एनएसएस एचआर-2

(ख) निशिन स्टील के विनिर्देशन

एनएसएस 436

एनएसएस 432 .....जिंदल की उत्पाद लाइन-अप में 432 का कोई ग्रेड नहीं है

एनएसएस 439

एनएसएस 409 एम 1

### V. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर अतिरिक्त प्रस्तुतिकरणों पर घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए प्रत्युत्तर का संक्षिप्त विवरण

**क. मैसर्स मेटल वन इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड और मैसर्स बाहूरू स्टेनलेस एसडीएन, मलेशिया द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दायर किया गया प्रत्युत्तर**

- क. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भारी संख्या में उत्पाद प्रकारों को एनपीयूसी के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। तथापि, याचिकाकर्ता ने इन लेनदेनों को पीयूसी के लेनदेन के रूप में नहीं माना है। जहां तक उन अन्य लेनदेनों का संबंध है जिन्हें याचिकाकर्ता द्वारा पीयूसी माना गया है वहां इन उत्पादों को पीयूसी के रूप में ही मानकर उत्तर दिया गया है। उत्पाद प्रकारों के बारे में भी संगत साक्ष्य संलग्न हैं।
- ख. हितबद्ध पक्षकारों ने यह उल्लेख किया है कि कई ऐसे सौदे हैं जहां मापन की इकाई नहीं है और यह प्रश्न किया है कि इन लेनदेनों में आयात मात्रा का निर्धारण कैसे किया गया है। याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करता है कि इन आयात लेनदेनों पर याचिकाकर्ता ने आयातों की मात्रा एवं मूल्य का निर्धारण करते वक्त विचार नहीं किया है क्योंकि इन आयात आंकड़ों को भार के रूप में अनूदित करने के लिए कोई तथ्यपरक आधार उपलब्ध नहीं था।
- ग. यह भी नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकार आंशिक अवधि के आधार पर अपने दावे करते रहे हैं। यदि यह हितबद्ध पक्षकार आयातों की मात्रा के संबंध में अपना कोई अलग दावा करना चाहते हैं तो घरेलू उद्योग को उस पर कोई आपत्ति नहीं है। तथापि, इन हितबद्ध पक्षकारों को यह करना चाहिए कि वे ऐसी दावे संपूर्ण अवधि के लिए आंकड़ों के आधार पर करें जो अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए हितकर हो। हितबद्ध पक्षकार संपूर्ण अवधि के लिए आयातों की मात्रा दर्शाए बिना केवल चालू वर्ष के लिए ही अपना दावा करते रहे हैं। यह स्पष्टतः धोखाधड़ी है और जांच में अवरोध डालने का एक प्रयास है।

**ख. मैसर्स निप्पन स्टील एंड सुमिकिन स्टेनलेस स्टील कारपोरेशन, मैसर्स निशिन स्टील कंपनी लिमिटेड और मैसर्स जेएफई स्टील कारपोरेशन द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतिकरणों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दायर किया गया प्रत्युत्तर।**

- क. जापान की कंपनियों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों के अगोपनीय पाठ से उत्पाद विवरण और विनिर्देशनों की समझ नहीं मिल पाती है।
- ख. विचाराधीन उत्पाद के किसी विशिष्ट ग्रेड का अपवर्जन करने के लिए किए गए किसी दावे का आधार और उसका विवरण घरेलू उद्योग के साथ अनिवार्यतः शेयर किया जाना अपेक्षित है क्योंकि वह अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम हो सके।
- ग. कतिपय ग्रेडों का उत्पादन न करने या उनका प्रतिस्थापन न होने के तथ्य का सुनिश्चयन तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि घरेलू उद्योग इस तथ्य के प्रति जागरूक है कि वास्तव में उत्पाद में क्या शामिल हैं।
- घ. जापान की कंपनी द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतिकरणों में उल्लिखित ग्रेडों के संबंध में याचिकाकर्ता ने उन सभी अपवर्जनों, जिनकी एनएसएसएससी, जेएफईएससी और निशिन द्वारा मांग की गई थी, के लिए सभी उत्पादों के समान/तुलनीय ग्रेडों की आपूर्ति की है।

- ड. जहाँ तक एनएसएससी 190ईएम, एनएसएससी 441 एम1, एनएसएससी 429 एनएफ और एनएसएससी 448 ईएम ग्रेडों तथा पेटेंट के रूप में दावाकृत दो अन्य ग्रेडों अर्थात् एनएसएससी एफडब्ल्यू1 और एनएसएससी एफडब्ल्यू2 का संबंध है याचिकाकर्ता इन ग्रेडों की तुलना जेएसएल के उत्पादों के साथ करने में सक्षम नहीं है क्योंकि उनके संबंध में कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है।
- च. याचिकाकर्ता कोई सूचना उपलब्ध न होने के कारण जेएफई 20 - 5 यूएसआर और जेएफई 18 - 3 यूएसआर ग्रेडों की तुलना जेएसएल के उत्पादों से करने में सक्षम नहीं हैं।
- छ. इसके अतिरिक्त, ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी ने, वास्तव में, भारत में पेटेंट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया हो। आज की स्थिति के अनुसार अभी तक कोई पेटेंट नहीं दिया गया है।
- ज. याचिकाकर्ता पूर्ण समन्वित उत्पादक है जिसके पास मेल्टिंग, एओडी, वीओडी, हाट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग सहित पूर्ण सुविधाएं हैं। इसलिए याचिकाकर्ता कोई भी ग्रेड/विनिर्देशन उत्पादित करने के लिए सक्षम है।
- झ. इसके अतिरिक्त, कोई भी उत्पादक अपने उत्पाद की बिक्री तब तक नहीं कर सकता है जब तक उसे किसी उपभोक्ता के क्रय आदेश न मिले। व्यवसाय की यह एम मूल स्थिति होती है कि जब तक किसी उत्पादक को आर्डर नहीं दिया जाता है तब तक उस उत्पादक द्वारा उस वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है क्योंकि हर उत्पादक को किसी न किसी सामग्री की आवश्यकता होती है। अतः केवल उन ग्रेडों को छोड़कर जिनके लिए बाजार में स्टैंडर्ड/रिपीटेड/रूटीन आवश्यकता होती है, का उत्पादन करने के अलावा प्रत्येक उत्पादक अन्य ग्रेडों का उत्पादन केवल तभी करता है जब उन ग्रेडों की खरीद करने के लिए उसे क्रय आदेश प्राप्त हो जाते हैं। चूंकि याचिकाकर्ता को ऐसा कोई क्रय आदेश प्राप्त नहीं हुआ इसलिए, स्वाभाविक रूप से, याचिकाकर्ता ने इन उत्पादों का उत्पादन नहीं किया।

## VI. जांच एवं जांच परिणाम

- मैंने इस मामले के रिकार्ड की, घरेलू उत्पादक, प्रयोक्ता/आयातकों, निर्यातकों और निर्यातक राष्ट्रों द्वारा दायर प्रत्युत्तरों की सावधानीपूर्वक जांच की है। उनके द्वारा किए गए लिखित प्रस्तुतिकरणों और प्रत्युक्ति प्रस्तुतिकरणों पर भी समुचित रूप से विचार किया गया है। विभिन्न पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों और उनसे उत्पन्न मुद्दों का इस जांच में समुचित स्थानों समाधान कर दिया गया है।
- सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख में आयातों पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का प्रावधान है। उपधारा (1) में केंद्रीय सरकार द्वारा किसी ऐसी वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का प्रावधान है जिसका भारत में इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत किया जाता है कि उससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो।
- सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली 1997 में जांच की शासित करने वाले ढंग एवं सिद्धांतों का उल्लेख है।
- यह जांच उक्त नियमावली के अनुरूप आयोजित की गई है और इस अधिसूचना के जरिए अंतिम जांच परिणाम रिकार्ड किया गया है।

## क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

- क. वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद (जिसे एतदपश्चात् पीयूसी कहा गया है) सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 के सीमाशुल्क प्रशुल्क उप-शीर्षक संख्या 72193112, 72193111, 72193210, 72193310, 72193410, 72193510, 72202021 और 72209021 के अंतर्गत वर्गीकृत 400 सीरीज क्रोमियम टाइप के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोलड फ्लैट उत्पाद जिनमें एएसटीएम ए 240/ए 240एम के अनुरूप सभी मार्टेनसिटिक तथा फेरिटिक ग्रेड और अन्य स्टैंडर्ड जैसे यूएनएस, आईएस, चाइनीज डीआईएन, जेआईएस, वीआईएस, ईएन आदि के समकक्ष/तुलनीय विनिर्देशनों के सभी ग्रेड शामिल हैं, परंतु जिसमें (i) 1700 एमएम तथा उससे अधिक की चौड़ाई और (ii) जेबीएस (जिंदल ब्लेड स्टील) ग्रेड तथा उसके समकक्ष शामिल नहीं हैं। इस विचाराधीन उत्पाद का मुख्यतः प्रयोग सफेद उपभोक्ता वस्तुओं, प्रासेस्ड उपकरणों, दुग्धशाला उपकरणों, आटोमोटिव संघटकों, रेल कार्टस, मेट्रो कोच, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग एवं कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। कई हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि इस विचाराधीन उत्पाद का दायरा उपयुक्त नहीं है। तथापि, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह सिद्ध नहीं किया है कि यह दायरा किस तरह उपयुक्त नहीं है और इस विचाराधीन उत्पाद के दायरे में कौन से ऐसे उत्पाद प्रकारों को शामिल किया गया है जिन्हें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार इस संबंध में किए गए सभी तर्क सारहीन हैं और पूर्णतया असाक्ष्यंकित हैं। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह मुद्दा उठाया है कि उन सभी उत्पाद प्रकारों को जिनका आयात किया जा रहा है और जिनका घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन नहीं किया जा रहा है, इस विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए। तथापि, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने उत्पाद के दायरे से अपवर्जन किए जाने के लिए अपने दावे के साक्ष्य के रूप में कोई भी वास्तविक साक्ष्य दायर नहीं किया है और इसलिए उनके यह दावे या मुद्दे केवल कल्पनाओं पर आधारित हैं और इसलिए उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने कभी भी किसी भी माल की आपूर्ति करने से तकनीकी क्षमताओं के आधार पर मना नहीं किया है। याचिकाकर्ता किसी उत्पाद की आपूर्ति तभी कर सकता है जब उसे उपभोक्ता से उसका क्रयादेश मिले। कोई भी उत्पादक किसी भी माल का उत्पादन तब तक नहीं कर सकता है जब तक उसे उसकी खरीद करने का आदेशन मिले। जापान के कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने कतिपय ऐसे ग्रेडों का इस विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जन करने का अनुरोध किया है जिसका घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादन नहीं किया जा सकता है अथवा जहां याचिकाकर्ता के समकक्ष ग्रेड निर्यातकों के ग्रेड विनिर्देशन से अलग हैं। घरेलू

उद्योग ने अपने प्रत्युत्तर में यह आपत्ति उठाई है कि जापान की कंपनियों द्वारा दायर किए गए प्रस्तुतिकरणों के अगोपनीय पाठ से उत्पाद विवरण और विनिर्देशन की समझ प्राप्त नहीं होती है और विचाराधीन उत्पाद के किसी विशिष्ट ग्रेड का अपवर्जन करने के किसी भी आधार की भागीदारी घरेलू उद्योग के साथ की जानी चाहिए थी और इसलिए वे अपने हितों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने यह दावा भी किया कि उन्होंने जापान के उत्पादकों द्वारा जिन-जिन ग्रेडों का अपवर्जन करने की मांग की है, उन सभी उत्पादों के समकक्ष/तुलनीय ग्रेडों की उन्होंने आपूर्ति की है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि जापान के उत्पादकों के कुछ उत्पादों के लिए पेटेंट अभी भी प्रदान नहीं कराया गया है। इस संबंध में मैं इस बात से सहमत हूँ कि विचाराधीन उत्पाद के किसी विशिष्ट ग्रेड का अपवर्जन करने के लिए किए गए किसी विवरण या आधार को निश्चित रूप से घरेलू उद्योग के साथ शेयर किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि घरेलू उद्योग अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम हो सके। जापान के उत्पादकों ने यह दर्शाते हुए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि जापान की कुछ कंपनियों द्वारा उत्पादित कुछ उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा पेटेंट प्रदान कर दिया गया है और इसलिए उनका अपवर्जन करने का कोई औचित्य नहीं है।

- ख. उपर्युक्त के मद्देनजर, यह संपुष्टि की जाती है कि विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 के सीमाशुल्क प्रशुल्क उप-शीर्षक संख्या 72193112, 72193111, 72193210, 72193310, 72193410, 72193510, 72202021 और 72209021 के अंतर्गत वर्गीकृत 400 सीरीज क्रोमियम टाइप के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद जिनमें एएसटीएम ए 240/ए 240एम के अनुरूप सभी मार्टेनसिटिक तथा फेरिटिक ग्रेड और अन्य स्टैंडर्ड जैसे यूएनएस, आईएस, चाइनीज डीआईएन, जेआईएस, बीआईएस, ईएन आदि के समकक्ष/तुलनीय विनिर्देशनों के सभी ग्रेड शामिल हैं, परंतु जिसमें (i) 1700 एमएम तथा उससे अधिक की चौड़ाई और (ii) जेबीएस (जिंदल ब्लेड स्टील) ग्रेड तथा उसके समकक्ष शामिल नहीं हैं। तदनुसार, यह भी प्रतिपादित किया जाता है कि घरेलू रूप से उत्पादित "400 सीरीज के क्रोमियम टाइप के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद जांचाधीन आयातित उत्पाद के बारे में सभी समान या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी वस्तु के अंतर्गत आते हैं और यह कि घरेलू रूप से उत्पादित 400 सीरीज के क्रोमियम टाइप के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 2(ई.) के आशय के अंतर्गत आयातित 400 सीरीज के क्रोमियम टाइप के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के समान उत्पाद है।

#### ख. घरेलू उद्योग (डीआई)

5. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8बी (6) (बी) में घरेलू उद्योग को निम्नवत परिभाषित किया गया है।

"बी "घरेलू उद्योग" का आशय

(i) भारत में समान उत्पाद या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पाद के समग्र रूप से उत्पादकों; अथवा

(ii) उन उत्पादकों से होता है जिनका समान उत्पाद अथवा भारत में प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पाद का सामूहिक उत्पादन भारत में उक्त वस्तु के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है।"

6. यह आवेदन मैसर्स जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, जिंदल सेंटर, 12, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 द्वारा दायर किया गया है। यह आवेदक 85 प्रतिशत से अधिक का भारतीय उत्पादन करने के लिए उत्तरदायी है और इसलिए प्रमुख उत्पादक है। तदनुसार, यह प्रतिपादित किया जाता है कि आवेदक घरेलू उत्पादक सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8बी (6) (बी) (i) के अंतर्गत परिभाषित एवं अपेक्षित आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और वह घरेलू उद्योग (डीआई) का प्रतिनिधित्व करता है।

#### ग. सूचना का स्रोत

7. इस विचाराधीन उत्पाद का आयात सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 72 के अंतर्गत सीमाशुल्क प्रशुल्क शीर्षक 72193112, 72193111, 72193210, 72193310, 72193410, 72193510, 72202021 और 72209021 के अंतर्गत किया जाता है। यह रक्षोपाय जांच वर्ष 2011-12 से 2014-15 (अप्रैल से जून, 2014) तक के लिए साइबेक्स, नोएडा के आयात आंकड़ों (सौदावार) के आधार पर शुरू की गई थी। वर्ष 2011-12 से 2013-14 (जनवरी, 2014 तक) तक के घरेलू आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और उनका सत्यापन जरूरी समझी गई सीमा तक उत्पाद शुल्क के आधार पर इस विभाग द्वारा स्थल सत्यापन करके किया गया। फरवरी, 2014 से जून, 2014 तक के लिए घरेलू आंकड़े, विधिवत प्रमाणित, घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए हैं जिनका उत्पादन शुल्क रिकार्डों से विधिवत सत्यापन किया गया है। क्षति विश्लेषण के लिए वर्ष 2014-15 के वार्षिक समेकित आंकड़ों पर पहुंचने के लिए आवेदक द्वारा अपने लिखित प्रस्तुतिकरणों/प्रत्युक्तियों में यथाप्रस्तुत विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों के संबंध में जुलाई, 2014 से दिसम्बर, 2014 के लिए आयात आंकड़ों तथा घरेलू आंकड़ों को लिया गया है।

#### घ. जांच की अवधि (पीओआई)

8. न तो सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 में और न ही सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 में विशेष रूप से "जांच की अवधि" को अथवा रक्षोपाय जांच के लिए विचारित कम से कम अवधि को परिभाषित किया गया है। रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार जांच की अवधि का चयन करने के लिए न तो कोई सामान्य या विशिष्ट प्रावधान है और न ही कोई दिशानिर्देश है। तथापि जांच की अवधि से संबंधित मुद्दे का विस्तृत विवरण कोरिया के विरुद्ध यूएस लाइन पाइप मामले में (पैरा 7.196, 7.199 और 7.201) उल्लेख किया गया है। इस मामले में पैल ने यह निर्धारित किया है कि आयातक देश के जांचकर्ता प्राधिकारी को "जांच की अवधि की दीर्घता" और इसके "भंग" होने का निर्धारण करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने का अधिकार है। "हम नोट करते हैं कि इस करार में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि रक्षोपाय जांच में जांच की अवधि कितनी लंबी होनी चाहिए, और न ही यह उल्लेख है कि विश्लेषण के प्रयोजनार्थ भंग की अवधि क्या होनी चाहिए। इस प्रकार जांच की अवधि और इसके भंग होने की अवधि जांचकर्ता प्राधिकारियों के विवेक पर छोड़ दी गई है। हमारे समक्ष उपस्थित मामले में आईटीसी द्वारा चीन की गई अवधि पांच वर्ष और

छह माह थी, यह अवधि अर्जेंटीना फुटवीयर रक्षोपाय में अर्जेंटीना की जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की गई जांच की अवधि के समकक्ष है। तथापि, हम नोट करते हैं कि अपीलीय निकाय ने अपने जांच परिणाम में जांच की अवधि की लंबाई के संबंध में तर्क देने के लिए कोरिया पर भरोसा किया है, उसमें न केवल अवधि की लंबाई पर बल दिया गया है परंतु अभिनव आयातों पर फोकस होना चाहिए और न कि जांच की गई अवधि पर। लाइन पाइप जांच में आईटीसी ने न केवल अंतिम बिन्दु की तुलना में या जांच की अवधि की समग्र प्रवृत्ति की जांच की (जैसा कि अर्जेंटीना ने अर्जेंटीना फुटवीयर रक्षोपाय में जांच के लिए किया था)। इसने पूरे 5 वर्षों के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आयातों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया और यह भी विचार किया कि क्या अंतरिम 1998 की तुलना में अंतरिम 1999 में वृद्धि हुई थी। हमारा विचार है कि एक ऐसी अवधि का चयन करके जो 5 वर्ष छह माह की थी आईटीसी ने अनुच्छेद XIX और अनुच्छेद 2.1 से असंगत कार्य नहीं किया। यह निष्कर्ष निम्नलिखित विचारों पर आधारित है : प्रथम करार में ऐसा कोई विशिष्ट नियम नहीं है जिसमें जांच की अवधि की लंबाई बताई गई हो; द्वितीय, आईटीसी द्वारा चयनित अवधि अभिनव आयातों पर प्रकाश डालती है; और तृतीय, आईटीसी द्वारा चयनित अवधि, संवर्धित आयातों की मौजूदगी के संबंध में निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त दीर्घ है।" (पैरा 7.196, 7.199 और 7.201)<sup>1</sup>

9. इन तथ्यों तथा ऊपर उल्लिखित सूचना के स्रोत पर विचार करते हुए, उपर्युक्त के मद्देनजर वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ वर्ष 2011-12 से 2014-15 (वार्षिकीकृत) तक की अवधि के आंकड़ों को उपयुक्त माना गया।

#### ड. प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता

10. रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.2 तथा सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 7 में कतिपय सूचना को गोपनीय मानने का प्रावधान है। नियम में प्रावधान है कि किसी हितबद्ध पक्षकार को ऐसी सूचना का प्रकटन वास्तविक आधार पर करना अपेक्षित नहीं है जो कंपनी की गोपनीय सूचना हो और जिसका प्रकटन करने उक्त पक्षकार के व्यापारिक हितों को गंभीर क्षति पहुंचने की पूर्वावधारणा हो, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न हो और जिसका याचिकाकर्ता ने विगत में कभी भी सार्वजनिक रूप से प्रकटन न किया हो।

11. घरेलू उद्योग ने कुछ सूचना गोपनीय आधार पर प्रदान कराई है और प्रस्तु सूचना/आंकड़ों की गोपनीयता का दावा किया है। घरेलू उद्योग ने रक्षोपाय नियमावली, 1997 तथा दिनांक 06.09.1997 के व्यापार नोटिस संख्या एसजी/टीएन/1/97 के प्रावधानों के अनुसार आवेदनपत्र का अगोपनीय पाठ प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने आवेदन दायर करते समय गोपनीयता की मांग करने वाले कारणों का भी उल्लेख किया है जो तर्कसंगत प्रतीत होता है तथा उसे स्वीकार कर लिया है।

#### च. संवर्धित आयात :

12. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8(बी) में रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की केंद्रीय सरकार के अधिकारों का उल्लेख करता है और इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान करता है :

*"(1) यदि केंद्रीय सरकार, ऐसी जांच जिसे वह उचित समझे करने के पश्चात् इस तथ्य से संतुष्ट है कि किसी वस्तु का भारत में इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में आयात किया जा रहा है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो तो यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित कर सकती है।"*

13. नियम में यह अधिदेशित है कि रक्षोपाय शुल्क का अनुप्रयोग करने के लिए संवर्धित आयात एक आधारभूत पूर्वपेक्षा है। अतः, यह निर्धारित करने के लिए संवर्धित शुल्क का अनुप्रयोग करने के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद के आयातों में "इतनी अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है" कि जिससे नियमों के अंतर्गत इन संवर्धित आयातों का विश्लेषण, घरेलू उत्पादों के संगत रूप में और समग्र रूप में करना आवश्यक हो गया है।

14. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 2 में "संवर्धित मात्रा" की निम्नलिखित परिभाषा दी गई है :

*"(सी) संवर्धित मात्रा में आयातों में वृद्धि उत्पादन के समग्र या रूप में होना शामिल है।"*

15. आयातों में वृद्धि की प्रकृति के संबंध में, अर्जेंटीना फुटवीयर (ईसी) में अपीलीय निकाय ने पैनल को विरुद्ध यह धारित किया कि आयातों में वृद्धि अत्यधिक अभिनव, अचानक, तीव्र और इतनी अधिक होनी चाहिए कि वह उससे क्षति कारित हो सके अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो सके। उसका संगत सार निम्नलिखित हैं :

*"131. इस अपेक्षा का निर्धारण की क्या आयातों में "इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में" वृद्धि को पूरा करने कील अपेक्षा केवल गणितीय अथवा या तकनीकी निर्धारण नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में किसी जांच के लिए केवल यह दर्शाना ही पर्याप्त नहीं होता है कि इस वर्ष किए गए आयात पिछले वर्ष .....विगत पांच वर्ष पहले किए गए उत्पादों के आयात से अधिक हुए हैं। पुनः, और यह पुनरावृत्ति प्रतीत होती है कि केवल आयातों की कोई संवर्धित मात्रा ही पर्याप्त नहीं होगी बल्कि यह वृद्धि ऐसी बड़ी हुई मात्रा में हुई हो जिससे रक्षोपाय साधन का अनुप्रयोग करने की जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो रही हो और रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 तथा गाट 1994 के अनुच्छेद-XIX : 1(क) दोनों की भाषा से हमारा विश्वास है कि यह अपेक्षा की जाती है कि आयातों में यह वृद्धि अत्यधिक अभिनव, अत्यधिक अचानक, अत्यधिक तीव्र और अत्यधिक भारी मात्रा में, परिणामात्मक और गुणात्मक रूपों में होनी चाहिए जिससे कि गंभीर क्षति हो सके या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो सके।"*

16. यूएस-व्हीट ग्लुटेन संबंधी पैनल में "ऐसी संवर्धित मात्रा में" वाक्यांश की व्याख्या निम्नवत की गई है :

<sup>1</sup> डब्ल्यूटी/डीएस 202/आरडीटी दिनांक 29.10.2001, यूएस पाइप लाइन मामले में पैनल रिपोर्ट

8.31 गाट 1994 के अनुच्छेद-XIX : 1(क) और रक्षोपाय करार ("एसए") के अनुच्छेद 2.1 में आयातों में केवल वृद्धि की ही बात नहीं की गई है। बल्कि संबंधित उत्पाद के आयातों में वृद्धि की परिमाणात्मक और गुणात्मक प्रकृति की होनी चाहिए। गाट 1994 के अनुच्छेद-XIX : 1(क) तथा रक्षोपाय संबंधी करार (एसए) के अनुच्छेद 2.1 में यह अपेक्षा की जाती है कि उक्त उत्पाद का आयात संबंधित सदस्य के भू-भाग में इतनी अधिक बड़ी हुई मात्रा (घरेलू उत्पादन के संगत रूप से) में की जा रही हो कि उससे गंभीर क्षति हो रही हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो। अतः केवल आयातों में वृद्धि होना ही पर्याप्त नहीं है। बल्कि हम अर्जेंटीना-फुटवीयर रक्षोपाय मामले में अपीलीय निकाय के इस जांच परिणाम से सहमत हैं कि आयातों में यह वृद्धि परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में पर्याप्त रूप से अभिनव, अचानक, तीव्र और इतनी अधिक हुई हो कि उससे गंभीर क्षति कारित हुई हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो सके।

17. इस विचाराधीन उत्पाद के संबंधित आयातों का विश्लेषण डब्ल्यूटीओ विधि संग्रह और उपर्युक्त विधि के आलोक में किया गया है।

#### आयातों में समग्र रूप में वृद्धि

18. इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में प्रवृत्ति का विश्लेषण उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में किया गया है। इस पीयूसी का भारत में कई देशों से और मुख्यतः जापान, कोरिया, चीन, ईयू, यूएसए, और मैक्सिको से आयात किया जा रहा है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह आपत्ति जताई है कि घरेलू उद्योग द्वारा सीटीएच 72 के अंतर्गत सौदावार प्रविष्टियों में आयात आंकड़ों का पृथक्करण करने के लिए जो क्रियापद्धति अपनाई है वह सही नहीं है क्योंकि इसमें कई सौदों में ऐसी विसंगतियां हैं जिनसे किसी भी ढंग से यह संकेत नहीं मिलता है कि क्या वह विचाराधीन उत्पाद है या नहीं। हितबद्ध पक्षकारों ने यह आपत्ति भी उठाई है कि उन्हें सौदावार आंकड़े प्रदान नहीं कराए गए हैं और यह कि घरेलू उद्योग ने मापन की अन्य इकाइयों को एमटी में कैसे संपरिवर्तित किया है। इस संबंध में मीट्रिक टन, टन या किलोग्राम में दिए गए आयात आंकड़ों के संबंध में ही विचार किया गया है और सौदावार आयात आंकड़ों के लिए उस स्रोत को पहले ही उपलब्ध करा दिया गया है कि उन्हें कहां से लिया गया है। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि केवल एक तिमाही (अप्रैल, 14 से जून, 14 तक) के आंकड़े ही आयातों में वृद्धि का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इस संबंध में मैं इस आपत्ति में कोई दम नहीं पाता हूं क्योंकि यह जांच, प्राधिकारी को उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई और चूंकि जांच की अवधि वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों तक के लिए खुली है, इसलिए क्षति विश्लेषण के लिए दिसम्बर, 2014 तक आंकड़ों पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग द्वारा पीयूसी के रूप में आंकड़ों का पृथक्करण करने के लिए अपनाई गई क्रियापद्धति में कोई अनियमितता नहीं है। जांच की शुरुआत के समय विचाराधीन उत्पाद के रूप में माने गए आयात आंकड़े की विस्तार से पुनः जांच की गई और अधोलिखित तरीके से अभिज्ञात की गई प्रविष्टियों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से हटा दिया गया क्योंकि वे विचाराधीन उत्पाद के विवरण की संपुष्टि नहीं करती हैं।

- सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 के अंतर्गत स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोलड फ्लैट उत्पादों के लिए समर्पित सीटीएच के अंतर्गत रिपोर्ट की गई प्रविष्टियां जहां 400 सीरीज या उनके यूरोनार्म संख्या जैसे 1.45;0, 1.4512 आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।
- सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 के अंतर्गत स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोलड फ्लैट उत्पादों के लिए असमर्पित सीटीएच के अंतर्गत रिपोर्ट की गई प्रविष्टियां, जहां शब्द "400 सीरीज या उनके यूरोनार्म संख्या जैसे 1.4509, 1.4512 आदि सहित कोल्ड रोलड स्टेनलेस स्टील या सीआरएसएस का उल्लेख नहीं किया गया है।

19. उपर्युक्त के मद्देनजर वर्ष 2011-12 से 2014-15 (दिसम्बर, 2014 तक) तक इस विचाराधीन उत्पाद के आयात की प्रमात्रा निम्नलिखित हैं :-

अवधि	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15(दिसम्बर 2014 तक)	2014-15 (वार्षिकीकृत)
आयात (एमटी)	62,167	82,414	80124	73102	97469
अनुक्रमित	100	133	129	118	157

आयातों की तुलना	2011-12 और 2012-13	2012-13 और 2013-14	2013-14 और 2014-15 (वार्षिकीकृत)
पिछले वर्ष की तुलना में आयातों में वृद्धि (एमटी)	20247	-2290	17345
पिछले वर्ष की तुलना में आयातों में वृद्धि की दर (एमटी)	33%	-2.78%	21.64%

20. उपर्युक्त तालिका में दिए गए आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2012-13 और 2013-14 के संपूर्ण वर्षों के दौरान समग्र रूप से आयातों में कोई उद्रेक नहीं आया अर्थात् वर्ष 2012-13 की अवधि के दौरान आयात बढ़कर 20247 एमटी तक हो गए। परंतु वर्ष 2013-14 तक इनमें 2290 एमटी की कमी आ गई। इससे यह प्रदर्शित होता है कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के संपूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान आयातों में वृद्धि 33 प्रतिशत से घटकर -2.78 प्रतिशत रह गई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014-15 (वार्षिकीकृत) की अवधि के



दौरान आयातों की दर बढ़कर 21.64 प्रतिशत हो गई जो शुरूआती वृद्धि दर की तुलना में कम है। अब वर्ष 2014-15 को शेष तीन तिमाहियों के लिए आयात की स्थिति निम्नवत है जो अचानक, तीव्र और भारी वृद्धि प्रदर्शित नहीं करता है।

अवधि	2014-15 (पहली तिमाही)	2014-15 (दूसरी तिमाही)	2014-15 (तीसरी तिमाही)
आयात (एमटी)	25047	22416	25639
अनुक्रमित	100	89	102

21. उपर्युक्त के मद्देनजर संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान आयातों में हुई वृद्धि को अचानक, तीव्र तथा भारी वृद्धि नहीं माना जा सकता है।

#### उत्पादन के संबंध में आयात

22. जांच की संपूर्ण अवधि के दौरान भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में घरेलू उद्योग के उत्पादन के संगत रूप में कमी आई है। कुल उत्पादन के संबंध में आयात जो वर्ष 2011-12 में 78 प्रतिशत थे बढ़कर वर्ष 2012-13 में 85 प्रतिशत हो गए। इसके अतिरिक्त, उत्पादन के संबंध में आयात जो वर्ष 2012-13 में 85 प्रतिशत थे घटकर वर्ष 2013-14 में 74 प्रतिशत रह गए।

वित्तीय वर्ष	कुल आयात (एमटी)	अखिल भारतीय उत्पादन (एमटी)	उत्पादन के संबंध में आयातों का प्रतिशत
2011-12	62,167	79,857	78
2012-13	82,414	97,140	85
2013-14	80,124	108,829	74
2014-15 (वार्षिकीकृत)	97,469	114,117	85

23. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि जांच की अवधि के दौरान आयातों में समग्र रूप से या घरेलू उत्पादन के संगत रूप में अचानक तीव्र और भारी वृद्धि नहीं हुई है।

#### ख. गंभीर क्षति एवं गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण

24. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 8बी की उपधारा 6(सी) में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :

*"गंभीर क्षति" से आशय उस क्षति से है जिससे घरेलू उद्योग का समग्र ह्रास हुआ हो।*

25. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 8बी की उपधारा 6(डी) में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:

*"गंभीर क्षति की चुनौती" का आशय स्पष्ट एवं आसन्न खतरे से है।*

26. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 8 के अनुबंध के पैराग्राफ 1 में निम्नलिखित प्रावधान है :

*"यह निर्धारण करने में कि क्या संवर्धित आयातों ने घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित की है अथवा गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती उत्पन्न कर दी है तो महानिदेशक उन सभी संगत कारकों का उद्देश्यपरक एवं परिभाषात्मक प्रकृति का मूल्यांकन करेंगे जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, इनमें संवर्धित वस्तु के आयातों में संगत एवं समग्र रूप से तीव्र की दर एवं राशि, संवर्धित आयातों द्वारा घरेलू बाजार पर किए गए कब्जे की हिस्सेदारी, बिक्री के स्तर में परिवर्तन, उत्पादन, उत्पादकता क्षमता आयोग, लाभ एवं हानि तथा रोजगार शामिल है।*

27. तदनुसार, गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति का विश्लेषण करने के लिए उन सभी कारकों की जांच की गई जिनका उल्लेख नियमावली में किया गया है, इसके अलावा गंभीर क्षति कारित करने तथा गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती को निर्धारित करने के लिए संगत पाए गए अन्य कारकों पर भी विचार किया गया। गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन उन सभी संगत कारकों के आलोक में किया गया जिनका घरेलू उद्योग पर प्रभाव पड़ता है :

क. **उत्पादन** : जैसाकि अधोलिखित तालिका से देखा जा सकता है, घरेलू उद्योग का उत्पादन जो वर्ष 2011-12 में 67876 एमटी था बढ़कर वर्ष 2013-14 में बढ़कर 94929 एमटी हो गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014-15 (वार्षिकीकृत) के दौरान आवेदक का उत्पादन बढ़कर 100217 एमटी हो गया।

वित्तीय वर्ष/ तिमाही	कुल आयात (एमटी)	उत्पादन (एमटी)	घरेलू बिक्री (एमटी)	कुल मांग (एमटी)	बाजार हिस्सा	
					आयात	घरेलू उद्योग
2011-12	62,167	<b>67,876</b>	<b>63,729</b>	138,292	45	46
2012-13	82,414	<b>83,240</b>	<b>75,391</b>	172,190	48	44
2013-14	80,124	<b>94,929</b>	<b>81,344</b>	176,048	46	46
2014-15 (दिसम्बर, 2014 तक)	73,102	75,163	68,801	151,773	48	45
<b>2014-15 (वार्षिकीकृत)</b>	97,469	100,217	91,735	202,363	48	45

ख. **बिक्री के स्तर में परिवर्तन** : उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री जो वर्ष 2011-12 में 63729 एमटी थी, बढ़कर वर्ष 2013-14 में 81344 एमटी हो गई। इसके अतिरिक्त, आवेदक की बिक्री वर्ष 2014-15 (वार्षिकीकृत) के दौरान 91735 एमटी हो गई।

ग. **बाजार हिस्सा** : उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाता है कि आयातों का बाजार हिस्सा जो वर्ष 2011-12 में 45 प्रतिशत था बढ़कर वर्ष 2013-14 में 46 प्रतिशत हो गया, जबकि उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा भी 46 प्रतिशत ही बना रहा। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014-15 (वार्षिकीकृत) के दौरान घरेलू उत्पादों का बाजार हिस्सा घटकर 45 प्रतिशत हो गया और आयातों का बाजार हिस्सा बढ़कर 48 प्रतिशत हो गया।

घ. **क्षमता उपयोग** : चूंकि आवेदक के पास इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए समर्पित क्षमता नहीं है, इसलिए सभी सीरीज के लिए कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के लिए क्षमता उद्योग का निर्धारण करने के लिए लिया गया है। घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता वर्ष 2011-12 में 61 प्रतिशत थी बढ़कर वर्ष 2014-15 (वार्षिकीकृत) में 66 प्रतिशत हो गई, जैसा कि अधोलिखित तालिका से देखा जा सकता है :

वित्तीय वर्ष/ तिमाही	समग्र रूप में सीआर का उत्पादन (एमटी)	सीआर की संस्थापिकता समग्र रूप से (एमटी)	क्षमता आयोग (%)
2011-12	262275	427500	61
2012-13	364855	765000	48
2013-14	437800	765000	57
2014-15 (Up to Dec, 14)	376513	573750	66
<b>2014- 15(वार्षिकीकृत)</b>	<b>502017</b>	765000	66

ड. **रोजगार और उत्पादकता** : क्षति अवधि के दौरान रोजगार और उत्पादकता में वृद्धि हुई है जैसाकि अधोलिखित तालिका से देखा जा सकता है :

वित्तीय वर्ष/ तिमाही	उत्पादकता (एमटी/प्रति दिन)	रोजगार (संख्या)
2011-12	107	2445
2012-13	140	2599
2013-14	166	2630

च. **लाभ एवं हानि (अनुक्रमित) :** घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में जांच की अवधि के दौरान कमी हुई है। यह अधोलिखित तालिका से स्पष्ट है :

वित्तीय वर्ष	बिक्री लागत	बिक्री कीमत	लाभप्रदता	लगाई गई पूंजी पर प्रतिलाभ
	रुपए/एमटी	रुपए/एमटी	(रुपए/एमटी)	(%)
2011-12	100	98	-2	100
2012-13	106	100	-6	-18
2013-14	119	101	-18	-267
2014-15 (पहली तिमाही)	122	104	-18	-309

तथापि, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट (करोड़ रुपए में) (विवरण अधोलिखित है) घरेलू उद्योग समग्र रूप से कंपनी में प्रचालन लाभ दर्शा रहा है परंतु मूल्यहास एवं वित्तीय व्यय के कारण उसे क्षति हुई है।

	मार्च, 11	मार्च, 12	मार्च, 13	मार्च, 14	सितम्बर, 14
प्रचालन लाभ	1081	904	615	886	554
वित्तीय व्यय	389	517	990	1235	684
मूल्यहास	356	409	701	688	257
विद्युत एवं ईंधन	560	646	1235	1272	728
शुद्ध लाभ/घाटा	318	-104	-821	-1390	-366

कुछ हितवत्र पक्षकारों ने यह आपत्ति जताई कि मूल्यहास प्रभारों और वित्तीय प्रभारों में वृद्धि होने के कारण घरेलू उद्योग को भारी क्षति हुई। तदनुसार, घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की नियत लागत में वर्ष 2011-12 से लगातार वृद्धि हो रही है। नियत लागत में यह वृद्धि घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन में प्रक्षेपित लाभप्रदता में प्रपाती गिरावट के अनुरूप है। यह भी प्रेक्षण किया गया है कि वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान मूल्यहास प्रभारों और वित्तीय प्रभारों में वृद्धि होने से घरेलू उद्योग को भारी घाटा हुआ और तद्वारा दोनों के बीच सकारात्मक सह-संबंध है। अतः, अपनी लाभप्रदता में गिरावट के लिए आयातों को दोषी ठहरना ऐसी स्थिति में तर्कसंगत नहीं है जब वर्ष 2012-13 और 2013-14 में आयातों की मात्रा में वास्तव में गिरावट आई है। यह दर्शाता है कि कुछ अन्य कारक भी हैं जो घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहे हैं जैसे असामान्य रूप से उच्च मूल्यहास और वित्तीय प्रभार। यह निष्कर्षात्मक रूप से दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को क्षति के लिए आयात नहीं बल्कि कुछ अन्य कारक उत्तरदायी हैं। इसलिए, वर्तमान जांच में कारणात्मक का विश्लेषण असफल हो जाता है।

#### छ. अन्य महत्वपूर्ण कारक

(i) **मालसूची :** मालसूची जो वर्ष 2013-14 में 4861 एमटी थी, कम होकर वर्ष 2014-15 (अप्रैल से दिसम्बर 14) में 4482 एमटी हो गई, जैसा कि अधोलिखित तालिका से देखा जा सकता है :

वित्तीय वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (अप्रैल से दिसम्बर 14)
मालसूची (एमटी)	1,959	1,549	4,861	4,482

(ii) **कीमत अधोरदन, निग्रहण/अवमंदन :** कीमत अधोरदन का परिकलन सीमाशुल्क 5 प्रतिशत की दर से (प्रभावी दर) लेकर और आयातों के सीआईएफ मूल्य पर शुल्क जोड़कर परिकलन किया है जो यह व्यक्त करता है कि कोई कीमत अधोरदन नहीं हुआ और आयातों की उतराई कीमत विचाराधीन उत्पाद की बिक्री कीमत से अधिक है। घरेलू एवं आयातित उत्पाद के बीच भारी कीमत अंतर है। आयातों की उतराई कीमत, बिक्री लागत, बिक्री कीमत निम्नलिखित है :

वर्ष 2011-12 के दौरान बिक्री लागत के संबंध में अनुक्रमित

	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (दिसम्बर 14 तक)
बिक्री लागत	रुपए/एमटी	100	106	119	प्रदान नहीं कराया गया
आयातों की उतराई कीमत	रुपए/एमटी	101	107	108	106
बिक्री कीमत	रुपए/एमटी	98	100	101	104
अधोरदन	%	-3	-7	-7	-2

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वर्ष 2012-13 की बिक्री कीमत की तुलना में 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो आयातों की उतराई कीमत में हुई वृद्धि (0.9 प्रतिशत) की तुलना में बिक्री लागत में (12 प्रतिशत) हुई वृद्धि से कम है। इस प्रकार आयात बाजारों में घरेलू उद्योग की कीमतों का निग्रहण नहीं कर रहे थे और अधोरदन ऋणात्मक है। इसके अतिरिक्त, कोई कीमत, निग्रहण नहीं हुआ क्योंकि जांच की अवधि के दौरान बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है।

(iii) **निर्यात :** अधोलिखित तालिका से यह देखा जा सकता है कि उत्पादन के संबंध में वर्ष 2011-12 में 4 प्रतिशत की और वर्ष 2013-14 में 8 प्रतिशत की अर्थात् 4 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

वित्तीय वर्ष/तिमाही	उत्पादन (एमटी)	निर्यात (एमटी)	उत्पाद के संबंध में निर्यात का प्रतिशत
2011-12	67876	2422	4
2012-13	83240	5331	6
2013-14	94929	7907	8
2014-15 (दिसम्बर 14 तक)	75163	5611	7
<b>2014-15 (वार्षिकीकृत)</b>	100217	<b>7481</b>	7

28. उपर्युक्त विश्लेषण से यह देखा जाता है कि संपूर्ण वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान विचाराधीन उत्पाद के आयातों में उत्पादन के संगत रूप में तथा समग्र रूप में वृद्धि नहीं हुई है। चूंकि घरेलू उद्योग के निष्पादन में कई पैरामीटरों में सुधार प्रदर्शित हुआ है, यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को आयातों के परिणामस्वरूप गंभीर क्षति नहीं हुई। वर्तमान मामले में, घरेलू उद्योग के निष्पादन में नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अधिकांश क्षति पैरामीटरों में सुधार हुआ है; जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है। जांच की अवधि के दौरान उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग, उत्पादकता में सुधार हुआ है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में कमी आई है। संपूर्ण अवधि के दौरान कीमत अधोरदन ऋणात्मक रहा। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि के दौरान उच्चतर उतराई कीमत को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत वृद्धि कर सकता था।

29. इस प्रकार, सभी संगत कारकों जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है को ध्यान में रखकर घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन उसकी स्थिति में सुधार दर्शाता है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई और न ही गंभीर क्षति की कोई चुनौती उत्पन्न हुई।

#### ज. संवर्धित आयातों और गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध

30. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 8 के अनुसार महानिदेशक (रक्षोपाय), अन्य बातों के साथ-साथ, इन नियमों के अनुबंध में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार घरेलू उद्योग को होने वाली गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण करना होगा।" इसके अतिरिक्त अनुबंध का पैराग्राफ 2 कथित संवर्धित आयातकों तथा गंभीर क्षति या गंभीर क्षति

की चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करना भी अपेक्षित होता है। नियम 8 के अनुबंध में पैराग्राफ 2 में निम्नलिखित प्रावधान है :

"पैराग्राफ (1) में उल्लिखित निर्धारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि, उद्देश्यपरक साक्ष्य के आधार पर, जांच से यह स्पष्ट नहीं होता है कि संबंधित वस्तु के संबंधित आयातों तथा घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध है। साथ ही, जब संबंधित आयातों के अलावा अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हो तो उस क्षति के लिए संबंधित आयातों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।"

31. कोरिया डेयरी पैनल ने "कारणात्मकता" का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित आधारभूत अधिगम निर्धारित किया है :

"अपना कारणात्मक संबंध आकलन करने में हमारा विचार है कि राष्ट्रीय प्राधिकारी को यह विश्लेषण करना और यह निर्धारित करना आवश्यक होता है कि क्या उद्योग में हुआ विकस, जिसे राष्ट्रीय प्राधिकारी ने गंभीर क्षति का प्रदर्शन करने के लिए विचार है, संबंधित आयातों के कारण कारित किया गया है। अपने कारणात्मक आकलन में राष्ट्रीय प्राधिकारी को उन सभी संगत कारकों का उद्देश्यपरक एवं परिमाणात्मक प्रकृति का मूल्यांकन करना होता है जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, यदि राष्ट्रीय प्राधिकारी ने संबंधित आयातों के अलावा कुछ अन्य ऐसे कारक अभिज्ञात कर लिए हों जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची हो तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि इन कारकों द्वारा कारित क्षति के लिए यह नहीं माना जाएगा कि वह क्षति संबंधित आयातों द्वारा कारित की गई है।

एक कारणात्मक संबंध स्थापित करने के लिए कोरिया को यह प्रदर्शित करना कि इसकी घरेलू उद्योग को क्षति संबंधित आयातों के कारण हुई है। दूसरे शब्दों में, कोरिया को यह प्रदर्शित करना पड़ा कि एसएमपीपी के आयातों द्वारा दुग्ध पावडर और अपरिष्कृत दुग्ध का उत्पादन करने वाली घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की स्थिति का विश्लेषण करने के उपरांत कोरियाई प्राधिकारियों की यह प्रतिबद्धता थी कि वह अन्य कारकों द्वारा कारित क्षति के लिए संबंधित आयातों को उत्तरदायी न ठहराएं।<sup>2</sup>

32. कारणात्मक का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उद्देश्यपरक एवं परिमाणात्मक प्रकृति के उन सभी संगत कारकों का मूल्यांकन किया गया जिनका घरेलू उद्योग की प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो यह कि आयातों में कोई उद्रेक नहीं हुआ और जांच की अवधि के दौरान उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग, उत्पादकता जैसे कारकों में सुधार हुआ। द्वितीयतः, जांच की अवधि के दौरान आयातों की उतराई, कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक है। इस प्रकार आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का बाजार में निग्रहण नहीं हो रहा था और कीमत अधोरदन ऋणात्मक है। अतः, ऐसे संकेत हैं कि घरेलू उद्योग को आयात कीमत के कारण क्षति नहीं हो रही है। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कमी आई परंतु वह कमी मूल्यहास प्रभारों, विद्युत और ईंधन प्रभारों और वित्तीय प्रभारों में वृद्धि के कारण हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट के लिए आयात उत्तरदायी नहीं हैं।

#### झ. समायोजन योजना

33. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 5(2)(बी) में "आयात प्रतिस्पर्धा के साथ सकारात्मक समायोजन करने के लिए बनाई गई योजना या किए जा रहे प्रयासों या दोनों" के संबंध में प्रस्तुतिकरण करना अपेक्षित होता है। इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 7.1 में प्रावधान है कि कोई सदस्य रक्षोपाय शुल्क का अनुप्रयोग समायोजन को सुलभ बनाने तथा गंभीर क्षति को रोकने अथवा उसका उपचार करने के लिए आवश्यकतानुसार कर सकता है।

34. निर्णयात्मक रक्षोपाय शुल्क का उद्देश्य घरेलू उत्पादकों को एक सीमित समयावधि प्रदान करना है जिसके अंदर वे अपना इस तरह पुनर्गठन कर सकें जिससे कि वे आयातों के साथ कारगर ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकें। सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8बी(4) तथा सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली 1997 के नियम 16(2) में ऐसे साधन का उपयोग करने का निषेध किया गया है तब ऐसे साक्ष्य हों कि घरेलू उद्योग समायोजन का प्रयास नहीं कर रहा है।

35. कुछ हितवद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि प्रदान की गई समायोजन योजना अधूरी है और आवेदक द्वारा अधिकांश सूचना को गोपनीय रखने का अनुरोध किया है।

36. इस मामले में घरेलू उत्पादकों ने निम्नलिखित समायोजन योजना निर्धारित की है :—

**क. संभारतंत्र लागत में कमी :** कच्चे माल की कीमत कुल लागत की लगभग 70 प्रतिशत होती है, इसलिए अंतर्ग्रस्त संभारतंत्रीय लागत में कमी का समग्र लागत ढांचे पर भारी प्रभाव पड़ेगा।

- (i) आयात कंटेनरों को निर्यात कंटेनरों में सम्परिवर्तित करना – कंटेनर त्रिकोणीयन
- (ii) लागत प्रभावी पत्तनों का प्रयोग
- (iii) कुल उतराई लागत से आधार पर शिपिंग लाइन्स का चयन
- (iv) संयंत्र में ट्रेलर्स के टर्न-एराउंड समय में कमी
- (v) अवरोधन एवं विलंब शुल्क में कमी के लिए पहल
- (vi) जाजपुर में संभारतंत्र पहल
- (vii) अन्य पहल

#### ख. प्रासेस लागत में बचत

- (i) स्टील मेल्ट शाप (एसएमएस) में लागत बचत
- (ii) हाट स्ट्रिप मिल (एचएसएम) में लागत बचत
- (iii) कोल्ड रोलिंग मिल (सीआरएम) में लागत बचत

**ग. प्रति यूनिट नियत लागत कम होना :** ओडिशा संयंत्र का रैम्प-अप नियत लागत/400 सीरीज के लिए एमटी में कमी होगी।

**घ. अधिप्रापण लागत में बचत :** लागत को कम करने के लिए पांच आयामी कार्यनीति जैसा कि विशेषज्ञ परामर्शदाता ने सुझाव दिया था।

<sup>2</sup> कोरिया पर पैनल रिपोर्ट – डेयरी, पैरा 7.89-7.90

- (i) **वैकल्पिक कच्चे माल का प्रयोग :** शुद्ध निकिल की तुलना में मेल्टिंग ग्रेड निकिल और यूटीलिटी निकिल का वैकल्पिक रूप में प्रयोग क्योंकि इन मदों के आयातों पर और थ्रिडेड एचएमएस, एलएसएस वेल्स और इन्सिनरेटेड स्क्रैप जैसे एमएस स्क्रैप के रूप में विकल्प का प्रयोग डिस्काउंट मिलता है।
- (ii) **नए आपूर्तिकर्ताओं को विकसित करना :** फेरो निकिल और डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन जैसे कच्चे माल के लिए नए आपूर्तिकर्ता की पहचान की गई।
- (iii) एसएस स्क्रैल अधिप्रापण के क्षेत्र में कार्यशील पूंजी का अधिक कारगर प्रबंधन
- (iv) फ्लक्स अधिप्रापण के क्षेत्र में सुधार की पहल
- (v) कच्चे माल की मिक्स का अनुकूलन

#### ड. ओडिशा फेज 1 से लागत कमी करने की पहल

- (i) चरण-2 में बेहतर क्षमता उपयोग से फेरो क्रोम और विद्युत के लिए बेहतर मांग होगी।
- (ii) चरण-1 में सृजित कोक ओवन गैस का चरण-2 में प्रोपेन के लिए प्रतिस्थायी के रूप में प्रयोग किया जाता है।

37. मैं यह पाता हूँ कि रूझान विनिर्माण लागत और बिक्री लागत में कमी पर है। तथापि, परिपोषी साक्ष्य के अभाव में समायोजन योजना भरोसे मंद नहीं है।

#### व. अनपेक्षित विकास

38. घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि महानिदेशक रक्षोपाय पर कोई ऐसा अभिव्यक्त दायित्व/अपेक्षा नहीं है कि वे अनपेक्षित परिस्थितियों का विश्लेषण करें क्योंकि भारतीय विधि में अथवा जीएटीटी में अथवा रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार में ऐसा कोई विशिष्ट मार्गदर्शन या क्रियापद्धति नहीं है जिसका अनुपालन अनपेक्षित विकास का विश्लेषण करते समय किया जाना चाहिए। इस संबंध में, मैं पाता हूँ कि गट, 94 के अनुच्छेद-XIX में प्रावधान किया गया है कि गंभीर क्षति अनपेक्षित विकास के परिणामस्वरूप होनी चाहिए।

39. गट 1994 के अनुच्छेद- XIX में निम्नलिखित उल्लेख है :

1. (क) यदि अनपेक्षित विकास के परिणामस्वरूप और इस करार के अंतर्गत किसी संविदाकारी पक्षकार द्वारा प्रशुल्क रियायतों सहित सौंपे गए किसी दायित्व के प्रभावीस्वरूप उस संविदाकारी पक्षकार के भूभाग से किसी उत्पाद का आयात इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में या ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत किया जाता है जिससे उस भूभाग के समान या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पाद के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति कारित होती है अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो जाती है तो संविदाकारी पक्षकार ऐसे उत्पाद के संबंध में ऐसी सीमा तक अथवा ऐसे समय तक के लिए जो उस क्षति से बचने अथवा उसका उपचार करने के लिए आवश्यक हो, उस प्रतिबद्धता को समग्र रूप से या उसके किसी भाग को समाप्त करने अथवा रियायत को वापस लेने या उसमें कोई संशोधन करने के लिए स्वतंत्र होगा।"

40. अर्जेंटीना-फुटवियर (ई सी मामला) में अपीलीय निकाय ने धारित किया कि पदबंध अनपेक्षित विकास का आशय उस विकास से है जो अप्रत्याशित हो। "अनपेक्षित विकास" यह अपेक्षा करता है कि वह विकास जिसके कारण किसी उत्पाद का इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में निर्यात किया जा रहा हो कि घरेलू उत्पादकों को अप्रत्याशित गंभीर क्षति होने लगी हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो। कोरिया-डेयरी मामले में अपीलीय निकाय ने यह धारित किया कि अनपेक्षित विकास वह विकास होता है जो अनपेक्षित न हो या किसी सदस्य द्वारा कोई दायित्व लिए जाने के समय प्रत्याशित न हो।

41. अर्जेंटीना-फुटवियर (ईसी) मामले में अपीलीय निकाय ने यह धारित किया कि "अनपेक्षित विकास" की जरूरत रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए कोई पृथक "शर्त" स्थापित नहीं करता है, परंतु यह केवल परिस्थितियों के एक निश्चित "समूह" को वर्णित करता है।

42. घरेलू उद्योग की निम्नलिखित अनपेक्षित विकास का प्रस्तुतिकरण किया है जिसके कारण आयातों में वृद्धि हुई है :

- (क) वर्ष 2010 में संपूर्ण विश्व में मांग एवं आपूर्ति में भारी अंतर
- (ख) पश्चिमी यूरोप में भारी मांग-आपूर्ति में अंतर
- (ग) जापान में भारी मांग-आपूर्ति में अंतर
- (घ) कोरिया में घरेलू मांग न होते हुए भी कोरिया द्वारा अपनी क्षमता में भारी वृद्धि करना। भारत सरकार द्वारा कोरिया, जापान जैसे विभिन्न देशों और आशियान देशों के साथ किए गए एफटीए/पीटीए।
- (ङ) भारत में पाटनरोधी शुल्क लगे होने के बावजूद आयातों की निरंतरता
- (च) विभिन्न बड़े निर्यातकों के विरुद्ध व्यापार उपचारों का अधिरोपण।

43. यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि भारत में आयातों में वृद्धि तथा वैश्विक मांग-आपूर्ति अंतर के बीच कोई कारणात्मक संबंध है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को इस तथ्य की निश्चयात्मक रूप से जानकारी थी कि यूरोप और कोरिया में क्षमताओं में वृद्धि हुई है क्योंकि उन्होंने वर्ष 2010 में ही इन परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए डीजीएडी प्राधिकारियों के समक्ष पाटनरोधी शुल्क के लिए आवेदन किया था और इसलिए पश्चिमी यूरोप और कोरिया में मांग-आपूर्ति अंतर की घरेलू उद्योग को पूर्ण जानकारी थी और इसलिए कथित विकास ऐसा नहीं है जो अनपेक्षित हो। जापान में मांग-आपूर्ति अंतर के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य संपूर्ण कोल्ड रोलड स्टील के बारे में हैं, न कि 400 सीरीज की सीआरएसएस के लिए। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़ों से यह प्रेक्षण किया गया है कि इस विचाराधीन उत्पाद के संबंध में मांग-आपूर्ति में अंतर में अंतराष्ट्रीय रूप से वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप इस विचाराधीन उत्पाद के वैश्विक उत्पादकों की क्षमता में अभूतपूर्व एवं विषम वृद्धि हुई है। इसके कारण वैश्विक उत्पादकों को अपने माल को कम कीमत पर भी बेचने के लिए बाजारों की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कीमत के प्रति अत्यधिक संवेदनशील विशाल भारतीय बाजार विदेशी उत्पादकों के लिए एक विकल्प बन रही है, इसके परिणामस्वरूप आयातों में उद्रेक

आया। यह अनपेक्षित विकास बनता है परंतु इस विकास के कारण आयातों में अचानक, तीव्र और भारी वृद्धि नहीं हुई है जिससे कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को क्षति कारित हुई हो।

44. कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि एफटीए/पीटीए के अनुसरण में शुल्क की दरों में कमी होना न तो अनपेक्षित है और न ही अप्रत्याशित बल्कि यह तो एक सामान्य ज्ञान की बात है। मैं हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क से इस सीमा तक सहमत हूँ कि एफटीए के प्रावधानों में प्रशुल्क में कमी करने और उसके परिणामस्वरूप आयातों में वृद्धि होने की उम्मीद की गई थी।

45. घरेलू उद्योग का यह तर्क कि पाटनरोधी शुल्क मौजूद होने के बावजूद उसे क्षति होना जारी रही, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस समय पाटनरोधी प्राधिकारी द्वारा उनकी दिनांक 17.04.2014 की जांच शुरुआत अधिसूचना के तहत पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता की जरूरत के लिए एक समीक्षा का आयोजन सभी सीरीज के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोलड फ्लैट उत्पादों के लिए की जा रही है और यदि घरेलू उद्योग को वास्तव में क्षति हुई होगी तो पाटनरोधी प्राधिकारी उस समस्या का समाधान करेंगे।

46. इस प्रकार यह देखा जाता है कि वर्तमान मामले में, यदि यह प्रकल्पना की जाती है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए यह तर्क कि आयातों में वृद्धि अनपेक्षित कारणों से हुई है परंतु उसे आयातों में उद्रेक के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह आयात अचानक तीव्र और बहुत अधिक मात्रा में नहीं हुए तथा घरेलू उद्योग को कोई क्षति आयातों के कारण नहीं हो रही है।

## ट. जनहित

47. केवल घरेलू उत्पादकों के हित को ही जनहित नहीं कहा जा सकता है। यदि यह मान भी लिया जाए कि विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से घरेलू उत्पादकों के हित संरक्षित होंगे तो भी उसे जनहित नहीं माना जा सकता है। घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई क्षति ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च मूल्यहास प्रभार विद्युत एवं ईंधन प्रभार तथा वित्त प्रभार के कारण हुई। सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 8 के अनुबंध के पैराग्राफ 2 में उल्लेख है कि जब घरेलू उद्योग को संवर्धित आयातों के अन्य कारक क्षति कारित कर रहे हों तो इस क्षति के लिए संवर्धित आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि संवर्धित आयात (जो अचानक, तीव्र एवं अधिक नहीं है) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट के लिए उत्तरदायी नहीं है, मेरा यह विचार है कि इन परिस्थितियों में रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में नहीं होगा।

## ठ. निष्कर्ष

48. इस विचाराधीन उत्पाद के आयात समग्र रूप में बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रहे हैं परंतु वह वृद्धि जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि अचानक, तीव्र और बहुत अधिक नहीं है क्योंकि वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान आयातों में 20247 एमटी की वृद्धि हुई थी परंतु इसमें 2012-13 और 2013-14 के दौरान कमी होकर यह आयात 2290 एमटी रह गए। इसका आशय यह है कि आयातों की दर में वास्तव में कमी हुई। अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जांच की अवधि के दौरान आयातों में समग्र रूप से तथा घरेलू उत्पादन के संगत रूप से दोनों तरह से नहीं हुई है।

49. जांच की अवधि के दौरान उत्पादन, घरेलू बिक्री क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है। तथापि, घरेलू उद्योग नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक प्रतिलाभ के कारण वास्तव में घाटा उठा रहा है। घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की नियत लागत में वर्ष 2011-12 से निरंतर वृद्धि हो रही है। नियत लागत में यह वृद्धि घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन में प्रेक्षित लाभप्रदता में प्रपाती गिरावट के अनुरूप है। घरेलू उद्योग की मालसूची में दिसम्बर 2014 में मामूली सा सुधार हुआ। संपूर्ण अवधि के दौरान कीमत अधोरदन ऋणात्मक बनी रही। इस प्रकार, घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत कारकों के आलोक में घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार हुआ है और उन्हें प्रचालनात्मक लाभ मिल रहा है, और कुछ अन्य ऐसे कारक हैं जो घरेलू उद्योग को निवल क्षति पहुंचा रहे हैं जैसे असामान्य रूप से उच्च मूल्यहास और वित्तीय प्रभार। निष्कर्षात्मक रूप से यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की क्षति के लिए आयात नहीं बल्कि कुछ अन्य कारक हैं जो इसके लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए, वर्तमान जांच में कारणात्मक का विश्लेषण असफल हो जाता है।

50. इस प्रकार, घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की कोई चुनौती उत्पन्न नहीं हुई है और इसलिए उसे रक्षोपाय विधि के अंतर्गत किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

## ड. सिफारिश

51. ऊपर की गई विस्तृत चर्चा और निकाले गए निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर एतद्वारा रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश नहीं की जाती है और इस मामले में यह जांच समाप्त की जाती है।

[ फा. सं. डी-22011/17/2014 ]

आर. के. सिंगला, महानिदेशक

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****[DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARDS (CUSTOMS & CENTRAL EXCISE)]****NOTIFICATION**New Delhi, the 23<sup>rd</sup> March, 2015**Subject:- Safeguard investigation concerning imports of Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel of 400 series – Final Findings****G.S.R. 219(E).**— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguards Duty), Rules, 1997 thereof;**I. Procedure**

1. An application has been filed before me under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 by M/s. Jindal Stainless Ltd., Jindal Centre, 12 Bhikaji Cama place, New Delhi-110066 for imposition of Safeguard Duty on imports of “Cold Rolled Flat Product of Stainless Steel of chromium type, 400 Series encompassing all Martensitic and Ferritic grades as per ASTM A 240/A 240M and equivalent/comparable specifications in other standards like UNS, IS, Chinese DIN, JIS, BIS, EN, etc”., excluding (i) width 1700 MM and above and (ii) JBS (Jindal Blade Steel) grade & its equivalent” (referred hereafter as Product under consideration (PUC)) into India to protect the domestic producer of Cold Rolled Flat Product of Stainless Steel of 400 Series against serious injury/threat of serious injury caused by the increased imports of Cold Rolled Flat Product of Stainless Steel of 400 Series into India.
2. In order to satisfy the requirements under Rule 5 of the said Safeguard Rules, the information presented by the applicant was got verified by on-site visits to the plants of the domestic producers to the extent considered necessary. On being satisfied that the requirements of the said Rule 5 were met, the Notice of Initiation of Safeguard investigation concerning imports of PUC into India was issued under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 on 19<sup>th</sup> September, 2014 and was published in the Gazette of India Extraordinary on the same day.
3. A copy of the Notice of Initiation dated 19<sup>th</sup> September, 2014 along with copy of non-confidential version of the application filed by the Domestic Industry were forwarded to the Central Government, in the Ministry of Commerce and other Ministries concerned, Governments of major exporting countries through their Embassies in India, and the Interested Parties mentioned under annexure 6 to 9 to the application filed by the domestic industry including domestic industry, in accordance with Rule 6(2) and 6(3) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997.
4. Questionnaires were sent to the known exporters, known importers/users and other interested parties as per the information available, with request to make their views known in writing within 30 days of the Notice of Initiation.
5. Requests to consider them as interested parties were received from the following parties and same has been accepted:-
  - (a) Vietnam Competition Authority (‘VCA’), Ministry of Industry and Trade, (on behalf of Government of the Socialist Republic of Vietnam) 25 Ngo Quyen St., Hoan Kiem Dist., Hanoi City, Vietnam.
  - (b) Japan Chamber of Commerce and Industry in India (JCCII), Flat No. 106, Nilgiri Apartments, 9, Barakhamba Road, New Delhi-110001.
  - (c) Government of Japan, Embassy of Japan, 50 G, Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi-110021.
  - (d) The Trade Representation of the Russian Federation in the Republic of India, Block 50-E, Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021.
  - (e) Ministry of Economy-Industrial Affairs, Department-Directorate of Anti-Dumping, P.O. Box 3625, Dubai, United Arab Emiraes.
  - (f) Goshi India Auto Parts Pvt. Ltd., 363-364, Sector-3, Industrial Growth Centre, Bawal, Phase-II, Distt. Rewari, Haryana-123501, India.
  - (g) ELP Advocates & Solicitors, 1502 Dalamal Towers, Nariman Point, Mumbai-400021 on behalf of M/s. Outokumpu Oyj.
  - (h) Metal Ore Corporation India Pvt. Ltd., Sood Tower, 1<sup>st</sup> Floor, 25 Barakhamba Road, New Delhi-110001 through Lakshmi Kumaran & Sridharan, Advocates, 5 Link Road, Jungpura Extension, New Delhi-110014.



- (i) Metal & Stainless Steel Merchant's Association (MSSMA), 63 Jamnadas Building, Ground Floor, 10<sup>th</sup> Khetawadi Lane, Mumbai-400004 through Lakshmi Kumaran & Sridharan, Advocates, 5 Link Road, Jungpura Extension, New Delhi-110014
  - (j) Japan Stainless Steel Association (JSSA), 3.2.10, Nihonbashi- Kayabacho, Chou-ku, Tokyo, 103-0025 Japan.
  - (k) Special Steel Association of Japan (SSAJ), Tekko Kaikan Building 3.2.10, Nihonbashi – Kayabacho, Chou-Ku, Tokyo, 103-0025.
  - (l) JFE Steel Corporation , Hibiya Kokusai Building, 2-3, Uchisaiwai-cho 2- chome Chiyoda-ku, Tokyo-100-0011, Japan
  - (m) Nisshin Steel CO. LTD., Shin Kokusai Building, 4-1 , Marunouchi 3 Chome, Tiyoda-ku, Tokyo, 100-8366 Japan.
  - (n) Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel Corporation, 2-6-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan.
  - (o) Maruti Suzuki India Limited, Palam Gurgaon Road, Gurgaon -122015 Haryana.
  - (p) Maruichi Kuma Steel Tube Pvt. Ltd., Plot No. 27, Sec 2-A, IMT- Maneser, Gurgaon-122050 (HR)
  - (q) Hero Moto Corp Ltd., 37 Km Stone, Delhi-Jaipur Highway , Sector-33 Gurgaon-122001 (Haryana).
  - (r) M/s Posco VST, 319, Nhon Trac 1 Industrial Zone, Dong Nai province Vietnam.
  - (s) M/s Posco , 1 Keodong-dong , Nam-gu, Pohang-si, Kyongsangbuk-do, 790-785 Republic of Korea. (authorizing POSCO South Asia No. 105, First Floor , Park Centra Building , Sector -30, Gurgaon-122001, Haryana to represent them)
  - (t) Japan Iron and Steel Federation, 3.2.10 , Nihonbashi- Kayabacho, Chou-ku, Tokyo, 103-0025 Japan.
  - (u) PT Jindal Stainless Indonesia, Kawasan Industry Maspion V, Desa Sukomulyo, Manyar Gresik 61151, Jawa Timur- Indonesia.
  - (v) Posco- Thinox Public Company Limited , 31/F Unit 3101-3 CRC Tower, All Seasons Place, 87/2 Wireless Road, Lumpini, Parhumwan Bangkok 10330, Thailand.
  - (w) Ministry of International Trade and Industry Malasia, (MITI), Level 14, Block 8 , Government Offices Complex, Jalan Duta , 50622 Kualalumpur, Malasia .
  - (x) Wirana Pte. Ltd., 20 Collyer Quay, #09-02, Singapore 049319 .
  - (y) PT. Jindal Stainless Indonesia, Kawansan Industry Maspion V, Desa Sukomulyo, Manyar Gresik 61151, Jawa Timur, Indonesia.
6. All the views expressed by the interested parties have been taken into account in making appropriate determination. The non confidential information received or acquired has been kept in the public file.

## II. **Views of the Interested Parties (Post Notice of Initiation) :**

### A. Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation:-

During the period of investigation from 2011 to 2014 the import of goods falling under sub-headings 72193112, 72193111, 72193210, 72193310, 72193410, 72193510, 72202021, 72209021 of the Customs Tariff Act, 1975 from the Russian Federation to India was 5.05 tons in 2011, 3.17 tons in 2012, 5.16 tons in 2013 and 5.98 tons in 2014. Accordingly share of these products from the Russian Federation to India is very small and did not exceed 0.01 percent of the total Indian import of these goods and did not cause deep damage to Indian industry.

### B. Vietnam Competition Authority ("VCA"), Govt of Vietnam

- (a) Production, sales of the domestic industry, sales of other India producers, productivity, employment and installed capacity has increased and has a trend of development. Therefore, it can be seen that the domestic industry has not suffered or threatened to suffer serious injury.
- (b) Notice of initiation does not contain any explanation on the causal link between increased imports and the serious injury.
- (c) Increase of imported PUC is due to the increase of demand. In particular, the fact that domestic capacity not meeting the domestic consumption.
- (d) Vietnam exported small volume of the PUC into India as per the export statistics of the PUC from the Customs Authority of Vietnam.

### C. Govt. of Indonesia

Imports from Indonesia increased by 0.13% in 2013-14 as compared to that of 2012-13. Thus imports from Indonesia are less than 3% and does not cause injury for the Indian domestic industry as under Article 9.1 WTO AD Agreement.

### D. Turkey Govt.

According to International Trade Centre (Trade Map) statistics, Turkey's individual share in India's cold rolled flat products of stainless steel imports, in terms of quantity and even in 6-digit HS Code, represents a ratio below 3 % which should be interpreted under the provisions of Article 9.1 of the Agreement on Safeguards.

## E. M/S Wirana Pte.Ltd. (exporter Singapore)

- (a) The product under consideration is wider in range (with various grades & sizes) and requires modifying/narrowing down to a particular grade for the purpose of adequate and appropriate injury analysis. PUC includes products of sizes which are neither produced by the petitioner nor produced by any other manufacturer in India. Imports of grade 409 constitute 80-90% of total import in 400 series grades.
- (b) The scope of investigation should be restricted to the individual grades (Example 409,410S,etc),which are produced & sold by the petitioner
- (c) In Cold Rolled 400 series grades, it is not just the chemical composition of the material or the size but the finish of the material & thickness tolerance which is most important. If the safeguard duty is applied without detailed investigation. It will cause Serious Injury to automobile sector In particular.
- (d) Considering the price of product, the impact of freight due to geographical situation is huge. Petitioner has plant in North India & East India. Majority of manufactures are based around Pune, Maharashtra. Petitioner is charging Freight as follows:  
Hlsar Plant to Pune :INR 2808/mt )USD 46.80/mt\*  
Odisha Plant to Pune: :INR 4206/mt IUSO 70.10/mt\*  
Therefore Petitioner is suffering from financial losses INR -957/mt in 2014-15 (Q1) not due to more Imports but because of Transportation Cost.
- (e) Sale of the producer is continuously increasing & from 2011-12. In year 2014-14 sale was 81,344 & in 2014-15 it has increased to 89,672. Net increase of +10.23% in sales in. Also of import with respect to production went down from 90% to 81% in year 2013-14.
- (f) The increase in imports is also due to the domestic utensils manufactures switching to grade 430 BA/28, etc for making utensils earlier they were useful grade 200/201, etc. produced by the petitioner.
- (g) The petitioner is already enjoying huge subsidy as import duty on stainless steel scrap is nil, which comprise of approx. 70% cost of production. Traders pay Import duty of 7.50% on import of finished products.
- (h) Antidumping duty is already in place on Cold rolled 400 series grades to protect the domestic industry.
- (i) Honorable Supreme Court of India has recently cancelled the coal blocks allotted to the petitioner. Therefore although the petitioner has the installed production capacity, they will find it difficult to use their installed production capacity due to lack of resources to produce material in material in near future.
- (j) There are many traders/Importers that solely depend on this trade to earn their livelihood. Many small traders/Importers/manufactures in India who will be affected by this safeguard duty don't have resources to collect data & to reply to this notification.
- (k) All grades in 400 series are not Imported In large quantity. Therefore petitioner should be very specific & clear in giving details of the grades that are affecting it's trade.

F. Vivek Metals

Vivek Metals is an importer & supplier of 400 series stainless steel to Automobiles, solar panels, kitchen equipments and decoration industries Manufacturers who uses only bright finish ( mirror finish ) which nobody makes in India including Jindal, SAIL etc.

G. DGS Associates-Posco Vietnam

Vietnam individually is below 1%, hence negligible. The sum of percentage of imports of the subject product from the developing countries having import share of less than 3% is also not more than 9%.

**H. DGS Associates-Posco Thainox**

The average percentage of imports from Thailand individually is approximately 1%, hence negligible.

**I. M/S PT Jindal Stainless Indonesia:-**

The import of Cold rolled flat product of Stainless Steel of 400 series from Indonesia is almost "Zero" and even in the year 2013-2014 the import from Indonesia has decreased by 77%. The import in 2013- 2014 is just 0.13% of the total import of 400 series received by India whereas to put a safeguard on any country must export minimum of 3% and hence Indonesia never come under this category as per the above data.

**J. M/S POSCO-Korea**

1. More than 99% of the PUC exported to India were finally consumed by automobile or automotive components producers. Since 400 series of stainless steel products are widely used in producing both cold and hot components of automobile exhaust systems, they require the application of more comprehensive and responsive technologies
2. POSCO also requests DG (safeguards) to exclude some grades of cold rolled stainless 400 series not produced by the domestic industry.
  - (a) 429EM: Heat resisting stainless steel. Si, Ti, Mn and Cu are added while the content of C and N is lowered. It has great high temperature strength, oxidation resistance, formability and weldability. It is mainly used for heat resisting parts, such as exhaust manifold and front pipe • Equivalent grades : POS429EM
  - (b) 430JIL: Cu and Nb are added to 430 stainless steel, which significantly increase corrosion resistance, drawability, weldability and high temperature oxidation resistance. It is mainly used for automotive exhaust systems, home appliances and exterior materials for building. Equivalent grades : STS430JIL, SUS430JIL, EN 1.4511 and etc.
  - (c) 444 : Higher Cr and Mo contents bring great inter-granular corrosion resistance and SCC resistance. It is mainly used for hot water system, heat exchanger and auto exhaust system

\* Equivalent grades : STS444, SUS444, ASTM 444, EN 1.4521 and etc

- (d) 445NF : Higher Cr content increases corrosion resistance and weldability. It is mainly used for elevator, household utensils and electronic components.

\*Equivalent grades : POS445NF

- (e) 446M : Superior in corrosion resistance to 445 stainless steel with higher Cr content. It is mainly used for roof and exterior building materials in coastal and industrial areas.

\*Equivalent grades : POS446M

3. POSCO has no surplus capacity even after the completion of capacity enhancement.
4. POSCO's stainless department has started its global expansion in Korea, Thailand, Vietnam and other countries from 2008 to 2011 to support our long-term global customer's world-wide supply chain, enhance our quality management and optimize productivity. India is not part of the main market for POSCO and its global subsidiaries.
5. Petitioner cited unreliable data when calculating the capacity utilization and Petitioner's data is far different from the data provided in JSL annual reports. Therefore, POSCO recalculated Petitioner's capacity utilization by putting together publicly available data. Their capacity utilization decreased to 51.95% in 2011-12 in view of excessive capacity increase. With production process normalizing, the capacity utilization improved again and increased to 85.33% during 2013-14.
6. Injury is not due to imports of subject goods into India but due to Petitioner's own internal reasons. These may be summarized up as follows:
  - (i) New plant set up in Odisha -leading to high startup costs
  - (ii) Excess capacity leading to extra inventory and sales at lower price
7. Petitioner is taking advantage of tariff barrier in addition to Anti-dumping measures

**K. European Commission**

1. Imports increased by around 30% between 2011-12 and 2012-13 and stabilized thereafter. In the most recent period 2014-15, figures have been annualised on the basis of data from the first quarter and therefore, it is not sure if that trend will really be confined once data of the full year is available.

2. Production and sales of the domestic industry increased by over 40% over the period. In view of increase in demand by 49%, the industry's market share slightly decreased by less than 2%.
3. Regarding profit/losses, the industry was already loss making at the beginning of the period (2011-12) although AD measures were in force since 2010.
4. In view of the huge capacity increase, the capacity utilisation which was at a rather low 60% decreased by around 10 percentage points to 49%
5. Losses started to plummet in 2012-13, coinciding with the industry's capacity building. Import prices remained stable over the period analysed. They increased in 2013-14 and are at the end of the period back to their initial level.
6. Injury is on account of excessive capacity building starting from a loss making situation with AD measures already in force despite world overcapacity and decreasing demand.

**L. M/S Tirthankar Steel & Alloys India (P) Ltd., Shubhlaxmi Metal, Tubes Pvt. Ltd Pacific Metal Trading Co. and B.V.S Overseas, Ashwin Impex, Aadinath Metals and Ranflex Metals.**

1. M/S Jindal Stainless steel (holds 90% market share) is trying to use its Political and Financial Strength to make the Indian Industry handicap by creating a Monopoly.
2. Over the period they have only attempted to trouble the industry by worsening the situation by initiating unnecessary investigations and increasing Product scope which was earlier exempted or excluded.

**M. M/S Bahru Stainless Sdn Bhd, Malaysia:-**

During the recent period, imports of subject goods from Malaysia have been below the prescribed 3% de-minimis level and hence there is no legal basis to continue the present safeguard investigation against imports of subject goods from Malaysia

**N. All India Stainless Steel Industries Association:-**

1. Domestic Industry control nearly 85% of the production of the country. There was already a large Anti dumping duty on this materials during the period of investigation and they have a large protection.
2. Imports have still shown a rising trend due to various factors such as:
  - a. Complex Needs of Industry
  - b. Jindal doesn't make BA finish stainless steel 400 series for kitchenware applications
  - c. There is export demand for several stainless steel kitchenware, accessories, hotel equipment, which could only productively made out of stainless steel 400 series BA finish.
  - d. Jindal does not make regular supplies of thickness of 0.3 and 0.4mm — 430 grade for the kitchenware industry.
  - e. Jindal doesn't make 420 J2 grade with higher carbon, used for the manufacture of kitchen knives
  - f. Till date, Jindal has failed to provide deep drawing quality of 430 grade, and upon deep drawing, their stainless steel is more than usual levels of roping and other defects which are unacceptable to customers in Europe, Japan and USA.
  - g. **Jindal wants to enjoy a Monopoly**
  - h. **Jindal does not commit anything in writing**
  - i. Jindal has the propensity to harass and **brow beat** small users of stainless steel by making a multitude of applications for imposition of Safeguard and Anti Dumping duties
  - j. Jindal manipulating and misrepresenting raw import data to buttress their claims and they are well aware that manufacturers of stainless steel kitchenware do not have the wherewithal to appoint expensive lawyers to verify data and to fight the case.

**O. Embassy of Mexico:-**

- a. The product is not correctly identified, the authority leaves the exporters in a total disadvantage since they cannot submit all the pertinent allegations in their defense.
- b. In the initial determination there is absolutely no analysis that describes and the information or documents considered by the investigating authority and the reasons why it determined that the PUC and domestic products are similar or directly competitive. Accordingly, in the absence of an appropriate identification of the like or directly competitive product, the investigation should have never been initiated, since it did not comply with articles 2.1 and 4, c) of the SA.
- c. In the initial determination there is no analysis on the volume of production of the petitioner and on the rest of the Indian producers, so that the investigating authority could verify that the petitioner indeed represents a major proportion of the domestic production. The information described in the initial determination cannot be considered, in any way, as adequate and sufficient to meet the above mentioned obligations of India. As a result of that, the parties are in a total state of helplessness, in violation of the applicable legal framework.
- d. since this is a global safeguard, the investigating authority should have had enough elements to sustain that exports were directed to India because of unforeseen circumstances. However, the initial determination does not contains or explain how this unforeseen circumstances are justified, acting in a manner contrary to the article XIX paragraph 1, a) of GATT.
- e. in the initial determination there is no explanation or analysis that justifies the assumption that imports increased in "such quantity" and in "such conditions" that are causing or threatening to cause serious injury. This is important if we consider that imports just passed from 87,051 MT in 2012-13 to 87,178 MT in 2013-2014.
- f. There is no evidence proving that there is an unforeseen circumstance and that because of the effect of the obligations acquired by India in its WTO accession, imports of cold rolled flat products increased in such quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry
- g. in the initial determination there is absolutely no explanation of the reasons of why the developments in import volumes could qualify as sufficiently recent, sudden, sharp and significant, qualitatively and quantitatively, as to cause serious injury to Indian producers. This deficiency in the initial determination, again, leaves interested parties in completely defenseless state, which, in our opinion, is totally contrary to the international obligations undertaken by India.
- h. it is not clear how the exclusion of certain products operates, there is a chance some Mexican products should be excluded and nevertheless are indeed taken into account. In that case, for example, if the products included in that subheading are excluded, Mexico will surely stand below the 3% of the total imports, in which case Mexico should be excluded from the adoption of any eventual measure according to Article 9 of the SA.
- i. in the initial determination there is no clear definition of the PUC, nor any analysis about the similarity between the imported and domestic products or the direct competition between them, and for that reason, the determination of who are the domestic producers and hence the domestic industry, is unfounded. Obviously, as a result of these shortcomings, the analysis of injury to the domestic industry has no factual and analytical basis, and as a consequence, again, the initial determination does not meet the standard defined in the international provisions.
- j. Aspect that should have been explained is if there is no injury regarding production, sales, productivity and employment, why and how the behavior of the rest of the factors is sufficient to consider the existence of serious injury.
- k. The initial determination does not contain any analysis at all on the causal link between the alleged increase of subject imports and the alleged injury.

**P. Taipei Economic and Cultural Center in India:-**

Directorate General of Safeguards' information and Taiwan's customs statistics show that Taiwan's export of the above-mentioned products to India accounts for averagely 1.2 percent of India's total imports during 2011-2015 period. Taiwan's statistics also indicate a decreasing trend of exports of these products to India and Taiwan's share of imports of the products concerned in India does not exceed 3 percent since 2011. Therefore, Article 9.1 of the Agreement on Safeguards shall apply to this case

**Q. OUTOKUMPU STAINLESS OYJ, FINLAND**

- a. Stainless Steel has a long history of trade remedial measures in India. Duties are already in force against largest sources.
- b. Petitioner had given Cybex data in AD investigation. The reliability of import data was held to be suspect in and led to Japan being eventually excluded on account of being *de minimis* in volumes.
- c. The examination in the most recent period (2014-15) is based on actual imports for merely 3 months (Q1 of 14-15) and not the entire financial year. Import figures of 2014-15 comprise of a prospective period and do not conform to a period of recent past. Hence, the analysis of increased imports is incorrect and flawed.
- d. Even if import data is annualized and analyzed, there is almost no increase in imports and the level of total imports into India since 2012-13 have stagnated and do not reflect any *‘sudden, sharp, significant’* increase.
- e. Director General (Safeguards) has specifically considered a period of 6 months or more in order to attain a fair examination of the alleged increased imports
- f. Decision of the DG Safeguards to consider only 3 months import data i.e. imports for the period of April 2014 to June 2014 for the purpose of arriving at increased imports is tantamount to departure from its earlier precedent and practice and is arbitrary, unfair and violative of the principles of natural justice
- g. the demand provided in the Initiation Notification does not tally with the addition of all the elements for calculating domestic demand
- h. Petitioner has claimed the source of information for other producers production to be market intelligence without providing an iota of evidence to substantiate the same and the Hon'ble Director General (Safeguards) has accepted the same without calling for such evidence.
- i. Petitioner has provided summary information for all other Indian producers, apart from itself, without providing a detailed listing of each domestic producer and its individual production
- j. The transaction-wise import data provided by the Petitioner as per Annexure 16 of the Petition is incomplete and covers only the period from January 2014 to June 2014
- k. there is no evidence to establish that the occurrence of a global demand supply gap was unforeseeable and that as such has led to the increased imports into India.
- l. One of the reasons which caused significant global demand and supply gap is the production expansion by the petitioner, which means that significant global demand and supply gap caused no change in competitive environment between the petitioner and exporters.
- m. The Petitioner has presented summary import data of various cold rolled stainless steel products in China. Petitioner ought to not only provide the source of the aforesaid summary import data but also the basis and manner including the sourced raw data from which the above summary was prepared
- n. The requirement of unforeseen circumstances relates to changes in the past and not future projections. Petitioner has merely relied upon the alleged increase in exports, including the projected increase and gap between domestic Chinese production and apparent consumption in China, while claiming that there has been an increase in capacities in Chinese Producers.
- o. At no occasion has the demand-supply gap in China and the position of net imports/exports by China been congruent.
- p. A mere perusal of the import data provided by the Petitioner reflects that there has been no increase in the imports from the EU and Korea. Figures of 2014-15 are not reliable.
- q. Petitioner has not provided any evidence to substantiate that the alleged excess capacity was diverted to India due in the period of investigation instead of China or other markets and have made mere bald assertions and statements.
- r. Neither the initiation notification nor the petition of the DI provides any information with respect to the unforeseen circumstances or events which has led to increase in imports in such quantities so as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry.
- s. Excessive confidentiality claimed on the following:
  - (i) Transaction-wise import data from 2011-12 to 2014-15 (April to June 2014)
  - (ii) Costing information. At least indexation should have been given.

- (iii) individual production quantity of Petitioners and other domestic producers
- (iv) The details of the import data from China Customs has not been provided, without any justification.
- (v) Reports from *Heinz H. Pariser Weekly Fax Service* and information from China Metal Information Network, Antaike.
- (vi) The CRU data for China, Japan, Korea and EU
- (vii) The complete adjustment plan
- t. Director General (Safeguards) has erred by considering the period of April 2014 to June 2014 to arrive at an annualised period for 2014-15. Notwithstanding, imports are at the same level in 2012-13 and 2013-14 and the apparent increase in 2014-15 is based on a temporary, estimated figure.
- u. There is no relative increase in imports with regard to the production in India
- v. Production and sales have increased
- w. Market share has remained constant.
- x. The basis on which the capacity has been segregated and considered for the product under consideration alone has not been clarified.
- y. There has been significant capacity addition by the Petitioner in 2012-13, despite which the production and capacity utilisation have been adequately utilised.
- z. Petitioner has not been able to achieve higher capacity utilisation on account of challenges in procuring chromite ore from domestic sources at cost effective prices
- aa. Initiation Notification disregarded the inventories of the petitioner for the purposes of the initiation notification.
- bb. the closing stock of the Petitioner has been maintained at about 2% of the total capacity for the product under consideration
- cc. No price undercutting and no price suppression.
- dd. Over the period, the actual cost for ferrochrome has come down which accounts for over 35% of the total cost of production.
- ee. Petitioner has throughout the POI been in a position of loss and hence, the projected decline in profitability of the Petitioner is not attributable to the increased imports
- ff. Increased losses of the Petitioner are not attributable to the alleged increase in imports and are on account of interest costs and exceptional losses
- gg. There is not an iota of evidence provided to establish that there is an imminent threat of increase in imports of the injury is likely to intensify
- hh. The mere fact, that the profitability of the Petitioner independently reflects a loss even when there was no alleged increased imports, sufficiently establishes that the alleged injury faced by the petitioner is not attributable to the imports.
- ii. Petitioner have been adversely affected on account of several factors, inter alia, such as adverse duty structure, increase in basic customs duty for import of steel scrap, increase in raw material prices and volatile currency.
- jj. self-inflicted injury achieved by inexplicably increasing capacities despite a loss- making scenario which continue to face sever stabilization issues reflecting a breach in the causal link
- kk. The auto parts suppliers have been importing stainless steel for the manufacture of exhaust systems to meet the standards set for low emissions the auto industry will have to bear high expense of the duty levied or in the alternate will have to revert to importing the exhaust system altogether.

**R. Metal & Stainless Steel Merchant's Association & Metal one Corporation(P) Ltd.:-**

1. Comprehensive Economic Partnership Agreement between India and Japan, Comprehensive Economic Partnership Agreement between India and Korea as well as India-ASEAN FTA provide for specific guidelines to be followed in cases of safeguard investigations initiated under the respective agreements. Therefore, investigation needs to be terminated as the correct forum is not DG Safeguards but mechanism set up under the respective FTAs.

2. No methodology used for sorting the import data has been provided in the petition filed by the Applicant. For a proper analysis of all the claims in the petition, it is requested that the DGS shall provide the transaction-wise raw import data as well as sorted import data to interested parties in MS-Excel format.
3. Annualizing of just 3 months import statistics not a correct way to determine actual import figures for 2014-15
4. Under safeguard law, there is no concept of injury margin. Thus, the exact level of safeguard duty that Applicant has requested is unknown. In addition, there is no methodology prescribed under the safeguard law that gives guidance to DGS in arriving at the level of safeguard duty. Thus, for the sake of transparency, DGS is required to disclose the methodology, which it may use to determine the level of safeguard duty.
5. The Applicant has not presented any factual or legal basis to establish that unforeseen developments exist in the present case
6. Article XIX of the GATT 1994 places a two-fold obligation on the Authority. Firstly, it requires the Authority to identify the specific obligation including tariff concessions, incurred by the member country, concerning the subject product under GATT. Secondly, it requires to establish a causal link between the aforesaid specific obligation and increase of imports of the subject product into India
7. Even if the Applicant fails the obligation remains on the Authority to analyse this issue and give a finding in this regard. Failure to do the same would render any finding by the Authority inadequate, unreasonable and non-compliant with the obligations under Article XIX of the GATT.
8. As customs duty decreased pursuant to obligation under CEPA, imports from Japan also showed a corresponding increase. This clearly shows that increase in imports is due to FTAs entered by India and this cannot be treated as unforeseen.
9. There has been miniscule increase in imports between 2012-13 and 2013-14. Further, data for 2014-15 based on 3 month's actual data cannot be taken as projecting trend for the entire year. Such an increase in imports cannot be referred to as "sudden" or "sharp" increase in imports and at best "gradual". Thus, it is concluded that there is no sudden, recent, sharp and significant increase in imports and such contention by the Applicant is to be rejected.
10. All the parameters such as production, sales and capacity does not show any injury whatsoever. the methodology prescribed for segregating capacity for 400 series from total capacity is still unclear
11. Landed value is calculated by adding customs duty and education cess to the assessable value and not CIF value of imports. . However, in the present case, Applicant has determined landed value by adding customs duty and education cess with CIF value of imports. This has greatly reduced the landed value computation and the price undercutting is also showing an inflated price undercutting range
12. DGS to compare slit form imported into India (after adding due adjustments to Wide Coil form) with Slit Form of subject goods sold by the Applicant.
13. Price underselling, depression and suppression data has not been indicated even in indexed form in the NCV of the petition filed by the Applicant
14. Applicant had to incur a significant amount towards power and fuel expense, which was one of the critical reasons for losses to Applicant
15. Even at the beginning of the 2011-12, when imports were low, Applicant had been suffering losses.
16. Significant losses to Applicant may be on account of increasing fixed expenses incurred for doubling its capacity
17. Imposition of anti-dumping duty on subject articles has already removed the injurious effects of imports of subject goods. If Applicant is not satisfied with the level of protection already provided, then anti-dumping provisions provide for MTR.
18. The factors now sought to addressed in the adjustment plan were already in existence and are anyways independent of existence of imports and must have been identified by Applicant long ago.
19. Adjustment plan should be specific only to product concerned and should not be used to rectify problem of entire company, irrespective of products in question.
20. Applicant has stated that its consultant has suggested five pronged strategy for lowering costs but has not disclosed, even in non-confidential terms, what this strategy is.

**S. M/S Maruti Suzuki India Ltd.**

1. During the period of investigation, i.e., the period commencing from financial year 2011 -- 2012 to 2014 – 2015 ("P01"), they imported the Product Under Consideration only from Japan.



2. Since a specific regime and mechanism has been provided to secure the bi lateral safeguard measures under the FTA. The Authority has completely ignored the provisions of the FTA in relation to bilateral safeguards and the special conditions and procedure set out therein.
3. There is a difference between the quality of the product manufactured by the domestic industry and the Product Under Consideration imported from other countries, including Japan. Imported good from Japan is manufactured through a state of the art patented technology and the Product is of a special design, specifications and of a much superior quality.
4. The Petitioner has not provided important economic parameters such as price underselling range, list of major raw materials, investments made, net worth, depreciation expense, interest expense, etc.
5. The adjustment plan provided is incomplete and most of the information has been considered as confidential by the Petitioner
6. The Authority is required to disclose the methodology to be adopted to determine the level of safeguard duty.
7. The importer have in place a process of strict testing and checking procedures, wherein the testing alone of a raw material/ product sometimes takes 2 - 3 years' time. It would be impractical for the Importer to discontinue imports of the subject product or supplement the imports with the production from domestic industry
8. It is pertinent to note that despite being aware that the Respondent would be one of the parties who would be substantially affected by the Safeguard Proceedings, Petitioner deliberately did not specify us as a noticee in the application and the Authority also failed to list the Respondent as a notice.

**T. Embassy of Korea:-**

- a. The Product of this safeguard investigation should be homogeneous enough to be treated as like or directly competitive products in terms of physical characteristics and the end use.
- b. Indian domestic steel producers do not meet the end-users' required standards due to lack of technology involved in producing automotive exhaust systems while more than 99% of the Korean Product exported to India was ultimately consumed by automobile or auto-part producers.
- c. The Product to this investigation, such as 429EM, 430J1L, 444, 445NF, and 446M are not produced by the domestic industry of India. In this respect, many Indian automobile or auto part companies still depend on imported steel products.
- d. If there were other factors affecting the situation of the failing of the domestic industry, they should be evaluated separately and independently.
- e. In 2012-2013, according to CRU Stainless Steel Flat Products Market Outlook, the petitioner established a new plant in Odisha, which doubled its existing capacity. This implies that petitioner's excessive investment combined with high start-up costs as well as high inventory cost and sales at lower price during the initial stage of production may have resulted in poor financial performance.
- f. In particular, it should be noted that while the domestic industry was allegedly suffering from financial losses, there was no significant increase in imports. One of the most important indicators of the domestic industry's performance is its profit and loss. The domestic industry has allegedly suffered from financial losses of 315 Rs/MT in 2012-13 and 953 Rs/MT in 2013-14. However, imports remained constant, 87,051 MT in 2012-13 and 87,178 MT in 2013-14.
- g. Though the petitioner claims that it has suffered from serious injury, it was not imports of subject goods but petitioner's own aforementioned internal reasons that caused financial losses. This means that the petitioner has failed to prove the causal link between the increased imports and the serious injury.
- h. The imposition of the safeguard measure is likely to cause adverse effect upon downstream industries and consumers in India.
- i. The domestic producer can only produce limited scope of stainless steel products, which is used for constructing other end-products such as automobile. Without diverse foreign materials imported, the scope of the end-products will be limited as well, and have negative effect upon public interest of India.

**U. M/S Paxal Corporation**

- a. One of the main reasons for surge in imports can be attributed to the rapid build up of capacity in China over the last 5-7 years at a rate which was far higher as compared to the growth in domestic demand.

- b. The huge surplus production of Stainless Steel in China is being diverted to growing markets like India.
- c. There has been persistent dumping of stainless steel by other countries as is evidenced through a number of notifications issued by the Government of India regarding the imposition of anti-dumping duty on stainless steel flat products
- d. The huge investment made by the domestic industry towards capacity expansion and modernization is in jeopardy today and the industry is constantly fighting a battle for survival because of a deluge in imports of Stainless Steel Flat Products from countries like China, Korea and Japan.

### III. PUBLIC HEARING

- (1) A public hearing was held on 14<sup>th</sup> January, 2015, notice for which was sent on 15<sup>th</sup> December, 2014 to the all Interested Parties. Following interested parties presented their views during the public hearing:-

M/S Jindal Stainless Ltd (Domestic Industry)
Embassy of Japan
Embassy of Indonesia
Embassy of Korea
Embassy of Mexico
Embassy of Turkey
M/s. Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel Corporation, M/s. Nisshin Steel Co., Ltd. and M/s. JFE Steel Corporation
M/S Outokumpu Stainless Oyj, Finland M/S Outokumpu Nirosta GMBH, Germany M/S Shanghai Krupp Stainless Co. Ltd
M/S POSCO , Korea
M/S Wirana Pte Ltd, Singapore
M/S Baharu Stainless, Malaysia, M/S Metal one India Pvt. Ltd & Stainless Steel Marchant's Association
M/S Maruti Suzuki India Ltd.
M/S Hindustan Syringes & Medical Devices Ltd.
M/S Goshi India Auto Parts Pvt. Ltd
M/S POSCO Vietnam/ POSCO Thainox

- (2) All Interested Parties who participate in the public hearing are required to file a written submission of the views presented orally in terms of Sub Rule (6) of Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997. Thereafter, copy of written submissions filed by an Interested Party is made available to all other Interested Parties. Interested Parties are also given an opportunity to file rejoinders, if any, to the written submissions of other interested parties. Following interested parties submitted written submissions in terms of above said rules.

- (3) The brief summary of the written submissions filed by various interested parties after public hearing are as under:

**A. M/S TPM Consultant filed written submission on behalf of M/S Jindal Stainless Ltd. (Domestic Industry)**

**T/T data not circulated**

- a. It was extensively argued by the interested parties that accuracy and adequacy of the imports has not been examined by the Director General as T/T data was not provided and it was also inferred that T/T data was not even given to the Directorate. It is submitted that T/T data was provided to the Directorate. In a situation where the Directorate conducts detailed verification prior to even initiation of safeguard investigation, it is very

surprising that the interested parties believed that the Directorate without even going through the data has accepted all the information provided by the petitioner on its face value.

- b. It is further submitted that the petitioner is not obligated under the law to give transaction wise import listing to the other interested parties.
- c. T/T data is relevant only to the Director General (Safeguards) for the purpose of satisfying itself with regard to accuracy of information and the same was provided to the Director General (Safeguards).
- d. The petitioner has provided entire T/T data to the Director General (Safeguards) and the same has been made available to all opposing parties. Therefore no prejudice can be claimed by the interested parties.
- e. The methodology adopted and import information for the period upto Dec., 2014 has been provided.

**One quarter data cannot determine increase in imports**

- f. It was argued by various interested parties that imports of one quarter is insufficient to determine increase in imports and that the Directorate has never, in the past, considered such short time period to determine increase in imports. It is however submitted that this Directorate has initiated investigations on the basis of two/three months import statistics in the matter concerning imports of Soda Ash and Caustic Soda into India.
- g. Petitioner has never submitted that the Director General (Safegaurds) should conclude existence of surge in imports based on three months period. Petitioner has already provided information for the period upto Dec.14 and the Director General (Safeguards) may kindly determine surge in imports on the basis of imports during April-Dec.14 period.
- h. It was also contended by some interested parties that if one quarter data was to be adopted for the present period, the Director General (Safeguards) is required to consider the previous year's data also on quarterly basis. It is submitted in this regard that even when information in the initiation notification or petition is presented on annual basis, the Director General (Safeguards) has actually considered even month by month information with regard to imports, capacity, production, capacity utilization, sales, stocks and employment. Only consolidated annual data has been presented in the notice of initiation. Thus, the decision of the Director General is based on month by month as well as annual data.

**Antidumping duty is already in place**

- i. It was argued by the interested parties that antidumping duty is already in place on Cold rolled 400 series grades to protect the domestic industry. It is however submitted that ADD has not been able to protect the domestic industry. While the importers themselves have argued that majority of imports are of wide products, which is beyond the scope of the product under consideration considered in the AD investigation. Further, imports from Japan are not attracting anti dumping duty and imports of narrow width products (CR<400 mm) are attracting anti dumping duty on the basis of benchmark form where the imports are happening above the benchmark prices.
- j. The petitioner requests the Director General (Safeguard) to kindly call the data from DG Systems and ascertain volume of imports that has been made after payment of anti dumping duties and the volume of import that has been made without payment of anti dumping duty. The information would readily establish the factual position and would show that despite anti dumping duties having been imposed on a number of countries, there are hardly any imports after payment of anti dumping duties.

**Demerger of the company**

- k. It was argued by the interested party that the company is being demerged. We are enclosing herewith extract from the document filed with SEBI regarding this scheme (on non confidential basis). It may be seen that the rationale behind this scheme is to unlock the shareholder value, to increase its profitability and to improve serviceability of debt by the company.
- l. The document specifically mentions that the transferor company is facing acute liquidity problems partly on account of influx of imports, especially from China. It is submitted that had it not been for the huge influx in imports cutting across all series, the Odisha plant would have been operating at much better capacity utilisation and there would have been no issues regarding the serviceability of the debt. Further, the influx of imports has led to price suppression, which has prevented the domestic industry from raising its prices in proportion to the increase in the input costs.
- m. The total liability of JSL will now be divided between JSL, JSL (Hisar Limited), JUSL & Jindal Coke Limited. The data of Jindal Stainless Limited currently submitted covers Odisha Phase II & Hisar. Therefore, the sum total of the de-merged entities will be practically equal to the current data in the petition.

**Product under consideration:**

- n. Imports of the product under consideration have been reported under a number of customs HS codes and therefore the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of present petition

and proposed investigation. The subject goods are used for manufacture of white goods, processed equipment, dairy equipment, automotive components, rail carts, metro coaches, architecture, building and construction, etc.

- o. A number of parties have contended that the scope of the product under consideration is not appropriate. However, none of the parties have established how the scope is not appropriate and what is the product type included in the scope of product under consideration which should not have been included. Thus all arguments on these accounts are vague and wholly unsubstantiated.
- p. Various interested parties have argued that products produced by domestic industry and imported product are not substitutable for auto industry like Tata Motors, General Motors, Hyundai, Bajaj Etc..
- q. It has been contended by some of the consumers and foreign producers that imports are necessary because some of the consumers have not approved the product produced by the petitioners. Petitioner submits in this regard that it is not the question of whether the consumer has approved the product produced by the domestic industry. The relevant question is whether the consumer has demanded a product from petitioner for its requirement and the domestic industry has regretted supply on the grounds of technical capabilities. The petitioner can supply a product only if a consumer places the order for the same. The only grades that petitioner has not supplied are 429,432,444 & 1.4521 and the reason for the same is that petitioner has never received any order for these grades. It is not even the claim of any of the interested parties that the petitioner was asked for a particular product and petitioner regretted supply pleading technical capabilities.
- r. It has been argued by some interested party that certain goods imported are special purposes such as surgical blades. It is however submitted that there is no order placed on the petitioner for supply of the product. The petitioner cannot supply something for which there is no order. If petitioner receives an order, petitioner would supply the material.

#### **Domestic industry**

- s. Petitioner constitutes domestic industry. Domestic industry is defined under the Customs Tariff Act, 1975 (Section 8B) as follows 6(b)"domestic industry" means the producers as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India ;
- t. Present application has been filed by M/s Jindal Stainless Ltd. There are four other producers of the product concerned in India. Production and sales of these known producers has been estimated as per market intelligence.
- u. It was argued that despite addition of capacities the standing has not changed. Standing of the applicant is based on the production and not on capacity. Further, it would be seen that petitioners share in total Indian production has increased.

#### **Increase in Imports:**

- v. Petitioner submits that the requirement under the law is that imports should have shown sudden and significant surge.
- w. The petitioner further submits that sudden, significant, sharp and recent increase in imports does not mean such increase necessarily be at the end of the period of investigation or at the time of determination. Both end to end comparison and intervening trends may be seen in order to determine increase in imports.
- x. The petitioner submits that the imports of product concerned have shown significant increase in absolute terms as well as in relative terms. The increase in imports is sudden and significant, causing serious injury and threat of serious injury. Thus imports of product under consideration has "increased within the meaning of the rules" as can be seen from the following:

#### **Increase in Imports in absolute terms**

- y. It was argued that the import statistics considered by the petitioner is incorrect. It is therefore requested that the Director General may kindly procure transaction wise imports as per DGCIS and analyse the same. Detailed methodology has been provided earlier.
- z. It may be seen that import have registered significant surge in absolute terms. The imports have further increased sharply in the period Oct-Dec 2014. Imports have shown increase in quarter wise movement as well. It would thus be seen that there is a sudden, sharp and significant increase in imports in the recent period.

#### **Increase in imports in relation to production of the domestic industry**

- aa. Imports of product under consideration in India have increased in relation to production of the domestic industry and the increase is highest in the most recent period.

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 Q1	2014-15Q2	2014-15Q3
Imports in relation to production (%)	81.26	89.61	80.11	94.19	81.79	96.01

#### **Increased Imports in relation to domestic consumption/demand**

- bb.** Consumption or demand for the product under consideration has been determined by the petitioner, as the imports of product into India, domestic sales of the domestic industry and domestic sales of other domestic producer. The imports of product under consideration have increased rapidly in relation to Indian consumption of product under consideration. Imports have increased to such an extent that the imports in relation to consumption constitutes 50% of Indian consumption. This is the situation when the petitioner itself has expanded capacities and the country has capacities sufficient to meet the present and potential demand for the product in the Country.

#### **Reasons for Increase in Imports:**

- cc.** It is submitted that obligation incurred by India under GATT 1994 was to grant a tariff concession of 40 per cent ad valorem. Thus, the Govt. of India has reduced Domestic Industry tariff under the obligations incurred by Govt. under GATT 1994. The FTA entered into reduces the tariff concession further. Major imports are from Japan, Korea, China, EU, Mexico and USA. The major surge is from China. The increase in imports is due to following reasons —

##### **a. Significant Global demand supply gap since 2010**

- i China, which was a net importer, has now become self sufficient and has surplus capacity
- ii Increasingly excessive capacities with Chinese producers leading to rising exports China has various advantages, such as following:
- iii. Sudden expansion in China's ferrochrome capacity and low cost on account of abundant amount of Reductants (Coke), Currency, Cheap electricity, Low Interest rate.
- b. Huge demand supply gap in Western Europe
- c. Huge demand supply gap in Japan
- d Korea's aggressive enhancement of capacities without having much domestic demand.
- e. FTA/PTA entered by the Indian Govt. with countries like Korea and Japan
- f. Continued imports despite anti dumping duty levied in India
- g. Imposition of trade measures against various major players

#### **Injury to the Domestic industry:**

- dd.** The petitioner submits that the all the parameters illustrated under the law shows injury suffered to the domestic industry namely:-
- a. Imports have increased significantly
  - b. Significant share of the market has been taken by imports
  - c. Sales, production, capacity utilization, productivity, profits and losses have declined.
- ee.** Demand for the product under consideration has been determined by the petitioner, as the imports of product into India, domestic sales of the domestic industry and domestic sales of other domestic producer. The overall demand for the product under consideration over the injury period has increased.
- ff.** Imports have increased in absolute terms and also in relation to production and consumption.
- gg.** Peculiarities of steel plant: Stainless steel plants run on Electric Arc Furnace (as scrap is the main raw material). The Furnace has to be run round the clock because if there is a stoppage after a particular batch is completed, the Furnace shall get colder by the time the next batch is ready to be processed and this require heavy power consumption for heating the Furnace Chamber. Therefore on account of the inherent technical nature of the plant, the furnace has to be run on a continuous basis or in other words at optimum levels of capacity utilization. A lowering of the capacity utilization will not only result in higher fixed overhead cost per unit of

production but also in higher variable cost on account of excessive consumption of power. In view of the same, a typical steel producer should run the plant on continuous basis and without any shut down.

- hh. Production of the domestic industry has increased over the period with decline in the most recent period of Oct-Dec 14.
- ii. It is submitted that the domestic industry commissioned fresh production facilities from new green field plant set up at a new location (the petitioner has set up a melting capacity of 1 million MT green field plant at Orissa for production of various hot and cold rolled steel products). The facilities are meant for both domestic and export markets.
- jj. Petitioner does not have dedicated capacity for the product under consideration, therefore (a) petitioner has considered the capacity deployed in product under consideration in 2011-12 (the first year of commercial production in Odisha) and capacity utilization in this period. The level of capacity utilization in this period has been considered for calculation of capacity during subsequent years; and (b) in addition to capacity utilization for the product under consideration, the petitioner has provided information on capacity utilization for all types of cold rolled products. Further, the company has enhanced its capacity for various cold rolled products, which includes product under consideration, from 4,27,500 MT to 765,000 at present. Capacities of this kind do not become fully operational the moment the capacities are commercialized. Capacity for the product under consideration has been therefore on the basis of production achieved in 2011-12. It would kindly be appreciated that once the company has achieved this level of production, there can be no dispute with regard to this capacity for the product.
- kk. It would be seen that the capacity utilization has declined over the period despite increase in demand. Further, the petitioner has also determined capacity utilization by considering full capacity as well. It would be seen that capacity for production of Cold Rolled Flat products of stainless steel in the domestic market has remained unutilized despite sufficient demand and imposition of anti dumping duty. Capacity utilization considering the

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15Q1	2014-15Q2	2014-15Q3
Capacity	MT	427,500	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000
Production	MT	262,275	364,855	447,833	509,616	532,246	464,188
Capacity Utilization	%	61.35	47.69	58.54	66.62	69.57	60.68

capacities on the basis of installed capacities.

- ll. **Market share:-** Movement of market share is shown in the table below:

Market share(%)	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 Q1	2014-15Q2	2014-15Q
Domestic Industry	45.33	42.75	44.59	43.50	46.13	43.57
Imports	46.15	49.36	47.79	50.31	47.59	50.39
Total Capacity- all types of Crproducts	4,27,500	7,65,000	7,65,000	7,65,000	7,65,000	7,65,000
Demand in India	1,40,600	1,76,342	1,82,423	2,06,121	2,02,835	2,11,098

\*Figure for Q1, Q2 and Q3 are on annaulised basis

- mm. It would be seen that imports are capturing half of the domestic market in a situation where domestic industry has sufficient capacity and imports are not a necessity in the domestic market. The market share of the domestic industry has declined over the injury period whereas that of the imports has increased.
- nn. It is further submitted that the decline is despite the efforts made by the domestic industry to counter the surge in imports by aggressively selling its product even at the cost of its prices and losses. The market share of the domestic industry is much less than the market share achieved earlier with lower capacities. Thus, with lower capacities, higher market share and with higher capacities, lower market share! This itself establishes that

adverse effect of increased imports on the domestic industry.

- oo. **Domestic Sales:** It would be seen from the information given below that sales of the domestic industry have increased.

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 Q1	2014-15Q2	2014-15Q3	
Domestic Sales(MT)	63,729	75,391	81,344	89,673	93,566	91,966	

\*Figure for Q1, Q2 and Q3 are on annaulised basis

- pp. It would be seen that the sales of the domestic industry increased. However, these sales levels could be achieved by the domestic industry at a huge cost of significant financial losses.
- qq. It would be seen that increase in production and sales of the domestic industry is lower as compared to the increase in demand, despite installation of significant capacities. Imports have shown increase. Despite imposition of anti dumping duties on dumped imports of the product under consideration from certain countries, volume of imports has not declined. The same has in fact increased significantly.

#### Price effect

- rr. **Price suppression/depression:** Landed price of imports have remained below the level of cost of sales of the domestic industry. It may be seen that both the cost of production and selling prices of the domestic industry has increased. However, the increase in selling price were lower than the increase in cost of production. Whereas cost of production increased by about 24% over the period, the selling price increased only by about 5%. The imports are below the level of cost of production and are thus significantly suppressing the domestic prices in the market.

	2011-12	2012-13	2013-14 Q1	2014-15 Q2	2014-15
Cost of production (Rs/MT)	****	****	****	****	****
Trend	100	106	119	122	125
Selling price(Rs/MT)	****	****	****	****	****
Trend	100	102	103	106	105

- ss. **Profitability:** The domestic industry is suffering significant financial losses. Further, the losses suffered by the domestic industry kept increasing throughout the injury period. as may be seen from the table below:

	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	Q1 2014-15	Q2 2014-15
Profits	Rs/MT	-100	-315	-953	-957	-1,148
Cash profit	Rs Lacs	100	-212	-1,258	-1,501	-1,803

\*Figure for Q1, Q2 are on annaulised basis

- tt. **Return on investment:** Return on investment was also negative and deteriorated over the injury period.

	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	Q1 2014-15	Q2 2014-15
ROCE-NFA	%	4.07%	-0.73%	-10.88%	-12.59	-15.67

- uu. It is submitted that the financial losses are crippling the Domestic Industry. The return on capital employed has remained negative throughout the injury period. It is further submitted that overall growth of the domestic industry remains negative because of significant financial losses.

### **Injury to the domestic industry - if only Hissar plant is considered**

- vv. it has been argued by the interested parties that price injury is on account of expansion of capacity by the petitioner. It is however submitted that petitioner has two plants for production of the product under consideration -. one at Hissar and one at Odisha. Petitioner had provided separate injury information for the two plants. It would be seen that performance of Hissar plant on standalone basis also shows that the performance of the domestic industry has deteriorated. This clearly establishes that the claimed deterioration in performance of the domestic industry is not because of commercialization of production at Odisha plant.

### **Conclusion on serious injury**

- ww. Domestic industry submits that from the foregoing, it can be concluded that:
- the imports of the product under consideration have increased significantly in absolute terms and in relation to production and consumption in India;
  - market share of the domestic industry has declined, despite (i) increase in demand, (ii) addition of significant capacities, (iii) imposition of anti dumping duty;
  - whereas the market share of imports has increased..Despite significant efforts made by the domestic industry to produce and sell even at the cost of its prices, the domestic industry has not been able to hold onto its market share, leave aside its efforts to increase the market share.
  - Despite increase in capacity and imposition of ADD on subject goods the legitimate market of the domestic industry has been taken away.
  - The domestic industry was not able to increase its prices in proportion to the increase in cost of production. Resultantly, imports were suppressing the domestic prices.
  - Performance of the domestic industry declined in terms of profits (significant losses) and ROI.
- xx. It would, thus, be seen that imports of the product into India has increased significantly in recent period in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India. Market share of imports have increased whereas market share of the domestic industry has declined, despite increase in demand and sufficient capacity with the domestic industry. The domestic industry is suffering financial losses, as it is not able to increase its selling price in proportion to the cost of production because of low priced imports. It is thus evident that increased imports have caused serious injury to domestic industry.

### **Threat of serious injury**

- yy. In addition to the serious injury already inflicted on the domestic industry, increased imports of product under consideration are threatening serious injury to the domestic industry. Petitioner submits that whereas the imports of the product under consideration are already causing serious injury, the same is likely to intensify in due course, should the safeguard duties not be imposed immediately.

### **Other Factors of Injury**

- zz. While there are no listed known other factors that are required to be examined by the Director General (Safeguards), petitioners examined possible injury due to some known other factors. There are no other factors that may be attributing to the serious injury to the domestic industry other than increased imports.
- Demand of the product: Demand of the product under consideration has increased. Thus, the injury to the domestic industry is not due to any decline in demand.
  - Changes in the patterns of consumption: The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Changes in the pattern of consumption could not have contributed to the injury to the domestic industry..
  - Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers: There is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.
  - Developments in technology: Technology for production of the product has not undergone any change. Developments in technology are, therefore, not a factor of injury.
  - Export performance: Domestic industry has provided information only for its domestic operations and therefore export performance cannot be a cause of injury. Further, increasing imports of the product are forcing the domestic industry to look for exports. Thus, injury to the domestic industry in exports is also a result of increased imports. The analysis of injury is in respect for domestic operations only. Therefore, possible deterioration in the export performance of the domestic industry is not a possible cause of claimed injury to the domestic industry.
  - Performance of other products being produced and sold by the domestic industry: Claimed injury to the domestic industry is on account of product under consideration. Petitioner has segregated data and provided in respect of product under consideration only.

### **Causal Link**

- aaa. As demonstrated in the preceding paragraphs, some of the possible known factors have not caused claimed injury to the domestic industry. Increased imports of the product have caused injury to the domestic industry.



Followings are relevant —

- a. There is a sudden, sharp, significant increase in volume of imports into the domestic market in the recent period.
- b. Volume of imports is very high and shows an increasing trend.
- c. The imports in relation to Indian production and demand have increased significantly;
- d. The domestic industry is faced with significant unutilized capacities in view of significant imports into India;
- e. The imports are causing (i) price suppression (ii) financial losses (iii) negative returns on capital employed (iv) underutilisation of production capacities of Domestic Industry;
- f. Imports have increased and as a direct consequence, whereas the market share of imports has increased rapidly, that of the Indian industry has remained very low and declined;

#### Public interest-

bbb. Petitioner submits that the imposition of safeguard duty shall be in public interest. The effect of safeguard measures on public interest is commonly studied from the perspective of three different parties — the producers, the consumers and the general public. When considered in this context, imposition of safeguard duty in the present case shall be in public interest, as would be seen from the followings:

- a) Producers interest:—The imposition of safeguard duty on imports of product under consideration would be in the interests of domestic manufacturers. The measure would prevent further injury to the domestic industry from increased imports.
- b) Consumers interest:—Imposition of safeguard duty would be in the interests of domestic consumers, as it is in the consumers interest to have a competitive Indian domestic industry capable of supplying the product under consideration to the consumers and compete with foreign producers. If the current situation is allowed to continue, the Indian domestic industry will face further injury, giving foreign producers increased leverage.
- c) Public at large interest:—It is in the interests of the public at large to have a strong, competitive Indian domestic industry. This will not be possible if injury to the domestic industry as a result of increased imports is allowed to continue. There are various other segments who are dependent on the domestic industry such as Packing Bags, Packing Drums, Pallets, Labour & Labour contractors, Services, Suppliers of raw materials, consumables, fuel etc, Transporters and Logistics providers, Banks and Financial Institutions.
- d) The need for domestic industry in the country:—If increased imports are unchecked, the injury to domestic industry will continue and worsen. If domestic industry is allowed to deteriorate to a condition in which it can no longer operate, Indian consumers will be almost completely dependent on foreign producers.
- e) Sufficient capacity in the country to meet the present and potential demand: Indian domestic producers have the capacity and capability required to meet the current and potential/future demand in the country. As such, they can be relied on to provide for the needs of domestic consumers of the product under consideration.
- f) Labour-intensive industry:—The subject goods manufacturing industry is a labour-intensive one and it provides large-scale employment in India. Allowing it to suffer injury due to increased imports will lead to the unemployment of many.
- g) Continuous production process:—The manufacture of subject goods is a continuous production process; if domestic industry is allowed to reach a point where it no longer operates, production cannot be reinitiated when the need arises.
- h) No significant financial impact on the end consumers:—The eventual impact on the cost of the end products is insignificant. Petitioner examined the consumer profile and found that the consumption of the product under consideration is insignificant as can be seen from the table below:

S.N.	Sector	Domestic Industry 400 series CRSS Cost as a % of the cost of end application	% of 400 series Sales
1	Automotive	0.12% to 0.43%	57%

2	Railway Wagon to Railway Coaches	1% to 7%	3%
3	Utensils & Kitchenware	0.10%	23%
4	Architecture, Building and Construction Sector	0.25%	
5	Consumer Appliances (White Goods & Brown Goods)	0.1% to 5.46%	
6.	Industrial Application	0.11% to 0.16%	17%
a	Process Industry Applications	0.15% to 1.65%	
b	Medical Equipment Sector	4%	
C	Miscellaneous Engineering goods	Around 0.2%	

ccc. In view of the foregoing, it is submitted that the imposition of safeguard duty will be in public interest and the interests of end users are well protected.

#### **Adjustment Plan**

ddd. The Petitioner requests imposition of safeguard duty for four years. Adjustment plan by the domestic industry is enclosed with the submission. It is submitted that the petitioner has provided sufficient details of adjustment plan. The Director General (Safeguards) has not raised any query with regard to adjustment plan. Nor the Director General (Safeguards) has found that the information given in this regard is insufficient. If the Director General (Safeguards) considers that any information with regard to adjustment plan is insufficient, the domestic industry needs to be appropriately directed.

#### **Conclusions**

eee. The investigation has clearly established that Imports of the product under consideration constitute increased imports within the meaning of the Rules. The domestic industry has suffered serious injury. Serious injury to the domestic industry is as a result of increased imports. Parameters for imposition of safeguard duty are fully met.

#### **Prayer**

fff. Wherefore, in the light of the contentions raised, information provided and submissions advanced, the Authority may be pleased to: a) CONCLUDE that increased imports of Cold Rolled Flat products of stainless steel of 400 series into India have caused and threatened to cause serious injury to the domestic producers and it will be in the public interest to impose safeguard duty on imports of Cold Rolled Flat products of stainless steel of 400 series into India. b) RECOMMEND imposition of safeguard duty, after taking into account the injury suffered by the domestic industry.

#### **B. Written Submission filed by Mexico Embassy, New Delhi**

- a. There was no explanation in the petition or in the initial determination regarding whether a debug of import volumes was performed or, in any case, the methodology that was used in order to ensure that the estimated import volume was not distorted.
- b. The correct and precise identification of the volume of imports is an essential requirement for the initiation of any investigation since this aspect is used to determine whether there was an increase on

imports of the product under consideration and the impact of those imports over the domestic industry, and these aspects cannot be corrected in later stages of the investigation.

- c. The explanation given by petitioners in this stage of the investigation should be rejected and the procedure must terminate immediately without the imposition of any safeguard measure.
- d. Mexico surely will stand below the 3% of the total imports, case in which Mexico must be excluded from the adoption of any eventual measure according to Article 9 of the SA.

**C. Written Submission filed by M/S Hindustan Syringes & Medical Devices Ltd**

- e. They are importing Stainless Steel Strips (HS Code 72209090) for manufacturing of Surgical Blades (HS Code 90189022) from Switzerland which is mainly used for exports in USA & Europe.
- f. The Stainless Steel grades/Chemical Composition which they are importing for manufacturing of Surgical Blades are not available in India for ensuring a sharp & durable cutting edge as well as toughness of Blade to avoid Accidental Breakage.
- g. Their import average price of Stainless Steel Strips is above Rs. 300 per kg. While the petitioner product under consideration (PUC) average price range is Rs. 82 to 90 per kg. Their import price is 3 to 4 times higher than the petitioner average price.
- h. Their imported Stainless Steel Strips is not directly/indirectly in competition with the petitioner's product under consideration (PUC) and it is mainly for consumption for the export market. Stainless Steel Blades are over 95% Exported.
- i. Imposing of Safeguard duty on import of Stainless Steel Strips will increase the cost of medical/healthcare products and make them non-competitive in export market.

**D. Written Submission filed by M/S POSCO, Korea**

- a. Many automobile producers are still dependent on imported steel products since Indian domestic suppliers do not meet the end-users' required standards.
- b. Abrupt safeguard measure could encourage monopoly in Indian domestic market, and as a result, local automobile makers could experience a short supply unless they lower their quality standards.
- c. Following grades of cold rolled stainless 400series not produced by the domestic industry may be excluded
  - (i) 429EM, POS429EM - used for heat resisting parts, such as exhaust manifold and front pipe.
  - (ii) 430J1L, STS430J1L, SUS430J1L, EN 1.4511 and etc : It is mainly used for automotive exhaust systems, home appliances and exterior materials for building.
  - (iii) 444, STS444, SUS444, ASTM 444, EN 1.4521 and etc : It is mainly used for hot water system, heat exchanger and auto exhaust system.
  - (iv) 445NF, POS445NF: It is mainly used for elevator, household utensils and electronic components.
  - (v) 446M, POS446M : It is mainly used for roof and exterior building materials in coastal and industrial areas.
- d. POSCO strongly requests Honorable Director General (Safeguards) to verify how much quantity actually imported between April 2014 and March 2015 before its final determination.
- e. Even though there has been 22 thousands increase in total imports between 2011-12 and 2012-13 according to the Petition, it is because of increase in Indian domestic demand. Despite of such increase, market share of Indian Producers has been always around 50%. It cannot be considered as significant increase.
- f. As per the annual report of Petitioner, their capacity utilization decreased to 51.95% in 2011-12 in view of excessive capacity increase. With production process normalizing, the capacity utilization improved again and increased to 85.33% during 2013-14. However, Petitioner hides this fact and has misreported its capacity utilization as only 58.54% during 2013-14.

- g. Injury is not due to imports of subject goods into India but due to Petitioner's own internal reasons. These may be summarized up as follows:
  - i) New plant set up in Odisha – leading to high startup costs
  - ii) Excess capacity leading to extra inventory and sales at lower price

**E. M/S Laksmi Kumaran & Sridharan Advocates filed written submissions on behalf of M/S Metal One Corporation India (P) Ltd, M/S Baharu Stainless Sdn, Malasiya and Metal & Stainless Steel Merchant's Association**

- a. The present investigation is required to be terminated as the period selected by the Applicant and considered by DGS is improper and incorrect. The Applicant failed to disclose that January 2014 onwards, its Odisha plant producing subject product was facing issues with the violation of pollution norms and was under the constant threat of being shut down by the concerned authorities.
- b. Applicant in its Petition only provided import statistics for a period of only 3 months (Apr'14-Jun'14), that too, on sample basis for each month.
- c. Import statistics had been provided to the Authority in PDF form and that too without any methodology on how the raw import data was sorted to arrive at the refined data for the product under consideration. Same was provided to interested parties only after oral hearing on 15.01.2015, that too, after vehemently arguing before DGS.
- d. Since Applicant neither provided import statistics in excel format nor provided a methodology, the PDF import data provided to the Authority, that too, without any methodology, needs to be rejected and consequently, the investigation needs to be terminated on this ground alone.
- e. The methodology for refining import statistics dated 15<sup>th</sup> January 2015 provided by the Applicant subsequently is incorrect and requires to be rejected. Applicant has sorted out import statistics in a manner, which has resulted in inflated import statistics.
- f. In step 1 and step 3 of the methodology, if Applicant has segregated import statistics based on description of the transactions, then it was under an obligation to undertake a similar exercise in case of Chapter heading 7219 and 7220 as well. This exercise has not been done by Applicant. This casts a serious doubt on the correctness of segregation of import statistics by the Applicant.
- g. In step 5 of the methodology, it is incorrect to state that only 400 series Cold Rolled Stainless Steel is used for automotive applications. There are other grades as well, such as 300 series (304L) which are also used in automotive sector. By taking products with description stating 'meant for automotive purpose', Applicant has also included other series as well, such as 300 series, thereby inflating the quantity of imports. In view of the same, the import data provided by the Applicant needs to be rejected.
- h. The methodology adopted by Applicant in considering all the transactions falling under chapter headings 72193210, 72193310, 72193410, 72193510, 72202021, 72209021 is totally incorrect and requires to be rejected. Above mentioned chapter headings cannot be blindly considered to contain only Cold Rolled Products of 400 series as there are many transactions of 300 series as well, which are falling under the above Chapter headings. Transaction by transaction details of import statistics for above chapter headings for the year 2012-13 and 2013-14, wherein 300 series is appearing has been provided as **Exhibit 3 of the submission**.
- i. The methodology followed by M/S Metal One Corporation India (P) Ltd is as follows:
  1. Firstly, raw import data was refined and the import statistics for Chapter headings relied upon by the Applicant Domestic Producer were identified;
  2. Secondly, from the filtered import statistics, those transactions which had reference to grades other than 400 series (321, 301, 303, 316, 304, 201, 310, 200, 305, 202, 309, 347 and 240 series) were segregated and classified as 'NPUC';
  3. Thirdly, from the segregated import statistics, transaction which included 'H.R.' or 'H.R.S.S' or 'HR' or 'HRSS' or "Hot Rolled" in the description were segregated and classified as 'NPUC';
  4. Fourthly, transactions whose descriptions did not indicate in any manner, whether it is subject product as defined in the initiation notice, were segregated and classified as 'Unknown';
  5. Resultant import statistics as filtered above were considered as 'PUC'.

- j. On making the above analysis, the total quantity for Apr-Jun'14 period works out to be 22,655 MT. In contrast, import quantity for this period provided by the Applicant Domestic Producer comes to 25,925MT.
- k. When there exists such significant difference for 3 month period, there may be significant difference in previous period as well; thereby making the import statistics provided by Applicant Domestic Producer unreliable.
- l. Annualizing of just 3 months import statistics not a correct way to determine actual import figures for 2014-15
- m. The Import information provided by the Applicant for the subsequent period from July'2014 to Dec'2014 is useless as Applicant has failed to provide corresponding information relating to demand and injury parameters such as production, sales, inventory, profitability, etc.
- n. Import statistics were provided by the Applicant needs to be rejected and investigation be terminated for not providing evidence relating to increase in imports in appropriate format.
- o. Applicant Domestic Producer should make available excel version of import statistics and the manner of identifying product under consideration from the raw import data.
- p. During November 2014 onwards Applicant's plant has been admittedly been shut down and there is no news of reopening yet. Thus, the injury parameters are bound to show negative results.

#### **Unforeseen developments**

- q. Article XIX GATT requires satisfaction of 2 essential conditions – (i) unforeseen developments and (ii) effect of obligations incurred under this Agreement including tariff concessions; which results in increase in imports threatening or causing injury to the domestic producers. Unless these conditions are satisfied, safeguard measure cannot be imposed.
- r. The Applicant has to show how certain developments were unforeseeable when India incurred the obligations under GATT in 1994, which have led to the increase of imports in the period of investigation. If the Applicant fails to explain the same, the burden still remains on the Authority to carry out the above analysis.
- s. Neither the petition, nor the initiation notification for the subject investigation has identified any unforeseen developments that led to an increase in imports of the subject product.
- t. Existence of FTA per-se does not constitute 'unforeseen developments' and it was in common knowledge in public domain.
- u. India has given a bound rate commitment before WTO for Steel Products as 40%. India has unilaterally reduced the Customs Duty to 5%. There is a further reduction by India in terms of FTAs entered into with some of the countries. Thus, the reduction has been a policy decision by India itself, which cannot be referred to as obligation incurred under GATT.
- v. The increase in imports as alleged in the petition could be due to existence of FTA with ASEAN and CEPA with Japan and Korea.
- w. As customs duty decreased pursuant to obligation under CEPA, imports from Japan also showed a corresponding increase. This clearly shows that increase in imports is due to FTAs entered by India.

#### **Existence of alternative remedy**

- x. India has already imposed anti-dumping duty on imports of Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel - 400 series from Korea RP, Thailand, China PR, EU, USA, South Africa and Taiwan vide customs notifications 14/2010-Customs dated 20<sup>th</sup> February, 2010 (modified pursuant to a review vide Customs Notification No 86/2011-Customs dated 6<sup>th</sup> September, 2011) as well as Customs Notification No 46/2012-Customs dated 4<sup>th</sup> October, 2012.
- y. The present case, imposition of anti-dumping duty on subject product has already removed the injurious effects of imports of subject goods.
- z. If Applicant felt that amount of protection provided by way of anti-dumping duty was insufficient, it could have applied for an interim review, wherein anti-dumping duty could have been increased depending on level of injury suffered by the Applicant.

#### **No surge in imports**

- aa. The imports are not recent, sudden, sharp and significant, because of which the threshold criteria itself is not met.

**No credible evidence of serious injury or causal link**

- bb. The applicant industry has presented *no credible evidence* to make out a case of serious injury. Furthermore, it has *withheld crucial injury information on a number of factors* apart from the fact that the facts presented in the application itself do not make out a case of serious injury.
- cc. The methodology prescribed for segregating capacity for 400 series from total capacity is still unclear.
- dd. Mere comparison of capacity utilization from base year to 2014-15 in isolation, as stated by Applicant, is an incorrect approach and needs to be seen vis-à-vis capacity addition by Applicant.
- ee. During 2012-13 and 2013-14, applicant had to incur a significant amount towards power and fuel expense, which was one of the critical reasons for losses to applicant.
- ff. Losses to Applicant due to factors such as abnormal increase in power expenses cannot be attributed to imports.
- gg. Significant losses to Applicant may be on account of increasing fixed expenses incurred for doubling its capacity.
- hh. From the annual report of Applicant, it is clear that fixed costs of the Applicant have been consistently increasing since 2010-11. This increase in fixed costs is commensurate with steep decline in profitability projected in the petition filed by the Applicant. It may also be seen that with increase in depreciation charges and finance charges, Applicant also incurred heavy losses, thereby exhibiting positive correlation between the two. Thus, it is illogical to blame imports for its significant decline in profitability, when import quantities have actually remained at same level with increasing landed value. This shows that there are some other factors, like abnormally high depreciation and finance charges which are causing injury to the Applicant. This conclusively shows that it is not imports but some other factors, which are responsible for losses to Applicant. Therefore, the causation analysis fails in the present investigation and the same is liable to be terminated.
- ii. Production cost per unit with respect to power & fuel cost, depreciation and finance charges have gone up each year compared to 2011-12. This proves that the losses to Applicant are indeed due to factors other than imports.

(Rs. in Lacs)	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Production of CRSS 400 series (as per petition)		67,876	83,240	94,929
Power & Fuel (Rs in crores) (Annual Reports)		815.5	1,235.18	1272.08
Per Unit (Rs/MT)		<b>0.012</b>	<b>0.015</b>	<b>0.013</b>
Depreciation	35,614	40,861	70,130	68,766
Per Unit (Rs/MT)		<b>0.60</b>	<b>0.84</b>	<b>0.72</b>
Finance Charges	38,874	51,680	99,029	123,470
Per Unit (Rs/MT)		<b>0.76</b>	<b>1.19</b>	<b>1.30</b>

- jj. Landed value is calculated by adding customs duty and education cess to the **assessable value** and not CIF value of imports.
- kk. Applicant sells subject goods in Slit form and not in Wide Coil form. Similarly, subject goods are imported into India in Wide Coils form, which is then cut into Slit form and sold further in India. The correct method of apple to apple comparison between imported goods and domestic like article is by comparing the Slit Form of subject goods only and not by comparing the import price of Wide Coils imported into India
- ll. Applicant has not indicated whether there exists any price underselling, price depression or price suppression and has claimed injury without providing any such data. Since such information has not been

provided in the non-confidential version of the petition, it goes without saying that same would not have been provided to DGS in confidential form as well.

**Requirement to establish causal link between increase in imports and serious injury**

- mm. As per Section 8B of the Customs Tariff Act 1975 read with Rules 5 and 11 of the Indian Safeguard Rules, the Authority is also required to establish a causal link between such “increased imports” and “serious injury” to the Applicant. Without such a causal link, no safeguard duty can be imposed in the present investigation.
- nn. The petition filed by the Applicant clearly shows the following:
  - (a). Even at the beginning of the 2011-12, when imports were low, Applicant had been suffering losses.
  - (b). Price effect of imports on performance of Applicant is clearly absent as even a smaller increase in imports (both quantity and price) led to a significantly disproportionate decline in profitability of Applicant. This trend is visible between 2011-12 and 2012-13.
  - (c). Between 2012-13 and 2013-14, there was complete lack of correlation or absolute negative correlation between imports and performance of Applicant, which proves lack of causal link. While import quantities remained constant and import prices actually increased, between 2012-13 and 2013-14, per unit losses almost tripled, cash losses increased by almost 6 times and ROCE declined by more than 15 times.

**Unworkable adjustment plan**

- oo. The adjustment plan should be specific only to product concerned and should not be used to rectify problem of entire company, irrespective of products in question.
- pp. Since nothing has been put on record, the Applicant does not have any concrete adjustment plan and is only trying to take undue advantage of safeguard measure.
- qq. Keeping all the details confidential, Applicant has suggested that there will be cost reduction in power cost as a result of readjustment. However, in support, it has not provided any supporting evidence to substantiate its claim.
- rr. Applicant did not substantiate the need for a provisional measure.
- ss. The DGS accepted the Applicant’s confidentiality claims and conclusions derived from it despite the fact that the NCV of the petition said nothing about why this information should be treated as confidential and why this information was not susceptible to public summarization.
- tt. For the sake of transparency, DGS is required to disclose the methodology, which it may use to determine the level of safeguard duty.

**F. M/S ELP Advocates & Solicitors filed written submissions on behalf of M/S. NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL CORPORATION, M/S. NISSHIN STEEL CO. LTD., M/S. JFE STEEL CORPORATION, M/S. OUTOKUMPU STAINLESS OY, FINLAND, OUTOKUMPU NIROSTA GMBH, GERMANY AND SHANGHAI KRUPP STAINLESS CO. LTD**

**Adequacy and Accuracy of Information**

- a. Transaction-wise import data provided by the Petitioner is incomplete and covers only the period from January 2014 to June 2014.
- b. The basis and manner in which the said import data has been segregated and refined to arrive at the final import data relied upon for the purposes of the initiation of the investigation has not been explained in the Petition.
- c. The import data based on which the present investigation was initiated itself contains entries that are not part of the product under consideration in the first place. Further, the import data provided by the Petitioner also contains various entries where the grade itself is unidentified.
- d. The import data should be determined afresh and all non-product under consideration transactions should be strictly excluded from the import data. Upon finalization of the import data, the same should be circulated to the interested parties and all the interested parties should be given a fresh opportunity to verify the same and present their views in a public hearing.
- e. Several of the products are still not manufactured by the Petitioner and should therefore be excluded.

**Absence of Unforeseen Circumstances**

- f. It is a well established principle under GATT Article XIX that it must be demonstrated that the increase in imports is caused by unforeseen developments.
- g. Neither the Initiation Notification nor the petition of the Domestic Industry provides any information with respect to the unforeseen circumstances or events which have led to increase in imports in such quantities.
- h. The Petitioner has yet to prove that the global demand and gap supply was unforeseen.
- i. The claim of the Petitioner is self-contradictory and inconsistent from the information provided by it pertaining to trend of imports/exports by China and demand-supply gap in China at page 16 and 17 of the Petition respectively.
- j. Cost advantage that producers may have in other countries is no basis for a sudden increase in imports. Further, these cost advantages are neither unforeseen nor arising out of India's obligations or concessions under the GATT.
- k. A mere perusal of the import data provided by the Petitioner reflects that there has been no increase in the imports from the EU and in fact, in 2014-15(annualised), the imports from the EU have marginally increased but show continued decline as compared to 2012-13.
- l. The Demand Supply Gap i.e. Production *less* Apparent Consumption, is constant in Japan, which indicates that no unforeseen trends were observed in the period in question.
- m. The reduction in duty rates pursuant to an FTA/PTA is neither unforeseeable nor unexpected but rather common knowledge.
- n. The submission of the Petitioner that the continued imports despite imposition of anti dumping duties is an unforeseen development is wholly baseless and illogical.
- o. Imposition of trade measures against producers based in Malaysia, China, Indonesia, Korea, Germany, Finland, Vietnam and Taiwan by merely 3 countries i.e., Vietnam, Taiwan and Brazil has caused an increase in imports into India is merely fanciful and incorrect.

**Abuse of Confidentiality by the Petitioner**

- p. Petitioner has failed to provide adequate disclosures of the data as required by the Questionnaire as Annexure to Trade Notice No. SG/TN/1/97 dated 6th September, 1997 issued by the Hon'ble Director General (Safeguards).
- q. Costing information of the Petitioner has been marked confidential and the same should have at the least been indexed.
- r. The actual individual production quantity of the Petitioners and other domestic producers has not been provided.
- s. The details of the import data from China Customs has not been provided.
- t. The various Reports from *Heinz H. Pariser Weekly Fax Service* relied upon for information on China demand, supply, exports and imports have not been provided.
- u. The CRU data for China, Japan, Korea and EU has not been provided.
- v. The complete adjustment plan of the Petitioner has not been provided and unreasonably has sought information to be kept confidential.

**Increased Imports**

- w. The analysis for the entire year(2014-15) is conducted based on data for only 3 months(April,14 to June,14) instead of the actual period of 12 months causing the examination of "increased imports" to be based on a prospective period and not a period in the recent past.

**Absence of Injury**

- x. The Petitioner has failed to provide adequate evidence to back up its claim of injury based on the factors viz production, market share and demand, sales of petitioner, productivity, capacity and capacity utilization, inventories, price effect, profitability and threat of serious injury

**Breach in Causal Link and other factors causing Injury**



- y. Rule 11(1) (b) of Safeguard Duty Rules provides that a causal link must exist between the increased imports and serious injury or threat of serious injury.
- z. The alleged increase in imports has not adversely affected the operations of the Petitioner, in fact the production, domestic sales and the market share of the Petitioner has increased in congruence with the demand in India.
- aa. The Petitioner has been adversely affected on account of several factors inter alia, such as increase in raw material prices, volatile currency, operational issues which affect capacity utilization; and the alleged serious injury is not attributable to the imports of the subject goods.

#### **Public Interest**

- bb. Imposition of Safeguard Duties on the product under consideration would be contrary to public interest as various downstream industries such as the automotive industry will suffer from the following adverse effects.
  - (a) In order to meet the prescribed statutory emission norms for motor vehicles under the Central Motor Vehicle Rules, 1989, the auto industry has to import high quality, fatigue resistant stainless steel products.
  - (b) If Safeguard Duty is imposed, then the auto industry will have to either pay higher prices or revert to importing the exhaust system in toto which will then lead to loss of employment in India.

### **G. Written Submission filed by M/S Maruti Suzuki India Ltd**

#### **Procedural Issues**

- a. The Authority has completely ignored the provisions of FTA between the Govt. of India and the Republic of Japan in relation to bilateral safeguards and the special conditions and procedure set out therein. Further, imposition of safeguard measures will be detrimental to the relationship between the two nations.
- b. Article XIX of GATT 1994 has not been complied with.

#### **Adequacy and Accuracy of Petition**

- c. The accuracy of import data provided by Applicant is questionable. The Applicant has not supplied any methodology of determining the PUC, raising serious doubts on the authenticity of the data.
- d. The paucity of time between the receipt of import data of the PUC and the timeline for making submissions before the Authority has made it difficult for the Respondent to analyze and independently verify the so-called import data.

#### **PUC and its Scope**

- e. There is fundamental and substantial difference between the PUC produced by the Applicant and the imported product. The PUC manufactured by the Respondent is of superior quality than the one manufactured by the Applicant. The Respondent manufactures the product using state-of-art technology and in accordance to the unique specifications of the consumers which the DI is not in a position to manufacture. Further, the Respondent's imported PUC is mostly used in the automotive exhaust system. The specifications and requirements of this sector are strictly adhered to. As such, this difference in specific quality of PUC of the Applicant and the Respondent should be taken into account.

#### **Standing**

- f. The Applicant claims to be the major producer of the PUC in India, and that its share increased from 85% to 88% in the total Indian production. As such, there is no reason why a market leader with such high market share be affected by the imports.

#### **Increased Imports**

- g. The increase in imports is minuscule. The import data considered for the year 2014-15 is only for three months. No reason has been provided by the Applicant for the annualizing of this data. Also, subsequent submissions by the Applicant with regard to imports cannot justify initiation of investigation.
- h. The increase in imports is not sudden or significant causing sudden disruption to the DI. The increase is gradual and hence, there is no causal link between the increase in imports and the injury suffered by the DI.

**Serious Injury**

- i. There is no evidence of a serious injury. Reliance and disclosure of certain information and the concealment of other selective information is a deliberate attempt on the part of the Applicant to initiate an investigation on fallacious pretexts.

**Other causes of injury**

- j. It is important that the other causes of injury should not be related to the imports. As such, the available information shows no injury in the volume effect, capacity, sales etc.
- k. In the recent past, the Applicant has seen unforeseen expenditure in the form of increasing power expenses. This has been a reason of injury to the DI.
- l. The Petition has maliciously not mentioned the fact about the closure of the Odisha Plant of the Applicant due to disregarding environmental norms.

**Causal Link**

- m. The Applicant has filed the Petition without any material proof and the Petition lacks any prima facie evidence.
- n. In determining the price undercutting the Applicant has inflated the landed value of imports. As a result, the price undercutting has also been inflated. In relation to the same, it is also pointed out that a mere three months' data is also unreliable.
- o. Price underselling, depression and suppression have not been mentioned even in indexed form in the NCV.

**Unforeseen Development**

- p. The unforeseen developments contributing to the increase in imports have not been provided in the Petition. Also, the import duty for imports from Japan might actually have been reduced over the past few years, as acknowledged by the Applicant also in the Petition.
- q. The DI in its submissions has denied the existence of the concept of "unforeseen development" in the Indian context. However, India is a signatory of the WTO Agreement on Safeguards and GATT, the existence of this parameter cannot be dismissed outrightly.

**Adjustment Plan**

- r. The adjustment plan provided is incomplete and most of the information has been requested to be kept confidential by the Applicant. Further, the Applicant has refrained from answering few important questions on the application format such as full and detailed information about existence of critical circumstances and how would delay cause damages which would be difficult to recover.

**Miscellaneous Issues**

- s. The Applicant has resorted to extreme confidentiality. The Applicant has not informed of the important economic parameters such as price underselling range, list of major raw materials, investments made, net worth, depreciation, expense, interest expense etc. The questionnaire prescribed for domestic producers is also not provided, detailing out the adjustment plan. Even in the Petition, the Applicant has been granted confidentiality on unreasonable grounds. No reason has been provided by the Applicant as to why the information should be treated as confidential.
- t. The Applicant has requested the safety duty to be in tandem with the injury margin. However, there is no injury margin in safeguard investigations. Thus, the methodology of determining the safeguard duty will have to be disclosed by the Authority for the sake of clarity.
- u. The PUC is already under the subjection of anti-dumping duty. The imposition of safeguard duty will only burden the consumers in India. The automobile industry will also suffer as there is anti-dumping duty levied on the imports and the scrapping of benefits on the industry by the Central Govt.
- v. The Indian State should abide by the WTO Agreements and provisions.
- w. The DI is banking on the doctrine of "legitimate expectation". However, this is not possible to the DI in isolation. The Govt. had not promised the DI anything and Rights under Article 14 and 21 do not arise to the Applicant.
- x. The Applicant has relied on other countries like Thailand etc., imposing safeguard measures on the Respondent. However, the named countries have not done so in actuality.

(4) Following interested parties submitted rejoinders, to the written submissions of other interested parties

M/S Jindal Stainless Ltd (Domestic Industry)
--

M/s. Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel Corporation, M/s. Nisshin Steel Co., Ltd. and M/s. JFE Steel Corporation
M/S Outokumpu Stainless Oyj, Finland
M/S POSCO , Korea
M/S Baharu Stainless, Malaysia, M/S Metal One India Pvt. Ltd & Stainless Steel Marchant's Association
M/S Maruti Suzuki India Ltd.

(5) The brief summary of the rejoinder filed by above interested parties to the written submissions of other interested parties are as under:

**A. Brief of Rejoinder filed by M/S TPM Consultant on behalf of M/S Jindal Stainless Ltd. (Domestic Industry)**

- a. There has been no concealment of facts by the petitioner. The questionnaire response was filed in October whereas the temporary shut-down took place in the month of November. The petitioner was forced to briefly suspend production of Odisha because of its inability to install certain Pollution Control Equipments within the time frame given by Govt. of Odisha. Consequently, the petitioner was not able to produce the product temporarily, during the period 16<sup>th</sup> November 2014 to 20<sup>th</sup> December, 2014 and there is no interruption thereafter
- b. The petitioner has enclosed herewith production record (ER) for the month of Dec'2014 which would clearly show that the plant has commenced production after a brief shut down
- c. The petitioner is not obligated to provide transaction wise import data. T/T data is relevant only to the Director General (Safeguards) for the purpose of satisfying itself with regard to accuracy of information and the same was provided to the Director General (Safeguards). Notwithstanding, on demand of Director General (Safeguards), the petitioner has provided entire T/T data to the Director General (Safeguards) and the same has been made available to all opposing parties. All relevant information has been submitted to the Director General to analyse the imports and come to a reasoned conclusion
- d. Petitioner has provided complete information for the period upto Sept 2014 in the written submissions filed earlier. Imports and volume parameters has been further given for the period upto Dec 2014. This was the specific request of the interested parties at the time of hearing. This was the specific direction of the Director General to the petitioner.
- e. The product scope considered under the AD investigation is different than the product scope in the present investigation. Majority of imports are of wide products, which is beyond the scope of the product under consideration considered in the AD investigation. Further, imports from Japan are not attracting anti-dumping duty and imports of narrow width products (CR<400 mm) are attracting anti-dumping duty on the basis of benchmark form where the imports are happening above the benchmark prices.
- f. Petitioner has never submitted that the Director General (Safeguards) should conclude existence of surge in imports based on three months period. Petitioner has already provided information for the period upto Dec.14 and the Director General (Safeguards) may kindly determine surge in imports on the basis of imports during April-Dec.14 period
- g. A long drawn process is required to be followed by the Director General (Safeguards) before the Director General (Safeguards) may draw any conclusions. Thus, at the stage of initiation, the Director General has not drawn any conclusion with regard to the need for imposition of safeguard duty
- h. The petitioner has indeed relied on product description to segregate PUC. This is precisely the reason why petitioner has chosen those entries where plate/sheet/strip were appearing under the heading of 7219 & 7220. What the respondent has chosen to ignore is that part of the methodology where the petitioner has stated that grade identification was also done. This implies that even in those cases where the word stainless was missing from the product description, petitioner has considered the entry only if a 400 series stainless steel grade was appearing
- i. The quantity involved in other grades as well, such as 300 series (304L) which are also used in automotive sector is negligible and will have no bearing on the analysis
- j. Grade MH-1 is a ferritic grade which can be ascertained from a simple search on the internet. Interested parties are simply trying to impede the investigations by misleading the Director General. Further, one of the interested part, M/s Maruti, itself have claimed that they are importing product under consideration, MH-1 from Japanese Companies.

- k. It cannot be a case that the volume of imports upto 2013-14 are considered from petitioner's submissions and the conclusion of interested parties is superimposed on the same.
- l. Petitioner fails to understand why the product should be imported in wider width and an additional cost should be incurred in India, when seller of the product can supply the product in a width required by the consumer. The goods produced and sold by the petitioner are not required to be slit by some standalone slitters. The goods are being procured by the consumers and thereafter used for the eventual purpose
- m. It is well understood legal position that there may be a number of factors which may collectively lead to increased imports. It is not necessary to identify one single parameter which has resulted in increased imports, nor there may be one single parameter in a complex market situation that may lead to increased imports
- n. Steep reduction of customs duty as a result of obligations incurred by Govt. of India before WTO is the starting point for the increased imports. The Govt. of India reduced customs duty on the product from over 85% about two decades back to 7.5% in the current period. This has been the starting point for increased imports.
- o. Surplus capacities with the global producers, compulsion with the global producers to make effort in optimizing production in view of the production process involved, shrinking market opportunities in domestic and other markets for these foreign producers, reduction in customs duty in India, increasing demand for the product in India have collectively and cumulatively encouraged foreign producers to look for Indian market as a major market opportunity
- p. These Agreements themselves envisage that result of these FTAs may be an increase in imports and the situations may even demand invoking safeguard measures. This itself establishes that it is not foreseen while signing these agreements that the result of these agreements shall be increased imports and consequent injury to the domestic industry
- q. It is not the petitioner's case that FTA per-se is an unforeseen development. Reduction of customs duty by India under WTO obligation coupled with concessions granted under FTA is unforeseen development. Had the Government not reduced customs duty under the WTO obligation, the tariff concessions given under the FTA would not have caused injury to the domestic industry. This gets established by the fact that if tariff under WTO is restored to the levels prevailing prior to the negotiations, the effective customs duty on the FTA countries would have been significant enough to protect the domestic industry, despite the FTA concessions.
- r. Major exporting nations China and Korea, have attracted anti-dumping duty since late 2013. The EU Notification issued in Dec 2014 in the matter of anti dumping investigation concerning imports of stainless steel cold-rolled flat products originating in the People's Republic of China and Taiwan, making imports from these countries subject to registration, also recognizes the fact of imposition of duties on the product concerned
- s. Capacity for the product under consideration has been determined on the basis of production achieved in 2011-12. Once the company has achieved this level of production, there can be no dispute with regard to this capacity for the product, which shows decline in capacity utilization.
- t. As regards the per unit calculation of power, depreciation and interest cost, the respondent has divided the total figure appearing in the annual report by the production of the domestic industry. This method defies logic as the respondent has taken the figures for the company as a whole and loaded it only on PUC. The per unit power and fuel consumption in Odisha for PUC has actually come down since the start of operations and yet the losses have gone up.
- u. 1% is added to the CIF import price only for the purpose of determining customs duty. This 1% is not payable to any party. Such being the case, there is no basis for the submissions that 1% should be added to the CIF value to determine landed price of import
- v. Both the cost of production and selling prices of the domestic industry has increased. However, the increase in selling price were lower than the increase in cost of production. Whereas cost of production increased by about 24% over the period, the selling price increased only by about 5%
- w. The industry was incurring loss even in the start of the investigation period as the dumped imports were causing injury as a result of which ADD was imposed. Further, there is no basis for the argument that the imports were "low" in 2011-12
- x. The Rupee went down from levels of Rs 55 in 2012-13 to Rs 61-62 in 2013-14 and it has remained at those levels thereafter. However, despite more than 10% depreciation of the Indian rupee, the landed price increased only marginally in 2013-14 and thereafter, in fact, came down in 2014-15. This resulted in significant suppression of the prices of the petitioner as the cost went up during this period but the legitimate price increase did not happen
- y. While it is accepted and appreciated that the phased reduction was widely known the moment the FTA were made public, what was not known at that time was that these reductions in FTA shall cause injury to the domestic industry. The contention of the interested parties seems to be that the Govt. of India signed

- these FTAs after being fully aware that these concessions shall be causing injury to the domestic industry in several hundred/thousand products!
- z. The petitioner has provided a non-confidential version of the Adjustment plan to interested parties which provide an outline of initiatives proposed to be undertaken. It is submitted that specific details cannot be shared with other parties as the same would be detrimental to the interest of the petitioner
  - aa. Relevant provisions of the Rules would reveal that the adjustment plan is mentioned in the context of duration of measure. Adjustment plan is not mentioned in the context of imposition of measure. Adjustment plan is not relevant with regard to the question of imposition of safeguard duty
  - bb. petitioners price parameters are being asked to be disclosed whereas the even the volume parameters of the interested parties are being claimed confidential.
  - cc. At one hand the party is asking for the range of underselling, which is not a concept recognized under Safeguard rules, but at the same time it is disregarding the concept of injury margin. Petitioner has claimed injury and quantified the same considering the past practices of the Directorate
  - dd. The listed parties are not the only parties to whom Metal One Corp has supplied. Metal One Corp has supplied to several automobile companies. Petitioner has also sold to several automobile companies. This is yet another instance of interested parties making misleading and even false statements.
  - ee. The domestic industry has never regretted supply of the material on the grounds of technical capabilities. The petitioner can supply a product only if a consumer places the order for the same. However, for similar application, petitioner has supplied the product to other consumers in the country. There is no legal requirement under the safeguard law that the petitioner should have met the requirements of each and every consumer of the product in the country
  - ff. It is not the submission of the petitioner that increased imports should be concluded on the basis of 3 months imports. The trend projected by the petitioner was correct and in fact imports have further increased.
  - gg. The petitioner has determined volume of imports after considering all these technicalities. In fact, the petitioner has considered only those import entries wherein the unit of measurement was either in the kilogram or in MT. In steel industry, majority business happens on weight basis, even if the consumer requires the product in a unit other than weight. As regards products not forming part of PUC, since the petitioner has not included those entries, in any case, such transactions have not vitiated the analysis.
  - hh. The interested party has cleverly referred to the investigation concluded in 2009 and has ignored the investigation thereafter concerning imports of Stainless Steel Cold Rolled Flat Products of 400 Series having width below 600 mm originating in or exported from European Union, Korea RP and USA, wherein no exclusions were provided for.
  - ii. The non substitutability claims have not been shared with the petitioner. This is grossly inappropriate and is violation of Rule 7 of the Safeguard Rules. The interested party should establish how the difference in process results in the imported product being different from the product produced by the domestic industry. Such information should be made available to the petitioner for comments.
  - jj. Increased imports are not required to be seen in respect of individual company or country. Increased imports are required to be seen collectively from all sources. This is a fundamental difference in anti dumping and safeguards. Further, unforeseen developments are also not required to be identified with individual countries
  - kk. The countries having surplus capacities were utilizing their capacities by exporting to other countries or were not able to tap the Indian market in the past. Now that these producers are looking for Indian market in an increased manner when domestic industry has significantly expanded capacities was clearly an unforeseen development. Additionally, the demand for the PUC in Europe declined in this period, which was clearly an unforeseen development.
  - ll. Low cost of power and coking coal in China was present in China for quite sometime. However, China has capitalised on these cost advantages because of continued power crisis in South Africa which is clearly an unforeseen development as South Africa is the biggest manufacturer of chromite ore; South Africa has power crisis and therefore is not able to convert chromite ore into ferrochrome which is one of the most important raw material for the product concerned; China imports chromite ore from South Africa; South Africa had announced some major power projects which were expected to come online by 2013 and would have taken care of the power deficit. However, evidence enclosed would show that no project has even started operation. This fact was unforeseeable leading a situation where China continued to capitalize its cost advantages.
  - mm. The demand for the PUC in Korea has not shown a significant increase and has not been sufficient enough to absorb capacities available with the Korean producers. Thus, the Korean producers have to look for international market for exporting the product
  - nn. The interested parties have on one hand contended that the tariff concessions under FTA were well known; and at the same time, have contended that the reduction in customs duty have been too

- insignificant to trigger an increase. At the same time, a number of interested parties in fact have conceded that the increase in imports is due to tariff concessions
- oo. Further, surge in imports has occurred during 2014-15. Therefore imposition of duties in 2013-14 is an important development relevant to show reason for increase in imports. After imposition of duty, the market of the country taking action gets restricted. Further, it can be fairly assumed that exports by subject countries involved were significant to these countries which are now being further diverted to India
  - pp. The petitioner has stated in the Annual Report that inspite of the challenges, the production was not allowed to suffer on this account. It nowhere states that the production declined in view of the difficulty in obtaining chromite ore. Further, while the plant was under ramp up in 2011-12 & 2012-13, it was fully functional/operational in 2013-14 & 2014-15.
  - qq. Imports increased significantly in 2012-13 when the profits dipped. Similarly imports were at similar region (at significant level) in 2013-14. While the raw material costs increased significantly, import prices went up only marginally. Thus, profits declined significantly. The continued high imports in 2013-14 caused further price injury to the domestic industry. Thereafter imports have further increased in the current year, leading to further decline in the profitability. Thus there is a direct causal link between the imports and profitability.
  - rr. The capacity expansion was planned in 2003-04 in view of the growing demand in India. Thereafter, when dumped imports increased the petitioner expected that imposition of anti dumping duty would lead to curbing of dumped imports leading to increased sales and profitability to the domestic industry in the segments covered under anti dumping duty. However, ADD has not yielded the desired effect and the global situation also changed leading to increase in imports
  - ss. The argument that traditionally steel trade increases during the first quarter of every fiscal year when importers finished clearing the goods in stock is incorrect as the quarter wise analysis of imports from the period April-Dec 2014 shows increasing trend.
  - tt. world globally knew that China is expanding its steel capacity. The fact that was unforeseen was that China would expand much more than the demand and would be able to leverage heavily because of power crisis being faced in South Africa. China was a net importer until 2009. The sudden expansion of capacities was unforeseen.
  - uu. POSCO has not filed questionnaire response. The claim of absence of surplus with POSCO cannot be accepted without questionnaire response. Without prejudice, it is a safeguard investigation and therefore individual company data/situation is entirely immaterial
  - vv. The Mexican imports constitute almost 12% share in total imports. Furthermore, Mexico embassy's shows even higher share in total imports
  - ww. When the FTA itself provides for safeguard measures, it means that such a situation is envisaged by the nations while entering into the agreement. The safeguard measures are a temporary phenomenon. The duties are not perpetual to disturb the relations between the nations
  - xx. The argument means that if a company is catering to 95-100% of market and is the sole producer, it is unlikely to be impacted by imports! There is nothing in the law or in the practice which can be implied to mean such a situation.
  - yy. Petitioner reiterates that unforeseen development is not at all required under the Indian Rules. In fact, this is not the view of petitioner alone. The Director General has repeatedly recorded in the Final Findings that unforeseen development is not a requirement for the Director General's determination
  - zz. The impact on automobile industry is negligible. The interested party has not quantified the alleged burden on the automobile industry. Further, the petitioner is regularly supplying product to various auto companies and therefore the respondent also has the option of procuring supplies from the petitioner.
  - aaa. If stainless steel forms a very small portion of the overall requirement, then the impact of imposition of safeguard duty is going to be negligible on Hindustan Syringes & Medical Devices Ltd

**B. Brief of Rejoinder filed by M/S Laksmi Kumaran & Sridharan on behalf of M/S Metal One Corporation India (P) Ltd, M/S Baharu Stainless SdnBhd and Metal & Stainless Steel Merchant's Association**

- a. The import statistics relied upon by the Applicant has not been provided along with the Application copy. A non-confidential version of the Application should be a replica of the confidential version of the Application. If transaction by transaction import statistics were indeed made available along with the application, then the same should have been provided along with non-confidential version of the application as well.
- b. There is nothing confidential about the import statistics (which is evident from the belated disclosure by the Applicant itself). Since the same was not made available to interested parties, there was a reasonable apprehension that import statistics were not made available.

- c. It is the Applicant who is alleging surge in imports into India. Thus, onus is on the Applicant to prove that there exists surge in imports by providing substantial evidence.
- d. Upon inspecting the public file, it was found that Applicant had filed only the PDF version of the import statistics.
- e. The PDF version is useless in examining the correctness of the import statistics provided. From the same, it cannot be determined whether the import listing contains only the subject products or some other products as well.
- f. The methodology provided by the Applicant has serious problems and any segregation of import statistics based on such methodology cannot be relied upon.
- g. Respondent has already provided its own methodology for segregation of import statistics and import statistics for 3 months (April'14 to June'14), which itself shows a huge difference in the import quantity as compared to Applicant's data.
- h. Following are few of the transactions, which do not indicate whether they are covered under the definition of product under consideration but included in the import statistics:
  - i) For chapter headings – 72192299, 72191190 (Relating to Hot Rolled Coil); 72091620 (Flat Rolled Products of iron or non-alloy steel); 72189990 (Stainless Steel in ingots or other primary form); which do not concern with subject product;
  - ii) For following transaction descriptions, which do not indicate whether it belongs to 400 series or not:
    - a. Cold Rolled Stainless Steel Sheet in coil (JFE MH-1) (Size: 1.50MM x 1028MM x C) 3 coils
    - b. Cold Rolled Stainless Steel in coils: SUS 340 2B: (1.00MM x 1260MM x C)
    - c. Cold Rolled Stainless Steel Sheet – Size: 1.2MM x 1260MM x C -) Grade: QCA0964C), etc
- i. If Applicant was not satisfied with the level of protection, it could have applied to Anti-Dumping Authority for an interim review (including product scope review to expand the scope).
- j. Applicant has also alleged circumvention of anti-dumping duties by stating that despite anti-dumping duties in force, imports are being cleared without payment of anti-dumping duty. There is a separate mechanism prescribed under the anti-dumping law to take care of the situation wherein circumvention exists. The correct remedy lies before the Designated Authority, DGAD and not before DG Safeguards.
- k. Applicant has admitted that it has not supplied certain grades such as 429, 432, 444 and 1.4521. Since there is no competing like article in India for these grades, such grades need to be excluded from the scope of the present investigation and imports of such grades should not be taken into account while determining the quantum of imports.
- l. Applicant's cold rolling mill in Odisha was closed by Pollution Control Authority in November 2014. It is not known whether it has reopened or not. Applicant has not provided anything yet so far to show that the plant has indeed reopened.
- m. in order to show an increasing trend, Applicant has compared complete years of 2011-12, 2012-13, 2013-14 with annualized figures of each of the three quarters of 2014-15, when it could have simply given annualized figure of April-December 2014.
- n. if entire data for April to December 2014 were taken into account as a whole instead of quarter-wise, then following trend would have resulted:

Particulars	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
Imports (MT)	64,889	87,051	87,178	102,200
Demand (MT)	140,600	176,342	182,423	206,685
Imports in relation to demand(%)	46%	49%	48%	49%

- o. The Applicant's own data shows that imports have only increased in proportion to increase in demand and there is no extraordinary or sudden or sharp or significant increase in imports
- p. Though there was excess supply in global market for last 5 years and imports from such countries were happening, then how all of a sudden, increase in imports for only 3 months caused such a significant injury, that Applicant was forced to approach the Authority.
- q. Reduction of customs duties as a result of FTAs is a well-known fact and such an independent obligation incurred by India cannot be considered as an unforeseen development.

- r. To counter trade remedy measure imposed against imports of subject goods by other countries, which resulted in diversion of subject goods into India, India has already imposed anti-dumping duties into India.
- s. Applicant is also alleging that anti-dumping protection granted is inadequate in addition to the fact that circumvention of anti-dumping duty is also taking place.
- t. As regards possible circumvention of anti-dumping duties, the Designated Authority in DGAD has powers to conduct investigation with respect to circumvention of anti-dumping duties.
- u. The lacuna in the injury analysis conducted by the Applicant is the comparison of yearly data with the quarterly data in its trend analysis. Instead of clubbing together the three quarter of 2014-15 and then annualizing it, Applicant has annualized each of the three quarters and compared with previous full years to show an absurd trend.
- v. Imports in relation to total demand has always remained constant.
- w. As regards decline in production during the last quarter, it was not due to imports of subject goods but due to closure of its Cold Rolled Plant in Odisha due to Pollution norms violation.
- x. Based on installed capacities, the capacity utilization has infact improved over the period of investigation.
- y. Capacity utilization during Q3 of 2014-15 was bound to decline as Cold Rolled Plant of the Applicant was shut down by pollution control board.
- z. As regards the contention that market share of the Applicant has been taken away by imports, the market share of imports since 2011-12 has been around 47 to 48%, whereas Applicant has had market share of 44 to 45%.
- aa. As regards the position of the Applicant in respect of domestic sales, it is undisputed that its domestic sales have increased consistently over the period of investigation.
- bb. Further, the claim of the Applicant that its sales did not increase proportionate to increase in demand is baseless even in terms of its own data.
- cc. As regards price effect, Applicant has claimed that its cost of production has increased considerably and because of which, it is not able to match its selling price to that level. Firstly, the Applicant substantially almost doubled its capacity in 2012-13. Such a huge increase in capacity is bound to increase the cost of production in the initial years of installation and will go down subsequently as yield improves.
- dd. Decline in profitability of the Applicant was not due to imports but due to intrinsic factors such as power and fuel expenses, high depreciation, finance charges, etc.
- ee. As regards the factor Significant capacity with exporting countries, it is a settled position that mere existence of excess capacity is not conclusive of injury or threat of injury to the domestic industry. In this regard, Respondent places reliance on the decision of CESTAT in an anti-dumping dispute in Indian Spinners Association vs Designated Authority [2004 (170) ELT 144 (Tri-Del)], wherein Tribunal held *existence of surplus production capacity cannot be taken as posing a clearly foreseen and imminent threat of injury*.
- ff. As regards other two submissions made by the Applicant with regard to increase in imports of subject goods and increase in market share of imports, it is to point out again that the increase in imports are not significant or sudden but only in response to market demand. This is evident from the market share of imports in total demand, which has more or less constant throughout the investigation period. Thus, the argument of the Applicant has no merit and needs to be rejected.
- gg. Applicant has stated at Para 96 of its written submissions that there are no other factors that may be attributed to serious injury to the domestic industry, apart from increased imports. In this regard there exist certain other factors causing injury to the Applicant such as power and fuel cost, depreciation and finance cost, start-up cost relating to new plant set up by the Applicant, apart from environmental problem faced by the Applicant including closure of plant by Pollution Control Board.
- hh. In the present case, there does not exist any 'increased' imports in the form of 'sudden, sharp, significant and recent' increase in imports. Further, there is no serious injury due to imports of subject goods into India apart from the fact that Applicant has not provided sound adjustment plan, which will enable it to stabilize in coming years.

**C. M/S ELP Advocates & Solicitors filed rejoinder on behalf of M/S. NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL CORPORATION, M/S. NISSHIN STEEL CO., LTD., M/S. JFE STEEL CORPORATION, M/S OUTOKUMPU STAINLESS OYJ,**

**Transaction-wise data not circulated**

- a. The Petitioner provided the other interested parties with a low resolution scan of the printed import data. Thereby, any analysis of such data was automatically rendered cumbersome since it was difficult to even read some of the entries due to the poor quality of the documents.



- b. The non-confidential version of the Petition contained only a sliver of the transaction-wise data. There was no reason provided as to why part of the import data was hidden in the non-confidential version. In fact, since the same data was disclosed fully at a later stage in the investigation, there is no merit in any confidentiality claim therein.
- c. The import data has several non-product under consideration transactions included in it to exaggerate the increase in imports.
- d. The import data has been filed, it must be kept in mind that the data was provided at a delayed stage, after repeated requests and three months delay.

#### **One Quarter data cannot determine Increase in Imports**

- e. The Petitioner's claim that no increase in imports is based on the annualisation of the three month period is itself factually incorrect and should be disregarded altogether.
- f. The Petitioner claim at paragraph 8 of its submissions that no conclusion is arrived at in an initiation notification. The Petitioner has submitted that a long drawn process is required to be followed by the Hon'ble Director General (Safeguards) for coming to its conclusion. At paragraph 10, the Petitioner also claims that quality and quantity of information improves as the investigation progresses.
- g. The Exporters have repeatedly averred that comparison methodology of a single quarter (albeit in annualised form) is inadequate for the comparison of increased imports.

#### **Anti-dumping Duty is already in Place**

- h. The Petitioner has claimed that the Anti-dumping Duty is unable to protect the domestic industry.  
Any injury caused to the domestic industry on account of dumping is not within the purview of the Hon'ble Director General (Safeguards) in the first place.
- i. As per the Petitioner's own import data summary provided for April to December, 2014, the imports from AD duty levied sources is more than half the total imports in the period.

Particulars	2014-15 (Ann)
ADD Countries	38,807.00
Total Imports	76,650.00
%	50.63

#### **Demerger of Company**

- j. The Petitioner explicitly admits that the de-merger of the company is on account of various reasons only one of which is the increase in imports from China PR. In this behalf, it is interesting to note that subject imports from China PR could accordingly have been targeted by way of an anti-dumping investigation. However, despite being fully aware that it is Chinese imports that are hurting the domestic industry, the Petitioner has cleverly sought to target all other imports as well. The present investigation should therefore be referred to the DGAD immediately for an investigation on dumping from China PR.

#### **Product under Consideration**

- k. The Exporters rely upon their detailed submissions made in this behalf on the scope of the product under consideration.
- l. The present product scope includes several grades and categories of products which were previously excluded from the product scope in the Anti-dumping investigation.

#### **Like goods**

- m. It is obligated to provide evidence of manufacture and supply of the specific alleged grades. If it cannot supply those specific grades and has its own grading methodology, it must establish that its own supplied grades are substitutable with the grades alleged for exclusion.
- n. The domestic industry was asked to provide commercial invoices establishing evidence of sale for each separate grade.

- o. With regard to the claim of the Petitioner at paragraph 25 of submission where it has claimed that no product can be supplied without an order being placed, it is submitted that the product scope involves certain highly specific and specialised product types where even minor differences can lead to substantial differences in quality.
- p. The exclusion requests of the various interested parties, particularly the Exporters are already on record. The Exporters reiterate their exclusion request, and also attach herewith an update in addition list of the grades (“**Exhibit 1**” (**Non-Confidential**)) on which they have sought exclusion.
- q. With regard to the Petitioner’s conclusion on like or directly competitive products, it is pertinent to note that the Petitioner has based its averment on the finding of the Appellate Body in *Korea – Alcoholic Beverages*, in particular the Appellate Body’s examination of “directly competitive or substitutable” products. It must be noted that the referred report is with regard to an anti-dumping investigation and not a safeguard investigation.

### **Domestic Industry**

- r. The source for details of other producer’s production remains unknown. There is no source or data in the public file indicating how this figure was arrived at other than “market intelligence”.
- s. The transparency of the process is as important as the nature and source of the data itself. The Hon’ble Director General (Safeguards) is humbly requested to demonstrate what exercise was undertaken to obtain this information and how its sanctity was validated.

### **Increase in Imports**

- t. The Exporters submit that the alleged increase in imports is based on faulty data which has been sorted while including several non-PUC categories of products.
- u. The import data should be determined afresh and all non-product under consideration transactions should be strictly excluded from the import data. Upon finalization of the import data, the same should be circulated to the interested parties and all the interested parties should be given a fresh opportunity to verify the same and present their views in a public hearing.

### **Reasons for Increase in Imports**

- v. The Petitioner’s submissions do not address any of the objections and issues raised by the interested parties in the preliminary submissions and the public hearing.
- w. With regard to the Petitioner’s claim on imports increasing on account of India and Japan’s FTA, it is relevant to take into consideration the Hon’ble Director General (Safeguards)’s findings in the Safeguard Investigation concerning imports of Flexible Slabstock Polyol (FSB), at paragraphs 39 and 40 of the Final Findings dated 13th January, 2015:

### **Serious Injury**

- x. With regard to the specific injury parameters and the data provided, it is noted that the Petitioner has yet again annualised three quarters individually and then compared three quarters with three previous financial years.
- y. The correct and therefore widely adopted methodology for a comparison of the interim/partial period is to compare the same to the corresponding interim period of the previous year.
- z. For the purposes of three quarters, the Petitioner could simply have compared the data from April-December 2014 to April-December 2013 and previous such periods.
- aa. The three quarters which now indicate sufficient figures to be annualised together may accordingly be combined and annualised for a preliminary comparison.

### **Peculiarities of Steel Plants**

- bb. With regard to Petitioner’s averments regarding the peculiarities of steel plants, it seems the Petitioner itself has admitted at paragraph 75 of its written submissions that there is a severe breach in causal link due to non-attributive factors. As always claimed by the interested parties, the Petitioner’s injury parameters are exaggerated on account of the poorly performing plant at Jajpur.

- cc. Due to the low utilisation of the Jajpur plant, the Petitioner has suffered injury which is now being attributed unfairly to the subject imports.

#### **Capacity and Capacity Utilisation**

- dd. It is critical to note that the nature of the product under consideration is such that the capacities of the Petitioner are swing capacities, i.e., the Petitioner's capacities can be used to make a wide variety of steel products.
- ee. Installed capacity of the domestic industry are not dedicated to the product under consideration
- ff. The Petitioner has not been able to achieve higher capacity utilisation on account of inefficiency of Jajpur Plant, slowdown of ramp-up and stabilisation at Jajpur Plant and challenges in procuring chromite ore from domestic sources at cost effective prices and not owing to the alleged increased imports.

#### **Cost Allocation**

- gg. It is possible for the Petitioner to easily load the costs and losses associated with other products on to the product under consideration.
- hh. The Hon'ble Director General (Safeguards) is therefore requested to verify the cost audit reports of the Petitioner, internal records and systems maintained by the Petitioner as well as the costing provided to the Directorate General of Anti-dumping & Allied Duties considering that the costing methodology and the data remains common.
- ii. The Hon'ble Director General (Safeguards) is requested to verify the cost audit reports of the Petitioner, internal records and systems maintained by the Petitioner as well as the costing provided to the Directorate General of Anti-dumping & Allied Duties considering that the costing methodology and the data remains common.

#### **Demand, Market Share and Domestic Sales**

- jj. the market share of the domestic industry has remained stable in the recent period, and in fact has increased from 2012-13. On an end-to-end basis, there is only a minor decline in market share of less than 1%.

Particulars	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (Ann)
Demand	1,40,600	1,76,342	1,82,423	2,06,685
Domestic Industry Sales	63,734	75,386	81,342	91,735
<b>Market Share in Demand</b>	<b>45.33</b>	<b>42.75</b>	<b>44.59</b>	<b>44.4</b>

- kk. There is a clear and substantial increase in domestic sales over the recent period of analysis.

#### **Price Effects**

- ll. The Petitioner has claimed at paragraph 86 of its submissions that the selling price has not been increasing in conjunction with the cost of production.
- mm. In this behalf, the Exporters submit that the price undercutting continues to be negative even in the recent quarters. Therefore, it is not the import prices that have kept the prices of the Petitioner lower than cost. Rather the Petitioner itself has kept its prices low.
- nn. Further, the cost of production of the Petitioner is admittedly ailed with low utilisation of plants and high logistics costs in raw material procurement.

#### **Profitability**

- oo. The profitability figures for the latest period (i.e. Oct-Dec 2014) have conveniently not been provided by the Petitioner
- pp. The Petitioner should not be allowed to submit figures that suit its claims and conveniently omit figures that may reflect an improvement.

#### **Threat of Serious Injury**

- qq. The Exporters have filed their detailed comments and rebuttals to the same by way of their Preliminary Submissions as well as post hearing Written Submissions. The Exporters' prior submissions are relied upon and may be deemed to be incorporated herein.

**Breach in Causal Link and other factors causing Injury**

- rr. The submissions made by the Petitioner in this behalf are merely covering the illustrated parameters as per the Safeguard Rules such as demand, changes in patterns of consumption.
- ss. There are various other factors which have caused injury that have already been placed on record for the consideration of the Hon'ble Director General (Safeguards).
- tt. There are various instances of a severe breach in causal link between the surge in imports and the alleged decline in the Petitioner's performance. In fact this breach is further substantiated by the existence of other causes which attribute to the alleged injury claimed by the Petitioner.
- uu. In *Argentina — Footwear (EC)*<sup>3</sup>, the Panel set forth the following approach to the analysis of causation:
- "whether an upward trend in imports coincides with downward trends in the injury factors, and if not, whether a reasoned explanation is provided as to why nevertheless the data show causation";
  - "whether the conditions of competition in the Argentine footwear market between imported and domestic footwear as analysed demonstrate, on the basis of objective evidence, a causal link of the imports to any injury"; and
  - "whether other relevant factors have been analysed and whether it is established that injury caused by factors other than imports has not been attributed to imports."
- vv. As held by the Panel above, the first step to establishing a causal link is to examine whether or not there is a correlation between the impugned imports and the behaviour of the injury parameters identified by the Hon'ble Director General (Safeguards).

**Incongruence of Imports with Injury Parameters**

- ww. Volume Parameters: The alleged increase in imports has not adversely affected the operations of the Petitioner; the domestic sales have increased while the market share has remained constant.
- xx. The imports and domestic sales have behaved completely independently of each other. In fact, domestic sales were varying even in years where there was no change in imports i.e. 2012-13 to 2013-14.
- yy. Price: There has been no price undercutting caused by the imports. The Petitioner has been able to increase its prices in accordance to increase in costs and even the landed prices of the imports of the subject goods have increased.
- zz. Profitability: Interestingly, the loss suffered by the Petitioner appears to be behaving independent of the imports into the country.
- aaa. The Petitioner has claimed to have suffered grievous losses in the period of analysis. However, it does not appear that any of those losses are correlated with the price or volume of imports.
- bbb. In fact, in a period where the Petitioner suffered its largest drop in profits i.e. 2012-13 to 2013-14, there was absolutely no change in import volumes or import price.

**Impact of Anti-dumping Duty:**

- ccc. The Petitioner has admitted that it is aggrieved by the continued arrival of dumped imports which have not been curbed by the anti-dumping duties. Pertinently, about 57% of the total imports in Q1-2014-15 and about 61% of the imports in 2013-14 are imports which are already covered by anti-dumping duties.

**Annual Report Extracts**

- ddd. By its own admission the operations of the Petitioner have been adversely affected on account of several factors, inter alia, such as adverse duty structure, increase in basic customs duty for import of steel scrap, increase in raw material prices and volatile currency.
- eee. In the Annual Report of the Petitioner for F.Y. 2012-13 at Page 37, it has been clearly recorded that the Hisar unit of the Petitioner is operating at 98% planned capacity utilisation whereas the Jajpur unit is stabilising post capacity expansion and is facing several operational issues that have affected the capacity utilisation.
- fff. The injury claimed by the Petitioner is clearly a case of self-inflicted injury achieved by inexplicably increasing capacities despite a loss-making scenario which continues to face severe stabilisation issues reflecting a breach in the causal link.

**Public Interest**

ggg. In this behalf it is most humbly submitted that the interest of the domestic producers alone cannot be seen as public interest. The Hon'ble Director General (Safeguards) must also examine the impact on the interest of the users, the final consumers, and the market as a whole.

hhh. If the domestic industry is unable to supply to a notable portion of the consumers, the duties may not be in public interest. In this behalf, it is most humbly submitted that even in the present case, the Petitioner is incapable of providing several types of the product to the user industry.

#### **Adjustment Plan**

iii. The Petitioner's submissions do not address any of the objections and issues raised by the interested parties in the preliminary submissions and the public hearing. The Exporters have filed their detailed comments and rebuttals to the same by way of their Preliminary Submissions as well as post hearing Written Submissions.

#### **D. Brief of rejoinder filed by M/S Maruti Suzuki India Ltd**

a. The Respondent is an importer of the Product Under Consideration from NISSHIN STEEL - Japan, NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL CORPORATION (NSSC) - Japan, JFE STEEL Japan and POSCO — Korea.

#### **Initiation and continuance of Investigation**

b. The Petitioner has blatantly ignored in its Submissions that the requirement under the Safeguard Rules is to initiate investigation only when there is 'sufficient evidence' to suggest that the increased import of the product has caused an injury to the Domestic Industry. It is submitted that as of the present date the Petitioners have not been able to establish sufficiency of evidence with regards to injury to the domestic industry as a result of import of the Product Under Consideration. The Petitioner in its Submissions has not been able to establish and create any causal link between the import of the Product Under Consideration and the losses that are being suffered by the domestic Industry.

c. As stated in the Annual Report for the FY 2013 -2014, the operations of the Petitioner have been adversely affected on account of several factors, inter alia, such as adverse duty structure, increase in basic customs duty for import of steel scrap, increase in raw material prices and volatile currency.

d. Further, in the Annual Report of the Petitioner for F.Y. 2012-13 at Page 37, it has been clearly recorded that the Hisar unit of the Petitioner is operating at 98% planned capacity utilisation whereas the Jajpur unit is stabilizing post capacity expansion and is facing several operational issues that have affected the capacity utilisation.

e. Hence the injury claimed by the Petitioner is clearly case of self-inflicted injury achieved by inexplicably increasing capacities despite a loss-making scenario which continue to face sever stabilization issues reflecting a breach in the causal link.

f. The Petitioner has failed to establish any 'causal link' between the alleged increased imports and the loss suffered by the domestic Industry and the Petitioner has been adversely affected on account of several other factors inter alia, such as increase in raw material prices, volatile currency, operational issues which affect capacity utilization; and the alleged serious injury is not attributable to the imports of the subject goods.

#### **Accuracy and methodology adopted in analysing import data**

g. The transaction-wise import data made available by the Petitioner has various discrepancies and at various instances proper gradation and series identification with respect to the imported product has not been done by the Petitioner. Therefore certain products identified by the Petitioner in the Note on Methodology and thereafter set out in the DI Submissions for the import data are not correct and fall outside the scope of Product Under Consideration.

h. The accuracy of the import data relied upon by the Petitioner is doubtful and is being strongly contested by the Respondent and other interested parties. It may be noted that the Petitioner has only provided the alleged manner in which it has proceeded in identifying the Product Under Consideration. However, the Petitioner has not provided the methodology adopted for determining the Product Under Consideration or for evaluating the same.

i. Upon finalization of the import data, the same should be circulated to the interested parties and all the interested parties should be given a fresh opportunity to verify the same and present their views in a public hearing.

- j. The Petitioner has till date not provided corresponding information, even in the DI Submissions, relating to demand and injury parameters such as production, sales, inventory, profitability, etc in relation to the import data for the period July 2014 to December 2014.

**'Like Product' — Product under Consideration**

- k. The Petitioner in the DI Submissions at Para 23 have wrongly proceeded by stating the incorrect definition of like product as provided in the Safeguard Rules.
- l. The Petitioner in its DI Submissions has proceeded to submit its representations on the basis of the incorrect definition and have compared the Product Under Consideration with the products manufactured by the Domestic Industry.

**Quality of the Product Under Consideration**

- m. There is fundamental and substantial difference between the quality of the Product manufactured by the Domestic Industry and the Product Under Consideration imported from other countries, including Japan, has been ignored by the Authority in its Initial Notification.
- n. The Interested Parties have, during the course of investigation submitted the evidence to support that the Product Under Consideration is of specific quality than the ones manufactured by the domestic producers. The Product Under Consideration as imported from Republic of Japan by the Respondent is manufactured through a state of the art patented technology and the Product is of a special design, specification and of a much superior quality, which the domestic producers are not able to manufacture or supply in the quantity and as per requirements of the Respondent.

**Excessive Confidentiality claimed by the Petitioner**

- o. It is submitted that excessive confidentiality has been claimed by the Petitioner and sufficient information has not been supplied by the Petitioner so as to determine the manufacturing, production and sales of the domestic market.
- p. In the NCV of the petition, the Petitioner has not provided important economic parameters such as price underselling range, list of major raw materials, investments made, net worth, depreciation expense, interest expense, etc.
- q. The adjustment plan provided is incomplete and most of the information has been requested to be considered as confidential by the Petitioner. Further, the Petitioner has refrained from answering few important questions on the application format such as full and detailed information about existence of critical circumstances and how would delay cause damage which would be difficult to recover.
- r. The Petitioner did not provide any reasons for claiming the confidentiality on the information provided to the Authority. Further, the Authority has treated such information as confidential and has not recorded any reasoning for the same.

**Determination of Injury on products imported from Japan**

- s. In its Initial Notification, the Authority has not determined any methodology for determining the safeguard duty. Further, the Petitioner has requested the Authority to determine the safeguard duty to the extent of the exact injury margin. In law relating to imposition of Safeguard duty, there is no concept of injury determination. Thus for the sake of clarity, the Authority is required to disclose the methodology to be adopted to determine the level of safeguard duty.
- t. Initiation Notification is silent on any unforeseen developments that have led to increase of imports of Product Under Consideration
- u. In the present matter there has only been a miniscule increase in the import data as provided in the Petition and the Initiation Notification between 2012- 2013 and 2013-2014. Further, the data considered for 2014-2015 is only for a period of 3 months, which cannot suggest or project the trend for the entire year.
- v. There is a gradual increase in the import of Product Under Consideration and there is no 'sharp', significant' or 'sudden' increase in imports.
- w. There is no causal link between the increased imports and injury or threat to injury to the domestic market. Therefore, the Authority has even wrongly held that there exists a prima facie case of imposition of the safeguard duty in the present matter, much less "sufficient evidence".

**No credible evidence whatsoever to make out a case of serious injury or causation.**

- x. None of the parameters submitted by Petitioner in its Petition show any injury whatsoever, much less any serious injury. Petitioner has fared consistently well in terms of production, domestic sales and total sales. Further, it faced no problem in doubling its capacity from capacity existing in 2011-12.
- y. The Petitioner has provided a table showing adverse price effect in the form of positive price undercutting by imports of subject products. However, in determining price effect, Petitioner has deflated the landed value of imports to show a higher level of price-undercutting. As a direct result of deflated landed value, the price undercutting is also showing an inflated range.
- z. Price underselling, depression and suppression data has not been indicated even in indexed form in the NCV of the petition filed by the Petitioner.
- aa. From the profit & loss account of Petitioner for last few years, particularly during 2012-13, it is observed that Petitioner had to incur significant expenditure towards power and fuel expenses, which was one of the critical reasons for losses to Petitioner.

**Causal link between the import of goods and the injury to the domestic industry**

- bb. The Authority has not corroborated any piece of information provided by the Petitioner and has without recording any reasons assumed a prima facie case and initiated the investigation process.
- cc. The data relied upon by Petitioner is unauthenticated and in complete variance to the official data available and published by the Ministry.
- dd. As per the various recent news paper reports the steel plant of the Petitioner situated at Orissa was also shut down due to non compliance with environmental norms. Therefore, it is apparent that the Petitioner is running into losses and the lucrative imports pose a threat to the Petitioner. The Petition, on the face of it, is malicious and an attempt to bring down the necessary import of the Product Under Consideration.

**Public interest**

- ee. Presently, there is a heavy burden on the automobile industry and, there are already existing duties on import of Product Under Consideration and also the excise rebate available to the auto industry has been done away with by the Central Government. In the light of this scenario, if further safeguard measures are imposed on the import of Product Under Consideration, there will eventually be a burden on the domestic consumers and the public at large buying vehicles as the prices of automobiles will substantially increase. Hence, the imposition of safeguard duty would be contrary to the larger public interest.

**Unforeseen Development**

- ff. The Petitioner has claimed significant global demand supply gap to have caused exporters to intensify their exports to India. However, it is required to be established that the occurrence of a global demand supply gap was unforeseeable and that as such has led to the increased imports into India. The Petitioner has yet to prove that the global demand and gap supply was unforeseen.
- gg. Further, the submission of the Petitioner that the continued imports despite imposition of anti dumping duties is an unforeseen development is wholly baseless and illogical. Further, the claim indicates the manner in which the Petitioner has been seeking trade remedial protection to unfairly create barriers to imports. It is trite in law that anti-dumping duties are imposed to prevent dumping that is causing injury to the domestic industry and not means to arrest imports. Hence, the submission of the Petitioners that it had a reasonable expectation for curtailment of all imports in light of the anti-dumping duty is unintelligible and unjustified.

**Other Issues**

- hh. From the information presented in the petition, it does not appear that the Petitioner in the present investigation is attempting to seek protection from dumped imports but rather all imports due to a surge in volumes.
- ii. Further the Government of India should ensure its commitment to International trade and Commerce as against Japan. The vision of the Government of India vis a vis the investment and trade with Government of Japan has been encouraged recently by the Government of India and to

foster the trade and commerce relations between the two countries, it is necessary to allow a regime in India that does not put fiscal pressures on the exporters and importers.

- jj. The increase in imports as alleged in the petition could be due to existence of FTA with ASEAN and CEPA with Japan and Korea. Even the Applicant in its petition has stated that customs duties have come down significantly over the years pursuant to FTA and CEPAs.
- kk. The Petitioner incorrectly and unsuccessfully relied on the factum of Thailand,, Brazil and other countries having imposed Safeguard restrictions against imports from various countries with respect to the Product Under Consideration. It is pertinent to note that none of these countries have imposed any Safeguard restrictions on imports from Japan. This goes on to prove that imports from Japan are of state of the art and patented products, which otherwise the Domestic Industry is not in a position to manufacture

**E. Brief of rejoinder filed by M/S POSCO, Korea**

**Accuracy and Adequacy of the Imports Data**

- a. The official transaction wise import data from DGCIS should be procured for the exact analysis regarding the surge in imports.
- b. Final determination should be based on the actual import data from April 2014 through March 2015.

**Like Goods**

- c. The grades 429EM, 430J1L, 444, 445NF, 446M, should be excluded from PUC as it is substantiated by the Petitioner's brochure that the grades are not the available for the customers to order.

**Increase in Imports**

- d. Even suppose that the import data provided by the Petitioner is fully reliable, the increase during 2014-15 Q2 and 2014-15 Q3 is because of the initiation of the safeguard investigation. Importers, afraid of import blocking and domestic price increase, started to increase their stocks after hearing the news about the safeguards investigation.
- e. Regarding increase in imports during 2014-15 Q1, it is traditional that steel traders increase their purchase during the first quarter of every fiscal year because importers finished clearing the goods in stock by the end of last year.
- f. Regarding increase in imports in relation to domestic production and to domestic demand, the chart provided by the Petitioner is zigzagging, repeating up and down during the POI. It cannot be considered as a significant increase.

**Reasons for Increase in Imports**

- g. Though the Petitioner listed some reasons for increase in imports, there is nothing unforeseen. For the sake of brevity, POSCO is not reiterating the submissions herein again and submission filed in this regard on 22/01/2015 may be relied upon.

**Injury to the Domestic Industry**

- h. Although the Petitioner suggested domestic demand in paragraph 73 of its written submission, there is no source or manner how they estimated the demand. Normally, reliable sources such as CRU, Metal Bulletin or other materials made by any steel association, do not publish the demand-supply data only for the 400 series of stainless steel.
- i. Petitioner is showing more than 85% of capacity utilization in recent years and it can be defined as "very good condition"

**Public Interest**

- j. As the Petitioner proved by their own, they are a dominant producer in Indian domestic market. Regulating imports means limiting competition in domestic market, and the consumers, as a result, will be suffering from abuses of monopoly such as over-valued price, narrow selection, delay in shipments, poor quality management and etc.

**IV. Additional Submission**



**A. Additional submissions filed M/S Lakshmi Kumaran & Sridharan on behalf of M/S Metal one India(P) Ltd and M/S Bahru Stainless Sdn, Malasiya**

- a. On 19-Jan-2015, the Applicant Domestic Producer placed on record import statistics for additional period (July'14 to Dec'14).
- b. Metal One again procured import statistics for a further period of 6 months (Jul'14-Dec'14). Since the time period provided for filing the rejoinder submission was very limited, Metal One filed preliminary rejoinder submission with a request to the Authority to allow Metal One to place additional submission to the new evidence submitted by the Applicant Domestic Producer
- c. From the data obtained as above the product description was examined and following were excluded:
  - (i) Those transactions which had reference to grades other than 400 series (321, 301, 303, 316, 304, 201, 310, 200, 305, 202, 309, 347 and 240 series) were segregated and classified as 'NPUC';
  - (ii) Transactions which included 'H.R.' or 'H.R.S.S' or 'FIR' or 'HRSS' or 'Hot Rolled' in the description were segregated and classified as 'NPUC'.
  - (iii) Transactions whose descriptions did not indicate in any manner, whether it is the subject product as defined in the initiation notice, were segregated and classified as 'Unknown'.
- d. On making the above analysis, the total quantity for July'14 to Dec'14 period arrives to 33,270 MT.
- e. In contrast, import quantities for this period provided by the Applicant Domestic Producer vide letter date 19th January 2015 comes to 50,725 MT.
- f. Further, if the revised import statistics as per Metal One is taken into consideration and compared with import data for past period as provided by the Applicant Domestic Producer in its petition, it will be clear that there was no increase in imports.
- g. The import statistics of Applicant Domestic Producer is also unreliable as these include number of transactions, for which unit of measurement includes Nos, pieces, SQMs, Doz, Rol, Sht, Set and Mtr. It is not known how the Applicant Domestic Producer converted such import transactions into MT.
- h. The import statistics of the Applicant Domestic Producer is also unreliable as it contains number of transactions with descriptions which does not indicate in any manner whether the same is product under consideration or not.
- i. The correct quantity of imports from Malaysia for the period Apr'14 to Dec'14 comes to 1,311MT out of total of 55,924MT or only 2.34% of total imports. **Thus, even during Apr'14 to Dec'14 period, the imports from Malaysia were below de-minimis level.**

**F. Additional submissions filed by M/S ELP Advocates & Solicitors on behalf of M/S. NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL CORPORATION, M/S. NISSHIN STEEL CO., LTD., and M/S. JFE STEEL CORPORATION**

- a. The Exporter reiterates in this behalf, that there are various grades/product categories which fall under the product definition in the present investigation but are not produced by the Petitioner as also certain goods which are patented products developed by the Exporter.
- b. Further, the grades which are produced by the Petitioner, however are not like article in all respects especially on grounds of consumer perception as well as technical capabilities linked to product standards meant for certain end user application which can be substituted by the products being currently exported by the Exporter.
- c. The Exporter submits that in order to examine this issue, the Hon'ble Director General (Safeguards) must compare the products of the Exporter with the products produced and sold by the Petitioner.
- d. The exporters requested to exclude the certain grades from the scope of PUC, which Domestic producers cannot produce or where the Petitioner's equivalent grade is differentiated from the specification of exporters grade. The list of such grades are as under:-

**(i) Exemption Request from JFE STEEL**

Steel Grade	Main use	The reason that JSL cannot produce
-------------	----------	------------------------------------

JFE20-5USR JFE18-3USR	Catalytic converter(Metal honeycomb)	<p>1. JFE will soon acquire a patent in India for which the patent has already been granted in Japan.</p> <p>2. Materials of Metal honeycomb are specified by all design drawings of automotive or motor-cycle maker.*</p> <p>3. It is necessary for around three years for the time to certification.*</p> <p>4. Future demand of thickness is thinner than 50µm.*But minimum thickness of JSL is 50µm.</p> <p>5. These grade include 3-5% Aluminum and 18-20% Chromium. So, it is very difficult to produce at all processes, such as steel making, casting, hot-rolling and cold-rolling, because of very low fracture toughness. (Figure</p>
JFE429EX JFEMH-1 JFETF-1	Exhaust manifold	<p>1. These materials are JFE original grades and have been used by car makers with their certification.</p> <p>2. Exhaust Manifold is one of important preservation parts.</p> <p>3. JSL have never produced the special material for exhaust manifold except for standard grade such as type 441.</p> <p>4. Property of standard grade 441 at high temperature is poorer than that of JFE original grades. So, 441 is not usable to a engine for environment.</p> <p>5. Exhaust manifold needs high formability. JFE original grades are made by special process technology. ( attached paper 1)</p> <p>6. It is necessary for around three years for the time to certification.</p>
JFE443CT JFE430CUN JFE432LTM JFE439L JFE409L	Exhaust system	<p>1. These materials are JFE original finish, it's called KB,KD.(Photograph 1 and figure 2)</p> <p>2. Surface roughness of KD is rougher than that of 2B.(Table 1)</p> <p>3. KB,KD finish is made by Tandem-CAL process*. JSL do not have Tandem-CAL process.</p>

(ii) **Exemption Request from M/S. NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL CORPORATION**

Steel Grade	The reason that JSL cannot produce
-------------	------------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>● Excellent formability for automobile industry NSSC 409L (SUH 409L), NSSC 436S (SUS 436L), NSSC 432 (SUS 436J1L), NSSC 439 (SUS430LX), NSSC 180 (SUS 430J1L), NSSC FHZ, NSSC 190 (SUS 444), NSSC 190EM (SUS 444), NSSC 444M1 (SUS 444), NSSC 429NF (SUS 429), NSSC 448EM.</li> <li>● World's only one products based on the patent NSSC FW1, NSSC FW2</li> </ul>	<p><b>1. Competitive Edge in Production Process and Technology of NSSC</b></p> <p>(The petitioner does not have the following each facility and technology.)</p> <p>1.1 Molten steel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Excellence in refining technology and high purity molten steel produced through blast furnace and converter process for the production of 400 series</li> </ul> <p>1.2 Hot rolling process</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Continuous hot rolling mill bringing greater cost-competitiveness</li> </ul> <p>1.3 Cold rolling process</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● NSSC's 400 series products for automotive industry are produced through tandem cold rolling mill that has large diameter rolls, providing improvement of Lankford-value (r-value), enabling to achieve excellent formability.</li> </ul> <p><b>2. Comparative Evaluation by India Yamaha Motors ("IYM") as Downstream Industry</b></p> <p>2.1 Formability</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Due to absence of the facility and inferiority of the technology to achieve customer's requirement, the petitioner's products are easily cracked, making it impossible to satisfy requirement of downstream industry.</li> </ul> <p>2.2 Corrosion resistance</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Due to impurity of molten steel decided by steel making process, the petitioner's products rust easily, making it impossible to satisfy requirement of downstream industry.</li> </ul>
--	---

(iii) **Exemption Request from M/S. NISSHIN STEEL CO., LTD**

(a) Nisshin Steel's Patented Original SteelGrade

NSS HR-2

(b) Nisshin Steel's Specifications

NSS 436

NSS 432...No Grade of 432 in Jindal's Products Lineup

NSS 439

NSS 409M1

**V. Brief of reply filed by domestic industry on additional submission filed by Interested parties**

**A. Reply filed by DI On the additional submissions of M/S Metal one India(P) Ltd and M/S Bahru Stainless Sdn, Malasiya**

- a. Large number of product types have been listed by the interested parties as NPUC. These transactions have however not been considered at all as PUC transaction by the petitioner. As regards other transactions that have been considered PUC by the petitioner, the explanation is given for treating these transactions as PUC. Relevant evidence is also enclosed in respect of product types.

- b. The interested parties have stated that there are number of transactions where unit of measurement is not weight and have questioned how volumes of imports have been determined in these transactions. The petitioner submits that these import transactions have been ignored by the petitioner in determining volume and value of imports in view of no factual basis available to translate these import data on weight basis.
- c. It is also noted that the interested parties continue to make claim based on partial period. If these interested parties wishes to lodge an independent claim on volume of imports, the domestic industry has no objection to the same. However, the least such interested parties should do in order to be fair to all other parties is to lodge such claim based on data for entire period. The interested parties continue to lodge claim only for the current year, without showing volume of imports for the entire period. This is clearly mischievous and an attempt to impede the investigations.

**B. Reply filed by DI on additional submissions of M/S. NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL CORPORATION, M/S. NISSHIN STEEL CO., LTD., and M/S. JFE STEEL CORPORATION**

- a. Non confidential version of submissions made by Japanese companies do not permit understanding the product description and specifications.
- b. Details and basis of any claim made for exclusion of a particular grade of product under consideration need to be necessarily shared with the domestic industry to enable it to defend its interest.
- c. The fact of non production or non substitution of certain grades cannot be ascertained until and unless the domestic industry is made aware of what exactly the product consist of.
- d. With regards to grades mentioned in the additional submission by Japanese , petitioner has supplied equivalent/comparable grades of all the products for each exclusions that have been sought by NSSSC,JFESC and NISSHHIN.
- e. As regards grades NSSC 190EM, NSSC 441M1, NSSC 429NF and NSSC 448EM and the two grades claimed to be patented, i.e., NSSC FW1 and NSSC FW2, petitioner is not able to compare these grades with JSL products since no information is available.
- f. Petitioner is not able to compare grades JFE20-5USR and JFE18-3USR with JSL products since no information is available.
- g. Further, it appears that the company has in fact filed an application seeking patent of products in India. No patent has been granted as of today.
- h. Petitioner is a fully integrated producer having full facilities including Melting, AOD, VOD, Hot Rolling and Cold Rolling. Petitioner is, therefore, capable of producing any grade / specification.
- i. Further, no producer can sell the product unless an order for the same is placed on the company. It is fundamental business situation that unless the order is placed on a producer, the goods are not produced by the producer, as every producer has its own requirement of material. Thus, barring those grades where there are standard/repeated/routine requirements in the market, every producer tends to produce a product only after receipt of a firm order. Since petitioner received no such orders for supply, naturally, the petitioner has not produced the product.

**VI. EXAMINATION & FINDINGS:**

1. I have carefully gone through the case records, the replies filed by the domestic producer, user/importers, exporters and exporting nations. The written submissions and the rejoinder submissions made by them have also been considered appropriately. The submissions made by various parties and the issues arising there from are dealt with at appropriate places in the findings below:
2. Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 deals with imposition of Safeguard Duty on imports. Its sub-section (1) provides for imposition of Safeguard duty by the Central Government on an article if the article is being imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry.
3. The Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 provides the manner and principles governing investigation.
4. The investigation has been conducted in accordance with the said rules and the Final Findings are recorded through this notification.

**A. The Product Under Consideration (PUC):**

- a. The product under consideration (hereinafter referred to as PUC) in the present case is “Cold Rolled Flat Product of Stainless Steel of chromium type, 400 Series encompassing all Martensitic and Ferritic grades as per ASTM A240/A240M and equivalent/comparable specifications in other standards like UNS, IS, Chinese DIN, JIS,BIS, EN, etc”, excluding (i) width 1700 MM and above and (ii) JBS (JindalBlade Steel) grade & its

equivalent” classified under Customs Tariff sub-heading nos. 72193112, 72193111, 72193210, 72193310, 72193410, 72193510, 72202021 and 72209021 of Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975. The ‘PUC’ are mainly used for the manufacture of white consumer goods, processed equipment, dairy equipment, automotive components, rail carts, metro coaches, architecture, building and construction, etc. A number of parties have contended that the scope of the product under consideration is not appropriate. However, none of the parties have established how the scope is not appropriate and what is the product type included in the scope of product under consideration which should not have been included. Thus all arguments on these accounts are vague and wholly unsubstantiated. Some of the interested parties have raised the issue that all those product types which are being imported and which are not being produced by the domestic industry should be excluded from the scope of the product under consideration. However none of the interested parties have filed any material evidence to substantiate their claim for exclusion from the product scope and hence claims or issues merely based on conjectures cannot be accepted. It is noted that the domestic industry has never regretted supply of the material on the grounds of technical capabilities. The petitioner can supply a product only if a consumer places the order for the same. No producer can sell the product without an order. Some of the interested parties from Japan requested to exclude certain grades from the scope of PUC, which Domestic producers cannot produce or where the Petitioner’s equivalent grade is differentiated from the specification of exporters grade. The domestic industry in reply raised objections that non confidential version of submissions made by Japanese companies do not permit understanding the product description and specifications and basis for exclusion of a particular grade of product under consideration has not been shared with the domestic industry and hence they are not in a position to defend its interest. Also domestic industry claimed that they have supplied equivalent/comparable grades of all products for each exclusion that have been sought by the Japanese producers. Domestic industry claimed that patent has not yet been granted for the certain product of Japanese producers. In this regard I agree that details and basis of any claim made for exclusion of a particular grade of product under consideration need to be necessarily shared with the domestic industry to enable domestic industry to defend its interest. The Japanese producers has not produced any evidences showing that patent has been granted by Indian Govt. for some of the product produced by the Japanese producers and hence there is no justification for its exclusion.

- b. In view of above, it is confirmed that the product under investigation is “Cold Rolled Flat Product of Stainless Steel of chromium type, 400 Series encompassing all Martensitic and Ferritic grades as per ASTM A240/A240M and equivalent/comparable specifications in other standards like UNS, IS, Chinese DIN, JIS, BIS, EN, etc”, excluding (i) width 1700 MM and above and (ii) “JBS (Jindal Blade Steel) grade & its equivalent” classified under Customs Tariff sub-heading nos. 72193112, 72193111, 72193210, 72193310, 72193410, 72193510, 72202021 and 72209021 of Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975. Accordingly, it is also held that domestically produced “Cold Rolled Flat Product of Stainless Steel of chromium type, 400 Series falls under the ambit of like or directly competitive article in all respects to the imported product under investigation and that the domestically produced “Cold Rolled Flat Product of Stainless Steel of chromium type, 400 Series is a like article to the imported “Cold Rolled Flat Product of Stainless Steel of chromium type, 400 Series within the meaning of Rule 2(e) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997.

**B. Domestic Industry (DI):**

5. Section 8B(6)(b) of the Customs Tariff Act 1975 defines Domestic Industry as follows:  
*“(b) “Domestic Industry” means the producers -  
 (i) as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or  
 (ii) whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India;”*
6. The application filed by M/s. Jindal Stainless Limited, Jindal Centre, 12 Bikaji Cama Place, New Delhi-110066. The applicants account for more than 85% of the Indian production and hence are major producers. Accordingly, it is held that the applicant domestic producer constitutes and represents the Domestic Industry (DI) within the meaning required and defined under Sec 8B(6)(b)(ii) of the Customs Tariff Act, 1975.

**C. Source of information:**

7. The product under investigation is imported into India under Custom Tariff Heading 72193112, 72193111, 72193210, 72193310, 72193410, 72193510, 72202021 and 72209021 of Chapter 72 of First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The Safeguard investigation was initiated on the basis of import data of Cybex, Noida (Transaction wise) from 2011-12 to 2014-15 (April to June 2014). The domestic data from 2011-12 to 2013-14 (Till January 2014) has been submitted by the domestic industry and the same has been verified by on-site visit by the department on the basis of excise records to the extent deemed necessary. The domestic data for February 2014 to June 2014 has been provided by the DI, duly certified, which was verified on the basis of excise records. The import data as well as the domestic data from July, 14 to Dec, 14 in respect of various

economic parameters has been taken as furnished by the applicant, in their written submissions/rejoinder, in order to arrive at yearly consolidated data for the year 2014-15 for injury analysis.

#### D. Period of Investigation (POI):

8. Neither the Customs Tariff Act, 1975, nor the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, specifically define 'Period of investigation' or the minimum period to be considered for a Safeguard investigation. The WTO Agreement on Safeguards does not contain any general or specific provision or guidelines for choosing the investigation period. However the issue of period of investigation has been dealt in detail in Panel findings in US-Line Pipe Case against Korea (Para 7.196, 7.199 and 7.201). The Panel in this case ruled that it is up to the discretion of the investigating authority of the importing Country to decide the "length of the period of investigation" and its "breakdown".

*"We note that the Agreement contains no requirements as to how long the period of investigation in a safeguards investigation should be, nor how the period should be broken down for purposes of analysis. Thus, the period of investigation and its breakdown is left to the discretion of the investigating authorities. In the case before us the period selected by the ITC was five years and six months, which is a period similar in length to the one used by the Argentine investigating authority in Argentina — Footwear Safeguard. However, we note that the Appellate Body, in the findings relied upon by Korea to argue the question of the length of the period of investigation, emphasized not the length of the period per se, but that there should be a focus on recent imports and not simply trends over the period examined. In the case of the line pipe investigation the ITC did not merely compare end points, or look at the overall trend over the period of investigation (as Argentina had done in the investigation at issue in Argentina — Footwear Safeguard). It analyzed the data regarding imports on a year-to-year basis for the 5 complete years, and also considered whether there was an increase in interim 1999 as compared with interim 1998. We are of the view that by choosing a period of investigation that extends over 5 years and six months, the ITC did not act inconsistently with Article 2.1 and Article XIX. This conclusion is based on the following considerations: first, the Agreement contains no specific rules as to the length of the period of investigation; second, the period selected by the ITC allows it to focus on the recent imports; and third, the period selected by the ITC is sufficiently long to allow conclusions to be drawn regarding the existence of increased imports."*(paras. 7.196, 7.199 and 7.201)<sup>1</sup>

9. In view of above, considering these facts, and source of information stated above, it is considered appropriate to adopt data for the period 2011-12 to 2014-15 (annualized) for the purpose of the present investigations.

#### E. Confidentiality of information submitted:

10. Rule 7 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguards Duty), Rules, 1997 and Article 3.2 of WTO Agreement on Safeguards provides for confidentiality treatment to certain information. The rules provide that an Interested Party is not required to disclose such information on actual basis which is confidential information of the company and disclosure of which can cause serious prejudice to the business interests of such party, which is not in public domain and which the petitioner has not disclosed before public at large in the past.
11. The Domestic Industry has provided some information on confidential basis and sought confidentiality on the information /data submitted. The Domestic Industry provided non-confidential version of the application for safeguard measure as per the provisions of Safeguard Rules 1997 and Trade Notice No. SG/TN/1/97 dated 06.09.1997. Further, the Domestic Industry has submitted reasons for seeking confidentiality at the time of filing the application. which appears to be reasonable and, therefore, has been accepted, whenever claimed.

#### F. Increased Imports:

12. Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 deals with the power of the Central Government to impose safeguard duty and provides as follows:  
*"(1) If the Central Government, after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any article is imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to Domestic Industry, then, it may, by notification in the Official Gazette, impose a safeguard duty on that article :"*
13. The Rules mandate increase in imports as a basic prerequisite for the application of a safeguard measure. Thus, to determine whether imports of the product under consideration have "increased in such quantities" for purposes of applying a safeguard measure, the rules require an analysis of the increase in imports, in absolute terms or in relation to domestic production.

<sup>1</sup> WT/DS202/R DT, 29.10.2001 Panel report in US-Line Pipe case

14. Rule 2 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 defines 'increased quantity' as follows:  
*"(c) "increased quantity" includes increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production."*
15. With regard to the nature of the increase in imports, the Appellate Body in Argentina—Footwear (EC), in contrast to the Panel, held that the increase in imports must have been recent, sudden, sharp and significant enough to cause or threaten to cause serious injury. Relevant extract is as follows:  
*"131. [T]he determination of whether the requirement of imports 'in such increased quantities' is met is not a merely mathematical or technical determination. In other words, it is not enough for an investigation to show simply that imports of the product this year were more than last year — or five years ago. Again, and it bears repeating, not just any increased quantities of imports will suffice. There must be 'such increased quantities' as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry in order to fulfill this requirement for applying a Safeguard measure. And this language in both Article 2.1 of the Agreement on Safeguards and Article XIX:1(a) of the GATT 1994, we believe, requires that the increase in imports must have been recent enough, sudden enough, sharp enough, and significant enough, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause 'serious injury'."*
16. The Panel on US — Wheat Gluten<sup>4</sup>, interpreted the phrase "in such increased quantities" as follows:  
*"8.31 [A]rticle XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1 [of the Agreement on Safeguards ("SA")] do not speak only of an 'increase' in imports. Rather, they contain specific requirements with respect to the quantitative and qualitative nature of the 'increase' in imports of the product concerned. Both Article XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1 SA require that a product is being imported into the territory of the Member concerned in such increased quantities (absolute or relative to domestic production) as to cause or threaten serious injury. Thus, not just any increase in imports will suffice. Rather, we agree with the Appellate Body's finding in Argentina — Footwear Safeguard that the increase must be sufficiently recent, sudden, sharp and significant, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause serious injury."*
17. The analysis of the increased imports of the product under consideration has been conducted in the light of the above mentioned law and WTO jurisprudence.
- Increased Import in absolute terms:**
18. The analysis of the trend in imports of PUC in the light of the above mentioned provisions has been done. PUC is imported into India from a number of countries, and primarily from Japan, Korea, China, EU, USA and Mexico. Interested parties raised objections that methodology adopted by the domestic industry in segregation of import data with in the transaction wise entries under CTH 72 is not correct as it contains number of transaction with discrepancies which does not indicate in any manner whether the same is product under consideration or not. The interested parties also raised objections that transaction wise data not provided to them and how the domestic industry converted the other unit of measurement to the unit MT. In this regard the import data with quantity in Metric tons, tons, or Kgs has only been considered and for transaction wise import data, the source has already been provided from where the said data can be obtained. It was argued by various interested parties that imports of one quarter (April, 14 to June, 14) is insufficient to determine increase in imports. In this regard I find no merit in this objection as the investigation has been initiated on the basis of data available to the authority and as the period of investigation is open till the latest data available for the period 2014-15, hence the data up to Dec, 2014 is being considered for injury analysis. Further, I find no abnormality in the methodology adopted by domestic industry for segregation of data as PUC. The import data considered as PUC at the time of initiation of investigation has been further examined in detail and the entries identified as per the method given below have been removed from product under consideration as the same do not confirm to the description of PUC.
- The entries reported under dedicated CTH for Cold Rolled Flat products of Stainless Steel under Chapter 72 of Customs Tariff Act, 1985 where either 400 series or their euronorm number like 1.4509, 1.4512 etc has not been mentioned.
  - The entries reported under non-dedicated CTH to Cold Rolled Flat products of Stainless Steel under Chapter 72 of Customs Tariff Act, 1985 where the word "Cold Rolled stainless steel or C.R SS along with 400 series or their euronorm number like 1.4509, 1.4512 etc has not been mentioned.
19. In view of above the quantum of imports of PUC during 2011-12 to 2014-15 (Up to Dec, 14) are as under:

Period	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (up to Dec, 2014)	2014-15 (Annualised)
--------	---------	---------	---------	---------------------------	----------------------

Import(MT)	62,167	82,414	80124	73102	97469
Indexed	100	133	129	118	157

Comparison of Import	2011-12 & 2012-13	2012-13 & 2013-14	2013-14 & 2014-15(A)
Increase in Import Vis-à-vis previous year (MT)	20247	-2290	17345
Rate of Increase in import Vis-à-vis previous year(MT)	33%	-2.78%	21.64%

20. It is apparent from the data in the table above that there is no surge in import in absolute terms during the complete years 2012-13 & 2013-14 i.e Import increased during the period 2012-13 by 20247 MT but decreased during 2013-14 by 2290MT . This shows that during complete financial years from 2011-12 to 2013-14 the rate of import has been decreased from 33% to -2.78%. Further during period 2014-15(A) the rate of import increased to 21.64% which is lower than the initial rate of increase in import. Now for rest of three complete quarter during the year 2014-15 the import position is as under which is also not showing sudden, sharp and significant increase.

Period	2014-15(Q1)	2014-15(Q2)	2014-15(Q3)
Import(MT)	25047	22416	25639
Indexed	100	89	102

21. In view of above the surge in import during the entire period of investigation cannot be considered as sudden, sharp and significant.

**Import in relation to Production:**

22. The imports of product under consideration in India during the complete years of P01 have decreased in relation to production of the Domestic Industry. The import with respect to total production increased from 78% in 2011-12 to 85% in 2012-13. Further Imports in relation to production decreased from 85% in 2012-13 to 74% in 2013-14.

Financial Year	Total Imports (MT)	All India Production (MT)	% of import with respect to production
2011-12	62,167	79,857	78
2012-13	82,414	97,140	85
2013-14	80124	108,829	74
2014-15 (Annualised)	97469	114,117	85

23. It is apparent from the above that there is no sudden, sharp and significant surge in imports during the Period of Investigation, both in absolute terms as well as in relation to domestic production.

**G. Determination of Serious Injury and Threat of Serious Injury:**

24. Section 8B sub-section 6(c) of Customs Tariff Act provides as follows:

“Serious injury” means an injury causing overall impairment in the position of a Domestic Industry;

25. Section 8B sub section 6(d) of Customs Tariff Act provides as follows:

“threat of serious injury” means a clear and imminent danger of serious injury.

26. The Paragraph 1 of Annex to Rule 8 of the Customs Tariff(Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules’ 1997 provides as follows:

“In the investigation to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to a domestic industry, the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and



*quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the article concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilization, profits and losses, and employment."*

27. Accordingly, in analyzing serious injury or threat of serious injury all factors, which are mentioned in the Rules as well as other factors which are relevant for determination of serious injury or threat of serious injury, have been considered. The determination of serious injury or threat of serious injury is based on evaluation of the overall position of the Domestic Industry, in the light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.

- a. **Production:** As seen from the table below, the production of the Domestic Industry increased from 67876MT in 2011-12 to 94929 MT in 2013-14. Further the production of the applicant during 2014-15 (A) increased to 100217 MT.

Financial Year/quarter	Total Imports (MT)	Production (MT)	Domestic Sales(MT)	Total Demand(MT)	Market Share	
					Import	DI
2011-12	62,167	<b>67,876</b>	<b>63,729</b>	138,292	45	46
2012-13	82,414	<b>83,240</b>	<b>75,391</b>	172,190	48	44
2013-14	80124	<b>94,929</b>	<b>81,344</b>	176,048	46	46
2014-15(Up to Dec,14)	73102	75163	68801	151,773	48	45
<b>2014-15(A)</b>	97469	100217	91735	202,363	48	45

- b. **Changes in the level of Sales:** It is seen from the table above that the sales of the Domestic Industry increased from 63729MT in 2011-12 to 81344MT in 2013-14. Further the Sales of the applicant during 2014-15 (A) increased to 91735MT.
- c. **Market Share:** It is seen from the table above that the Imports had a market share of 45% in 2011-12 which increased to 46% during 2013-14 whereas the market share of Domestic industry remains same as 46% during the same period. Further during 2014-15(A) the market share of the domestic producer decreased to 45% and market share of import increased to 48%.
- d. **Capacity Utilisation:** As the applicant does not have dedicated capacity for the product under consideration, therefore capacity for cold rolled flat products for all series is taken to determine the capacity utilization. Capacity utilization of the Domestic Industry has increased from 61% in 2011-12 to 66% in 2014-15(A), as seen from the table below:

Financial Year/Quarter	Production of C.R as a whole(MT)	Installed Capacity of C.R as a whole(MT)	Capacity Utilization(%)
2011-12	262275	427500	61
2012-13	364855	765000	48
2013-14	437800	765000	57
2014-15(Up to Dec,14)	376513	573750	66
<b>2014-15(A)</b>	<b>502017</b>	765000	66

- e. **Employment & Productivity:** The employment and the productivity over the injury period increased, as seen from the table below:

Financial Year/quarter	Productivity(MT/day)	Employment(Nos)
2011-12	107	2445
2012-13	140	2599

2013-14	166	2630
---------	-----	------

- f. **Profit & Loss (Indexed):** The profitability of the Domestic Industry has decreased during period of investigation. This is evident from the table below:-

Financial Year	Cost of sales	Selling price	Profitability	ROCE
	Rs/MT	Rs/MT	(Rs./MT)	(%)
2011-12	100	98	-2	100
2012-13	106	100	-6	-18
2013-14	119	101	-18	-267
2014-15(Q1)	122	104	-18	-309

However, it is apparent from the annual report of the company (Rs. In Crores) (details below) the DI is showing operating profit in r/o Company as a whole but is in loss due to depreciation and financial expenses etc..

	March,11	March,12	March,13	March,14	Sept,14
Operating Profit	1081	904	615	886	554
Financial Expenses	389	517	990	1235	684
Depreciation	356	409	701	688	257
Power & Fuel	560	646	1235	1272	728
Net Profit/Loss	318	-104	-821	-1390	-366

Some of the interested parties raised objections that due to increase in depreciation charges and finance charges, domestic industry incurred heavy losses. Accordingly from the annual report of DI, it is clear that fixed costs of the domestic industry have been consistently increasing since 2011-12. This increase in fixed costs is commensurate with steep decline in profitability projected in the application filed by the domestic industry. It has also been observed that with increase in depreciation charges and finance charges during 2012-13 and 2013-14, domestic industry also incurred heavy losses, thereby exhibiting positive correlation between the two. Thus, it is illogical to blame imports for its decline in profitability, when import quantities have actually decreased during 2012-13 and 2013-14. This shows that there are some other factors, like abnormally high depreciation and finance charges which are causing injury to the domestic industry. This conclusively shows that it is not imports but some other factors, which are responsible for losses to domestic industry. Therefore, the causation analysis fails in the present investigation.

g. **Other Important Factors:-**

- (i) **Inventories:** Inventories have decreased from 4861MT in 2013-14 to 4482MT in 2014-15(April to Dec,14), as seen from the table below:

Financial Year	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 ( April to Dec,14)
Inventory (MT)	1,959	1,549	4,861	4,482

- (ii) **Price undercutting, suppression/depression:** The price undercutting has been calculated by taking in to consideration the customs duty @5% (Effective Rate) and adding duties to CIF value of import which reveals that there is no price undercutting and landed price of import is higher than the selling price of the PUC . There is a significant price difference between the domestic and imported product. The variation of landed prices of imports, cost of Sales, selling price are as under:-

INDEXED with respect to cost of sales during the year 2011-12.

	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15(Upto Dec,14)
Cost of Sales	Rs./MT	100	106	119	not provided
Landed price of imports	Rs./ MT	101	107	108	106

Selling Price	Rs./ MT	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>104</b>
Undercutting	%	-3	-7	-7	-2

It is seen from the above table that both the cost of Sales and the selling price increased during the period. The increase in the selling price by the DI in 2013-14 over 2012-13 was 1%, lower than the rise in cost of sales (12%) as against increase in landed price of import (0.9%). The imports were thus not suppressing the Domestic Industry prices in the market and the undercutting is also negative. Further there is no price depression as the selling price increases during POI.

(iii) **Export:** It is noticed from the table below that, the export with respect to production increased from 4% in 2011-12 to 8% in 2013-14, i.e., by 4%.

Financial Year/quarter	Production (MT)	Export (MT)	% of export with respect to production
2011-12	67876	2422	4
2012-13	83240	5331	6
2013-14	94929	7907	8
2014-15(Up to Dec,14)	75163	5611	7
<b>2014-15(A)</b>	<b>100217</b>	<b>7481</b>	<b>7</b>

28. From the above analysis, it is seen that the imports of the product under consideration during the complete financial years 2011-12 to 2013-14, have not increased in relation to production as well as in absolute terms. Since the performance of the domestic industry has shown improvement in a number of parameters, it is evident that the domestic industry has not suffered serious injury as a result of imports. In the present case, performance of the domestic industry has shown improvement in majority of the injury parameters listed under the Rules, as demonstrated above. Production, domestic sales, capacity utilization, productivity, have improved during POI. Inventories with the Domestic Industry have decreased during the injury period. Price undercutting is negative throughout the period. Further, keeping in view the higher landed price during the period of investigation the Domestic Industry could have increased their selling price.
29. Thus, an evaluation of the overall position of the Domestic Industry, in the light of all the relevant factors having a bearing on the situation of the Domestic Industry, shows improvement in their position. It is thus concluded that, there exists no serious Injury or threat of serious injury to the domestic industry in the period of investigation.

#### H. Causal Link between Increased Import and Serious Injury or Threat of Serious Injury:

30. As per Rule 8 of the Customs Tariff(Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997, The Director General(Safeguards) is obligated to "*determine serious injury or threat thereof of serious injury to the domestic industry taking into account, inter alia, the principles laid down in Annex to the these rules*". Further, paragraph 2 of the Annex requires establishment of causal link between alleged increased imports and serious injury or threat thereof. The Paragraph 2 of Annex to Rule 8 provides as follows:

*The determination referred to in paragraph (1) shall not be made unless the investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the article concerned and serious injury or threat thereof. When factors other than increased imports are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports.*

31. The Panel on Korea — Dairy set forth the basic approach for determining "causation":

*"In performing its causal link assessment, it is our view that the national authority needs to analyse and determine whether developments in the industry, considered by the national authority to demonstrate serious injury, have been caused by the increased imports. In its causation assessment, the national authority is obliged to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry. In addition, if the national authority has identified factors other than increased imports which have caused injury to the domestic industry, it shall ensure that any injury caused by such factors is not considered to have been caused by the increased imports.*

*To establish a causal link, Korea has to demonstrate that the injury to its domestic industry results from increased imports. In other words, Korea has to demonstrate that the imports of SMPP cause injury to the domestic industry producing milk powder and raw milk. In addition, having analyzed the situation of the domestic industry, the Korean authority has the obligation not to attribute to the increased imports any injury caused by other factors.”<sup>2</sup>*

32. For the purpose of determining causation, all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry have been evaluated. First of all there is no sudden, sharp and significant surge in import and the factors like production, domestic sales, capacity utilization, productivity have improved during the period of investigation. Secondly the landed price of imports is higher than the selling prices of the domestic industry during POI. The imports were thus not suppressing the Domestic Industry prices in the market and price undercutting is negative. Thus, there are indications that the Domestic Industry is not suffering on account of import prices. The profitability of the Domestic Industry has decreased during period of investigation but that seems to be due to increase in depreciation charges, power & fuel charges and finance charges. It appears that imports is not responsible for decline in profitability of domestic industry.

#### I. Adjustment Plan:

33. Rule 5(2)(b) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 requires submission of a statement on “efforts being taken or planned to be taken or both to make positive adjustment to import competition”. Further Article 7.1 of WTO Agreement on Safeguard provides that a member shall apply safeguard measure only to the extent necessary to prevent or remedy serious injury and facilitate adjustment.
34. The purpose of definitive safeguard measure is to provide the domestic producers with a limited period of time in which to restructure so as to more effectively compete with the imports. Section 8B (4) of Customs Tariff Act 1975 and Rule 16(2) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules’ 1997 prohibits any possible extension of measure if there is no evidence that the domestic producers are adjusting.
35. Some of the interested parties have contended that the adjustment plan provided is incomplete and most of the information has been requested to be kept confidential by the Applicant.
36. The domestic producers in this case have laid down adjustment plan which is as under
- a. **Logistics Cost Reduction-** raw material accounts for almost 70% of the total cost, therefore reduction in the inbound logistic cost will have a significant impact on the overall cost structure
    - i. Conversion of import containers to exports- Container Triangulation.
    - ii. Use of cost effective ports
    - iii. Selection of shipping lines based on the total landed cost
    - iv. Reduction in turnaround time of trailers in the plant
    - v. Initiatives for reducing detention and demurrage
    - vi. Logistics initiatives at Jajpur
    - vii. Other Initiatives
  - b. **Savings In Process Cost**
    - i. Cost Savings in Steel Melt Shop ( SMS)
    - ii. Cost Savings in Hot Strip Mill (HSM)
    - iii. Cost savings in Cold Rolling Mill (CRM)
  - c. **Lowering Of Fixed Cost Per Unit-** Ramp up of Odisha Plant will reduce Fixed Cost/MT for 400 series
  - d. **Savings In Procurement Cost-** a five pronged strategy for lowering costs as suggested by the specialized consultant.
    - i. **Use Of Alternative Raw Materials-** Use of melting grade nickel and utility nickel as an alternative to pure nickel because of the discounts applicable on the import of such items and Use of alternate forms of MS Scrap like Shredded HMS, LMS bales & incinerated scrap
    - ii. **Developing New Suppliers-** New suppliers identified for key raw materials like Ferro Nickel & Direct Reduced Iron
    - iii. More efficient management of working capital in the area of ss scrap procurement
    - iv. Improvement initiatives in the area of flux procurement
    - v. Optimization of raw material mix

<sup>2</sup> [Panel Report on Korea — Dairy](#), paras. 7.89–7.90

**e. Cost reduction initiatives from Odisha phase i**

- i. Better capacity utilization in Phase II will lead to greater demand for power and Ferro Chrome
- ii. Coke oven gas generated in Phase I can be used as a substitute for propane in Phase II.

37. I find that the thrust is on reduction in the cost of manufacture and cost of sale. However, the adjustment plan lacks credibility in absence of corroboratory evidences.

**J. Unforeseen developments:**

38. It has been contended by the domestic industry that there is no express obligation/requirement on the Director General (Safeguards) to analyse unforeseen circumstances as there is no specific requirement in the Indian Law and even in the GATT or the WTO Agreement on Safeguards, there is no specific guidelines or methodology that should be followed for analysing unforeseen developments. In this regard, I find that Article XIX of GATT,<sup>94</sup> provides that serious injury has to be as a result of unforeseen developments.

39. Article XIX of GATT 1994 states as follows:

*1.(a)If, as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a contracting party under this Agreement, including tariff concessions, any product is being imported into the territory of that contracting party in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten serious injury to domestic producers in that territory of like or directly competitive products, the contracting party shall be free, in respect of such product, and to the extent and for such time as may be necessary to prevent or remedy such injury, to suspend the obligation in whole or in part or to withdraw or modify the concession.*

40. The Appellate Body in Argentina – Footwear (EC case) held that the phrase “Unforeseen Developments” means the developments which were unexpected. ‘Unforeseen developments’ requires that the developments which led to a product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers must have been ‘unexpected’. The Appellate Body in Korea-Dairy case held that unforeseen developments are developments not foreseen or expected when the member incurred that obligation.

41. The Appellate Body, in Argentina — Footwear (EC), then held that the requirement of “unforeseen developments” did not establish a separate “condition” for the imposition of safeguard measures, but described a certain set of “circumstances”.

42. The domestic industry has submitted the following as unforeseen developments resulting in increased import:-

- a) **Significant Global Demand supply gap since 2010**
- b) **Huge Demand supply gap in Western Europe**
- c) **Huge Demand supply gap in Japan**
- d) **Korea’s aggressive enhancement of capacities without having much domestic demand. FTA/PTA entered by the Indian Govt. with different countries like Korea, Japan and ASEAN Countries**
- e) **Continued imports despite anti dumping duty levied in India**
- f) **Imposition of trade measures against various major players**

43. No evidences have been produced to prove the causal nexus between the alleged increase in imports into India and global demand-supply gap. Interested parties contended that the domestic industry clearly had the information about expanding capacities in Europe and Korea as they filed application for anti- dumping with DGAD authorities mentioning these situation in the year 2010 and hence demand supply gap in western Europe and Korea is well in the knowledge of domestic industry and hence the alleged development is not unforeseeable. With regard to demand supply gap in Japan , the evidences submitted by domestic industry pertains to entire Cold Rolled Steel and not specific to CRSS 400 series. From the data provided by Domestic industry, it has been observed that demand supply gap of product under consideration has increased internationally, which has resulted in unprecedented and uneven surplus capacities with global producers of the product under consideration. This has forced the global producers to search for markets even at reduced prices. Vast Indian highly price sensitive market is becoming a choice for the foreign producers, resulting in surge in imports. This constitutes unforeseen developments but this development has not resulted in the sudden, sharp

and significant increased import so as to cause serious injury to the domestic industry during the period of investigation.

44. *It has been argued by some of the Interested Parties that reduction in duty rates pursuant to an FTA/PTA is neither unforeseeable nor unexpected but rather common knowledge. I agree with this contention of the interested parties to the extent that the provision of FTA had already envisaged lowering of tariff as well as the reasonable expectation that due to this, imports may increase.*
45. The contention of domestic industry that despite the existence of anti-dumping duty, it has continued to suffer injury is not acceptable as at present a sunset review for Cold Rolled flat products of stainless steel of all series is being conducted by anti-dumping authority vide their initiation notification dated 17/04/2014 to review the need for continuance of anti-dumping duty and if domestic industry is indeed injured, Antidumping authority will take care of the problem.
46. It is thus seen that in the instant case, if it is presumed that the arguments put forth by the domestic industry as the reason for increase in imports may be unforeseen but same cannot be considered, as the surge in imports is not sudden sharp and significant and domestic Industry is not suffering on account of import.

**K. Public Interest:**

47. Interest of domestic producers alone cannot be seen as public interest. Even if it is admitted that imposition of safeguard duty on the product under consideration shall protect the domestic producers, the same cannot be termed as public interest. The losses incurred by the domestic industry appears to be due to high depreciation charges, power & fuel charges and finance charges. Paragraph 2 of Annex to Rule 8 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997, states that "when factors other than increased imports are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports.". Keeping in mind that increased import (which is not sudden, sharp and significant) is not responsible for decline in profitability of domestic industry, I am of the view that imposition of safeguard duty will not be in public interest.

**L. Conclusion:**

48. The imports of the product under consideration showing increasing trend in absolute terms but same is not falling under the category of sudden, sharp and significant increase in imports of PUC during the period of investigation as the import increased during the period 2012-13 w.r.t 2011-12 by 20247 MT but decreased during 2013-14 w.r.t 2012-13 by 2290 MT. It means the rate of import actually decreased. It is thus concluded that there is no surge in imports during the Period of Investigation, both in absolute terms as well as in relation to domestic production.
49. Production, domestic sales, capacity utilization, productivity have improved during the period of investigation. However, the Domestic Industry is indeed suffering losses with a negative return on capital employed. From the annual report of DI, it is clear that fixed costs of the domestic industry have been consistently increasing since 2011-12. This increase in fixed costs is commensurate with steep decline in profitability projected in the application filed by the domestic industry. Inventories with the Domestic Industry have slightly improved in Dec, 2014. Price undercutting was negative throughout the period. Thus, an evaluation of the overall position of the Domestic Industry, in the light of all the relevant factors having a bearing on the situation of the Domestic Industry, it is observed that the position of the domestic industry improved and they are running on operating profits and there are some other factors, like abnormally high depreciation and finance charges which are causing net losses to the domestic industry. This conclusively shows that it is not imports but some other factors, which are responsible for losses to domestic industry. Therefore, the causation analysis fails in the present investigation.
50. Thus, there exists no serious Injury or threat of serious injury to the domestic industry in the period of investigation and hence no protection is required under safeguard law.

**M. Recommendations:**

- 
51. In view of the discussions detailed above and the conclusions reached, safeguard duty on the imports of the PUC is hereby not recommended and the investigation in this case is terminated.

[ F. No. D-22011/17/2014 ]

R.K SINGLA, Director General.